

( सभापतीस्थानी मा.तालिका सभापती श्री. मोहन जोशी )

तालिका सभापती ( श्री.मोहन जोशी ) : नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चेला सुरुवात करण्यात येत आहे.

पृ.शी. राज्यात भेसळ युक्त दुधाची होत असलेली विक्री

मु.शी. राज्यात भेसळ युक्त दुधाची होत असलेली विक्री  
या विषयावर श्री. एस.क्यू.जमा, राजन तेली, प्रकाश  
बिनसाळे, श्रीमती उषाताई दराडे, सर्वश्री हेमंत टकले,  
रमेश शेंडगे, विक्रम काळे, किरण पावसकर, डॉ.दीपक  
सावंत, डॉ.नीलम गोन्हे, सर्वश्री दिवाकर रावते, परशुराम  
उपरकर, जयवंतराव जाधव, अनिल भोसले, संदिप  
बाजोरीया, संजय केळकर, विनोद तावडे, रामनाथ मोते,  
सतिश चव्हाण, एम.एम.शेख, मनिष जैन, चरणसिंग सप्रा,  
माणिकराव ठाकरे, प्रा.सुरेश नवले, सर्वश्री अरुण  
गुजराथी, अशोक उर्फ भाई जगताप, चंद्रकांत पाटील,  
भगवानराव साळुंखे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती अलका  
देसाई, सर्वश्री सुभाष चव्हाण, उल्हास पवार, श्रीमती दिप्ती  
चवधरी, सर्वश्री जयप्रकाश छाजेड, मोहन जोशी, जैनुद्दीन  
जव्हेरी, श्रीमती शोभाताई फडणवीस, सर्वश्री केशवराव  
मानकर, रामदास कदम, दिपकराव साळुंखे, डॉ.सुधीर  
तांबे, सर्वश्री अमरनाथ राजुरकर, धनंजय मुंडे, वि.प.स.  
यांनी उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा.

**तालिका सभापती** : या अल्पकालीन चर्चेसंबंधी औपचारिक प्रस्ताव मांडता येणार नाही.

सूचना देणारे सन्माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा आपली सूचना वाचतील आणि भाषण करतील.

श्री.एस.क्यू.जमा (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 97 अन्वये आपल्या अनुमतीने पुढील विषयावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करतो.

"राज्यातील सहकारी खाजगी दूध डेअरी, दूध संघ, यांच्यामार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या दूधात पाण्याबरोबरच युरीया, ग्लुकोज, चरबी, वॉशिंग पावडर, मिसळली जात असल्याने 65 टक्के दूध भेसळ असल्याची बाब फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने दिलेल्या अहवालाद्वारे

श्री एस. क्यू. ज़मा....

नुकतीच उघडकीस येणे, राज्यातील प्रमुख शहरांतील दूध भेसळीमुळे जनतेच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असून गर्भवती महिला व लहान मुलांना गंभीर आजार होत असणे, अन्न व औषध प्रशासनात सह आयुक्तापासून सहाय्यक आयुक्तांपर्यंतची विविध सुमारे 178 पदे रिक्त असल्याचे तसेच पुणे शहरात अन्न सुरक्षेसाठी फक्त 13 अधिकारी असल्याचे उघडकीस येणे, सदरहू पदे रिक्त असल्यामुळे अन्न भेसळीची वेळेवर तपासणी होत नसणे, ही रिक्त पदे तात्काळ भरणे आणि भेसळयुक्त दूधाची विक्री थांबवून सकस व उत्तम दर्जाचे दूध उपलब्ध व्हावे याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना."

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इसी महीने की 13 तारीख को तारांकित प्रश्न की चर्चा के दौरान आए हुए प्रश्न के संदर्भ में कहा था कि इस विषय पर वे अल्पकालीन चर्चा की अनुमति देंगे. अपनी उसी रुलिंग के अनुसार माननीय सभापति महोदय ने इस विषय पर आज हमें अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से अपने विचार यहां पर रखने का मौका दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं माननीय सभापति महोदय का तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं.

सभापति महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार यहां पर रखना चाहते हैं. इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार यहां पर रखना चाहूंगा. यह इतना सामान्य विषय है कि सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है और आम लोग भी इस समस्या से अच्छी तरह से परिचित हैं. हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए ही मैं इस विषय की चर्चा यहां पर शुरू कर रहा हूं.

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों यह विषय अखबारों में काफी चर्चित हुआ. इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट में भी इस बारे में एक पीआईएल दाखल हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार और यहां पर जो महाराष्ट्र मिल्क डेअरी फेडरेशन है, महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, उनको भी नोटिस दिया गया. मेरी जानकारी के अनुसार उस पीआईएल पर अभी चर्चा चालू है, उस संबंध में फाइनल ऑर्डर अभी नहीं आया है.

श्री एस. क्यू. ज़मा....

सभापति महोदय, मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में छोटे बच्चों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध ही सबसे अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रीशन है. हमारे यहां पर दूध की सप्लाई या तो निजी पैकिंग कंपनियां करती हैं या फिर को-ऑपरेटिव सोसायटीज के मार्फत उसकी सप्लाई की जाती है. उस दूध में 60-65 या 70 प्रतिशत तक यदि मिलावट हो तथा उस दूध में पानी की मात्रा भी ज्यादा हो तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए यह दूध कितना हानिकारक हो सकता है. जांच से मालूम पड़ा है कि यूरिया, चरबी, वाशिंग पावडर जैसे हानिकारक पदार्थ दूध में मिलाए जाते हैं. इस तरह की अशुद्धता उस मिलावटी दूध में पाई गई हैं. हमारे शरीर के लिए इतने हानिकारक पदार्थ उस दूध में यदि मिलाए जाएंगे तो उस दूध को पीने के बाद कितना विपरित परिणाम या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर होगा इसका अंदाज सहज रूप से लगाया जा सकता है. यह दूध उस क्षेत्र के बच्चों के लिए तो और भी हानिकारक साबित हो सकता है, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और जिस जगह के बच्चे पहले से ही बहुत कमजोर तथा कुपोषण के शिकार हैं.

सभापति महोदय, यह बात सही है कि इन सब गलत चीजों को रोकने के लिए हमारे यहां पर फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन नाम की संस्था पहले से ही है. उस संस्था के द्वारा खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जाती है और वे दावा करते हैं कि उन्होंने समय-समय पर इतने खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई तथा उन्होंने समय-समय पर उनके खिलाफ ये-ये कार्रवाइयां भी की हैं. मेरा कहना है कि उनके द्वारा पाए गए मिलावटी केसीज की संख्या बहुत कम है. वास्तव में देखा जाए तो मिलावटी पदार्थों की संख्या हमारे यहां पर बहुत ज्यादा है.

सभापति महोदय, हमारे एफडीए विभाग की हालत भी किसी से छिपी नहीं है. इस विभाग के पास आवश्यक स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी इस विभाग के पास नहीं है, प्रॉपर नेटवर्किंग भी इस विभाग के पास नहीं है. मिलावटी सामान का पता लगाने के लिए इस विभाग के पास फूल प्रुफ चेकिंग सिस्टम नहीं है. अपनी मन-मर्जी के हिसाब से किसी इंस्पेक्टर ने कहीं पर छापा मार दिया और एकाध बार कहीं पर मिलावटी सामान का कोई केस इनके हाथ लग गया तो वे एफआईआर दर्ज करा देते हैं. इस तरह की व्यवस्था इस विभाग की है. परन्तु मिलावटी सामान पकड़ने का कोई परफेक्ट आधुनिक सिस्टम इस विभाग के पास नहीं

..4

श्री एस. क्यू. ज़मा....

है. किसी व्यक्ति पर कभी कोई केस दर्ज कर भी दिया तो वे मामूली सी जमानत देकर वापस घर आ जाता है. मुश्किल से हजार-पांच सौ रुपए जुर्माना किया जात है. उस छोटे-मोटे जुर्मान से उन पर कोई असर नहीं पड़ता. क्योंकि जो लोग मिलावट करके लाखों-करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन को थोड़े-बहुत जुर्माने से क्या फर्क पड़ने वाला है. जो केस उनके खिलाफ दर्ज भी होता है, अच्छे वकील को लगाकर उस केस को भी वे खत्म करा देते हैं. ये सब बातें सभी माननीय सदस्यों का अच्छी तरह से मालूम हैं.

इस चर्चा के माध्यम से मैं महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, वहां के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. मेरा कहना है कि मिलावट को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीनरी हमको तैयार करनी पड़ेगी. अभी यह व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस तरह की मशीनरी को जल्द से जल्द तैयार करने की जरूरत है. अपने मन मुताबिक कहीं पर रेन्डम चेक करके बोल देते हैं कि वहां 80-90 प्रतिशत से ज्यादा केसीज सही पाए गए और 2-4 प्रतिशत केसीज में ही मिलावट पाई गई, जबकि वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है. वास्तव में देखा जाए तो मिलावटी पदार्थों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको पकड़ने का कोई सही तरीका या आधुनिक तरीका हमारे सरकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. इसलिए मेरा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर ऐसी कोई एक मशीनरी तैयार करे जिसके मार्फत इन गलत लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सके. यह चेकिंग प्रोसेसिंग स्टेज से लेकर डिस्ट्रीब्युशन स्टेज तक सभी जगहों पर होनी चाहिए. हमारे यहां पर गांवों से लेकर बड़े शहरों तक करीब तीन-चार सौ पैकिंग कंपनियां हैं. मेरा कहना है कि इन पैकिंग फूड के लिए जहां से कलेक्शन होता है, जहां पर प्रोसेसिंग होती है, जहां पर पैकिंग होती है तथा जहां पर इसका डिस्ट्रीब्युशन होता है, यानी कलेक्शन से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक की सभी जगहों पर इस सामान पर सरकारी विभाग का चेक रहना बहुत आवश्यक है. इसके अलावा एक सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम भी सभी कंपनियों में होना चाहिए यानी जो इसके मालिक हैं, ये मालिक चाहे को-ऑपरेटिव सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों या ये सरकारी विभाग की यूनिट हों इन

..5

श्री एस. क्यू. ज़मा....

सभी को वहां पर कड़क चेक रखना चाहिए. इस सबके बाद भी वहां पर सरकारी विभाग द्वारा कड़क चेकिंग होनी चाहिए. हमें देखना चाहिए कि हर स्तर पर सामान की क्वालिटी संबंधी चेकिंग हो. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिय ने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, उसके मुताबिक यदि उस सामान का स्टैंडर्ड नहीं है तो गलती करने वाले लोगों पर कड़क कार्रवाई किया जाना बहुत आवश्यक है.

सभापति महोदय, मेरा तो व्यक्तिगत मत यह है कि मिलावट किसी भी समान में हो, चाहे  
नंतर श्री.सरफरे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री एस. क्यू. ज़मा....

वह दूध में हो या किसी दूसरे किसी सामान में मिलावट की गयी हो, उन पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए. आज स्थिति यह है कि जीवन रक्षक दवाईयों में भी मिलावट की जाती है. जो दवाईयां जीवन रक्षा के लिए बनायी जाती हैं, उन दवाईयों में भी यदि मिलावट होती है तो फिर इससे गलत काम और क्या हो सकता है ? मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को तो कॅपटिव पनीशमेंट दी जानी चाहिए. ऐसे लोगों को मौत की सजा दिया जाना बहुत आवश्यक है. जो लोग दवाई में, दूध में तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, उनको तो क्रिमिनल माना जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इससे बड़ा क्राइम तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता. It is crime against humanity. अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों की जान से खेलने वाले लोगों को तो मौत की सजा ही दी जानी चाहिए. मुझे लगता है कि यदि हमने उनको कॅपटिव पनीशमेंट की सजा दी तो मिलावट करने का यह दुष्कर्म 50 प्रतिशत तो अपने आप ही रुक जाएगा.

इसलिए आखिर में एक-दो बातें कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं. मेरा कहना है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए. सेल्फ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए. इसके लिए मॅन पावर पूरी तरह से अपने पास होना चाहिए तथा एक स्ट्रॉंग मॅकेनिजम बनाया जाना चाहिए. पैकिंग सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक होनी चाहिए. ताकि किसी भी स्टेज पर या किसी भी स्थिति में मिलावट जैसा गलत काम नहीं हो सके तथा गलत लोगों को हम समय पर पकड़ सकें. मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि 24 ऑवर्स के लिए एक हेल्प लाइन सिस्टम भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति कहीं पर मिलावट होने की घटना देखता है तो वह व्यक्ति तुरंत उस मिलावट की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे सके.

सभापति महोदय, मेरा अंतिम सुझाव यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्युश के लिए जिस तरह से एगमर्क लगाने की व्यवस्था की गयी है उसी तरह यहां मिल्क पर भी मिल्क-मार्क लगाने की व्यवस्था यदि हम कर सके तो बहुत अच्छा होगा ताकि दूध की क्वालिटी की स्ट्रीक्ट मॉरिटरिंग हो सके.

अंत में फिर से मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो मिलावट के इस पाप से निबटने के लिए कॅपटिव पनीशनमेंट का प्रावधान यदि यहां पर किया जा सकता है तो वह किया जाना चाहिए. इतना ही मुझे कहना है. धन्यवाद.

नंतर श्रीमती रणदिवे

श्री.हेमंत टकले (विधानसभेद्वारा निर्वाचित) : सभापती महोदय, याठिकाणी नियम 97 अन्वयेच्या अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून आज एका अतिशय जीवनावश्यक विषयाच्या बाबतीत उहापोह या सदनमध्ये होत आहे. गेल्या काही दिवसापासून वर्तमानपत्रातून आणि वाहिन्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दुधातील भेसळीचे अनेक किस्से पहावयास मिळाले आणि वाचावयास मिळाले.एकूणच या राज्यामध्ये जीवनावश्यक आणि विशेषतः लहान मुलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या दुधाच्या बाबतीत ज्याप्रमाणात युरिया, ग्लुकोज, चरबी, वॉशिंग पावडर इ.पदार्थांची सर्रास भेसळ करून अतिशय दूषित दुधाचा पुरवठा संपूर्ण राज्यभर होत असल्याचे आता निदर्शनास आले आहे. या बाबतीत वर्षभरापूर्वीच दूधामध्ये वॉशिंग पावडरचा वापर करून भेसळ करण्यात आली होती. तसेच ज्या काही मान्यताप्राप्त दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्था आहेत, त्याठिकाणी वितरणाच्या स्तरावर फेरफार करून दुधामध्ये भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे हा अतिशय गंभीर आणि धोकादायक असा विषय झाला आहे.

सभापती महोदय, राज्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभाग आहे आणि या विभागामध्ये गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये ज्या प्रमाणात तांत्रिक कौशल्य आणि मनुष्य बळामध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते,ते तेवढे दुर्दैवाने झालेले दिसत नाही.त्यासाठी शासन यंत्रणेकडे जी तत्परता असावयास पाहिजेत, ज्या प्रमाणात प्रयोगशाळा निर्माण व्हावयास पाहिजेत तसेच या सर्व बाबींवर देखरेख करण्यासाठी असलेली जी यंत्रणा आहे ती देखील सजग व्हावयास पाहिजे.परंतु प्रत्यक्षात याबाबतीत अजून खूपच काही गोष्टी करावयाच्या राहून गेलेल्या आहेत असे चित्र आपल्यासमोर येते.खरे म्हणजे दुधाच्या आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या भेसळीबद्दल आपल्याला माहिती असते की, दिवाळी आली की ठिकठिकाणी दुधापासून तयार केलेल्या पदार्थांचा भेसळयुक्त साठा जप्त केला जातो. मला आठवते काही दिवसांपूर्वी माननीय गृह मंत्री महोदयांनी स्वतःभल्या पहाटे उठून ज्याठिकाणी वितरण यंत्रणे- मध्ये भेसळ होण्याची शक्यता आहे अशा ठिकाणी धाडी घालून भेसळ काही प्रमाणात रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. याबाबतीत गृह विभागाचे आणि आपल्या विभागाचे नेमके अधिकार काय आहेत, आपल्याकडे मनुष्यबळ किती आहे आणि या व्यवसायात असलेल्या लोकांच्या प्रमाणिकतेबद्दलची कायमची कसोटी कशा पध्दतीने करता येईल याबाबतीत कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे.

सभापती महोदय,गेल्या काही महिन्यापूर्वी असे लक्षात आले की, राज्यातील खाजगी दूध वितरण व्यवस्थेमधील आणि दूध निर्मितीमधील ज्या प्रमुख संस्था आहेत,त्यांच्या दुधाच्या दर्जाबद्दल

श्री.हेमंत टकले . . . .

लोकांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण झालेला असतो. अशा वेळी वितरणाच्या माध्यमातून जेव्हा हे दूध ग्राहकांपर्यंत जाते तेव्हा या यंत्रणे मध्ये कुठेतरी फार मोठ्या प्रमाणात तेथे चुकीचे गैरमार्ग वापरले जात असल्याचे लक्षात आले आहे आणि आरोग्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. यासाठी आपल्या विभागामध्ये एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याची आवश्यकता असेल तर याबाबतीत विचार करावा. यासाठी आपल्याला ज्यांच्या देखरेखीखाली एखादे पथक निर्माण करावयाचे असेल तर ते करावे अशी माझी सूचना आहे. तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.सय्यद जमा यांनी सुरुवातीला सांगितले की, जे कोणी दुधामध्ये भेसळ करणारे लोक आहेत त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला तरतूद करता आली तर त्यादृष्टीने देखील कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो व माझे भाषण संपवितो.

---

यानंतर श्री.बरवड . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी



डॉ. नीलम गोन्हे ( विधानसभेने निवडलेल्या ) : सभापती महोदय, दूध भेसळीच्या संदर्भात दोन्ही सभागृहांमध्ये वारंवार चर्चा होते परंतु आज विधान परिषदेमध्ये याच विषयावर विस्तृत चर्चेसाठी माननीय सभापती महोदयांनी अनुमती दिली आणि त्यावर आज चर्चा होत आहे त्याबद्दल मी सर्वप्रथम माननीय सभापती महोदयांचे आभार मानते. यामध्ये पाच सहा मुद्दे स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या महिन्यात 15 एप्रिलला दूध भेसळीच्या संदर्भात तीन महिन्यात निर्णय घ्या अशा पध्दतीचे आदेश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. आपण जर हे आदेश पाहिले तर त्यामध्ये पारनेरमधील दूध उत्पादक संघटनेचे श्री. गुलाबराव ढेरे यांनी जी याचिका दाखल केली त्या निमित्ताने काही महत्वाचे मुद्दे रेकॉर्डवर घेणे गरजेचे आहे. या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपण सांगतो की, दूध भेसळ हा संघटित गुन्हा असून त्याला फाशीची शिक्षा देऊ. परंतु मुळामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी जो अहवाल प्रसिध्द केला आहे त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 65 टक्के दुधामध्ये भेसळ आहे असे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्या संदर्भात गोवा आणि पॉण्डेचरी राज्यामध्ये शून्य टक्के भेसळ आहे. याचा अर्थ असा की, एखादी गोष्ट करून दाखवावयाची ठरविली तर ती करून दाखविता येते आणि ते गोवा आणि पॉण्डेचरी राज्यामध्ये करून दाखविलेले दिसते पण महाराष्ट्रामध्ये ते झालेले दिसत नाही. अन्न भेसळ रोखण्याबरोबरच दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी आम्ही काय पावले उचलतो हा पहिला मुद्दा आहे आणि त्याकडे मी शासनाचे लक्ष वेधू इच्छिते.

सभापती महोदय, दुसरा मुद्दा असा आहे की, ही संघटित गुन्हेगारी आहे. आमच्या स्मरणाप्रमाणे सन्माननीय श्री. अजितराव पवार यांनी विधानसभेमध्ये जाहीर केलेले आहे की, दूध भेसळीसाठी फाशीची शिक्षा मिळाली तर आम्ही देऊ. परंतु फाशीच्या शिक्षेपर्यंत जाण्याच्या आधी चार्ज शीट दाखल होणे, गुन्हा सिध्द होणे, त्यांना अटकपूर्व जामीन न मिळणे, सक्त मजुरी या सगळ्या पायऱ्या आहेत. त्यामुळे फाशीची शिक्षा सिध्द होईपर्यंत जाण्यासाठी दूध भेसळ करणारे लोक कोठे कोठे सापडले हे जर दिसले तर गेल्या वर्ष दोन वर्षांमध्ये जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते सातारा, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली या पश्चिम महाराष्ट्रातील सगळ्या ठिकाणी त्याची लिंक दिसते आणि ती मुंबईपर्यंत पोहोचलेली आहे. यामध्ये असे चित्र दिसते की, मुंबईमध्ये या रिकाम्या दुधाच्या पिशव्या इतर वस्तू ठेवण्यासाठी धुऊन स्वच्छ करून ठेवतात त्या

RDB/ D/ KTG/

डॉ. नीलम गोन्हे .....

पिशव्या नंतर बाजारात जातात आणि परत त्या दुधाच्या पिशव्यात दूध भरून त्या सिल केल्या जातात. अशी ही संघटित गुन्हेगारी आहे. माझा पुढचा मुद्दा असा आहे की, एफडीएमधील काही पदे रिक्त आहेत. ती पदे भरलेली आहेत असे सांगण्यात येते. आतापर्यंत जे जे गुन्हे दाखल झाले, ज्याच्यावर विधानसभेत आणि विधान परिषदेत चर्चा झाली, त्या गुन्ह्यांमधील आरोपींना कोणत्या प्रकारची शिक्षा केलेली आहे, कोर्टांमध्ये गुन्हे दाखल झाले का, याबद्दल आपण सध्याच्या पटलावर सविस्तर माहिती मांडली पाहिजे. हे लोक जर परत नामानिराळे असतील तर त्यांच्या पाठीमागे फार मोठे सूत्रधार आहेत हे यामधून स्पष्ट होते.

सभापती महोदय, या दूध भेसळीचा फटका आपल्या परिचयातील हजारो लोकांना बसतो. यामुळे अनेक आजार होतात, लोकांची पोटे बिघतात, अॅलर्जी होते. या दुधामध्ये बहुतेक वेळा युरीक ॲसिड किंवा त्यासारख्या अन्य अतिशय विषारी गोष्टी मिसळलेल्या असतात. यामध्ये जे लोक सापडले त्यामध्ये वैयक्तिक एक एक समाजकटक नसून समाजातील अनेक घटक त्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत, असे दिसते. म्हणून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जे आदेश दिलेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी दुधाची भाववाढ करणे, दूध भेसळ रोखणे आणि दूध भेसळ न रोखल्यामुळे सामान्य दूध उत्पादकांना त्याचा होणारा त्रास याबाबत स्पष्ट म्हटले आहे. या सगळ्या मुद्द्यांवर आपल्याला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. परंतु या चर्चेचे फलित काय आहे ? आपण चर्चा करतो. चर्चा केल्यानंतर लोक आपल्याला विचारतात की, चर्चेतून काय निघाले ? त्यामुळे यातील काही खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात नेऊन ते गुन्हे सिध्द होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या पाठीमागे कोण सूत्रधार आहेत हे शोधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण एक टास्कफोर्स तयार करून पुढच्या दोन महिन्यामध्ये असे काही खटले निकाली निघण्यापर्यंत आम्ही काही प्रगती केली असेल का या संदर्भामध्ये राज्य सरकारकडून उत्तर अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर दूध भेसळ रोखण्यासाठी जी पथके आहेत आणि ठराविक जिल्ह्यांमधील जे स्पॉट आहेत त्या ठिकाणी आता आपण कोणत्या प्रकारची पावले उचललेली आहेत हे देखील स्पष्ट व्हावे अशी आमची अपेक्षा आहे. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपविते.

---

...3...

श्री. रामनाथ मोते ( कोकण विभाग शिक्षक ) : सभापती महोदय, या सदनाने सन्माननीय सदस्य श्री. जमा आणि अन्य सन्माननीय सदस्यांनी जी चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे आणि माननीय सभापती महोदयांनी या चर्चेला जी अनुमती दिली त्यामुळे या महत्वाच्या विषयावर आज चर्चा होत आहे त्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी दूध भेसळीच्या संदर्भात आपले विचार मांडलेले आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की, सातत्याने आम्ही दररोज वर्तमानपत्रातून बातम्या वाचतो की, अन्य खाद्य पदार्थांमध्ये जशा प्रकारची भेसळ होते त्याच पध्दतीने ज्या दुधाला आम्ही पूर्ण अन्न समजतो त्यामध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत आहे.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.रामनाथ मोते...

या राज्यातील, या देशातील गोरगरीब, सर्व सामान्य, अगदी लहान मुलांपासून अबाल वृद्ध लोक दुधाचे सेवन करतात. चांगले दूध मिळण्याचा त्यांचा हक्क असताना त्यांना भेसळयुक्त दूध दिले जात असेल व त्याचा दुष्परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत असेल तर ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.

जानेवारी महिन्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरणाने भेसळीच्या संदर्भात केंद्र शासनाला अहवाल एक सादर केलेला आहे. त्या प्राधिकरणाने देशातील 30-32 राज्यांमधील विविध विभागातील दुधाचे नमुने घेतले होते. त्या नमुन्यांची तपासणी केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 65 ते 68 टक्के भेसळयुक्त दूध असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब आहे. केवळ महाराष्ट्रातच दुधामध्ये भेसळ होत आहे असे नाही तर देशातील इतर राज्यांमध्येही होत आहे. हे खरे असले तरी 100 टक्के भेसळमुक्त दूध सुध्दा काही राज्यांमध्ये दिले जाते. पॉण्डेचेरी या राज्यात 100 टक्के चांगले दूध मिळते.

सभापती महोदय, दुधाच्या भेसळीच्या बातम्या सातत्याने वर्तमानपत्रात छापून येत असतात. "कराड तालुक्याचा दूध भेसळीत अव्वल क्रमांक, सहकारी संस्थांना मलई, ग्राहकांना पाणीदार दूध, सातारा जिल्ह्यातील 56 ते 60 दूध सेंटर्सची तपासणी केल्यानंतर, धाडी टाकल्यानंतर भेसळयुक्त दूध आढळून आले, त्यासंबंधी 83 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केलेले आहेत," अशा प्रकारच्या बातम्या वर्तमान पत्रातून आल्या होत्या. 83 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यापूर्वीही दूध भेसळीसाठी अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात, त्यांना पुढे कोणती शिक्षा झाली, त्या प्रकरणाचे काय झाले याची कोणतीही माहिती वाचण्यात येत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकांपासून वितरकापर्यंत एक साखळी तयार झालेली आहे. दुधात भेसळ करणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा झालेली नसल्यामुळे त्यांच्यावर जरब बसलेली नाही. आपण दुधात भेसळ केली तर आपल्याला कडक शिक्षा होऊ शकते असा धाक त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेला नाही किंवा तो निर्माण करण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. जनतेला भेसळमुक्त दूध दिले पाहिजे असे शासनाला सुध्दा वाटत नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. भेसळीच्या संदर्भात जो कायदा

2....

NTK/ KTG/ D/

श्री.रामनाथ मोते....

आहे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन भेसळ करणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. नव्हे तशी शासनाची भूमिका असावयास पाहिजे. शासनाने त्यादृष्टीने महत्वाच्या उपाययोजना कराव्यात अशी मी या निमित्ताने मागणी करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि माझे मनोगत पूर्ण करतो.

-----

3....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

प्रा.सुरेश नवले ( नामनियुक्त ) : सभापती महोदय, आदरणीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा साहेबांनी अतिशय महत्वाच्या विषयावर नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा सभागृहात उपस्थित केलेली आहे. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी व माझे विचार मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे.

सभापती महोदय, दूध हे पूर्ण अन्न आहे. पृथ्वीतलावर दूध अमृत समजले जाते. परंतु दुर्दैवाने हे अमृत नासवण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात सुरु आहे. पूर्वी ऋषी मुनींच्या आश्रमामध्ये गाईचे पालनपोषण, संगोपन होत असे. ज्याच्याकडे दूधदुभते अधिक त्याच्यावरून त्याचे ऐश्वर्य मोजले जात असे. दुधामध्ये पहिली भेसळ केव्हा सुरु झाली याचा मी विचार करीत होतो. दुधाच्या भेसळीची सुरुवात महाभारतापासून झाली असल्याचा इतिहास सांगतो. अश्वत्थामाला त्याच्या आईने भेसळयुक्त दूध दिले होते. पण ते मायाळू दूध होते.

यानंतर श्री.शिगम....

प्रा. सुरेश नवले...

परिस्थितीच्या रेट्यामुळे ती त्याला दूध देऊ शकली नाही. मग पाण्यामध्ये पीठ कालवून आपल्या मुलाला पहिल्यांदा भेसळयुक्त परंतु मायाळू दूध अश्वत्थामाच्या आईने दिले.

आज महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे भेसळयुक्त दूध मिळते. आमच्याकडे एक म्हैस दूध प्यायली. दूध संघाच्या वाहणा-या दुधाच्या पाटाचे दूध ती म्हैस 10-15 दिवस प्यायली. त्यामुळे तिच्या अंगावर गांधी आल्या आणि ती म्हैस मृत्युमुखी पडली. आणखी एक आश्चर्याची गोष्ट मी आपणास सांगतो. आमच्याकडे कुत्रा दूध प्यायला आणि त्याच्या अंगावरचे केस गेले. दूध प्यायल्या नंतर अंगावर केस येतात. पण दूध प्यायल्यानंतर अंगावरचे केस जातात हे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच घडले. लोकांनी तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाने प्रयोगशाळेत नमुने पाठविले. दूध संघ वस्ताद आहे. त्याने प्रयोगशाळा अॅरेंज केली. सगळे रिपोर्ट चांगले आले. दुधामध्ये कसलीही भेसळ नाही, दूध शरीराला पोषक आहे, चिंता करण्याचे कारण नाही, असे रिपोर्ट आले. मग अंगावरचे कसे कसे गेले, म्हैस कशी मेली ? याची जाणीव आपल्या अधिका-यांना असणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधीजींनी सत्याचे प्रयोग केले. त्यामध्ये दुधाचे महत्व विशद केलेले आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.विनायक मेटे हे नेहमी दूध पितात आणि मराठा महासंघाची संपूर्ण धुरा वाहतात.

सभापती महोदय, माझा मुद्दा एवढाच आहे की, दूध आहे तसे नैसर्गिक स्थितीमध्ये लोकांना मिळाले पाहिजे. सन्माननीय सदस्य श्री. एस.ब्यू.जमा यांना असे वाटते की, यानंतरची तरुण पिढी अतिशय निकोप अशा स्थितीमध्ये वाढावी, मुलांनी दूध पिरून अंगणामधून रणांगणामध्ये जावे आणि स्वतःचे कौशल्य दाखवावे. दूध हे शक्तिवर्धक आहे. अशा शक्तिवर्धक दुधामध्ये भेसळ करून त्याची उपयुक्तता उद्ध्वस्त करण्याचे काम कोणी करीत असतील तर त्याला प्रतिबंध करण्याचे सामर्थ्य शासनाने निश्चितच आहे. पण ते सामर्थ्य प्रकट होत नाही, ते प्रकट व्हावे एवढीच अपेक्षा व्यक्त करून मी माझे भाषण संपवितो.

---

..2..

श्री. विनायक मेटे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा यांनी नियम 97 अन्वये एका महत्वाच्या विषयावर या ठिकाणी चर्चा उपस्थिती केली त्याबद्दल मी त्यांचे आणि सभापती महोदय, आपण या चर्चेला परवानगी दिल्या त्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार मानतो.

सभापती महोदय, सर्वच सन्माननीय सदस्यांनी दूध भेसळीबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे. त्याबाबतीत अनेक कारणे सांगितली गेली. आता मुंबई शहराचेच उदाहरण घेऊ. मुंबईमध्ये शासकीय डेअरीमधून दूध येते, महानंदचे दूध येते, खाजगी दूध संघातून दूध येते, तबेल्यातून दूध येते, गुजरात राज्यातूनही दूध येते. या दुधामध्ये युरिया, चरबी टाकून भेसळ केली जाते. दूध उत्पादक हे पाणी आणि युरिया टाकून भेसळ करतात. त्यानंतर दूध संघ आणि खाजगी डेअरीवाले भेसळ करीत असतात. दुधामध्ये होणाऱ्या भेसळीला प्रथमपासूनच सुरुवात होते. दूध पातळ कसे अशी विचारणा केली तर सांगितले जाते की म्हैस अधिक पाणी प्यायली. दुधामध्ये होणा-या भेसळीला अनेक लोक जबाबदार धरता येतील. सन्माननीय सदस्य प्रा. सुरेश नवले यांनी सांगितले की, या भेसळीकडे अधिका-यांनी लक्ष दिले पाहिजे.

.....नंतर श्री. गिते...



श्री.विनायक मेटे.....

अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेच पाहिजे त्यात दुमत असण्याचे कारण नाही. ती त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु आज आपण पाहिले तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जेवढे दूध उत्पादन होते, या उत्पादन होणाऱ्या दुधापैकी बहुतांशी दूध उत्पादन आठ ते दहा जिल्हयांमध्ये होत आहे. खरी अडचण आठ ते दहा जिल्हयापुरती मर्यादित आहे.

महोदय, संपूर्ण विदर्भात 1 लाख लिटरही दूधाचे उत्पादन होत नाही. खानदेशात वेगळी परिस्थिती नाही. मराठवाडयातील बीड जिल्हयात 5 ते 6 लाख लिटर दूध उत्पादन होते, तेवढे दूध उत्पादन सोडले तर उर्वरित मराठवाडयात दूध उत्पादनाची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. हा आठ ते दहा जिल्हयांचा प्रश्न आहे. भेसळ कुठे होत असेल तर ती दूध उत्पादित होणाऱ्या आठ ते दहा जिल्हयात होत आहे म्हणून या आठ ते दहा जिल्हयांवर कंट्रोल करणे गरजेचे आहे. तसेच मुंबई शहरात देखील दूध भेसळ मोठया प्रमाणात भेसळ होत आहे त्यावर देखील कंट्रोल करणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी दूध भेसळीच्या विरोधात धाडी टाकल्या, अन्य कारवाई केली तर त्यांना लागलीच फोन येतात. दूध खरेदी विक्री संघ, खाजगी डेअऱ्या सगळया मोठया लोकांच्या आहेत. माननीय श्री.नवले साहेब, कोणते अधिकारी कारवाई करण्याची हिंमत करतील. मोठया लोकांवर अधिकारी कारवाई करू शकत नाही ही खरी मोठी अडचण आहे. या गोष्टीच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे.

महोदय, आमचे गृह राज्यमंत्री कोल्हापूर जिल्हयातील आहेत. कोल्हापूर जिल्हयात किती दूध उत्पादित होते याची त्यांना माहिती आहे. दुधात कोणत्या ठिकाणी भेसळ होते, दुधात पाणी कोठे टाकले जाते या सर्व गोष्टीची माहिती त्यांना आहे. दूध भेसळ बंद व्हावी यासाठी त्यांनी काही ठिकाणी प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नांना यश आले नाही. प्रयत्न करून ते थकले. मी त्यांच्या जिल्हयातील राजकारणात जाऊ इच्छित नाही. दुखणे म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला असा प्रकार भेसळीच्या बाबतीत सुरु आहे. तुम्ही म्हशीलाच का इंजेक्शन देत नाही ? म्हशीला इंजेक्शन दिले तरच तिचे दुखणे कमी होईल. यात मूळ मुद्दा असा आहे की, या सगळया मोठया मंडळींवर जोपर्यंत कंट्रोल आणणार नाही, तोपर्यंत ही भेसळ सुरु राहील. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दूध भेसळीचे प्रकार जास्त होत होते. याबाबतीत माननीय श्री.अजितदादा पवार यांनी कठोर भूमिका घेतली. खरे म्हणजे त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले पाहिजे.

2...

श्री.दिवाकर रावते : आम्हाला देखील बोलावे लागेल. माननीय श्री.अजितदादा यांचे कौतुक कशासाठी करीत आहात ?

श्री.विनायक मेटे : तुम्ही बोलू शकता. माननीय श्री. रावते साहेब, माननीय श्री. अजितदादा पवार यांचे नाव घेतल्या बरोबर तुम्हाला एवढे का वाईट वाटते हे मला कळत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दुधात जास्त प्रमाणात भेसळ होत होती, त्या भेसळीच्या विरोधात माननीय श्री. अजितदादा पवार यांनी कठोर भूमिका घेतली म्हणून त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. त्यांचे कौतुक मीच नव्हे तर सगळ्यांनी केले पाहिजे. तुमच्या सारख्या माणसांनी देखील त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. जे चूक आहे, ते चूक आहे असे म्हणण्याची दानत ठेवली पाहिजे. तशी दानत तुम्ही ठेवत नाही, तो भाग वेगळा आहे. दुधात भेसळ करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशी पर्यंतची शिक्षा दिली पाहिजे असे माझे मत आहे.

सभापती महोदय, गेल्या दोन,चार महिन्यापूर्वी औरंगाबाद येथे शेकडो टन भेसळयुक्त मावा पकडला गेला. तो कृत्रिम दुधातून निर्माण केलेला मावा होता. तो मावा गुजरात राज्यातून आलेला होता. आपल्या महाराष्ट्रावर कंट्रोल करून उपयोग नाही. गुजरात राज्यातून येणाऱ्या भेसळयुक्त दुग्ध पदार्थावर कंट्रोल कशा प्रकारे केले जाणार आहे याकडे शासनाने गांभीर्याने बघितले पाहिजे. आमच्या जिल्ह्यात तर केमिकलचे दूध तयार होत होते. ते सर्व दूध महानंदला जात होते. महानंद डेअरीतून सदर दुधाचे चांगले रिपोर्ट यावयाचे. दूध कोठे कोठे बनविले जात होते, दुधात भेसळ कोठे कोठे होते, या सर्व गोष्टींची माहिती सन्माननीय सदस्या अॅड.उषाताई दराडे यांना देखील आहे. या सगळ्या भानगडीमध्ये मला जावयाचे नाही. मला या प्रश्नात राजकारण आणावयाचे नाही. तसेच कोणावर हेत्वारोप देखील करावयाचे नाहीत. परंतु मूळ मुद्दा असा आहे की, शासनकर्ते आणि प्रशासन या बाबतीत कठोरपणे भूमिका घेतली तरच दूध भेसळीचे प्रकार थांबू शकतील व उद्याची पिढी निरोगी होऊ शकेल, अन्यथा त्या पिढीस मारणारे कोणी असतील तर शासनकर्ते आणि प्रशासनकर्ते असतील, दुसरे कोणीही असणार नाही. या अनुषंगाने हा प्रश्न महत्वाचा आहे. तो प्रश्न गांभीर्याने सोडविण्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अशी विनंती करतो आणि माझे मनोगत पूर्ण करतो.

3...

अॅड.उषा दराडे (विधानसभेने निवडलेल्या ) : सभापती महोदय, दूध भेसळीच्या संदर्भात सभागृहात चर्चा उपस्थित करण्यात आली आहे. आपण राज्यातील सर्व समाजाला व त्यांच्या बालकांना विषयुक्त दूध देत आहोत. भेसळयुक्त दुधासंबंधी अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केलेली आहेत. दूध भेसळीच्या संदर्भात दुसऱ्या एका पैलूवर मला सभागृहाचे लक्ष वेधावयाचे आहे. विदर्भात आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आता आत्महत्या करू लागले आहेत. या शेतकऱ्यांना वाचवावयाचे असेल तर दुधाचा जोडधंदा करणे गरजेचे आहे. शासनाने ती भूमिका डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱ्यांना जनावरे कशी देता येतील याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

महोदय, राज्यात जनावरांच्या चान्याचा प्रश्न मोठा निर्माण झालेला आहे. या वर्षी पाच रुपयाला एक पेंढी या दराने शेतकरी आपल्या जनावरांसाठी चारा खरेदी करित आहेत. जनावरे सांभाळावयाची कशी याबाबतीत शेतकरी चिंताग्रस्त झालेला आहे. आमच्या शेतकऱ्यांच्या दारातील गायी, म्हशी, शेळ्या चान्या अभावी कमी कमी होत आहेत. जनावरामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात लक्ष्मी येते, ते धन कमी होत आहे. महाराष्ट्रात दूध हा शेतकऱ्यांसाठी दुय्यम व्यवसाय म्हणून उभा केला तर दूध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. एक उद्योगधंदा म्हणून महाराष्ट्र संपन्न होईल.

यानंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्ध झालेला

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

H.1

SGB/ KTG/ D/ पूर्वी श्री.गिते

10:35

अॅड.उषा दराडे.....

त्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासन सकारात्मकपणे लक्ष देईल. परंतु भेसळ बंद केलीच पाहिजे. त्या भेसळीचे समर्थन कोणी करणार नाही.

सभापती महोदय, आमच्या भागात खवा, पेढा किंवा जे काही दुग्धजन्य पदार्थ तयार केले जातात ते सर्व भेसळयुक्त असतात. शासनामार्फत अनेक ठिकाणी धाडी घालण्याचे काम केले जाते. काही दिवस त्या धाडीबद्दलची चर्चा सुरु होते. या सभागृहात देखील या विषयावर चर्चा झालेली आहे. पुढे काय झाले? किती धाडी पडल्या? त्यामध्ये सातत्य दिसून येत नाही. या प्रकरणामध्ये सातत्य असले पाहिजे. जोडधंदा म्हणून दुधाचा धंदा महाराष्ट्रामध्ये उभा करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. चारा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे एवढे बोलून वेळेअभावी मी माझे भाषण संपविते.

---

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.सतेज ऊर्फ बंटी डी.पाटील (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, अत्यंत महत्वाच्या विषयावर सभागृहामध्ये चर्चा घडवून आणली आहे. राज्याची परिस्थिती विचारात घेतली तर दररोज 1.90 कोटी लीटर दूध उत्पादन होते. मुख्यतः ग्रामीण भागातून मुंबई, ठाणे, पुणे आणि संपूर्ण राज्यात दुधाचा पुरवठा केला जातो. मुळात दूध विक्रीसाठी येत असताना शेतकऱ्यांकडून दूध संकलित केल्यानंतर ते चिलिंग प्लँटमध्ये जाते. चिलिंग प्लँटमधून दूध संघाला दूध पुरवठा केला जातो. दूध संघाच्या माध्यमातून पॅकेजिंग करून वितरकांकडे दूध येऊन वितरकांमार्फत डिस्ट्रिब्यूटर्सकडे आणि त्यांच्याकडून ग्राहकांपर्यंत जाते. साधारणतः मॅन्युफॅक्चरिंग ते पॅकेजिंग आणि डिस्ट्रिब्यूशनपर्यंत 8 ते 10 लोकांचा संबंध या प्रक्रियेमध्ये येतो.

सभापती महोदय, नेमकी कोणत्या टप्प्यावर भेसळ होते या दृष्टीने या नव्या कायद्यामध्ये काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्या तरतुदींची अंमलबजावणी आपण करणार आहोत. प्रामुख्याने ज्या सर्व्हेचा उल्लेख काही वृत्तपत्रांनी केला त्या "नॅशनल सर्व्हे ऑफ मिल्क अँडल्टरेशन"बद्दल मला खुलासा करावयाचा आहे. या सर्व्हेमध्ये 65 टक्के नमुने अप्रमाणित आढळून आले अशी बातमी आली होती. नवीन कायद्याप्रमाणे 4 प्रकारे अँडल्टरेशन आढळून येते. मिसब्रॅण्ड, सब स्टॅण्डर्ड, एक्स्ट्रॉनियस मॅटर आणि अनसेफ फूड असे ते चार प्रकार आहेत. मिसब्रॅण्ड म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकांना पिण्यासाठी योग्य नाही असे दूध पुरविले जाते. एका ब्रॅण्डचे दूध दुसऱ्या ब्रॅण्डच्या नावाने विकले जाते. त्यात काही वस्तूंची भेसळ केली जाते. सब स्टॅण्डर्ड म्हणजे भेसळ करण्यासाठी पाण्याचा वापर केला जातो आणि अनसेफ फूड म्हणजे जे एस.एन.एफ.मॅटेन केले पाहिजे ते केले जात नाही.

सभापती महोदय, जे एकूण 126 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले त्याबाबत कोणत्याही सर्कलमध्ये एक्स्ट्रॉनियस मॅटरचा उल्लेख नाही. सब स्टॅण्डर्ड म्हणून प्रमाणित केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने पाणी मिसळले गेले अशा प्रकारची परिस्थिती समोर आली. हा अहवाल देखील आम्हाला प्राप्त झाला आहे. संबंधित संस्थेकडे आम्ही ही देखील मागणी केली की, जे नमुने घेतले त्याची माहिती देण्यात यावी. त्यामधील चार मुद्दे मी सभागृहाच्या माहितीसाठी वाचून दाखवितो.

"Presence of sodium chloride in one sample of Assam. Presence of neutralizers in two samples of Nagaland. Presence of SNF & SNP in 6 samples of Mizoram and one sample of Tripura. All the 250 samples are non

..3..

श्री.सतेज ऊर्फ बंटी डी.पाटील.....

confirming due to presence of detergents in Eastern Regions." म्हणजे जो वरचा भाग आहे त्या ठिकाणी डिटर्जंट किंवा युरियाचा वापर केला जातो. आपल्या राज्यामध्ये कुठेही 126 सॅम्पलपैकी अशा प्रकारचे सॅम्पल आढळून आले नाही हे मी सभागृहाला सांगू इच्छितो.

सभापती महोदय, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे विक्रेता असेल, टँकरद्वारे दूध पुरवठा करणारा असेल, चिलिंग प्लँट असेल, पॅकेजिंग विभाग असेल, डिस्ट्रिब्यूटर असेल या सगळ्यांची साखळी आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे या सगळ्यांना रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक आहे. परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही परवानगी घेण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न केले जातात. नवीन कायदा 5 ऑगस्टला देशामध्ये लागू झाला. मला सभागृहाला हे सांगितले पाहिजे की, राज्यामध्ये हा कायदा लागू झाल्यानंतर या कायद्याची जास्तीत जास्त चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी करणारे देशातील एकमेव महाराष्ट्र राज्य आहे.

नंतर श्री.खर्चे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील.....

5 ऑगस्ट नंतर आजपर्यंत जवळपास 1.40 लाख आस्थापनांचे रजिस्ट्रेशनस आपल्या राज्यात केले आहे. पूर्वीच्या काळात लाखाच्या घरात जमा होणारा महसूल आता या नवीन रजिस्ट्रेशनसची संख्या वाढल्याने रु. 37 कोटी इतका गोळा झाला आहे. हा कायदा आल्यानंतर त्यातील प्रोसिजरनुसार मात्र सप्टेबर महिन्यापर्यंत हे सर्व रजिस्ट्रेशनस पूर्ण करावयाचे आहे व त्यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेत फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट पध्दतीने एक नवीन कार्यप्रणाली आपण कार्यान्वित करणार आहोत. या कायद्याखाली ज्या सर्व नोंदी आलेल्या आहेत, त्यानुसार कार्यवाही चालू झालेलीच आहे. पण एखादी सिस्टम जेव्हा आपण तयार करतो तेव्हा या सर्व यंत्रणा सिस्टमेटिक मॅनरप्रमाणे आपल्या हाताखाली येणार आहेत. या विषयावर बोलत असताना इन्फ्रास्ट्रक्चरबद्दल देखील सांगण्यात आले. त्या संदर्भात मी असे सांगू इच्छितो की, हा कायदा अत्यंत कडक स्वरूपाचा असून तो लागू करण्यापूर्वी सन 2006 नंतर दरवर्षी वेगवेगळ्या राज्यांचे अभिप्राय मागवून केंद्र शासनाने आता त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या विभागाच्या माध्यमातून फूड अॅडॉल्ट्रेशन हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. यामध्ये केवळ दुधाचाच समावेश होत नाही तर सर्व खाद्य पदार्थ येतात. म्हणून यासंदर्भात शासनाच्या वतीने परवाच माननीय वित्त मंत्र्यांना एक विनंती करण्यात आली की, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रयोगशाळा आवश्यक आहे. त्याचे कारण असे की, या कायदानुसार नमुने घेतल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत त्या नमुन्यांचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. तसेच स्पॉटवर जाऊन टेस्टिंग करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक मोबाईल व्हॅनची गरज आहे.

महोदय, माननीय राज्यपालांनी या अर्थसंकल्पीय भाषणातून अशा प्रयोगशाळा जिल्ह्याच्या ठिकाणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे, तेव्हा निश्चितपणे अशा सर्व गोष्टींबाबत शासन वेगळ्या पध्दतीने विचार करित आहे. अशा प्रकारे सर्व प्रयत्न केल्यानंतर मला खात्री आहे की, येणाऱ्या भविष्य काळात ही दूध भेसळ कोणत्या टप्प्यावर होते हे रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच येथे रिक्त जागांच्या संदर्भातही उल्लेख करण्यात आला. मी इतर राज्यांशी तुलना करणार नाही परंतु एफएसओची एकूण 265 पदे राज्यासाठी मंजूर असून त्यापैकी 208 पदे भरलेली आहेत व 57 पदे रिक्त आहेत, ही पदे देखील भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. मधल्या काळात ड्रगज

....2

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील.....

इन्स्पेक्टरची पदे हायकोर्टमध्ये मॅटर होते म्हणून रिक्त होती पण आता कोर्टानेच परवानगी दिल्यानंतर ही रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत, त्याचप्रमाणे एफएसओची 57 रिक्त पदे देखील भरण्यात येतील.

महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. हेमंत टकले यांनी सांगितले की, या विभागाकडे ज्या पध्दतीने बघणे गरजेचे आहे त्या पध्दतीने न बघितल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, हे मी नाकारत नाही. म्हणूनच हा कायदा लागू झाल्यानंतर या विभागातील अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. आपण आतापर्यंत 1.40 लाख एस्टॅब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड केल्या असून अजून 2 लाख एस्टॅब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे राज्यातील प्रमुख शहरातील सर्वच आस्थापना या कायद्याखाली आपण आणणार आहोत. त्याचबरोबर या कायद्यान्वये अनेक गुन्हे सुध्दा दाखल केले आहेत. सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी अशा गुन्ह्यांचे कामकाज फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुरु करून प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघतील असा प्रयत्न करावा, त्याशिवाय अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांना जरब बसणार नाही अशी सूचना केली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात तीन महिन्याची शिक्षा किंवा दंडात्मक तरतुदी होत्या. पण 5 ऑगस्ट नंतर मात्र यातील तरतुदी बदलल्या असून आजपर्यंत या कायदानुसार 89 केसेस दाखल केल्या आहेत. या सर्व 89 केसेसमध्ये नवीन कायद्याप्रमाणेच कारवाई करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच हे सर्व निर्णय जलद गती न्यायालयातच व्हावे असाही आमचा प्रयत्न राहिल.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....



श्री. सतेज उर्फ बंटी डी.पाटील ....

शासनाकडून यांसंदर्भात ज्या काही उपाययोजना केल्या जात आहेत त्याची दखल घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे.

मला सभागृहाच्या निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, येत्या 27 तारखेला सर्व दूध संघाची बैठक आयोजित केली जाणार असून 1 जून रोजी जागतिक दुग्ध दिनी दुधाच्या संदर्भात लोकांना माहिती द्यावयाची आहे. सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोन्हे म्हणाल्या की, महिला दुधाच्या पिशव्या कट करुन बाजारात विकतात. दुधाच्या पिशव्या मधुन कट करुन टाकून दिल्या पाहिजे. आपल्या भागात दुधाचा जो वितरक आहे त्यावर यासंदर्भातील जबाबदारी फिक्स कशी करता येईल यासंदर्भात ज्या ज्या उपाययोजना आहेत त्या 1 जून पासून संपूर्ण राज्यभर राबविण्याची मोहीम आपण घेणार आहोत.

सभापती महोदय, या विषयाच्या संदर्भात काही सन्माननीय सदस्यांनी हेल्पलाईनचा उल्लेख केलेला आहे. यासंदर्भात मी सांगू इच्छितो की, हेल्पलाईनमार्फत नंबर कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटीकडे 1800222262 हा नंबर कार्यान्वित करीत आहोत. तसेच केंद्रशासनाच्या वतीने 1800112100 हा नंबर देखील कार्यान्वित करीत आहोत. हे दोन नंबर 24 तास उपलब्ध राहणार आहेत. गृह विभाग व अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून जेथे जेथे दूध भेसळीचे प्रकार उघडकीस येतात किंवा दुधामध्ये भेसळ होत तेथे आळा बसविण्याचे काम शासनामार्फत केले जात आहे. पूर्वी बीड जिल्हयामध्ये 13 लाख लिटर दुधाचे संकलन होत होते परंतु भेसळीच्या दुधाच्या संदर्भात कारवाई करण्यात आली तेव्हा पासून बीड जिल्हयात दुधाचे संकलन 13 लाख लिटरवरून 10 लाख लिटरवर आलेले आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केलेली नाही, असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. बीड जिल्हयात कारवाई केल्यामुळेच दुधाचे संकलन कमी झालेले आहे. भविष्यातही दुधाच्या भेसळीबाबत कारवाई करण्याला शासनाची निश्चितपणे प्रायोरिटी राहणार आहे असे मी या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितो. लॅबोरिटरीच्या तसेच स्टाफच्या विषयाच्या संदर्भात मी अगोदरच माहिती दिलेली आहे. फिरत्या प्रयोगशाळेच्या संदर्भात राज्याच्या प्लॅनमध्ये या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव केला असून दूध भेसळ रोखण्याचा शासन निश्चितपणे प्रयत्न करीत आहे.

....2

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, दुधाच्या 126 नमुन्यात कोणतीही भेसळ सापडलेली नाही. तसेच तीन महिन्यात केवळ एकदाच दुधाची तपासणी आपण केली का ? दुधाच्या भेसळीच्या संदर्भात आतापर्यंत किती चार्जशिट दाखल झालेले आहेत ? या सर्व मुद्याचा मी उल्लेख केला होता परंतु केवळ दुग्ध दिनाच्या समारंभाची माहिती देण्याचा प्रयत्न माननीय मंत्री महोदयांकडून केला जात आहे.

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी.पाटील : सभापती महोदय, 126 सॅम्पल्स केंद्रशासनाच्या माध्यमातून घेतले गेले होते, त्यामध्ये भेसळ आढळून आली नव्हती. भेसळ आढळून आली नाही. असे असताना त्यात भेसळ होती असे सन्माननीय सदस्यांच्या समाधानासाठी मी कसे काय सांगू. दुधात भेसळ आढळून आलीच नाही तर मी यापेक्षा अधिक काय सांगणार ?

तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) : अल्पकालीन चर्चा संपली आहे.

-----

..3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्ध प्रत

**हरकतीच्या मुद्यासंदर्भात**

श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, मागच्या मंगळवारी ठाणे महापालिकेच्या संदर्भात मी एक विषय उपस्थित केला होता व त्याला शासनाकडून दोन दिवसात उत्तर दिले जाईल असे सांगण्यात आले होते. आता सभागृहात नगरविकास विभागाचे माननीय राज्य मंत्री श्री. भास्कर जाधव उपस्थित आहेत, त्यांना माझ्या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देण्याची सूचना करावी.

**तालिका सभापती** : ठीक आहे. आता पुढील नियम 97 अन्वयेच्या अल्पकालीन चर्चेला सुरुवात करण्यात यावी.

----

.....4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**तालिका सभापती ( मोहन जोशी )** : नियम 97 अन्वयेच्या चर्चेला सुरुवात करण्यात येत आहे.

पृ.शी. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 86 हजार बेधर कुटुंबाचे अद्याप पुनर्वसन न करणे

मु.शी. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 86 हजार बेधर कुटुंबाचे अद्याप पुनर्वसन न करणे या विषयावर श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. यांनी उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा.

**तालिका सभापती ( श्री. मोहन जोशी )** : या अल्पकालीन चर्चेसंबंधी औपचारिक प्रस्ताव मांडता येणार नाही. सूचना देणारे सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण, सर्वश्री प्रकाश बिनसाळे, रमेश शेंडगे, हेमंत टकले, वि.प.स. आपली सूचना वाचतील आणि भाषण करतील.

श्रीमती विद्या चव्हाण (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी नियम 97 अन्वये आपल्या अनुमतीने पुढील विषयावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करते.

"मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील सुमारे 86 हजार कुटुंबाची घरे वन विभागाने तोडलेली असणे, हजारो कुटुंबाचे अद्यापही पुनर्वसन करण्यात आलेले नसणे, सदर वनजमिनी संदर्भात बेकायदेशीर निर्णय घेतले जात असल्याची गंभीर माहिती, राष्ट्रीय उद्यानातील सर्व्हे नं. 239 पैकी 206 एकर जमीन नॅशनल पार्कमध्ये समावेश नसल्याचे महसूल व वन विभागाने सन 1996 मध्ये जाहिर केलेले असतांनाही सदर जमिनीवर वन विभागाने ताबा घेतलेला असणे, सदर जमिनीवर ताबा घेत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय न घेताच कारवाई करण्यात आलेली असणे, तत्कालीन उपवनसंरक्षक श्री.आनंद भारती यांनी सदर प्रकरणी केलेला मनमानी गैरकारभार पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करणे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा विपर्यास करून वन विभागाशी संबंध नसलेल्या जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी व इतरांना बेधर करण्यात आलेले असणे, सन 2002 व 2007 मध्ये सुमारे 33 हजार रहिवाश्यांनी पैसे भरूनही त्यांना घरे देण्यात आलेली नसणे, त्याचबरोबर 527 एकर जमिनीवरील तबेल्यांची जागा वन विभागाकडे परत जमा करून घेण्यात आलेली नसणे व शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेले

.....5

श्रीमती विद्या चव्हाण .....

नसणे, मालाड येथील हजारो रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणे, शासनाची त्यांच्याविषयी असलेली अन्यायी भूमिका, श्री देबी गोयंका (पर्यावरणवादी) व तत्कालीन उपवन संरक्षक आनंद भारती यांनी वन विभागाशी संबंध नसलेल्या आदिवासी लोकांची घरे पाडणे व त्यांना बेघर करणे, बेकायदेशीर कार्यवाही करणाऱ्या वन विभागातील अधिकाऱ्यांवर व देबी गोयंका याचे विरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याची आवश्यकता, वन विभागाच्या अन्यायी धोरणामुळे येथील आदिवासी आणि इतर रहिवाश्यांवर होत असलेले अन्याय, अत्याचार, सदर संशयास्पद प्रकरणाची उच्च स्तरीय सखोल चौकशी करून कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आणि शासनाची प्रतिक्रिया."

यानंतर श्री. भारवि ....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

K 1

BGO/ KTG/ D/

जुन्नरे

10:50

श्रीमती विद्या चव्हाण.....

सभापती महोदय, गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. सन 2000 साली जवळ जवळ 79 हजार लोकांची पक्की घरे, शाळा, वस्त्याच्या वस्त्या बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करण्यात आल्या होत्या. हे वन क्षेत्र आहे असे सांगून कष्टकरी लोकांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. यामध्ये फार मोठे कटकारस्थान पर्यावरणवादी आणि वन विभागाचे अधिकारी यांनी केले हे मी आपल्या निदर्शनास आणून देणार आहे. या संबंधातील सविस्तर पार्श्वभूमी मी आपल्याला पाच मिनिटांमध्ये सांगते.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, ही चर्चा मुंबईतील आदिवासींच्या पुरतीच मर्यादित ठेवावी. यावर महाराष्ट्रातील चर्चा नको. मग मूळ विषयावर अन्याय होतो. हा प्रश्न सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी अनेक वेळा मांडलेला आहे.

श्रीमती विद्या चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय महसूल मंत्र्यांनी उपस्थित रहावे अशी मी विनंती केली होती. येथे महसूल विभागाचे मंत्रिमहोदय नाहीत. तरी त्यांना आपण निरोप द्यावा ही विनंती.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सभागृहात वन मंत्री देखील उपस्थित नाही.

**तालिका सभापती (श्री.मोहन जोशी) :** सभागृहामध्ये माननीय वन राज्यमंत्री उपस्थित आहेत.

श्रीमती विद्या चव्हाण : सभापती महोदय, वेळ कमी मिळालेला आहे. मला असे वाटते की, सन्माननीय सदस्यांनी माझे विचार शांतपणे ऐकले तर बरे होईल. मी गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या बाजूने बोलते आहे. पर्यावरण आणि वन या दोन्ही विषयी सरकारला, सर्वसामान्यांना आणि कोर्टाला प्रेम आणि आस्था वाटते. ते स्वाभाविकच आहे. आम्हाला देखील तसेच वाटते आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना देखील वना विषयी प्रेम वाटते. त्यांना त्या विषयी आकस नाही. मुंबई सारख्या शहरात पर्यावरणाचा न्हास होता कामा नये अशी आपणा सर्वांची जशी भावना आहे, तशीच झोपडपट्ट्या म्हणजे शहरांचे सौंदर्य बिघडवणाऱ्या असल्यामुळे मनाच्या कोपऱ्यामध्ये कुठे तरी सर्वसामान्य माणसांच्या मनामध्ये घृणा देखील आहे. पर्यावरणा विषयीची सहानुभूती आणि झोपडपट्ट्यासंबंधीची घृणा या दोघाचे एक हत्यार म्हणून अत्यंत हुशारीने एका

..2

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

K 2

BGO/ KTG/ D/

जुन्नरे

10:50

श्रीमती विद्या चव्हाण ...

पर्यावरणवादी संघटनेच्या म्हणजे बॉम्बे एन्व्हॉयर्मन्टल अॅक्शन ग्रुपचे सदस्य समजणाऱ्या श्री.देवी गोयंका यांनी कशा प्रकारे वापर केला ते मी सांगणार आहे. त्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अतिशय चाणाक्षपणे वनाचा न्हास होत आहे, असे सांगितले. परंतु, तेथील लोक हे प्रत्यक्षात स्लम अॅक्टने सुरक्षित होते. त्यांचा वनाशी काहीही संबंध नव्हता. आज तेथे नॅशनल पार्कमधील झाडे किंवा वने पहायला मिळत नाही. तेथे आज मोठ-मोठे टोलेजंग टॉवर झाले आहेत. आज तेथे खाणी आहेत. डोंगर फोडून तेथील जमिनी मोकळ्या केल्या आहेत. अशा प्रकारे पर्यावरणाचा तेथे न्हास झालेला असताना त्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोधा केलेला नाही हे मला खेदाने सांगावेसे वाटते.

बॉम्बे एन्व्हॉयर्मन्टल अॅक्शन ग्रुपने 1995 मध्ये 305 ची जन हित याचिका सादर केली. नॅशनल पार्क मध्ये जे काही गैर उद्योग चालू आहेत ते ताबडतोब बंद करावेत आणि अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत अशी याचिका त्यांनी सादर केली. कोर्टाने याचा पूर्ण विचार करून असे आदेश पारित केले की, जर खरोखर वन क्षेत्रात लोक रहात असतील तर 18 महिन्यांच्या आत या लोकांचे पश्चिम उप नगरामध्ये शासनाने पुनर्वसन करावे. परंतु, 18 महिन्यांच्या कालावधीत शासनाने काहीही केले नाही. नंतर मात्र बुलडोझर लावून एकदम 78 हजार लोकांची घरे तोडण्यात आली. तेथे मोठा हाहाकार माजला. लोकांना कळेना की, आमची जागा वन क्षेत्रात नसताना आमची घरे का तोडण्यात आली, आमच्या मुलांच्या शाळा का तोडल्या ?

या जमिनी बदलची थोडी वस्तुस्थिती मला सांगावयाची आहे.

यानंतर श्री.सरफरे....

श्रीमती विद्या चव्हाण...

या जमिनी कुणाच्या मालकीच्या होत्या, त्या संदर्भातील कोर्टाचे आदेश काय होते, या जमिनीचा इतिहास काय आहे याची आपणास माहिती व्हावी म्हणून मी सांगू इच्छिते. सन 1950 साली हे जंगल कृष्णागिरी म्हणून ओळखले जात होते. या जंगलाचा परिसर 20 चौरस किलोमीटर इतका असून 1960 साली या जंगलाचे क्षेत्र वन विभागाकडे सोपविण्यात आले. त्यानंतर 1968 साली हे जंगल बोरीवली नॅशनल पार्क म्हणून घोषित करण्यात आले. 1972 मध्ये त्याचे सबडिव्हिजन करण्यात आले.त्यानंतर 1976 मध्ये 68.9 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र वाढविण्यात आले. . त्यातील 44.45 चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे बोरीवली उपनगरातील व 58.64 चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे ठाण्यातील आहे. 1981 मध्ये या वन क्षेत्राचे नामकरण करण्यात आले असून तेव्हापासून ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 1983 मध्ये 83 किलोमीटर पर्यन्त क्षेत्र विस्तारीत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे 1975 साली महाराष्ट्र खाजगी वन संपदा अधिनियम 1975 अंतर्गत वन जमिनीच्या हद्दीलगत 12 हेक्टरपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी संपादित करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये मालाड येथील कुरार गावातील सर्व्हे नं. 239 मधील जमीन संपादित केली, त्यानंतर कांदिवली, अकुर्ली येथील सर्व्हे नं.87 अ व सर्व्हे नं. 42 मधील जमीन तसचे दहिसरमधील सर्व्हे नं. 345 अ मधील जमिनी संपादित करण्यात आल्या.

त्या ठिकाणी स्वतःला पर्यावरणवादी म्हणविणारे जे.बी. गोयंका आणि उप वनसंरक्षक व वन अधिकारी श्री. आनंद भारती व त्यांच्यानंतर आलेले श्री. पी.एन. मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कलम 305 अन्वये याचिका दाखल करून कोर्टाचे आदेश आहेत असे सांगून त्या लोकांची घरे तोडली. परंतु ही घरे तोडीत असतांना ती जमीन कुणाची आहे याची शहानिशा केली नाही. त्यामध्ये 69 हजार कुटुंबे उद्ध्वस्त करण्यात आली असून त्यामध्ये दलित आणि ओ.बी.सी. च्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात उघडयावर आणण्यात आले. या लोकांना घटनेच्या कलम 15 आणि 18 मधील तरतुदीनुसार संरक्षण देण्यात आले आहे ते हक्क आणि अधिकार हिरावून घेण्यात आले. त्याबाबत शासनामध्ये कुठेही विचार झालेला नाही. सभापती महोदय, राज्य घटनेच्या कलम 21 क अन्वये मुलांना शिक्षणाचा अधिकार दिला असतांना त्या मुलांच्या शाळा तोडण्यात आल्या, लोकांची घरे तोडून त्यांचे सामान जाळून टाकण्यात आले. राज्य घटनेने त्यांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यांचा शासनाने विचार केलेला नाही. त्या बाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली



श्रीमती विद्या चव्हाण...

आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घरे तोडण्यात आल्याचे सांगितल्यानंतर आम्ही एकही दिवस स्वस्थ बसलो नाही. त्यासाठी अनेक आंदोलने व लढे दिले आहेत.

त्यानंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्या जमिनी कुणाच्या आहेत किंवा कोणते झोपडे कुणाचे आहे, ते वन विभागाच्या जमिनीवर आहे की, वन विभागाच्या जमिनीच्या क्षेत्रा बाहेर आहे हे ठरविण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत. हे ठरविणारी स्टॅट्युटरी अॅथॉरिटी म्हणून कलेक्टर, भू मापन अधिकारी ही यंत्रणा कार्यरत आहे. या यंत्रणेकडून जाऊन चार महिन्यात याबाबतचा निर्णय लावून घ्या. सुप्रीम कोर्टाची लेखी ऑर्डर मिळाल्यानंतर त्या दिवसापासून आम्ही शासनाकडे दाद मागण्यासाठी वारंवार गेलो, शासनाला वेळोवेळी सांगितले की, या झोपड्या वन विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. तरीसुद्धा या झोपड्या वन परिक्षेत्रामध्ये असून उच्च न्यायालयाने आपली याचिका फेटाळून लावली आहे असे आम्हाला सांगण्यात आले. माननीय मुख्यमंत्र्यांना विशेष बाब म्हणून या जमिनीचा सर्व्हे करावा अशी आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. परंतु सर्व्हे करण्याबाबत कुठेही निदेश देण्यात आलेले नाहीत असे त्यांनी सांगितले. या झोपड्या वन परिक्षेत्रामध्ये आहेत की वन परिक्षेत्राच्या बाहेर आहेत हे ठरविण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत त्यांची मिली भगत कशी असते हे मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे.

मालाडमधील ज्या जमिनींना अॅक्विझिशनची नोटिस लावण्यात आली ती सर्व्हे नं. 289 वरील असून मूळ जमीन ही एफ.इ.दिनशा ट्रस्टची असून ती 1694 एकर इतकी जमीन आहे.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

श्रीमती विद्या चव्हाण . . . .

या 1694 एकर जमिनीतील 206 एकर जमीन ही मूळ शेत जमीन म्हणून मूळ मालकाने 1971 मध्ये वेगळी केली होती आणि संपादनाचे क्षेत्र हे 1488 एकर इतके होते. याठिकाणी 1488 एकर क्षेत्राला वन विभागाने नोटीस दिली होती आणि 206 एकर जमीन ही 1971 मध्येच वेगळी करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याठिकाणी आमचा अॅक्वीझिशनच्या नोटीस बाबत काही संबंध नसताना त्या जमिनी ठराविक बिल्डर लॉबीला रिकाम्या करून घेण्यासाठी तेथे नोटीसचा वापर करण्यात आला. त्यावेळी नगर भू-मापन अधिकारी, वास्तुविशारद, पी.डब्ल्यू.डी., उप वन संरक्षक व झोपडी बचाव परिषदेचे आर्किटेक्ट यांच्या उपस्थितीत कलेक्टर कचेरीमार्फत कॉम्प्युटर सर्व्हे करण्यात आला होता. त्यानुसार दिनांक 17 मे 2002 रोजी वन विभागाने लेखी स्वरूपामध्ये दिलेले आहे की, आम्ही 220 एकर जमीन जास्त घेतलेली आहे.असे असताना सुध्दा ज्या वस्त्यांचा वन विभागाशी काही संबंध नव्हता त्या सर्व वस्त्या तोडण्यात आल्या आहेत आणि तरीही याबाबतीत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही.

सभापती महोदय, यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, त्याठिकाणी जी संपादनाची नोटीस लावण्यात आली होती आणि जे नोटीफीकेशन निघाले होते ते डब्ल्युटी-41 ही संपादनाची नोटीस ट्रस्टच्या संपूर्ण क्षेत्राला लागलेली होती. याबाबतीत कोर्टामध्ये समझोता करार झाला होता. त्या करारामध्ये एकूण क्षेत्रफळापैकी 848 एकर 20 गुंठे आणि 12 हेक्टर इतकी जमीन वन विभागाला दिलेली आहे आणि उरलेले जे क्षेत्र आहे त्यातील 44 एकर क्षेत्र हे बीएमसीच्या पाण्याच्या टाकीसाठी रिझर्व आहे. 5 एकर रस्त्यांसाठी, 3 एकर चिल्ड्रन पार्कसाठी आणि 572 एकर ही बीएमसी ला तबेले हटविण्यासाठी एवढी मोठी जमीन दिली होती.बीएमसी ने सांगितले की,आम्हाला ही जागा नको.कारण आम्ही तबेले हटविण्यासाठी मीरा रोड येथे जागा घेतलेली आहे.त्यामुळे जेव्हा ही जमीन बीएमसी ने नाकारली तेव्हा ती पुन्हा वन विभागाकडे द्यावयास हवी होती.परंतु संजय गांधी उद्यानातील 206 एकर जमीन तर फॉरेस्टमध्ये नव्हतीच.पण जी जमीन फॉरेस्टमध्ये होती त्याला अॅक्वीझिशनची नोटीस लागली होती, ती 572 एकर जमीन जेव्हा तेथील तबेले हटविण्यासाठी बीएमसी ने घेतली नाही तेव्हा ती पुन्हा फॉरेस्ट विभागाकडे जावयास हवी होती.पण प्रत्यक्षात ती जमीन फॉरेस्टकडे गेली नाही आणि त्याबाबत 1989 मध्ये जो समझोता करार झाला होता त्यावेळी सदरहू जमिनीच्या संबंधातील गर्हमेंट गॅझेट,संपादनाची नोटीस, तहसीलदार, बोरीवली यांचे अहवाल, जिल्हाधिकारी उपनगरे कार्यालयातील नोंदी, तसेच अप्पर ...

श्रीमती विद्या चव्हाण . . .

जिल्हाधिकारी यांची नोंद याबाबत तहसील कचेरीने असे स्पष्टपणे दिलेले आहे की, या मूळ क्षेत्राची मोजणी करणे अत्यंत जरूरी आहे. कारण प्रत्यक्षात मोजणी झालेली नाही केवळ कागदोपत्री ताबा घेण्यात आलेला आहे. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे अभिप्राय घेतलेले नाहीत. तसेच फॉरेस्टने केवळ कागदोपत्री या जागेचा ताबा घेतलेला आहे आणि प्रत्यक्षात तेथे काय आहे याबाबत देखील खुलासा करण्यात आला आहे त्यानुसार यामध्ये असे म्हटलेले आहे की, "भूमी संपादन कायदा 1894 प्रमाणे संपादनाचे काम चालू होते.परंतु भूमी संपादनाचे काम तहकूब करून नंतर रद्द करण्यात आले."

सभापती महोदय, अशा परिस्थितीत वन विभागाकडून सदर 572 एकर जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय किंवा महाराष्ट्र खाजगी वने व संपादन कायदा 1975 च्या कलम 21 अन्वये राखीव वन म्हणून पुन्हा संपादन करण्याची कार्यवाही का करण्यात आली नाही? त्याबाबत शासनाकडे अहवाल सादर का केला नाही? मालाड येथील खोतास जागा का सोडून देण्यात आली आणि याबाबत संजय गांधी उद्यान, येथील उप वन संरक्षक यांनी याबाबत खुलासा करावा अशी लेखी स्वरूपाची नोट असताना सुध्दा 572 एकर जमीन जी आज फॉरेस्टच्या ताब्यात असावयास पाहिजे, ती जमीन फॉरेस्टच्या ताब्यात नाही. ज्या जमिनीवर गरीबांच्या वस्त्या होत्या, ज्या जमिनीच्या बाबतीत अॅक्वीझिशनची नोटीस लागली नव्हती, त्या जमिनीवर बुलडोझर लावून लोकांची घरे तोडून एका बिल्डरला त्या जमिनी देण्याचे कट-कारस्थान पर्यावरणवादी आणि फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी केले. जी जमीन फॉरेस्ट विभागाकडे जावयास हवी होती, जेथे अर्धा डोंगर फोडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट झालेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही 572 एकर जमीन पुन्हा फॉरेस्टच्या ताब्यात यावयास हवी होती. पण प्रत्यक्षात ती ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. याठिकाणी गोरगरिबांवर प्रचंड अन्याय करण्यात आलेला आहे.

यानंतर श्री.बरवड . . .

श्रीमती विद्या चव्हाण .....

आमची सारखी मागणी अशी आहे की, ही जी फसवाफसवी आणि चोरी वन विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे त्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.

सभापती महोदय, त्याचप्रमाणे जेव्हा पर्यावरणवादी हायकोर्टात गेले तेव्हा दिनांक 22.6.2005 रोजी महसूल विभागाने कलम 35(3) च्या नोटिशीमधील सर्व क्षेत्रावर वनाच्या नोंदी 31 जुलै, 2006 च्या आत घेण्याचे काम पूर्ण करावे अशा सूचना दिल्या. त्या अनुषंगाने उप वनसंरक्षक श्री. भास्कर वाळिंबे, वन विभाग, ठाणे यांनी 20.2.2006 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे यांना पत्र पाठवून सांगितले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, संबंधित तहसीलदार व नगरभूमापन यांनी नोंद घेण्यास सुरुवात केली. परंतु श्री. पी.एन.मुंडे जे उप वनसंरक्षक होते त्यांनी माननीय जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांना 29.5.2006 रोजी मालाड येथील उपरोक्त सर्व क्रमांकाच्या जागेवर वनाची नोंद घेण्यात येऊ नये असे पत्राने कळविले. आमच्याकडे लेखी पत्र आहे. तसेच संपादनाची नोटीस डब्ल्यूटी-41/1956 मागे घेण्यात आलेली आहे असे असत्य सांगितले आहे. त्याबाबत पुन्हा ठाणे येथे खुलासा मागितला तेव्हा त्यांनी आम्हाला लेखी पत्र दिले की, अशा प्रकारे एकदा जे नोटिफिकेशन निघालेले आहे ते रद्द करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आणि अशा प्रकारे श्री. मुंडे जी माहिती देत आहेत ती चुकीची आहे, असे त्यांनी आम्हाला लेखी दिलेले आहे.

सभापती महोदय, माझी पहिली मागणी अशी आहे की, या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी मुख्य सचिव यांच्या मार्फत करण्यात यावी. या संबंधीचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा. दुसरी मागणी अशी आहे की, जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणात गुंतलेल्या व निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन थांबविण्यात यावे. माझे असे म्हणणे आहे की, एखाद्या माणसाचा खून केला किंवा दरोडा टाकला तर त्याला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होते. या ठिकाणी 69 हजार गरीब लोकांचे संसार उद्ध्वस्त केलेले आहेत. त्या ठिकाणी दोन ते अडीच लाख लोकांना उद्ध्वस्त केलेले आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला आणि लहान मुले बाधित झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे वन

...2...

RDB/ D/ ST

श्रीमती विद्या चव्हाण .....

विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कारस्थाने इतकी मोठी आहेत की त्यांनी बिबट्यांची छोटी पिल्ले त्या वनामध्ये सोडली होती. ती पिल्ले मोठी झाल्यानंतर त्यांनी वस्त्यांवर जे हल्ले केले. जगाच्या इतिहासामध्ये कोठेही झाले नसतील एवढ्या 117 माणसांवर त्या ठिकाणी हल्ले झाले. त्यामध्ये गर्भवती महिला होत्या तसेच लहान मुले यांच्यावर हल्ले झाले. मालाड, चांदिवली, बोरिवली येथील हल्ले संपल्यानंतर त्यांनी पर्वरमधील श्रीमंत वस्त्यांवर जेव्हा हल्ले करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी संबंध हाहाकार माजला आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्या बिबट्यांना पकडावे लागले. म्हणजे त्या ठिकाणी लोकांवर किती निर्घृणपणे अत्याचार झालेले आहेत हे दिसून येते. माझी तिसरी मागणी अशी आहे की, संबंधित अधिकारी यांचे निलंबन करून पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. न्यायालयीन निर्णयाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.

सभापती महोदय, माझी चौथी मागणी अशी आहे की, स्वतःला पर्यावरणवादी म्हणविणाऱ्या व्यक्तीने शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कटकारस्थान केले असे जे श्री. देबी गोयंका आहेत अशा तथाकथित पर्यावरणवाद्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. माझी पाचवी मागणी अशी आहे की, ज्यांच्या झोपड्या तोडण्यात आल्या त्यांचे पुनर्वसन आपण चांदिवलीला करत आहात. त्यांना आपण चांदिवलीला नेत आहात. आमचा चांदिवलीशी काय संबंध आहे ? त्या ठिकाणी वाहतुकीचे कोणतेही साधन नाही. त्या ठिकाणी बस नाही, ट्रेन नाही. त्या ठिकाणी काम नाही. ज्या ठिकाणी वन विभागाचा काही संबंध नव्हता अशा ठिकाणची महिलांची घरे तोडून टाकली. ज्या 206 एकर जमिनीला अॅक्विझिशनची नोटीस नव्हती तेथील झोपड्या तोडून टाकल्या. आम्ही त्या ठिकाणी 206 एकर जमीन मागत नाही. आपण 12 ते 15 हजार लोकांना जबरदस्तीने त्या ठिकाणी नेले आहे. त्या ठिकाणी ज्या एनजीओला विकास करण्यासाठी दिले आहे तेथे प्रत्येकाकडून नागरी हक्क निवारावाल्यांनी 200 रुपयांच्या, 400 रुपयांच्या पावत्या फाडलेल्या आहेत. त्यातून कोट्यवधी रुपये गोळा केलेले आहेत. फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला खालचे घर पाहिजे का, वरचे घर पाहिजे का असे सांगून त्या ठिकाणी असा प्रकार केलेला आहे. लोक 12 वर्षे त्या ठिकाणी

...3...

RDB/ D/ ST/

श्रीमती विद्या चव्हाण ....

प्लास्टिक आणि बांबूच्या झोपडीत अत्यंत वाईट अवस्थेत राहतात. त्या ठिकाणी पाणी नाही, संडास नाही.

मी नगरसेविका होते. त्या ठिकाणी पाणी द्यावयाचे म्हटले तर ते देता येत नाही. अशा अवस्थेमध्ये ज्या ठिकाणी वन विभागाचा संबंध नव्हता त्या ठिकाणी बोअर घ्यायला गेलो तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या ठिकाणी बोअरवेल घेऊ शकत नाही. म्हणजे त्यांचा संबंध नसलेल्या जमिनीवर ते अधिकारी येतात आणि लोकांवर अत्याचार करतात. हे आम्ही सहन करावयाचे का ? गेली बारा वर्षे आम्ही सहन केले. आता आम्ही सहन करणार नाही. ज्या 206 एकर जमिनीचा फॉरेस्टशी काही संबंध नाही त्या ठिकाणी उरलेल्या लोकांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे.

यानंतर श्री. खंदारे ...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

O-1

NTK/ D/ ST/

पूर्वी श्री.बरवड

11:10

श्रीमती विद्या चव्हाण...

हायकोर्टाने या संदर्भात यापूर्वीच आदेश दिलेले आहेत. 18 महिन्यांच्या आत त्यांचे पुनर्वसन करावे अशी लोकांनी मागणी केलेली आहे. त्या मागणीचा मी पुनरुच्चार करुन माझे विचार येथेच थांबविते.

-----

2....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ D/ ST/

श्री.जयंत प्र.पाटील (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी महत्वाच्या विषयावर नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केलेली आहे. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे.

सभापती महोदय, या मुंबईचे मूळ मालक कोण आहेत ? या मुंबईचे मूळ मालक आगरी, कोळी, भंडारी, माळी आणि आदिवासी आहेत. (अडथळा ) सन्माननीय सदस्य श्री.संदिप बाजोरिया हे माझ्या भाषणाच्या वेळी नेहमी व्यत्यय आणतात, त्याबाबत माझी तक्रार आहे. ते केवळ त्यांच्या प्रश्नासाठी येतात, सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून सदस्यांची लिक तोडतात. या मुंबईचे मालक आम्ही आहोत. पण जे लोक बाहेरून येथे येतात, झोपड्या बांधतात त्यांना शासन पर्यायी जागा देते आणि जे मूळ मालक होते त्यांना बाहेर हुसकावण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. याबाबत मला सरकारला जाब विचारावयाचा आहे. या मुंबईत बांगलादेशातून लोक आले आहेत, पश्चिम बंगाल राज्यातून आले आहेत. त्या लोकांनी मुंबई झोपड्या बांधल्यानंतर त्यांना पर्यायी घरे दिली जातात. पण मुंबईचे जे मूळ मालक आहेत त्यांना बाहेर काढले जात आहे.

विधानसभेच्या माजी सदस्या श्रीमती मृणाल गोरे यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. 1957 साली बोरीवली तहसील अंतर्गत गोरेगाव ग्रामपंचायतीच्या त्या सरपंच होत्या. त्यांचे पुस्तक मी पुन्हा पुन्हा वाचत होतो. या महाराष्ट्रामध्ये अशा आदिवासी वस्त्या आहेत की, त्यांची शासनाच्या दप्तरामध्ये नोंद झालेली नाही. अलिबाग तालुक्यातील सांबरपूरमध्ये आदिवासी राहतात, त्यांच्या घरांना घर क्रमांक नाही. तेथे ग्रामपंचायत नाही. त्यांच्या घरांची नोंद नसल्यामुळे त्यांना शासनाच्या कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. या मुंबईत पूर्वी आणि आताही आदिवासी राहतात. एका बाजूला मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे असे सांगून आपण शेखी मिरवितो आणि दुसऱ्या बाजूला या मुंबईच्या मूळ मालकांना बेघर करण्याची कृती शासनाकडून केली जाते. हा दैवदुर्विलास म्हटला पाहिजे. या मुंबईत तथाकथित पर्यावरणवादी लोक बिल्डरला हाताशी धरतात. राज्यात लोकशाही जिवंत असताना मूळ मालकांची घरे पाडली जातात ही शोकांतिका आहे. मी माननीय वन मंत्र्यांना विनंती करतो की, ज्या अधिकाऱ्यांनी ही घरे पाडली आहेत त्यांना ताबडतोब निलंबित करण्यात यावे. झोपड्या पाडल्यानंतर तेथे इमारती बांधण्यात आल्या आहेत,

3...



श्री.जयंत प्र.पाटील....

त्यासाठी त्यांना कोणी परवानगी दिली, वन खात्याची जमीन असताना बांधकामाची परवानगी कोणी व कशी दिली आहे याचेही उत्तर आम्हाला मिळणे आवश्यक आहे. मी मंत्री महोदयांना असा प्रश्न विचारतो की, गोयंका हे सरकारचे जावई आहेत काय, त्यांना शासनाने समितीवर नेमले आहे, हे गोयंका कोण आहेत ? ते स्वतःला पर्यावरणवादी म्हणवून घेतात. मर्सिडिज गाडीतून फिरतात. त्यांचा पेहराव कसा असतो तो पहा. त्यांच्या बैठका फाईव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये होतात. आपल्याला मुख्य सचिवांच्या केबिनमध्ये लगेच प्रवेश मिळत नाही. परंतु त्यांना तेथे केव्हाही प्रवेश मिळतो. मंत्रालय त्यांना पोसत आहे. ही चुकीची गोष्ट आहे. या राष्ट्रीय उद्यानात कार्यरत असलेले अधिकारी श्री.मुंडे यांची मंत्री महोदयांनी चौकशी केली पाहिजे. त्यावेळी सन्माननीय मंत्री डॉ.पतंगराव कदम हे असते तर हे घडले नसते. त्यांची कार्यक्षमता, गरिबाबद्दलची कळवळ, कष्टकऱ्यांबद्दल बांधिलकी आम्हाला माहीत आहे.

सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण या सभागृहाच्या सदस्या झाल्यापासून हा विषय सातत्याने मांडत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची तड लागली पाहिजे. परंतु ती लागत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना असे वाटत असते की, सभागृहात सदस्य फक्त चर्चा करत राहतात. त्यांनी आमचे काय वाकडे केले आहे ? आम्ही पर्यावरणवादी लोकांना मॅनेज केले आहे.

यानंतर श्री.शिगम....

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

P-1

MSS/ D/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

11:15

श्री. जयंत प्र. पाटील...

या राज्यामध्ये कोण एनजीओ आहेत, या एनजीओना मान्यता कशी द्यायची हे ठरविण्याची वेळ आता आलेली आहे. कोणीही येतो आणि एनजीओ बनतो. या चर्चेच्या निमित्ताने माझी मागणी आहे की, हे जे कोणी पर्यावरणवादी एनजीओ आहेत त्यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. या एनजीओ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस असे धोरण जाहीर केले पाहिजे, एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवितो.

---

...2..

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

P-2

श्रीमती अलका देसाई (नामनियुक्त) : सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी नियम 97 अन्वये एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा घडवून आणलेली आहे.

सभापती महोदय, मुंबई शहरातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आणि आजुबाजूच्या परिसरातील 86 हजार कुटुंबांना वन विभागाने बेघर केलेले आहे. यांना नुसते बेघर केलेले नाही तर त्यांचे कसे हाल हाल होतील असा प्रयत्न तथाकथित एनजीओच्या माध्यमातून केलेला आहे. गोयंका पर्यावरणवादी आहेत. पण अधिका-यांना हाताशी धरून आम्ही काय करू शकतो याचे चित्र आज आपण मुंबई शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये पहात आहोत. हे करीत असताना आम्ही आमच्याशी इमान राखणार आहोत की नाही हा खरा प्रश्न आहे. आपण आपले इमान राखले नाही तर आपली सामाजिक बांधिलकी म्हणून जगताना आपल्याला कोठे तरी लाज वाटल्या शिवाय राहाणार नाही असे मला वाटते. मला विनंती करावयाची आहे की, हे जे कोणी गोयंका आहेत ते बिल्डराचे प्रतिनिधी आहेत का, याचा देखील तपास करून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच पी.एन.मुंडे आणि पारधी नावाचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्या बदल तर वर्तमानपत्रातून रकानेच्या रकाने भरून येत होते. त्यांची मानसिकता अशी आहे की जणुकाही ही आमचीच प्रॉपर्टी असून आदिवासींना मेहेरबानी म्हणून रहायला दिले होते आणि आता आमची मेहेरबानी संपलेली असल्यामुळे त्यांनी आता बाहेर जायला पाहिजे. त्यांनी हायकोर्टाचे आदेश असल्याचे खोटे सांगितले. हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आम्हाला विरोध केला तर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होईल असे सांगून त्या आदिवासींना निर्दयपणे बेघर केले. मी सन्माननीय सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण यांच्या मताशी पूर्णपणे सहमत आहे.

या निमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छिते की, आम्हाला चांदिवलीमध्ये जायचे नाही. या जागेमध्ये तुम्ही बिल्डरांना जागा दिली त्याच ठिकाणी आमच्या आदिवासींना सुध्दा जागा मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आमची दुसरी मागणी ही आहे की, कालपरवा कोठून तरी हिंदुस्थानातून आलेला माणूस सेन्सस नंबर हातामध्ये नाचवत घेऊन झोपडपट्टीवाला आहे म्हणून सांगतो आणि त्याला आपण चांगल्या वस्तीमध्ये, नव्या इमारतीमध्ये घर देता. पण जो येथील मूळ रहिवासी आहे मग तो मुलुंडमधील आदिवासी असो, गोरेगावचा आदिवासी असो किंवा बोरीवली येथील नॅशनल पार्कमधील आदिवासी असो हे सर्व भूमिपुत्र आहेत. त्यांना तुम्ही उद्ध्वस्त करीत

..3..

श्रीमती अलका देसाई...

आहात. हे जे बाहेरुन येतात त्यांच्या विरोधात आम्ही नाही. परंतु ते येथे येऊन काय करतात याबाबत देखील बोलायची आता वेळ आलेली आहे. आमचे मोठमोठे पुढारी त्यांचा कळवळा घेऊन त्यांच्या बरोबर नाचत असतात. त्यांचा देखील पर्दाफाश होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेव्हा या आदिवासींना जागा द्यावी अशी विनंती करुन मी माझे भाषण संपविते.

---

...4...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

P-4

MSS/ D/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

11:15

श्री. दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी नियम 97 अन्वये जी अल्पकालीन चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे त्या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी उभा आहे.

सभापती महोदय, मी माझे विचार थोडक्यात मांडणार आहे. सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी हा विषय सविस्तरपणे मांडलेला आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंह मुंबईमध्ये आले होते. त्यावेळचा बोरीवली ते मंत्रालय पर्यन्त निघालेला मोर्चा अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. 69 हजार कुटुंबे बेघर होणे हा साधा विषय नाही. मी केवळ आदिवासी नाही तर या देशाचा मूळ निवासी आहे असे सांगणारे हे आदिवासी. आपण कोणी नव्हतो तेव्हा पासूनचे हे आदिवासी. यामध्ये दोन प्रश्न उपस्थित झालेले आहे. एक म्हणजे ती वन जमीन असल्यामुळे ती आम्हाला ताब्यात घ्यायची आहे असे सांगून ती जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर ती वन खात्याकडे न जाता ती बिल्डरच्या ताब्यात गेली हा विषय महत्वाचा आहे. कोणीतरी एक उपटसुंभ्या येतो आणि मी एनजीओ आहे म्हणून सांगतो आणि मंत्रालयामध्ये जाऊन आपल्याला पाहिजे तसे करतो. सभापती महोदय, The Hon'ble Supreme court rejected the plea of the Bombay Environmental Action Group. त्या रिजेक्शनमध्येच त्यांचा खोटेपणा सिद्ध होतो. या बाबतीत वनखाते आणि महसूल खात्याने निर्णय घ्यावयास पाहिजे. कारण त्यांच्याकडे या संबंधातील जुनी कागदपत्रे आहेत. त्यांच्याकडे जाऊन निर्णय घ्या आणि त्यामध्ये काही त्रुटी वाटल्या तर न्यायालयाकडे या असे न्यायालयाने सांगितले.

मुंबईमध्ये जनावरांच्या गोठ्यांचा विषय गाजला. त्या अदिवासींना जमीन न देता त्या ठिकाणी बिल्डरच्या इमारती झाल्या असतील तर त्याबाबतीत मला मंत्री महोदयाकडून खुलासा हवा आहे.

...नंतर श्री. गिते...

श्री. दिवाकर रावते....

सन्माननीय सदस्यांनी ज्या पध्दतीने विषय मांडला. त्याच्यामध्ये वनाच्या नावाखाली बिल्डरला दिल्या गेलेल्या या जमिनी आहेत. हे सर्व केवळ बिल्डरांच्या हितासाठी केले जात आहे हा खरा एक नंबरचा विषय आहे. ज्या वन जमिनी नाहीत, त्या वन जमिनी आहेत, असे दाखवून वन विभाग त्या जमिनी बळकाविण्याचा प्रयत्न करून त्या जमिनींवर वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना हुसकविण्याचा प्रयत्न केला आहे हा यातील दोन नंबरचा विषय आहे. मुंबई,पुणे येथील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा विषय हा सर्वसामान्य झालेला आहे. परंतु या ठिकाणच्या मूळ मालकांचे काय हा खरा प्रश्न आहे. या ठिकाणी परप्रांतीयांची संख्या फार कमी आहे. या ठिकाणच्या जमिनीवर परप्रांतीय फार कमी आहेत. या ठिकाणच्या जमिनींवर आदिवासींचे पिढ्यांपिढ्या वास्तव्य आहे. या ठिकाणच्या आदिवासींना न्याय मिळावा म्हणून वन खात्याने आणि महसूल खात्याने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. हे भारताचे नागरीक आहेत.

महोदय, आज बांगला देशी प्रत्येक ठिकाणी घुसले आहेत. मुंबईच्या उपनगरामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बांगला देशी घुसलेले आहेत. नवी मुंबईत बांगला देशी घुसले आहेत. माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयांनी लोकसभेत उत्तर दिले की, या देशात 3 कोटी बांगला देशी नागरिकांपैकी 75 लाख बांगला देशी नागरीक मुंबई आणि नवी मुंबईत घुसले आहेत. या सर्वांना आपण सांभाळतो आहोत. आपले अधिकारी त्यांना ओळखपत्र उपलब्ध करून देत आहेत. या जमिनीवर आदिवासी कुटुंबे शेकडो वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्या ठिकाणी त्यांच्या किती तरी पिढ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या आदिवासी कुटुंबीयांना न्याय देण्याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. या संदर्भात आदर्श सारखी चौकशी नको आहे. या संदर्भात अत्यंत गंभीरपणे चौकशी झाली पाहिजे. त्या ठिकाणी जे काही दोष असतील ते पुढे आले पाहिजेत. तो दोष अहवाल आल्यानंतर आपल्याला त्यावर चर्चा करता येईल. आपण ॲक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करणार आहात. माननीय डॉ.पतंगराव कदम हे सभागृहात उपस्थित आहेत आणि ते याबाबतीत ठोस अशी कार्यवाही करतील

2..

श्री.दिवाकर रावते....

अशी मला अपेक्षा आहे म्हणून मी बोलत आहे. आपण या विषयास न्याय देण्यासाठी ठामपणे सभागृहात येऊन बसलात त्याबद्दल आम्ही तुमचे स्वागत करतो. परंतु आपण या ठिकाणी शेवटपर्यंत उपस्थित असणे आहे. प्रत्येक गरिबास निवारा मिळावा अशा प्रकारची भावना व्यक्त करतो आणि आपण या विषयाच्या बाबतीत योग्य निर्णय घ्याल अशी आशा व्यक्त करतो व माझे भाषण संपवितो.

3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.सुभाष चव्हाण (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, म.वि.प.नियम 97 अन्वये सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केलेली आहे त्यावर संक्षिप्तपणे मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. दिनांक 15 मार्च, 2012 पासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाले आहे. त्या दिवसापासून हा विषय सभागृहात चर्चेला यावा असा त्या प्रयत्न करीत होत्या. सन्माननीय सदस्या श्रीमती चव्हाण हया अतिशय आक्रमक आहेत. या विषयाची चर्चा सभागृहात उपस्थित व्हावी म्हणून नेहमी प्रतोदांना विचारणा करीत होत्या. आमचे मित्र विरोधी पक्ष नेते श्री. विनोद तावडे यांना देखील विश्वासात घेतले तसेच काल आम्ही माननीय सभापतींना भेटलो आणि ही अल्पकालीन चर्चा आम्ही लावून घेतली. सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्याताई यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी या विषयावर जे भाष्य केले, त्यास माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे. त्या अतिशय आक्रमक आहेत. अतिशय निर्मळ आहेत. मनाने मोठया आहेत. गेली कित्येक वर्षे या विषयाच्या बाबतीत त्या भांडत आहेत.

महोदय, महाराष्ट्र शासनाचा आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयात कार्यरत आहे. राज्याच्या एकूण बजेटच्या 9 टक्के एवढे बजेट आदिवासींचा विकासासाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्यात येते. तरी देखील गेली कित्येक वर्षे आदिवासी समाजावर अन्याय होत आलेला आहे व होत आहे. परंतु आता डॉ.पतंगराव कदम यांच्यासारखे पॉवरफूल व आक्रमक मंत्री पुनर्वसन विभागास लाभलेले आहेत. या 572 एकरावरील हजारो आदिवासी कुटुंबे लयाला गेलेली आहेत.

यानंतर श्री. भोगले....



17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

R.1

SGB/ D/ ST/ पूर्वी श्री.गिते

11:25

श्री.सुभाष चव्हाण.....

दुर्बल घटक असतील, दीनदुबळे असतील त्यांच्याबद्दल माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी भाष्य केले आहे. 572 एकर जमीन गिळंकृत करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमून वेळ पडल्यास सीआयडी चौकशी करण्यात यावी किंवा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानून माझे भाषण संपवितो.

---

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.विनोद तावडे (विरोधी पक्षनेता) : सभापती महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी व त्यावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी उभा आहे.

सभापती महोदय, वन विभागाच्या जमिनीबाबतचा हा मुद्दा आहे. वन विभागामार्फत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान घोषित झाले त्या पूर्वीपासून वन हद्दीमध्ये राहणारे लोक आहेत. ते मूळ निवासी आहेत. असाच नियम पर्यावरणाच्या संदर्भात उपस्थित झाला होता. या मुंबई शहरामध्ये समुद्रकिनारी राहणारे जे कोळी बांधव आहेत त्याच्या घरांचा विकास करण्यासाठी सीआरझेड कायद्याची आडकाठी पुढे केली जाते. सीआरझेड कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून हे कोळी बांधव त्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत. जगातील बदलत्या वातावरणाच्या अनुषंगाने नवीन नियम आवश्यक आहेत. परंतु ते नियम लागू करताना त्या परिसरात राहणारे जे आद्य रहिवासी आहेत त्यांना या नियमापासून काय सूट मिळणार याचा विचार केला असता तर या कायद्याचा फायदा झाला असता.

सभापती महोदय, मुलुंड पश्चिम येथे मुलुंड कॉलनीमध्ये हनुमानपाडा ही वसाहत स.नं.377 वर वसलेली आहे. एकूण 77 एकर जमीन आहे. 1950 साली 50 एकर जागा वनमुक्त करण्यात आली. 1958 मध्ये पुन्हा 3 एकर जागा वनमुक्त केली गेली. तीन निवृत्त न्यायाधीशांची न्या.सिंदकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने जमीन वनमुक्त करावी असा अहवाल दिला होता या जागेवर 992 झोपडीधारक रहिवासी राहतात. त्यांना जिल्हाधिकार्यांकडून फोटोपास देण्यात आलेले आहेत. परंतु त्यांच्याकडे 7/12 चे उतारे नाहीत. ती जमीन वन विभागाची आहे की महसूल विभागाची आहे असा घोळ सुरु होता. मालमत्तापत्रावर "मलनिःस्सारण केंद्रासाठी महापालिकेसाठी राखीव जागा" म्हटले आहे. त्यामुळे ही जमीन वन विभागाची आहे, महसूल विभागाची आहे की महापालिकेची आहे हा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. परिणामी त्या जमिनीवर राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घराचा विकास होऊ शकत नाही. तेथे एसआरए योजना राबविता येत नाही. या जमिनीबाबत कोणीच स्पष्टता देण्यास तयार नाही. मध्यंतरी तेथील रहिवाशांचे शिष्टमंडळ मंत्रीमहोदयांना येऊन भेटले होते, ही बातमी नवाकाळ या दैनिकामध्ये देखील प्रसिध्द झाली होती. ही जमीन महसूल विभागाची, वन विभागाची की महापालिकेची आहे याबाबत गोंधळ सुरु असल्यामुळे तेथील रहिवाशांची टोलवाटोलवी सुरु आहे.

..3..

श्री.विनोद तावडे

सभापती महोदय, वन मंत्र्यांनी 100 कोटी झाडे लावण्याचा निश्चय केलेला आहे. त्यांनी तो ठोस निर्णय घेतलेला आहे. परंतु प्रत्यक्ष या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार? कारण झाडे लावण्यासाठी शेतीची कामे सुरु होतील तेव्हाच मजूर उपलब्ध होणार आहेत. मुळात शेतीच्या कामाला मजूर मिळत नाहीत, मग विभागाने दिलेल्या पैशामध्ये मजूर कसे उपलब्ध होणार? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. वन विभागाला जे अंदाजपत्रक मंजूर केलेले आहे त्या निधीमधून 100 कोटी झाडे विकत घेतली तरी ती झाडे लावण्यासाठी मजूर मिळणार नाहीत. अशा परिस्थितीत माननीय वन मंत्री फक्त जोरात बोलतात आणि करीत काही नाही अशी टीका होते. तो विषय वेगळा असला तरी अधिक निधी आल्याशिवाय हे काम पूर्ण होणार नाही. त्या संदर्भात ठोस निर्णय करावा अशी अपेक्षा आहे.

सभापती महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी जो विषय मांडला आहे त्याची सीआयडीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. राज्यात इको टेररिस्ट वाढत आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जे आवश्यक आहे ते केलेच पाहिजे. त्याबद्दल आमचे दुमत नाही. हे करीत असताना माणुसकीचा दृष्टीकोन असला पाहिजे. अन्यथा एकांगी बाजू कोर्टासमोर आणली जाते. वसईमधील विषय कोर्टासमोर गेल्यानंतर संपूर्ण ठाणे जिल्हयाला तो लागू झाला.

नंतर श्री.खर्चे...

**तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) :** मंत्री महोदयांचे उत्तर संपेपर्यंत सभागृहाची वेळ वाढविण्यात येत आहे.

श्री. विनोद तावडे : महोदय, अशा सर्व गोष्टींबाबत मंत्री महोदयांनी ठोस उत्तर द्यावे अशी विनंती करतो आणि माझे भाषण पूर्ण करतो.

डॉ. पतंगराव कदम (वन व पुनर्वसन मंत्री) : महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण या सभागृहाच्या सदस्या म्हणून येण्यापूर्वी पासूनच त्या या विषयाच्या बाबतीत आग्रही होत्या तसेच त्यांनी मी महसूल मंत्री असताना याच विषयाच्या संदर्भात माझ्याकडे बैठक घेण्याची विनंती केली होती व तशी बैठकही मी घेतली होती. त्यानंतर माझ्याकडे वन खात्याचा कार्यभार आल्यानंतर पुन्हा याच विषयाच्या बाबतीत त्यांनी नियम 97 अन्वये चर्चा घडवून आणली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

महोदय, या निमित्ताने मी प्रथम उल्लेख करू इच्छितो की, राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली या भागाचे मुख्य वनसंरक्षक म्हणून श्री. भारती हे होते, ते निवृत्त झालेले आहेत आणि त्यानंतर श्री. मुंडे तेथे आले, त्यांचीही बदली झाली आहे. या सर्व प्रकरणाची पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल असेही मी सभागृहाला सांगू इच्छितो. या चौकशीनंतर निष्कर्ष बाहेर येतीलच. तसेच याच विषयाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात 21 पिटीशन्स दाखल झाले होते पण हे सर्व पिटीशन्स न्यायालयाने फेटाळले आहेत. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय उद्यानात एकही झोपडी केंद्राच्या कायदानुसार ठेवता येत नाही अथवा त्या भागात राहण्याचे घर सुध्दा करता येत नाही. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश दिले त्यात अनेक प्रश्न आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न असा की, या भागात एकूण 43 आदिवासी पाडे असून त्या पाड्यांचे प्रथम पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे आणि ते सुध्दा राष्ट्रीय उद्यानाच्या शेजारी कसे करता येईल यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी म्हणून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि ठाणे जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासोबत एक बैठक आयोजित करण्यात येईल. सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी आताच सांगितले की, या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी साधा बोअर जरी घ्यायचा म्हटले तरी त्यासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते, पण तशी परवानगी मिळत नाही. तसेच मी याबाबत यापूर्वी बैठका घेतल्या असता महापालिका मात्र खालच्या

....2

डॉ. पतंगराव कदम....

अधिकान्यांना बैठकीसाठी पाठविते, वास्तविक आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांनीच अशा बैठकीसाठी आले पाहिजे, म्हणून याबाबत मी महापालिका आयुक्तांना तशी सूचना करणार आहे.

त्यानंतर माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी मुलुंड पश्चिम येथील हनुमान पाड्याचा विषय सांगितला. त्यासंदर्भात मी खुलासा करू इच्छितो की, या भागातील 10 एकर जमीन वनमुक्त झाली असे म्हटले तरी त्यातील 7 एकर जागा राष्ट्रीय उद्यानाचीच आहे, प्रत्यक्षात या हनुमान पाड्याला मात्र 3 एकर जागा मिळणार आहे. पण तरी देखील राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटविताना या जागेवरील लोकांचेही पुनर्वसन करून त्यांना आपल्याला बाहेर काढावे लागेल. खरे म्हणजे नियम 35 खाली दिनशॉ ट्रस्टची जमीन आपल्याकडे आली होती व त्यात विभागणी होऊन वन विभागाला 848 एकर जमीन मिळाली आणि 640 एकर जमीन मूळ मालकाला मिळाली. त्यानंतर तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विचारात घेतला तर जोपर्यंत या लोकांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत या पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आवश्यक सुविधा देण्यासाठी मान्यता दिली जाईल. आदिवासी विभाग त्यांच्या आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यास तयार असून वन विभागाच्या जमिनीवर जी अतिक्रमणे असतील त्यांचे पुनर्वसन वन विभाग करण्यास तयार आहे. त्यानुसार शासनाच्या पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून एसआरए स्कीममार्फत जी 25144 घरे बांधून तयार आहेत त्या ठिकाणी या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार आहे. त्यापैकी 9346 लोकांचे पुनर्वसन आतापर्यंत पूर्ण झालेले आहे.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

डॉ. पतंगराव कदम ....

राहिलेल्या 1700 घरांचे पुनर्वसन एक महिन्यात चांदिवली येथे केले जाणार आहे.

एसआरए योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यात आली असून 15 लाख रुपये किमतीचे घर 70 हजार रुपयांमध्ये आपण देत आहोत. 13 हजार घरे बांधण्याचे शिल्लक आहे. सुमेर कॉर्पोरेशन व डि.बी. रियालीटीची यासाठी निवड झालेली आहे. संबंधितांची निवड शासनाने केलेली नाही. मानखुर्द किंवा चांदिवली या ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. आदिवासींची 1800 कुटुंबे असून त्यांचा सर्व खर्च आदिवासी विकास विभाग करणार आहे. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते व सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी सांगितले आहे की, एनव्हायर्नमेन्ट ग्रुप सुप्रीम कोर्टात जातो. गोंयका ग्रुप नेमका काय करतो, त्यांची काय परिस्थिती आहे, कोर्टामध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय कसे होतात या सर्व प्रश्नांची माहिती घेतली जाईल व यामध्ये काही गैर असेल तर चौकशी करून निर्णय घेतला जाईल.

सभापती महोदय, ज्या वन जमिनीवर इमारती बांधल्या गेल्या आहेत त्या इमारती कशा बांधल्या गेल्या, त्यांना परवानगी कोणी दिली यासंदर्भात सर्व चौकशी केली जाईल. या विषयाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे अनंत निर्णय असून यामध्ये लोकांचे हाल होत आहेत हे माझ्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे या विषयाच्या संदर्भात माझ्या दालनात कमिशनर किंवा अॅडीशनल कमिशनर, दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच ज्या सन्माननीय सदस्यांनी या विषयाच्या संदर्भात सूचना केलेल्या आहेत त्यांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात येईल व सर्व प्रश्नाचा निर्णय केला जाईल.

श्रीमती विद्या चव्हाण : सभापती महोदय, आम्ही गेल्या 12 वर्षांपासून वन विभागाकडे या प्रश्नाच्या संदर्भात दाद मागत आहोत पण त्यांच्याकडून कोणतीच कार्यवाही होत नसल्यामुळे आता आम्ही वन विभागाकडे जाणार नाही. माझा मुद्दा असा होता की, जेव्हा दोन पाट्यांचे भाडण कोर्टात जाते तेव्हा अॅफेक्टेड पार्टी झोपडपट्टी होते व दुसरी होते वन विभाग. चोऱ्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्या असून 12 वर्षांपासून वन विभाग त्यांच्यावर पांघरुण घालण्याचे काम करीत आहे हे आम्ही अनुभवलेले आहे. आम्हाला अजून पुढची वर्षे वाया घालवायची नाहीत. आमचे म्हणणे होते की, महसूल विभागाकडे यासंदर्भात बैठक घेण्यात यावी. माननीय मंत्री महोदयांनी

श्रीमती विद्या चव्हाण...

सांगितले की, या विषयाचे 21 पिटीशन फेटाळण्यात आलेले आहे. परंतु हे पिटीशन कोणी फेटाळले आहेत ? हे पिटीशन हायकोर्टाने फेटाळले आहेत. हायकोर्टाने जी तक्रार निवारण समिती गठीत केली होती ती कमिटी सुप्रीम कोर्टाने खारीज केली असून अशा प्रकारे हायकोर्टाला आदेश देण्याचे अधिकार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने असेही सांगितले आहे की, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. हे आदेश फक्त वैधानिक प्राधिकरणाला आहे. परंतु आम्हाला असे वाटते की, महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी, भूमापन अधिकारी यांनी आमच्या 848 एकर जमिनीची मोजणी करावी.

मघाशी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री. विनोद तावडे यांनी सांगितले आहे की, मुलुंड येथे डक लाईनच्या खाली जिल्हाधिकारी ज्या जमिनीचे भाडे भरतात त्या जमिनीवर जे लोक राहतात, त्या जमिनीशी वन विभागाचा काही एक संबंध येत नाही त्या लोकांना वन विभागाने सांगितले आहे की, आम्ही तुमचे पुनर्वसन करणार आहोत. आमच्यावर कशासाठी तुम्ही उपकार करित आहात ? आम्ही सुखाने राहतो आहे. आम्ही वन विभागात येत नाही असे आमचे म्हणणे आहे. आम्ही गेल्या 12 वर्षांपासून वन विभागाकडे भीक मागत होतो परंतु वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्यावर अन्याय केल्यामुळे आम्ही यापुढे वन विभागाच्या दारात जाणार नाही. महसूल विभागाने या प्रश्नाच्या संदर्भात आमच्या बरोबर एक बेटक घ्यावी अशी विनंती आहे. या विषयाच्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही मी वारंवार विनंती केली आहे. त्यामुळे आमचा वाद महसूल विभागाने सोडवावा अशी विनंती करते.

श्री. विनोद तावडे : सन्माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी जो विषय उपस्थित केलेला आहे त्याचा संबंध दोन तीन खात्याशी येतो. त्यामुळे या विषयाच्या संदर्भात आपण माननीय सभापती महोदयांना विनंती करावी अशी माझी सूचना आहे. माननीय सभापती महोदयांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना बोलावले तर हा विषय मार्गी लागू शकतो.

यानंतर श्री. भारवि...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

U 1

BGO/ D/ ST/

जुन्नरे..

11:40

**तालिका सभापती (श्री.मोहन जोशी)** : आपण केलेली सूचना माननीय सभापतींच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल आणि या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल.

अल्पकालीन चर्चा संपली आहे. आता सभागृहाची बैठक स्थगित होत असून नियमित बैठक दुपारी 12.00 वाजता पुनः भरेल.

(सकाळी 11.40 ते 12.00 वाजेपर्यंत बैठक स्थगित झाली.)

.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही



**(सभापतीस्थानी माननीय सभापती)****पृ.शी./मु.शी.:** तोंडी उत्तरे

**सभापती :** आता सर्व प्रथम राखून ठेवण्यात आलेला तारांकित प्रश्न क्रमांक 25389 चर्चेला घेण्यात येईल.

---

**गोंदिया जिल्ह्यात मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी महामंडळाच्या वतीने****धान खरेदी करण्यात येत असल्याबाबत**

**\*25389** श्री. केशवराव मानकर, श्री. पांडुरंग फुंडकर, श्री. संजय केळकर, श्रीमती शोभा फडणवीस, श्री. राजेंद्र जैन सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- 1) गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी महामंडळाच्या वतीने धान खरेदी करण्यात येत असून मार्केटींग फेडरेशनने 39 केंद्रांवर दिनांक 30 डिसेंबर, 2011 पर्यंत 1 लाख 67 हजार 538 क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
- 2) असल्यास, आदिवासी महामंडळांतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून खरेदी करण्यात न आल्यामुळे तसेच आदिवासी विकास महामंडळाच्या कित्येक केंद्रांवर दोन महिन्यांपासून बारदाने उपलब्ध नसल्यामुळे खरेदी थांबविण्यात आली असल्याचे जानेवारी, 2012 च्या सुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
- 3) असल्यास, गोंदिया जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांवर मागच्या वर्षीप्रमाणे धान उघडयावर पडले असून मागील वर्षीप्रमाणे याहीवर्षी धान सडण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे शासनाकडून यावर कायमस्वरूपी उपाय का योजले जात नाही, गोदाम आणि बारदान्याची समस्या किती कालावधीत सुटणार आहे नसल्यास, विलंबाची कारणे ?

**श्री. अनिल देशमुख (अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री):** 1) होय. हे खरे आहे.

2) व 3) गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरीप पणन हंगाम 2009-10 मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या 555971 क्विंटल धानापैकी भरडाईविना शिल्लक राहिलेले धान अंतर्गत वाहतूक करून 26 खाजगी गोदामामध्ये साठवणूक केला आहे. खरीप पणन हंगाम 2010-11 मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या 425277 क्वि. धानापैकी भरडाईविना शिल्लक राहिलेले धान खरेदी केंद्रांवर उघडयावर सुरक्षितपणे साठवणूक करून ठेवण्यात आले आहे. खरीप पणन हंगाम 2011-12 मध्ये जानेवारी, 2012 अखेर खरेदी करण्यात आलेले 186439 क्वि. धान नवीन व जुन्या बारदानामध्ये खरेदी केंद्रावर उघडयावर सुरक्षितपणे ठेवण्यात आले असून बारदानाची समस्या नाही.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतर्गत अन्नधान्य साठवणुकीसाठी पुरेशी क्षमता निर्माण करण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत नाबार्डमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसहाय्यामधून 5.95 नवीन गोदामे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम राज्यात हाती घेण्यात आला आहे.

श्री. केशवराव मानकर : सभापती महोदय, मंत्री महोदय हे आमच्या जिल्ह्याचे पालक मंत्री आहेत त्यामुळे त्यांना या प्रश्नाची संपूर्ण जाण आहे. त्यांनी या ठिकाणी नाबार्डमार्फत 584 नवीन गोदामे बांधण्यात येणार आहेत असे सांगितले आहे. नवीन गोदामे बांधल्यामुळे हा प्रश्न सुटणार नाही. या ठिकाणी देण्यात आलेले उत्तर हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. गोंदिया जिल्हा हा धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे. त्याचबरोबर भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील गोदामांची व्यवस्था अत्यंत वाईट असल्यामुळे नवीन गोदामांची आवश्यकता आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, सन 2008-09, 2009-10 व 2010-11 या तीन वर्षांमध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या धानापैकी सन 2008-09 मध्ये किती धानाची भरडाई होऊन तो एफ.सी.आय. कडे पाठविण्यात आला व त्यापैकी सन 2009-10 आणि सन 2010-11 मध्ये किती धान शिल्लक आहे? दुसरा प्रश्न असा आहे की, नवीन मालाची उचल होते परंतु जुन्या मालाची उचल कां होत नाही, या संदर्भात शासनाने कोणती उपाय योजना केली आहे?

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

V 3

DGS/ ST/ D/ D/ KTG/

12:00

ता.प्र.क्र. 25389...

श्री. अनिल देशमुख : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी धान भरडाईचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सन 2009-10 मध्ये मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून साडे चार लाख क्विंटल आलेले धान शिल्लक होते. सन 2010-11 मध्ये 3.40 लाख क्विंटल धान शिल्लक होते, सन 2011-12 मध्ये 1.73 लाख क्विंटल धान शिल्लक होते. अशाप्रकारे शिल्लक असलेल्या धानापैकी सन 2010-11 व सन 2011-12 मधील धानाची भरडाई 15 दिवसात होईल. सन 2009-10 मधील शिल्लक धानाची भरडाई करण्यामध्ये थोडी अडचण आहे. त्या करिता केंद्र सरकार व एफ.सी.आय. बरोबर बोलणी करित आहोत. त्यामध्ये मुदतवाढीचा आणि ट्रान्सपोर्टचा प्रश्न आहे.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

या मुदतवाढीच्या प्रश्नासाठी 28 फेब्रुवारी ही शेवटची तारीख असते. आम्ही केंद्र शासनाला सहा महिन्यापर्यंत तारीख वाढवून देण्यास सांगितले असून तशा प्रकारे तारीख वाढवून मिळाल्यानंतर गोंदिया जिल्ह्यातील 2009-2010 या वर्षातील धान, भरडाईचा जो प्रश्न आहे, तो सुध्दा आम्ही संपुष्टात आणू.

श्री.सय्यद पाशा पटेल : सभापती महोदय, जर मार्केटींग फेडरेशनकडून धानाची खरेदी होत आहे तर मग आदिवासी महामंडळाची गरज का भासली? असा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की, मार्केटींग फेडरेशनच्या आणि आदिवासी महामंडळाच्या खरेदीमधील दरामध्ये काही फरक आहे काय? आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की, जर आदिवासी महामंडळ हे आदिवासी भागातील धान खरेदी करित असेल तर जनरल भागातील धानाच्या दरापेक्षा आदिवासी भागातील धानाची किंमत जास्त असावी की नसावी ?

श्री.अनिल देशमुख : सभापती महोदय, राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये आम्ही धान खरेदी करण्यासाठी दोन एजन्सी नियुक्त केलेल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे आदिवासी विकास महामंडळ आणि दुसरे म्हणजे मार्केटींग फेडरेशन. या दोन्ही एजन्सीच्या माध्यमातून राज्य शासन संपूर्ण महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये धान खरेदी करित असते आणि दोन्ही ठिकाणी दर सारखे आहेत. कारण एफ.सी.आय.सगळ्यांना सारखेच दर देते. त्यामुळे दरामध्ये फरक नाही.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, 2008-2009 पासून आतापर्यंत राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या वतीने जे धान्य खरेदी केलेले आहे. ते ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाहीत ही गोष्ट खरी आहे काय ? तसेच जे धान्य ठेवण्यासाठी जागा नाही म्हणून सध्या शेतकऱ्यांचे भात खरेदी केले जात नाही ही गोष्ट खरी आहे काय ?

श्री.अनिल देशमुख : सभापती महोदय, नाही.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मी स्वतःमार्केटींग फेडरेशनचा संचालक आहे आणि मी रायगड जिल्ह्यातील मार्केटींग फेडरेशनचा चेअरमन आहे.माझ्या जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे भात गोडाऊनमध्ये ठेवण्यासाठी जागा नाही म्हणून खरेदी केले जात नाही अशी स्थिती आहे.मी राज्य शासनाला, मार्केटींग फेडरेशनला सातत्याने पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांना भात कवडीमोल किंमतीमध्ये व्यापाऱ्यांना विकावे लागत आहे. म्हणून माझा असा प्रश्न

ता.प्र.क्र.25389 . . . .

श्री.जयंत प्र.पाटील . . . .

आहे की, राज्य शासन यासाठी तेथे तातडीने गोडाऊनची सोय करणार आहे काय?

श्री.अनिल देशमुख : सभापती महोदय, याठिकाणी प्रश्नामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असला तरी सन्माननीय सदस्यांनी येथे अतिशय व्यापक प्रश्न विचारला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मार्केटींग फेडरेशनच्या माध्यमातून 114 सेंटर्स सुरु करून त्यामार्फत धान खरेदी केले जाते आणि त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी महामंडळाच्या माध्यमातून 143 सेंटर्स उघडण्यात आली आहेत. त्यामुळे याबाबतीत सन्माननीय सदस्यांची कोणती अडचण असेल किंवा स्पेसिफिक कोणती तक्रार असेल. अडचण असेल तर मला सांगावे. मी स्वतः याबाबत आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगून तेथील अडचण दूर करण्यात येईल. मात्र यासंदर्भात आम्ही सर्व सेंटर्स उघडलेली असून त्याठिकाणी खरेदी सुरु आहे. जर कुठे एखाद्या सेंटरच्या ठिकाणी अडचण असेल तर ती देखील दूर करू.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी गोडाऊनच्या बाबत दुसरा प्रश्न विचारला आहे. आपल्याला कल्पना आहे की, दरवर्षी धान्याचे उत्पादन वाढत आहे, मग गहू असो किंवा तांदूळ असो. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये गोडाऊनची व्यवस्था देखील चांगल्या पध्दतीने व्हावी जेणेकरून धान्य खराब होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात पावले उचललेली आहेत. नाबार्डच्या माध्यमातून जवळजवळ 500 कोटी रुपये व्याजाने घेतलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये अनेक गोडाऊन बांधत आहोत. तसेच आम्ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला सुध्दा विनंती केली की, महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोडाऊन बांधण्याचे काम हाती घ्यावे. त्यांनी सुध्दा महाराष्ट्रात साडेसात लाख मे.टन क्षमतेचे काम पी.पी.मॉडेलवर प्रायव्हेट पार्टनरशीपमध्ये काम हाती घेतलेले आहे. राज्य शासनाला यावर्षी बजेट मध्ये 40 कोटी रुपये मिळाले होते, त्यामधून सुध्दा आमचे गोडाऊनचे काम सुरु आहे. त्यामुळे नाबार्ड कडून जे 500 कोटी रुपये मिळाले त्यामधून, एफसीआयच्या माध्यमातून आणि राज्य शासनाच्या बजेटच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोडाऊनची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी युध्द पातळीवर काम सुरु आहे.

-----

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

W-3

APR/ D/ KTG/

12:05

**आष्टी (जि.बीड) तालुक्याच्या सीमेवर साकत गावाच्या**

## शिवारात 11 मोरांची शिकार झाल्याबाबत

### विधान परिषद अल्पसूचना प्रश्न क्रमांक 29919

#### डॉ.नीलम गोन्हे, विधानपरिषद सदस्य

सन्माननीय वने मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) आष्टी (जि.बीड) तालुक्याच्या सीमेवर साकत गावाच्या शिवारात सीना नदीच्या पात्रात तसेच माळरानावर अज्ञात मारेकऱ्याकडून 11 मोरांची शिकार झाल्याचा प्रकार दिनांक 28-3-2012 रोजीच्या सुमारास निदर्शनास आला हे खरे आहे काय,
- (2) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
- (3) चौकशीनुसार पुढे कोणती करवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

#### डॉ.भास्कर जाधव, डॉ.पतंगराव कदम यांच्याकरिता :

- (1) हे खरे नाही, तथापि, आष्टी (जि.बीड) तालुक्यातील मौजे साकत गावाच्या शिवारात सीना नदीच्या पात्राच्या काठावर एक मृत मोर दिनांक 28-03-2012 रोजी निदर्शनास आला आहे.
- (2) प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. सदर ठिकाणी शिकार झाली नसून मोर मृत अवस्थेत आढळून आला आहे. सदरहू मृत मोराचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून अहवाल अप्राप्त आहे.
- (3) वनक्षेत्रपाल, आष्टी यांनी त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांसह समक्ष जागेवर जाऊन चौकशी केली. तसेच वन्यजीव अधिनियम 1972 (संरक्षण) कलम 9 नुसार प्रथम गुन्हा क्रमांक 1/2011-12, दिनांक 28-03-2012 अन्वये नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरु आहे.

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, आष्टी (जि.बीड) तालुक्यातील मौजे साकत गावाच्या शिवारात सीना नदीच्या पात्राच्या काठावर एक मोर मृत निदर्शनास आला आहे. परंतु याबाबतीत तेथील ग्रामस्थांनी जी माहिती दिलेली आहे, त्या नुसार पाच ते सहा मोरांचे सांगाडे तेथे सापडले आहेत आणि त्याचबरोबर मोराची पिसे सुध्दा सापडलेली आहेत.

यानंतर श्री.बरवड . . .

अल्पसूचना प्रश्न क्रमांक 29919 .....

डॉ. नीलम गोन्हे ...

आणि याच आष्टी तालुक्यामध्ये पोलिसांनी हरिणांची शिकार करताना तीन लोकांना पकडले होते. आपण यामध्ये शव विच्छेदनापुरती मर्यादित चौकशी म्हटलेली आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, अहमदनगर जिल्ह्यातून किंवा अन्य जिल्ह्यातून मोरांची शिकार करणारे लोक, आसपासच्या गावातून, अहमदनगर जिल्ह्यातील दहेगाव येथून त्या ठिकाणी येतात आणि मोरांची शिकार करतात. याबद्दल पोलीस विभाग किंवा अन्य मार्गाने आपण काय चौकशी केलेली आहे ? दुसरा प्रश्न असा की, हा गुन्हा आपण कोणाविरुद्ध नोंदविलेला आहे ? तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटले आहे की, कलम 9 अनुसार प्रथम गुन्हा क्रमांक नोंदविलेला आहे. परंतु तो गुन्हा कोणाविरुद्ध नोंदविलेला आहे ? कारण शिकार केलेली आहे म्हटल्यावर कोणावर तरी गुन्हा नोंदवावयास पाहिजे. शव विच्छेदन म्हटल्यानंतर आपण शेतकऱ्यावर गुन्हा नोंदविणार. जर शिकार झालेली दिसते तर ज्यांनी शिकार केली त्यांच्या विरुद्ध किंवा अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध तरी गुन्हा नोंदविला गेला पाहिजे. म्हणून या दोन प्रश्नांच्या संदर्भात मंत्री महोदयांनी खुलासा करावा.

श्री. भास्कर जाधव : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्या बाबत सांगू इच्छितो की, मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे आणि राष्ट्रीय पक्षाला मारणे हा खूप मोठा गुन्हा आहे. मोर हा राष्ट्रीय संरक्षित पक्षी असल्यामुळे तशा प्रकारचे कृत्य जर कोणी करित असेल तर फॉरेस्ट अॅक्टनुसार त्यांच्यावर कडक गुन्हा दाखल केला जातो. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की, त्या ठिकाणी एकच नाही तर पाच सहा मोरांचे सांगाडे दिसले. परंतु चौकशी केली असता तशी वस्तुस्थिती अजिबात नाही.

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, गुन्हा कोणाविरुद्ध दाखल केला आहे ? उत्तर नसेल तर प्रश्न राखून ठेवावा. या ठिकाणी काही तरी नाही किंवा हा असे सांगण्याच्या अगोदर अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करू असे तरी उत्तर शासन देणार का ?

श्री. भास्कर जाधव : सभापती महोदय, ज्यावेळी अशा पध्दतीने कोणाच्या नावाने तक्रार होत नाही त्यावेळी आपण झिरो नंबरने गुन्हा दाखल करतो. सर्वसाधारणपणे महसूल किंवा फॉरेस्ट अॅक्टमध्ये ज्या जागेमध्ये अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे त्याचा आपण तपास करतो. सध्या हा गुन्हा झिरो नंबरने दाखल आहे आणि ज्याच्या जागेत मोर दिसला त्याची चौकशी चालू आहे.

RDB/ D/ KTG/

राज्यातील नर्सिंग महाविद्यालयात जनरल नर्सिंग मिडवाईफ आणि ऑक्झीलरी नर्सिंग मिडवाईफ या अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थीनींना देण्यात आलेली रक्कम समाज कल्याण विभागाकडून वसूल करण्यात येत असल्याबाबत

(१) \* २५२२८ डॉ.रणजित पाटील , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्री.नागो पुंडलिक गाणार , श्री.भगवान साळुंखे : सन्माननीय सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नर्सिंग महाविद्यालयात जनरल नर्सिंग मिडवाईफ आणि ऑक्झीलरी नर्सिंग मिडवाईफ या अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थीनींना शिष्यवृत्ती देय नाही, त्यामुळे सन २००९/१० या वर्षापासून आतापर्यंत वाटप केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शासन जमा करण्याची कारवाई समाजकल्याण विभागाने सुरु केली असल्याचे दिनांक १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी वा त्या सुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला जिल्ह्यातील जवळपास तीनशे विद्यार्थीनींना वाटप केलेली १ कोटी ५३ लाख १९ हजार ७९९ रुपये वसुलीसाठी ८ नर्सिंग महाविद्यालयांना विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयाने नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नर्सिंग महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थीनींकडून शिष्यवृत्तीची वसुली करण्याची कारणे काय आहेत,

(४) असल्यास, सदर अभ्यासक्रमांस शिष्यवृत्ती देय नव्हती तर ती कोणत्या कारणास्तव देण्यात आली आहे ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : (१) नाही.

सदर अभ्यासक्रमांना केंद्र शासनाच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती वसुलीचा प्रश्न येत नाही.

(२) होय.

(३) राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते परंतु सदर अभ्यासक्रमांत जनरल नर्सिंग मिडवाईफ आणि ऑक्झीलरी नर्सिंग मिडवाईफ या अभ्यासक्रमांचा समावेश नसताना तसेच मान्यता प्राप्त संस्था नसताना शिक्षण व परीक्षा फी अदा करण्यात आली आहे. त्याची वसुली संबंधित महाविद्यालयांकडून करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण अकोला यांच्या स्तरावर नोटिस बजावण्यात आली आहे.

(४) परंतु, शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून अकोला जिल्ह्यातील नर्सिंग महाविद्यालयात शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची शासनाकडून मंजूर करून न घेता प्रतिपूर्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे, सदर नर्सिंग महाविद्यालयांना वसुलीची नोटिस बजावण्यात आली आहे. याबाबत त्यांचा खुलासा मागवून कार्यवाही करण्यात येईल.



RDB/ D/ KTG/

ता. प्र. क्र. 25228.....

डॉ. रणजित पाटील : सभापती महोदय, पहिल्या प्रश्नाला 'नाही' असे उत्तर दिलेले आहे. खरे पाहिले तर एएनएम आणि जीएनएम कोर्सपुरताच हा मर्यादित प्रश्न आहे. अल्पमुदतीच्या व्यावसायिक शिक्षणात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशीप देय आहे की नाही असा प्रश्न आहे. त्याबाबत 'नाही' असे उत्तर दिलेले आहे. प्रश्न क्रमांक 3 च्या उत्तरामध्ये असे म्हटले आहे की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते परंतु सदर अभ्यासक्रमात जनरल नर्सिंग मिडवाईफ आणि ऑक्झीलरी नर्सिंग मिडवाईफ या अभ्यासक्रमाचा समावेश नसताना तसेच मान्यताप्राप्त संस्था नसताना शिक्षण व परीक्षा फी अदा करण्यात आली आहे. या ठिकाणी आम्ही मान्यताप्राप्त नसलेल्या संस्थांच्या बदल प्रश्न विचारलेलाच नाही. आमचा प्रश्न मान्यताप्राप्त संस्थांबद्दलच होता आणि ते देय नाही असे शासनाने तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये मान्य केलेले आहे. मग पहिल्या प्रश्नाला 'नाही' असे उत्तर का दिले ?

जे शिक्षण शुल्क आकारले जाते त्या संदर्भात माझ्याकडे जी.आर. आहे. केंद्र शासनाच्या जी.आर. मध्ये या कोर्ससाठी वैद्यकीय शिक्षण शुल्क समितीतर्फेच शुल्क आकारण्यात यावे असे म्हटले आहे.. अधिकारात नसताना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेकडून एक पत्र समाजकल्याण विभागाच्या शिक्षण विभागाकडे गेले आणि त्याचा विपर्यास करून तसे पत्र संपूर्ण महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले. त्यावरून सन 2009-2010 मध्ये जी मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीबद्दलची देयके देण्यात आली. हा केवळ अकोल्याबद्दलचा विषय नसून हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा धोरणात्मक विषय आहे. आपण अकोल्यामध्ये पत्र देऊन हे सगळे शिक्षण शुल्क वसुलीचे आदेश दिले हे खरे आहे का ? अधिकार नसताना ज्या नर्सिंग परिषदेने असे पत्र देऊन शासनाची दिशाभूल करून असा निर्णय घेण्यास बाध्य केले त्या अध्यक्षोंवर काय कारवाई करणार ?

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.शिवाजीराव मोघे : सन्माननीय सदस्यांनी एएनएम व जीएनएम या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थींना शिष्यवृत्ती देय नाही काय असे विचारले होते. त्यांना लागू आहे असे उत्तर दिलेले आहे. ही विशिष्ट संस्था आहे, त्या संस्थेला मान्यता नसल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे. त्यामध्ये ज्या फाईडिंग्ज दिसून येतील त्यानुसार संबंधितावर कारवाई केली जाईल.

श्री.अरुण गुजराथी : सभापती महोदय, जी.आर.चा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्यातील जवळपास 300 विद्यार्थींनीना 1 कोटी 53 लाख 19 हजार 799 रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. शासनाच्या जी.आर.चा चुकीचा अर्थ कोणी लावला आणि त्यांच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे आणि त्या जी.आर.चा नेमका अर्थ काय होता आणि त्यांनी कोणता अर्थ लावला आहे ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, जीएनएम व एएनएमच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळण्याबाबत एक प्रोसेस असते. प्रथम महाराष्ट्रातील नर्सिंग परिषदेकडून अर्ज मागविले जातात. त्यानंतर संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांच्याकडून त्याची तपासणी केली जाते. शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून आवश्यकते प्रमाणे त्यांना इसेन्शियल प्रमाणपत्र दिले जाते. ते प्रमाणपत्र दिल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत इंडियन नर्सिंग कौन्सिलची त्याला मान्यता लागते. ती मान्यता मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन त्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देते. ही पध्दत योग्य आहे. परंतु ही पध्दत अंमलात न आणता त्यांना मान्यता दिलेली असल्यामुळे त्या संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे.

श्री.संजय केळकर : सभापती महोदय, चुकीच्या कार्यपध्दतीचा फटका मागासवर्गीय विद्यार्थींनीना बसलेला आहे. सन 2009-2010 या वर्षातील शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया शासनाने आता सुरु केलेली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची कार्यवाही केलेली आहे त्यांच्याविरुद्ध शासन कोणतीच कारवाई करित नाही. 1 कोटी 53 लाख रुपये एका जिल्ह्यातील आहेत. ही विभागातील अधिकाऱ्यांची चूक आहे. दोन वर्षापूर्वी दिलेली ही शिष्यवृत्ती असल्यामुळे शासन वसुलीची कार्यवाही थांबविणार आहे काय, ती रक्कम माफ करणार आहे काय, अन्यथा या विद्यार्थींनींच्या पालकांना कर्ज घेण्याची वेळ येणार आहे. ज्यांनी ही चूक केली त्यांच्याविरुद्ध शासन कोणती कार्यवाही करणार आहे ?

2...

ता.प्र.क्र.25228...

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, अकोला जिल्ह्यातील हे प्रकरण लक्षात आल्यानंतर राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी असा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, संचालक, व्यावसायिक शिक्षण, सहसंचालक, समाजकल्याण यांची एक समिती नेमलेली आहे. त्या समितीला ज्यांनी नियमबाह्य फी लादणे किंवा शासनाकडून वसूल करणे त्याला अधिकारी जबाबदार आहेत की, यंत्रणा जबाबदार आहेत याची चौकशी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्या चौकशीमध्ये जे दोषी सापडतील किंवा जे जबाबदार असतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या सहीचे एक पत्रक दि.23.10.2011 रोजी काढण्यात आलेले आहे. त्यात असे म्हटलेले आहे की, शिक्षण शुल्क समितीने प्रमाणित न केलेले कोणतेही शुल्क आकारणे, महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कॅपिटल फी अॅक्ट 1887 अंतर्गत गुन्हा ठरतो. असे प्रकार झाल्याचे जेथे प्रथम दर्शनी निदर्शनास येईल तेथे कारवाई करण्यात येईल.

प्रा.सुरेश नवले : सभापती महोदय, एक तर त्या संस्थेला मान्यता नव्हती. त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रमालाही मान्यता नव्हती. संस्थेला कसलीही मान्यता नसताना त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केलेली आहे. त्यामुळे त्या संस्थेविरुद्ध शासन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे का ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : त्याबाबतच नोटीस दिली असून, त्या प्रमाणे कारवाई केली जाईल.

श्रीमती शोभा फडणवीस : मुळात ही खाजगी विना अनुदानित संस्था आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. हा शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्न आहे. शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून दिले जाते. त्यामुळे शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासणी न करता शिष्यवृत्ती मंजूर कशी केली ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, अकोला जिल्ह्यापुरता प्रश्न नाही तर संपूर्ण राज्यात हा प्रश्न आहे. त्यामुळे चौकशीमध्ये....

( विरोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य उभे राहून बोलत असतात. )

3...

ता.प्र.क्र.25228....

मी सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे याबाबत चौकशी अॅथोरिटी नेमलेली आहे. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी परवानगी कशी दिली, त्यांनी खोटी कागदपत्रे दिली होती काय, हे पहावे लागेल आणि त्यानंतरच कारवाई करावी लागेल.

( विरोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य उभे राहून बोलत असतात. )

यानंतर श्री.शिगम....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

Z-1

MSS/ D/ KTG/

12:20

ता.प्र.क्र. 25228...

**सभापती** : या प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल असे उत्तर मंत्री महोदयांनी दिलेले आहे. मी आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळतो. ता.प्र.क्र. 26484...

(विरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.)

**सभापती** : मी पुढच्या प्रश्नाकडे गेलो होतो. पुढच्या प्रश्नाकडे गेल्यानंतर पुन्हा मागच्या प्रश्नावर येता येत नाही. परंतु अपवाद म्हणून मी विरोधी पक्षाच्या एका आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका सन्माननीय सदस्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देतो. सन्माननीय सदस्य श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करण्याची नोटीस काढण्यात आली आणि त्याचा फटका आदिवासी विद्यार्थीनींना बसलेला आहे. सन 2009-2010 या वर्षामध्ये ही घटना घडली असून चूक कोणी केली हे सिद्ध झालेले आहे. आता या प्रकरणी पुन्हा चौकशी काय करणार हा प्रश्न आहे. तेव्हा ज्या अधिका-याने नोटीस बजावली त्याच्यावर काय कारवाई करणार आहात ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : मी सुरुवातीलाच सांगितलेले आहे की, यामध्ये जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.

श्री. विनायक मेटे : हा मागासवर्गीय विद्यार्थीनींच्या संदर्भातील प्रश्न आहे. माननीय समाजकल्याण मंत्री हे आदिवासी समाजाचे आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थीनींवर अन्याय झालेला असल्याचे उत्तरात मान्य केलेले आहे. ज्या अधिका-याने चूक केलेली आहे त्याला निलंबित करावे अशा सभागृहाच्या भावना असताना अशा अधिका-याची बाजू मंत्री महोदय का घेत आहेत ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : मी सुरुवातीलाच सांगितले की, चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यास त्याला सस्पेण्ड करण्यात येईल.

(विरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य माननीय सभापतींच्या व्यासपीठाजवळ येऊन जोरजोराने घोषणा देत असतात.)

श्री. शिवाजीराव मोघे : सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता संबंधित अधिका-याला सस्पेण्ड करण्यात येईल.

---

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

Z-2

MSS/ D/ KTG/

12:20

राज्यातील मच्छीमारांना असलेले १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण ५ लाखापर्यंत वाढविण्याची  
आवश्यकता

(२) \* २६४८४ श्री.राजन तेली , श्री.सुभाष चव्हाण , श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप : सन्माननीय  
मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मच्छीमारांना असलेले १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण ५ लाखापर्यंत वाढविण्याची  
आवश्यकता असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मा.मत्स्यविकास मंत्री यांनी माहे  
सप्टेंबर, २०११ मध्ये वा त्या दरम्यान एका बैठकीत माहिती दिली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील काय आहे,

(४) तसेच किती कालावधीत मच्छीमारांच्या विमा संरक्षणाची रक्कम वाढविण्यात येणार आहे ?

श्री. भास्कर जाधव, श्री.मधुकरराव चव्हाण यांच्याकरिता : (१) नाही.

(२), (३) व (४) सदरची योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढविणे केंद्र  
शासनाच्या अखत्यारित आहे.

सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये सुधारणा करण्यास मला परवानगी द्यावी.

सभापती : ठीक आहे.

श्री. भास्कर जाधव : उत्तराच्या भाग (१)मध्ये "नाही" असे म्हटलेले आहे. त्याऐवजी "होय"  
असे वाचावे.

श्री. राजन तेली : मच्छीमार बांधवांच्या विमाची मर्यादा १ लाखावरून ५ लाखापर्यंत  
वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करित असल्यामुळे मी मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो. ठाणे, रायगड,  
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ४ जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांना सातत्याने फयानसारख्या नैसर्गिक  
आपत्तीचा, वादळाचा सामाना करावा लागतो.

...नंतर श्री. गिते...

ता.प्र.क्र.26484...

श्री.राजन तेली...

कोकणामधील 896 कि.मी. किनारपट्टी जवळील मच्छीमार आपला जीव धोक्यात घालून मच्छीमारी करण्यासाठी खूप दूर जातात. या राज्यातून 2 हजार कोटी रुपयांची मत्स्य निर्यात करतो. कर्नाटक, केरळ आणि गोवा राज्य हे मच्छीमारांसाठी चांगल्या प्रकारच्या सोयी सुविधा निर्माण करून देतात. मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकारच्या ज्या काही विविध योजना आहेत, त्या योजनांचा लाभ या ठिकाणच्या मच्छीमारांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मच्छीमारांना मिळावा म्हणून आपण प्रयत्न करता, परंतु तुमच्या विभागाचे अधिकारी मात्र काहीच प्रयत्न करीत नाहीत. या ठिकाणच्या मच्छीमारांना 2006-07 या वर्षापासून न्याय दिला जात नाही. मच्छीमारांना मॅचिंग गॅट दिली जात नाही. राज्यातील मच्छीमारांना असलेले 1 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण 5 लाखापर्यंत वाढविण्यासंदर्भात शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत काय ? कोकणातील मच्छीमारांसाठी नवीन काही योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे काय ?

श्री. भास्कर जाधव : कोकणाला 720 कि.मी.समुद्र किनारा लाभलेला आहे. या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमार बांधवांच्या दृष्टीने या ठिकाणी अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. सन्माननीय मत्स्यविकास मंत्री महोदय हे सप्टेंबर महिन्यात एका कार्यक्रमासाठी कोकणात गेले होते. मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकार जी विमा योजना राबवित आहे, त्या विमा योजनेची रक्कम 1 लाखाहून 5 लाखापर्यंत करावी अशा प्रकारची मागणी मच्छीमार संस्थांनी माननीय मंत्री महोदयाकडे केली. त्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यावेळी माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले. सभापती महोदय, मी सभागृहाचा थोडा जास्त वेळ घेऊ इच्छितो. दोन वेगवेगळ्या योजना आहेत. या विमा योजनेचा लाभ मच्छीमारांना केंद्र सरकारकडून दिला जातो. या विमा योजनेचा प्रिमियम वर्षाला 30 रुपये भरावयाचा असतो. यात 15 रुपये केंद्र शासन व 15 रुपये राज्य शासन प्रिमियम भरीत असते. राज्य सरकारची संकट निवारण निधी यातून सुध्दा 1 लाख रुपये मच्छीमारांना मिळणार आहेत. 1 लाख रुपयांऐवजी 5 लाख रुपये व्हावेत अशी या ठिकाणी मागणी केली आहे. एन.एस.डी.बी.च्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्या योजना मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांना लागू कराव्यात. गोड्या पाण्यात मच्छीमारी करणारे मच्छीमार असतील, खान्या पाण्यात मच्छीमारी करणारे मच्छीमार असतील अशा सर्व मच्छीमारांना या योजना लागू

2...

ता.प्र.क्र.26484...

श्री.भास्कर जाधव....

कराव्यात, यादृष्टीने आमचा विभाग निश्चितपणे कार्यशील आहे. आज संपूर्ण कोकण पट्टीवर 3 लाख, 23 हजार, 838 मच्छीमार आयडेंटिफाय झालेले आहेत. म्हणून मच्छीमारांची संख्या कशी वाढेल, त्यांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ कसा देता येईल याबाबतीत शासनाच्या वतीने पुढाकार घेतला जाईल, त्याचप्रमाणे कोकणातील देखील सन्माननीय सदस्यांनी देखील याबाबतीत पुढाकार घ्यावा अशी माझी सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे. विमा योजनेची रक्कम अधिक होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करील.

श्री. परशुराम उपरकर : हत्तीने मारले तर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. मच्छीमारी करताना मच्छीमार पाण्यात बुडून मृत झाला तर त्याच्या कुटुंबीयास 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मच्छीमारी करताना मच्छीमार पाण्यात बुडून मृत झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली पाहिजे. 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याऐवजी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची योजना राज्य शासनाच्या वतीने हाती घेण्यात येईल काय ?

श्री. भास्कर जाधव : आर्थिक मदत करण्यासंदर्भात प्रत्येक विभागाचा वेगवेगळा निर्णय असतो. 1 ऑगस्ट, 1994 पर्यंत पाण्यात बुडून मृत झालेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. 29 सप्टेंबर, 1998 या वर्षापासून आर्थिक मदतीची रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली. 1 एप्रिल, 2008 रोजी ही रक्कम 1 लाख रुपये करण्यात आली. दिनांक 9.8.2010 रोजी केंद्र शासनाने हे पैसे देण्याचे मान्य केले आहे. सन्माननीय सदस्यांच्या सूचनेचा शासन भविष्यात विचार करील.

श्री एस. क्यू. ज़मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक क्लेरिफिकेशन में चाहता हूं. मुझे पूछना है कि मच्छीमारों की जो बीमा योजना है, वह योजना सिर्फ कोकण क्षेत्र के लिए है या पूरे महाराष्ट्र राज्य के मच्छीमारों के लिए है ?

श्री भास्कर जाधव : यह योजना पूरे राज्य के मच्छीमारों के लिए है.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सध्या कोकणामध्ये मच्छिचा दुष्काळ आहे. समुद्रातील मच्छी ही खूप दूर अंतरावर चालली आहे. केंद्र सरकारने मद्रासमध्ये मच्छीमारांना फिश फायण्डर उपलब्ध करून

3...



ता.प्र.क्र.26484...

श्री.जयंत प्र.पाटील...

दिलेले आहेत. या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांना मी दिल्लीला भेटलो होतो. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी केंद्र शासनाकडून मच्छीमारांसाठी फिश फायण्डर दिले गेलेले आहेत. त्यामुळे समुद्रात कुठे मच्छी उपलब्ध आहे, कोणत्या दिवसात मच्छी उपलब्ध होणार या संबंधिची माहिती आधीच मिळते. आपल्या राज्यामध्ये मच्छीमारांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य घेऊन फिश फाईंडर उपलब्ध करून देणार काय ?

यानंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नही

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, या संदर्भात थोडीशी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री श्री.शरद पवार यांच्या अखत्यारित ही योजना आहे.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, चुकीचे रेकॉर्ड होत आहे.

श्री.भास्कर जाधव : आपण दुरुस्ती करू.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री.विलासराव देशमुख यांनी मला खास दिल्लीला बोलावले आणि माझ्याबरोबर चर्चा केली, संबंधित विभागाच्या सचिवांना बोलावून त्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान खात्यामार्फत माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री श्री.शरद पवार यांनी योजना आणली असेल तर आम्हाला आनंद आहे. परंतु त्या खात्याशी संपर्क साधून निश्चितपणे प्रयत्न केला तर प्रत्येक जिल्ह्यात 10 फिश फाईण्डर देण्याची तरतूद केंद्र शासनाकडून केली जाते, त्याचा पाठपुरावा शासन करणार आहे काय?

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी अधिक माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री श्री.विलासराव देशमुख यांच्याकडे हा विषय आहे हे मला या क्षणापर्यंत ज्ञान नव्हते. सन्माननीय सदस्यांना त्यांनी माहिती दिली असल्यामुळे निश्चितपणे त्यांनी त्या खात्याकडे प्रस्ताव पाठविले असावेत. त्या प्रस्तावाची प्रत त्यांनी माझ्याकडे द्यावी, मी त्याबाबत पाठपुरावा करेन. आपल्या राज्यात मच्छीमारांकरिता फिश फाईण्डर देण्याची योजना आज सुध्दा अस्तित्वात आहे. त्यांना आपण अनुदान देखील देतो.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, प्रश्नोत्तराच्या यादीतील पहिल्या प्रश्नाबाबत संपूर्ण सभागृहाच्या भावना तीव्र झालेल्या होत्या. अपवादात्मक परिस्थितीत पुढे गेल्यानंतर देखील आपण सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंबंधी न्याय देण्यासाठी प्रश्न पुन्हा पुकारण्याची संधी दिली आणि त्या विषयाला न्याय दिला. एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी न घालता मंत्री महोदयांनी त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले त्याबद्दल मी व्यक्तिशः व सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या वतीने आपले आभार मानतो.

**गोंधळी भटक्या विमुक्त समाजासाठी नेमण्यात आलेल्या रेणके आयोगाबाबत**

**(३) \* २५०७९ श्री.जयंत प्र. पाटील , श्री.कपिल पाटील :** सन्माननीय सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) गोंधळी भटक्या विमुक्त समाजासाठी सन २००४ मध्ये रेणके आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, या आयोगाने समाजाच्या सर्वांगीण विकासाबाबत अभ्यास करून दिनांक २ जुलै, २००८ रोजी वा त्यासुमारास सामाजिक न्याय मंत्री यांना अहवाल सादर केला, हे खरे आहे काय,
- (३) असल्यास, या अहवालातील शिफारशी कोणत्या आहेत व त्या शिफारशीबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे,
- (४) अद्याप, कार्यवाही झाली नसल्यास, विलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

**श्री.शिवाजीराव मोघे :** (१) सदर बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून त्यानुसार सदर आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली, हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, राज्य सरकारने रेणके आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती ही गोष्ट खरी आहे काय? रेणके आयोगाने केंद्र सरकारकडे शिफारशी सादर केलेल्या होत्या काय? असल्यास, त्याबाबत काय पाठपुरावा करण्यात आला?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, श्री.बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 मार्च, 2005 रोजी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आयोग जाहीर केला होता. दिनांक 6 फेब्रुवारी, 2006 रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या आयोगाने वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन मुलाखती घेतल्या आणि त्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जुलै, 2008 मध्ये अहवाल सादर केला.

श्री.रमेश शेंडगे : सभापती महोदय, या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही जबाबदारीची जाणीव न ठेवता दिले असावे असे मला वाटते. राज्यामध्ये 15 टक्के लोकसंख्या ही भटक्या विमुक्तांची आहे. भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी बजेट व इतर शासकीय योजना कार्यवाहीत नाहीत. 15 टक्के भटक्या विमुक्त समाजासाठी रेणके आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला शिफारशी करण्यात आल्या. त्या शिफारशीमधील 80 ते 85 टक्के भाग हा राज्यातील भटक्या व विमुक्तांबाबतचा आहे हे आम्ही मान्य करतो. त्यांच्या विकासासाठी केलेल्या शिफारशी राज्य सरकारच्या अखत्यारितील आहेत. त्या त्वरित लागू करून अंमलात आणणार का? वसंतराव नाईक भटक्या जाती व विमुक्त जाती महामंडळामार्फत त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न केला जातो. परंतु अ,

..3..

श्री.रमेश शेंडगे.....

ता.प्र.क्र.25079.....

ब, क व ड वर्गवारी केल्यामुळे त्या सर्व वर्गांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कर्ज वाटपाचे आदेश देणार काय?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारला आहे. देशाच्या पातळीवर रेणके आयोग स्थापन झाला होता. विमुक्त जाती, भटक्या जाती, अर्ध भटक्या जमाती या लोकांचे जीवन स्तर ऊंचावण्यासाठी, त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक उपाययोजना सुचविणे तसेच अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी विशिष्ट गरजांचा विचार करून चॅनेलाईज एजन्सीमार्फत उपाययोजना सुचविणे, शैक्षणिक विकास, आरोग्य या संदर्भात निर्देशित करणे, या समुहाच्या विकासासाठी विशिष्ट निर्देशित अशा शिफारशी आवश्यकतेनुसार आयोगाने करावयाच्या होत्या. या आयोगाने केंद्र शासनाला अहवाल दिलेला आहे.

नंतर श्री.खर्चे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

ता. प्र. क्र. 25079.....

श्री. शिवाजीराव मोघे .....

दुसरा प्रश्न असा आहे की, "अ, ब, क व ड" अशा चार प्रवर्गात व्हीजेएनटीसाठी आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीज केल्या असून त्यांना वसंतराव नाईक महामंडळाला त्या त्या कॅटेगरीप्रमाणे मदत करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच कर्जाचे वाटप करीत असताना त्यांनी या कॅटेगरीज प्रमाणेच कर्जाचे वाटप करावे.

श्री. रमेश शेंडगे : महोदय, राज्य शासनाच्या अखत्यारीत ज्या शिफारसी येतात त्यांची अंमलबजावणी शासन करणार काय आणि केव्हा करणार आहे ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : महोदय, केंद्र शासनाला या शिफारशी केल्या आहेत.

श्री. जयंत प्र. पाटील : महोदय, हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असला तरी राज्य शासन आपल्या बजेटमध्ये या समाजाची उन्नती करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणार काय ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : महोदय, ओपन बजेटमध्ये पैसे कमी पडतात म्हणून वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना आपण केली आहे व त्यातून या समाजाला अधिकचा निधी देण्याचा विचार चालू आहे.

डॉ. नीलम गोन्हे : महोदय, सन 2004 मध्ये या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली असून ज्याप्रमाणे केंद्र शासनाकडे या आयोगाने शिफारशी केल्या तशा वेळोवेळी राज्य शासनाकडे सुध्दा काही शिफारशी करण्यात येतात. तसेच यात निधीच्या तरतुदीप्रमाणे काही धोरणात्मक तरतुदी सुध्दा केल्या आहेत, त्यावर शासनाने काय विचार केला आहे ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : महोदय, देशात मागासलेपणाचा एक विशिष्ट झोन म्हणून या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती. देशात इतर कोणत्याही राज्यात नाही एवढ्या सुविधा आपण आपल्या राज्यात या समाजाला देत आहोत. असे असले तरी या निमित्ताने ज्या अनेक सूचना करण्यात आल्या त्यांचाही विचार शासन स्तरावर केला जाईल.

-----

**राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित  
अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद केल्याबाबत**

(4) \* 26412 श्री. एस. क्यू. जमा , श्री.राजन तेली, डॉ.सुधीर तांबे, श्री.एम.एम.शेख, श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप : सन्माननीय सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद केल्याचे माहे जानेवारी, 2012 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
- (2) असल्यास, विद्यार्थ्यांची अचानक शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे हे खरे आहे काय,
- (3) असल्यास, राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देण्याबाबत राज्य शासनाकडून कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
- (4) अद्याप, याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

**श्री.शिवाजीराव मोघे** : (1) नाही.

(2), (3) व (4) राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य योजनेतून शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 100 टक्के केंद्रपुरस्कृत असून त्यासाठी केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क मंजूर करण्यात येते.

तथापि, शासन निर्णय दिनांक 3/2/2012 अन्वये सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ड ई-10 वी ची शालांत परिक्षा (S.S.C./C.B.S.E. व तत्सम ) उत्तीर्ण होऊन महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमात (Full Time Course) शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना सदर योजना अनुज्ञेय राहिल यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची मान्यता नसल्याने वगळण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, आरोग्य विज्ञान विभाग तसेच कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत यांचे शासनमान्यता असलेले अभ्यासक्रमांना प्रतिपूर्ती योजना पूर्वीप्रमाणे लागू राहिल.

ता. प्र. क्र. 26412.....

श्री एस. क्यू. ज़मा : सभापति महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय जी ने और हमारी सरकार ने टेक्नीकल उत्तर दिया है. मेरा कहना है कि जो बिनाअनुदान तथा कायम बिनाअनुदान संस्थाएँ हैं और वोकेशनल कोर्स चला रही हैं उसमें एससी,एसटी, ओबीसी जाति के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा एडमिशन लेने के बाद उनको केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से जो स्कॉलरशिप मिलती है, वह अब बंद की गयी है. इस बारे में राज्य सरकार ने 29 नवम्बर 2011 को आदेश निकाला है. जबकि माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है. परन्तु बहुत सारे महाविद्यालयों में उन विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है. बाद में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि एसएससी या सीबीएससी के जो कोर्सेज हैं और फुल टाइम कोर्स में जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप बंद की है. मुझे पूछना है कि इस बारे में क्या सरकार स्पष्ट निर्णय लेगी कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी.

श्री. शिवाजीराव मोघे : महोदय, प्रश्नाच्या उत्तरातच मी असे म्हटले आहे की, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, आरोग्य विज्ञान विभाग तसेच कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत यांचे शासनमान्यता असलेले अभ्यासक्रमांना प्रतिपूर्ती योजना पूर्वीप्रमाणे लागू राहिल व ही प्रतिपूर्ती शासन मान्य कोर्सपुरतीच मर्यादित राहिल.

डॉ. सुधीर तांबे : महोदय, मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, मागील वर्षी शासनाने बीसीए व बीबीए या व्यावसायिक पदवीसाठी मान्यता दिली होती, त्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांनी या कोर्सेससाठी अॅडमिशन घेतली. पण आता या दोन्ही विषयांची मान्यता शासनाने बंद केल्यामुळे ज्या मुलांनी अॅडमिशन घेतली त्यांच्या फीच्या प्रतिपूर्तीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. माझी विनंती आहे की, किमान हे कोर्सेस पूर्ण होईपर्यंत शासन याला मान्यता देणार आहे काय ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : महोदय, ज्या मुलांना प्रवेश दिलेले आहेत त्यांचे कोर्सेस पूर्ण होईपर्यंत ही मान्यता राहिल.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

ता.प्र.क्र. :26412 .....

श्री. जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, शिष्यवृत्ती जून पूर्वी दिली जाईल असे माननीय मंत्री महोदयांनी गेल्या वर्षी या सभागृहात सांगितले होते. आज राज्यातील बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. रायगड जिल्ह्यात 12 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती देणे बाकी आहे ही वस्तुस्थिती आहे काय, तसेच सदर शिष्यवृत्ती कधी दिली जाणार आहे ?

श्री. शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य हे सिनियर मोस्ट सदस्य असल्यामुळे ते चुकीची माहिती देणार नाही याची मला कल्पना आहे. महाराष्ट्र शासनाने 15 लाख विद्यार्थ्यांना ई-स्कॉलरशीप दिलेली आहे. ही स्कॉलरशीप विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्ट जमा केलेली आहे. देशातील कोणत्याही राज्याने असे काम केले नाही ते काम महाराष्ट्र शासनाने केलेले आहे. स्कॉलरशीप देण्यामध्ये थोडा विलंब लागला ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या राज्यात ओबीसींना स्कॉलरशीप देतांना उत्पन्नाचे सिलींग लावण्यात आलेले नाही. काही राज्यात बीपीएल ओबीसींना स्कॉलरशीप दिली जाते, काही राज्यामध्ये 21 हजाराच्यावर उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जात नाही. काही राज्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप म्हणून 20 हजार रुपये दिले जातात व बाकीचे पैसे तुम्ही भरा असे सांगितले जाते. महाराष्ट्र खरोखर मोठा आहे त्यामुळेच महाराष्ट्राला "महाराष्ट्र" म्हटले जाते. तुम्ही केवळ "जय महाराष्ट्र" म्हणता परंतु आम्ही "महाराष्ट्र राज्य मोठे आहे" असे म्हणतो. सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र.पाटील यांनी जे म्हटलेले आहे ते बरोबर आहे. ओबीसीला पैसा जनरल फंड मधून दिला जातो. परंतु या वर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्ण पैसे देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे केली जाईल एवढे मी या प्रसंगी सांगू इच्छितो.

---

...2...



**यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ पंचायत समितीअंतर्गत देण्यात आलेल्या****घरकुल योजना तसेच दलितवस्ती सुधार योजनेत मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार**

(5) \* 25646 श्री.संदिप बाजोरिया , अॅड. उषाताई दराडे , श्री.विक्रम काळे , श्री.रमेश शेंडगे , श्री.किरण पावसकर , श्री.दीपकराव साळुंखे , श्री.अनिल भोसले , श्री.जयवंतराव जाधव , श्री.सतीश चव्हाण : सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(1) यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ पंचायत समितीअंतर्गत देण्यात आलेल्या घरकुल योजना तसेच दलितवस्ती सुधार योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत पुसद तालुक्यातील पिंपळगांव येथील नागरिकांनी दिनांक 15 जानेवारी, 2012 पासून आमरण उपोषण सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(3) असल्यास, यासंदर्भात चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(4) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार संबंधिताविरुद्ध कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

**श्री.जयंत पाटील :** (1) घरकुल योजनेत भ्रष्टाचार झालेला आहे. मात्र दलितवस्ती सुधार योजनेत भ्रष्टाचार झाला नाही.

(2) होय.

(3) होय.

(4) घरकुल योजनेतील चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने यवतमाळ पंचायत समितीचे श्री.टी.एम.महाजन, विस्तार अधिकारी व ग्रामपंचायत भोसा येथील श्री.आर.एस. दुधे व श्री.वाय.डब्ल्यू. काळे, ग्रामसेवक यांस निलंबित करण्यात आले आहे.

श्री. संदिप बाजोरिया : माननीय मंत्री महोदयांनी छापील जे उत्तर दिलेले आहे त्यामध्ये घरकुल योजनेत भ्रष्टाचार झालेला आहे हे मान्य केलेले असल्यामुळे मी त्यांना धन्यवाद देतो. माननीय मंत्री महोदयांना मी विचारू इच्छितो की, घरकुल योजनेत ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे, जे लोक यामध्ये गुंतलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे काय ? घरकुल योजनेच्या संदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत घरकुल योजनेची चौकशी करण्यात आली होती. परंतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीच भ्रष्टाचारी असून त्यांनी शासनाच्या जीआर मधील एका नियमात बदल केला होता व त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, "शासनाचा हा जीआर चुकीने आलेला आहे". घरकुल योजनेच खरे दोषी बीडीओ असून त्यांना निलंबित करून त्यांची सीआयडी मार्फत चौकशी केली जाणार आहे काय ?

..3

श्री. जयंत पाटील : सभापती महोदय, सदर प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे हे उघड झालेले आहे. चुकीच्या लाभार्थीची नावे घालून लाभ देण्यात आलेला आहे असे तपासाअंती सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे याबाबत सीआयडी चौकशीची आवश्यकता नाही. या प्रकरणातील दोषींची नावे उत्तरामध्ये देण्यात आलेली आहेत. विस्तार अधिकारी तसेच दोन ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. बीडीओ यांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून त्यांनी यासंदर्भात उत्तर दिलेले असून ते अमान्य करून विभागीय चौकशी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. संबंधितांची विभागीय चौकशी केली जाईल व यामध्ये संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

श्री. संदिप बाजोरिया : सभापती महोदय, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खोटा रिपोर्ट दिला असून त्यांनी ग्रामसेवकांना दोषी ठरवलेले आहे. परंतु या प्रकरणात मूळ दोषी बीडीओ असून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे काय ? सदर बीडीओ यांनी भोसाळ, यवतमाळ ग्रामीण व उमरसरा भागात काम न करता 80 लाखाची देयके परस्पर दिलेली आहेत त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी केली जाणार आहे काय ? तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली जाणार आहे काय ? अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली जाणार असेल तर ती कोणत्या अधिकाऱ्याकडून केली जाणार आहे.

श्री. जयंत पाटील : सभापती महोदय, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जे निष्कर्ष काढलेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी बीडीओ यांना देखील दोषी धरलेले आहे. सीईओ यांनी बीडीओ यांना यापूर्वीच कारणे दाखवा नोटीस दिली असून बीडीओ यांनी उत्तर दिले असून बीडीओ यांना 13 एप्रिल, 2012 रोजी विभागीय चौकशीची नोटीस देण्यात आलेली आहे. यामध्ये संबंधितांवर निश्चितपणे कडक कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणामध्ये संबंधितांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सिध्द होईल याबद्दल मला शंका वाटत नाही. या प्रकरणामध्ये अगोदरच 3 अधिकारी सस्पेंड करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणात एक बीडीओ दोषी असता तर त्यांना सस्पेंड करता आले असते परंतु या प्रकरणात 3 बीडीओ दोषी आहेत त्यामुळे तिघांवर जबाबदारी निश्चित करून कोणाकडून हा प्रकार झालेला आहे त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली केली जाईल. या प्रकरणात 3 बीडीओंना नोटीस देण्याची वेळ आलेली आहे. हा भ्रष्टाचार 3 बीडीओंच्या कार्यकाळात झालेला आहे.

यानंतर श्री. भारवि...

17-04-2012  
BGO/ D/ KTG/

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )  
जुन्नरे..

EE 1  
12:45

ता.प्र.क्र.25646...

श्री.जयंत पाटील...

त्यामुळे जो सापडेल त्याच्यावर कडक कारवाई होईल. निलंबित नाही तर बडतर्फी पर्यंत देखील  
आपण जाऊ शकतो.

.....

..2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुटुंबांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना व जननी शिशु सुरक्षा  
योजनेचा लाभ देण्याबाबत**

(6) \* 26641 श्री.विनोद तावडे , श्री.संजय केळकर , श्री.रामनाथ मोते , श्री.चंद्रकांत पाटील :  
सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिनांक 31 डिसेंबर, 2011 पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे म्हणून अधिकृतपणे नोंद झालेली किती कुटुंबे आहेत व ज्यांची अधिकृतपणे नोंद झाली नाही असे अर्ज प्राप्त झालेली किती कुटुंबे प्रतीक्षाधीन आहेत,
- (2) असल्यास, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब ठरविताना कोणकोणते निकष कोणकोणत्या यंत्रणाकडून वा अधिकाऱ्यांकडून तपासण्यात आले होते,
- (3) असल्यास, दिनांक 31 डिसेंबर, 2011 पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे म्हणून गणली गेली आहेत त्यातील अनुक्रमे किती कुटुंबांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना व जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय सुविधांचा लाभ देण्यात आला आहे,
- (4) अद्याप, किती कुटुंबांना या दोन योजनांतर्गत लाभ मिळणे बाकी आहे व तो त्यांना केव्हा देण्यात येणार आहे ?

**श्री.जयंत पाटील :** (1) दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची गणना 2002-2007 नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दि.31 डिसेंबर, 2011 पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे म्हणून 71,386 कुटुंबे आहेत. तसेच ज्यांची अधिकृतपणे नोंद झाली नाही असे अर्ज प्राप्त झालेली प्रतीक्षाधीन कुटुंबे नाहीत.

(2) दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची गणना 2002 करीता केंद्र शासनाने खालील प्रमाणे 13 निकष ठरविलेले आहेत.

- 1) कसणाऱ्या जमिनीच्या गटाचा आकार, 2) घराचा प्रकार, 3) सरासरी कपडे परिधान उपलब्धता (प्रती व्यक्ती कपडे संख्या), 4) अन्न सुरक्षा, 5) स्वच्छता, 6) उपभोग्य टीकाऊ वस्तुंची मालकी 7) घरातील जास्तीत जास्त शिकलेल्या व्यक्तींचे साक्षरता प्रमाण. 8) कुटुंबाच्या मजुर शक्तीचा दर्जा. 9) उपजीविकेचे साधन. 10) 5 ते 14 वयोगटातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जा. 11) कर्जबाजारीपणाचा प्रकार. 12) घरातून स्थलांतराचे कारण 13) सहाय्याची पसंती/आवड

उपरोक्त निकषानुसार नियुक्त प्रगणकांकडून सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे.

(3) व (4) राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अद्याप चालू केलेली नाही. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संस्थेत प्रसूत झालेल्या सर्व थरातील मातांना व त्यांच्या बालकांना लाभ देण्यात येतो. त्यानुसार या योजने अंतर्गत 31 डिसेंबर, 2011 पर्यंत 1318 लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे.

ता.प.क्र.26641...

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांसाठी जीवनदायी योजना राबवली गेली. यासाठी अर्थसंकल्पात 250 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित होती. याचा उल्लेख सन 2011 च्या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. या योजने अंतर्गत कोणकोणत्या जिल्ह्यांना, किती कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा यात समावेश आहे पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश नाही. तेव्हा या योजनेचे निकष काय होते ? खरी गरज ही डोंगराळ, मागास भागातील जिल्ह्यांसाठी आहे. असे असताना त्या जिल्ह्यांना आपण यात समावेश करीत नाही. मात्र, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा यात समावेश आहे. दिनांक 29 मार्च रोजी आम्ही याच विषयावर तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी माननीय आरोग्य मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आले होते की, लाभार्थींना ओळखपत्राचे वाटप करण्यात येत आहे. अजूनही ते काम सुरू आहे. त्यामुळे आम्हाला स्पेसिफिक प्रश्न विचारावयाचा आहे की, सदर योजनेचा लाभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळणार आहे काय ? तसेच पहिल्या टप्प्यामध्ये जे जिल्हे घेतले होते त्याचे निकष काय होते, याचा खुलासा मंत्रिमहोदयांनी करावा.

श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, राजीव गांधी आरोग्य दायी योजनेचा संपूर्ण निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. याची चर्चा मंत्रिमंडळामध्ये झाली होती. त्यामुळे मी आपल्याला माहिती देऊ शकतो. गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, धुळे, रायगड, सोलापूर, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा असे जिल्हे आपण या योजनेसाठी घेतले आहेत. प्रत्येक विभागातील मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकी एक जिल्हा या योजनेसाठी घेण्यात आला आहे. जो जिल्हा थोडासा मागे राहिलेला आहे, जेथे आरोग्याची सुविधा उपलब्ध आहे असा दोन्हीचा बॅलेन्स करण्यात आला आहे. नंदूरबार जिल्हा घेणे अभिप्रेत असताना आपण धुळे जिल्हा घेतला आहे. आपण धुळे जिल्हा घेतला कारण तेथे थोडीसी मेडिकल फॅसिलिटी आहे. त्यामुळे असे मुद्दे करून हे जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्याची आपली कल्पना आहे. या योजनेतील सक्सेस बघून पुढच्या काळात ही योजना महाराष्ट्रात लागू होणार आहे. खरे तर हा प्रश्न माझ्याशी संबंधित नाही. या योजने संबंधातील इतर उप प्रश्नांसंबंधीचे उत्तर माननीय आरोग्य मंत्र्यांकडून येणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

**सभापती** : हा प्रश्न आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे हे माननीय मंत्री महोदयांचे म्हणणे खरे आहे. अनवधानाने तो आपल्या विभागाकडे आला आहे आणि त्यास आपण उत्तरही दिलेले आहे. प्रत्येक डिव्हिजन मधील 8 जिल्हे या योजनेमध्ये आपण घेतले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा हा प्रश्न आरोग्य विभागाकडे डायव्हर्ट करायचा काय ?

श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करतो. त्याने सभागृहाचे समाधान झाले तर माझी काही अडचण नाही. प्रश्न वर्ग करण्याची तरतूद असेल तर त्यास माझी हरकत नाही. कारण माझ्याकडे तपशीलवार उत्तर नाही. यावर किती खर्च झाला, किती लाभार्थी आहेत, याचा तपशील माझ्याकडे नाही. असे उप प्रश्न विचारण्यात आले तर मला उत्तर देता येणार नाही.

**सभापती** : माननीय मंत्रिमहोदयांनी योग्य उत्तर दिलेले आहे. हा प्रश्न आरोग्य विभागाशी संबंधित असल्यामुळे हा प्रश्न त्या विभागाकडे वर्ग करण्यास मला कोणतीही अडचण नाही. मी आपला प्रश्न राखून ठेवलेला नाही. तो आरोग्य विभागाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांच्याकडे वर्ग करतो. हा प्रश्न 2-3 दिवसांमध्ये चर्चेला कसा घेता येईल ते मी बघतो.

.....

यानंतर श्री.सरफरे....

**राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाला इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी १५ टक्के वाढीव रक्कम मिळण्याबाबत**

(७) \* २६७४६ श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी : सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाला इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी १५ टक्के वाढीव रक्कम मिळावी, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी दिनांक २९/७/२०११ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन दिले आहे, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, याबाबतची उपाययोजना करण्यात आली आहे काय,
- (३) असल्यास, कोणत्या प्रकारे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे,
- (४) अद्याप, उपाययोजना करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील सर्वसाधारण कारणे काय आहेत ?

**श्री.जयंत पाटील :** (१) होय.

(२), (३) व (४) इंदिरा आवास योजना ही केंद्रपुरस्कृत योजना असून केंद्र शासनाचे निकषानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी : सभापती महोदय, अल्पसंख्याक समाजाला इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मी हा प्रश्न विचारला आहे. नागपूर विभागाच्या आयुक्तांनी सन २००८-०९ मध्ये घरकुल योजना मंजूर केली. त्यामध्ये राहिलेल्या घरकुलांचा समावेश सन २००९-१० च्या योजनेमध्ये करण्यात आला. यामध्ये काही लोकांना घरकुल योजनेसाठी शासनाने ७० हजार रुपये मंजूर केले तर या योजनेतील अल्पसंख्याक समाजाच्या लाभार्थ्यांना फक्त ४३ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. या योजनेला केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो. ४३ हजार रुपयांमध्ये कोणतेही घर बांधून होत नाही या करिता मी वारंवार शासनाला विनंती केली. या करिता विशेष बाब म्हणून आपण या योजनेला मंजूरी देणार काय?

श्री. जयंत पाटील : सभापती महोदय, शासनाच्या धोरणानुसार १ एप्रिल २००९ पासून राज्य शासनाच्या हिश्यामध्ये वाढ करून ही रक्कम ७० हजार करण्यात आली. त्यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ३३ हजार ७५० रुपये आहे आणि राज्य शासनाचा २५ टक्के हिस्सा ११ हजार २५० रुपये इतका आहे. या दोन्हीची बेरीज केल्यानंतर प्राप्त झालेली रक्कम त्यांना मिळालेली दिसते. त्या नंतर राज्य शासनाचा मंजूर झालेला अतिरिक्त हिस्सा प्रति घरकुल २३ हजार ५०० रुपये इतका असून तो जर त्यांना प्राप्त झाला नसेल आणि १ एप्रिल २००९ नंतरची ती घरे असतील म्हणजेच

१७-०४-२०१२

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

FF २

DGS/ KTG/ D/

१२:५०

ता.प्र.क्र. २६७४६...

श्री. जयंत पाटील...

राज्य सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरची असतील तर त्यांना सवलत देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात येईल.

-----

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही



**मौजा नागापूर (जि.अमरावती) येथील देवगावातील ई क्लासमधील पारधी कुटुंबांना घरकुले बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत**

(८) \* २६८६५ श्रीमती अलका देसाई , श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप , श्रीमती दिप्ती चवधरी , श्री.राजन तेली , श्री.सुभाष चव्हाण , श्री.एम.एम.शेख : सन्माननीय महसूल मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा नागापूर (जि.अमरावती) येथील सर्व्हे नंबर १ मध्ये देवगावातील ई क्लासमधील ३७ पारधी कुटुंबातील १८ ते २० कुटुंबांना घरकुले बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे, अमरावती यांना दिनांक ३ जानेवारी, २०१२ रोजी वा त्यासुमारास लेखी निवेदन दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पारधी समाजातील कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने तसेच रेल्वे प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) अद्याप, कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

**श्री. प्रकाश सोळंके, श्री.बाळासाहेब थोरात यांच्याकरिता :** (१) होय.

(२) व (३) निवेदनाच्या अनुषंगाने तहसिलदार, धामणगाव रेल्वे यांच्या स्तरावर तपासणी करण्यात येत आहे.

श्रीमती अलका देसाई : सभापती महोदय, पहिल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना "होय" असे म्हटले आहे. मला शासनाला सांगायचे आहे की, ही मंडळी १९८०-८५ सालापासून त्या अतिक्रमित जागेमध्ये वास्तव्य करून रहात आहेत. हे फक्त ३७ फासेपारधी लोकांचे कुटुंब असून त्यांना आपण किती कालावधीमध्ये जागा देणार आहात?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, मागणी करण्यात आलेली जमीन गायरान संवर्गातील आहे. मध्यंतरीच्या काळात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जगपालसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य सरकार या प्रकरणामध्ये दि. २८.११.२०११ रोजी निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने दिनांक १२.७.२०११ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये प्रमुख बाब अशी आहे की, गायरान जमीन केवळ शासकीय कामासाठी किंवा गावातील ग्रामस्थांच्या उपयोगासाठी वापरण्यात येईल अशाप्रकारची तरतूद आहे. मागणी करण्यात आलेल्या १.८९ हेक्टर जमिनीव्यतिरिक्त गावामध्ये अन्य शासकीय जमीन उपलब्ध नाही. ही जमीन पारधी कुटुंबांना देऊ नये अशाप्रकारचे ११८ ग्रामस्थांचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. नवीन शासकीय धोरणानुसार ही जमीन

ता.प्र.क्र. २६८६५...

श्री. प्रकाश सोळंके....

देता येत नाही. तरीसुद्धा या गावापासून ३ कि.मी. अंतरावरील खानापूर या गावामध्ये जर त्यांच्याकडून मागणी आली तर त्या ठिकाणी शासनाच्या वतीने जमीन देण्यात येईल.

श्री. रमेश शेंडगे : सभापती महोदय, पारधी समाजाचे पुनर्वसन व्हावे, त्यांच्या आयुष्यामध्ये स्थैर्य यावे म्हणून राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये घरकुल योजनेसाठी २५ कोटींची तरतूद केली आहे. आपण या ठिकाणी पैशाचे नियोजन केले आहे, जागा देखील उपलब्ध आहे. परंतु कुणीतरी येऊन सांगते की, पारधी समाजाला ही जागा देऊ नका म्हणून राज्य शासन त्यांची मागणी तत्काळ मान्य करते, आणि दोन ते चार कि.मी. अंतरावरील उपलब्ध असलेली जागा देतो म्हणून सांगते ही अन्यायकारक बाब आहे. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की, उपलब्ध असलेल्या जागेच्या ठिकाणी त्यांना घरकुले बांधून देणार काय?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, मी सविस्तरपणे उत्तर दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर शासनाने आपल्या धोरणामध्ये काही बदल केले आहेत. गायरान जमिनी घरकुल योजनेसाठी देता येत नाहीत. त्यामुळे नजिकच्या गावामध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीची मागणी जर त्यांच्याकडून आली तर ती निश्चितपणे देण्यात येईल.

श्रीमती अलका देसाई : सभापती महोदय, हे फासेपारधी लोक वकील किंवा डॉक्टर नाहीत. शासनाने एक जागा नामंजूर केली म्हणून दुसरी जागा मागणारे ते लोक नाहीत. याबाबत माझी अशी मागणी आहे की, ते आपले मतदार असल्यामुळे शासनाने त्या लोकांना भेटून सांगावे.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

की, आम्ही तुम्हाला ही जागा देऊ शकत नाही, याबाबतीत कायदेशीर अडचण आहे.मात्र आम्ही तुम्हाला अमुक गावामध्ये जागा देतो. जर संबंधितांकडून मागणी आली तरच आम्ही याबाबतीत सांगू अशा प्रकारचे उत्तर बरोबर नाही.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी काही सूचना केलेली आहे ती अंमलात आणली जाईल.

श्री.हेमंत टकले : सभापती महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये असे सांगितले आहे की, ती गायरान जमीन असल्यामुळे कोर्टाच्या निर्देशानुसार ती इतर उपयोगासाठी देता येत नाही.परंतु ग्रामस्थांसाठी देता येते.येथे प्रश्न असा निर्माण झालेला दिसतो की, समाजातील बहुमताचा जो घटक आहे त्याचे असे म्हणणे आहे की, या पारधी लोकांना येथे राहू देऊ नका, परंतु ते त्याठिकाणी गेली कित्येक वर्षे रहात आहेत. त्यांचे असे विस्थापन करण्याऐवजी तेथील इतर ग्रामस्थांना समजावून सांगितले पाहिजे की, हे लोक देखील तुमच्यातीलच आहेत. त्यामुळे त्यांना येथे राहू द्यावे आणि आपल्या नियमाप्रमाणे जर त्यांना तेथे जागा देता येत असेल तर आपण त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे.कारण यातून सामाजिक एकतेचा महत्वाचा प्रश्न तडीला जाऊ शकतो.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, मी यासाठी म्हटले की, साधारणपणे गावाच्या ज्या सार्वजनिक गरजा असतात, त्यासाठी ही जमीन वापरता येते म्हणजे गुरे चरण्यासाठी किंवा खळ्याचा माल साठविण्यासाठी अशा कारणांसाठी गावकऱ्यांना ही जमीन वापरता येते.परंतु ही जमीन घरकुलासाठी देण्यामध्ये कायदेशीर अडचणी आहेत.म्हणून मघाशी सन्माननीय सदस्या श्रीमती अलका देसाई यांनी सूचना केल्याप्रमाणे तेथील ग्रामस्थांना भेटून इतर ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे हे सांगण्याचा शासनाच्या यंत्रणेमार्फत प्रयत्न केला जाईल.

----

. . . .2 जी-2

**राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून 25 रुपये भरून रजिस्ट्रीची प्रत मिळत असल्याबाबत**

(9) \*27003 श्री.सुभाष चव्हाण, श्री.चरणसिंग सप्रा, श्री.एम.एम.शेख, श्री.एस.क्यू.जमा :

सन्माननीय **महसूल मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून रजिस्ट्री कार्यालयातून केवळ 25 रुपये भरून रजिस्ट्रीची प्रत मिळत असल्याने यामध्ये पैशांचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून दुसऱ्याची मालमत्ता आपल्या नावावर करण्याचे प्रकार घडत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 2012 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
- (2) असल्यास, शासनाने जिल्हाधिकारी रजिस्ट्री कार्यालयातून होणारे गैरव्यवहार रोखण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
- (3) अद्याप, याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

**श्री.प्रकाश सोळंके, श्री.बाळासाहेब थोरात यांच्याकरिता :** (1) हे खरे नाही.

(2) प्रश्न उद्भवत नाही.

(3) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री.सुभाष चव्हाण : सभापती महोदय, रजिस्ट्रेशनसाठी जी फी घेतली जाते आणि त्यासाठी सह निबंधक आणि सह दुय्यम निबंधक यांची जी कार्यालये आहेत, त्याबाबतीत असंख्य तक्रारी आहेत. तसेच तेथे प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. या कार्यालयांच्या बाहेर एजन्ट फिरत असतात आणि ते आपण थांबविणार आहात काय ? त्यांना बंदी करणार आहात काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सन्माननीय सदस्यांनी येथे सांगितल्याप्रमाणे नोंदणी कार्यालयामध्ये शासनाच्याही हे निदर्शनास आले आहे की, त्याठिकाणी काही प्रमाणामध्ये दलालांच्या माध्यमातून काम करून घेतले जाते. त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी जी सूचना केलेली आहे, त्याप्रमाणे कशा पध्दतीने दलाल तेथून नाहीसे करता येतील याबद्दल शासनाच्या वतीने . . .

(अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.)

संबंधितांना शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत अधिकाधिक सवलती देऊन किंवा माहिती देऊन तेथील दलालांनाच काही काम उरणार नाही अशा पध्दतीने प्रयत्न केला जाईल.

श्री.विक्रम काळे : सभापती महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी हे मान्य केलेले आहे की, नोंदणी कार्यालयाच्या ठिकाणी दलाल आहेत. आता या नोंदणी कार्यालयामध्ये शासनाच्या वतीने चांगली सुधारणा करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार सगळीकडे संगणकीकरण देखील झालेले आहे. त्यामुळे दलालांना बराचसा आळा बसलेला आहे.परंतु वारंवार जेव्हा एकाच मालमत्तेची तीन-

ता.प्र.क्र.27003 . . . .

श्री.विक्रम काळे . . . .

तीन वेळा विक्री होते आणि लोकांना फसविले जाते. त्याबाबतीत सरकार काही ठोस उपाययोजना करणार आहे काय ? एकाच मालमत्तेची तीन-तीन वेळा विक्री होऊ नये. या दृष्टीकोनातून आपण कॉम्प्युटरमध्ये तशा प्रकारचा प्रोग्रॅम केला तर मला वाटते की, असे प्रकार होणार नाहीत. त्यामुळे त्यादृष्टीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेऊन तातडीने पावले उचलणार आहे काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, होय.

---

. . . .2 जी-4

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

GG-4

APR/KTG

12:55

काळबादेवी व आरे (जि.रत्नागिरी) या गावातील बेकायदेशीर रेंती

## उत्खननामुळे गावाला धोका असल्याबाबत

(10) \*27271 श्री.परशुराम उपरकर, श्री.रामदास कदम , डॉ.दीपक सावंत : सन्माननीय महसूल मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) रत्नागिरी शहरानजिक समुद्रकिनारी वसलेल्या काळबादेवी आणि आरे गावातील बेकायदेशीर वाढत्या रेती उत्खननामुळे गावांना धोका असल्याबाबतचे लेखी निवेदन तेथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे माहे जानेवारी, 2012 मध्ये वा त्यादरम्यान दिले, हे खरे आहे काय,
- (2) असल्यास, या लेखी निवेदनानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
- (3) अद्याप, कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.प्रकाश सोळंके, श्री.बाळासाहेब थोरात यांच्याकरिता : (1) होय, हे खरे आहे.

- (2) प्राप्त निवेदनानुसार नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे संयुक्त भरारी पथक स्थापन करण्यात आले असून, तद्नंतर मौजे काळबादेवी व आरे येथे वाळूचे अवैध उत्खनन होत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही.
- (3) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री.परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, याठिकाणी काळबादेवी व आरे (जि.रत्नागिरी) या गावातील ग्रामस्थांनी जानेवारी 2012 रोजी लेखी निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेले आहे. ते निवेदन दिल्यानंतर शासनाने भरारी पथक कधी स्थापन करण्यात आले याची माहिती देण्यात यावी. तसेच याठिकाणी शासनाने रेती उत्खनन करण्याचा परवाना दिलेला आहे काय आणि जर दिला असेल तर तो कधीपासून देण्यात आला आहे, जर शासनाने अशा प्रकारचा परवाना दिला असेल तर त्याठिकाणी अवैध प्रकारे उत्खनन झालेले आहे की नाही याचे मोजमाप करण्यासाठी तेथे यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.परशुराम उपरकर यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, त्यासंदर्भात सांगावयाचे तर याठिकाणी महसूल कर्मचाऱ्यांनीच दिनांक 3-1-2012 रोजी तीन टेम्पो पकडलेले आहेत

यानंतर श्री.बरवड . . . . .

ता. प्र. क्र. 27271....

श्री. प्रकाश सोळंके ....

आणि त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून ती वसुली करण्यात आलेली आहे. या निमित्ताने मला एकच सांगावयाचे आहे की, आपण अशी भरारी पथके संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व तालुका स्तरावर स्थापन केलेली आहेत आणि अवैध उत्खनन होऊ नये यासाठी या भरारी पथकांकडे जबाबदारी दिलेली आहे.

श्री. राजन तेली : सभापती महोदय, माझा व्यापक प्रश्न आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आपण टारगेट दिले आहे का ? आज ग्रामीण भागामध्ये सर्वसामान्य लोक हा व्यवसाय करतात, गावातील लोक एकत्र येऊन व्यवसाय करतात अशाच लोकांना पकडले जाते. जे मोठे वाळू तस्कर लोक आहेत, जे दलाली करतात त्यांना सोडले जाते. त्यामध्ये काय हितसंबंध आहेत हे मला माहित नाही. एवढे महसूल वाढले पाहिजे म्हणून दंड करा अशा प्रकारे आपण जिल्ह्याला, तालुक्याला तहसीलदारांना टारगेट दिले आहे का ? यामध्ये गोरगरिबांना अडकविले जाते. मी वेंगुर्ला तालुक्याचे उदाहरण देईन. वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये स्थानिक लोकांनी एकत्र येऊन एक टेंडर घेतले होते. त्यांना सातत्याने त्रास दिला जातो. हा त्रास वाचविण्याचा शासन प्रयत्न करणार का ?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, या ठिकाणी गौण खनिज उत्खननाच्या बाबतीत जी रॉयल्टी मिळावयास पाहिजे किंवा जे स्वामित्व धन मिळावयास पाहिजे त्या बाबतीत टारगेट दिलेले आहे. परंतु अवैध उत्खनन होऊ नये यासाठी भरारी पथके नेमून आपण दंडात्मक कारवाई करतो किंवा फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवितो. सन्माननीय सदस्यांनी वेंगुर्ला तालुक्याच्या बाबतीत जी अधिकची माहिती दिलेली आहे त्या बाबतीत चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. यामध्ये जसा गावाला धोका होतो तसाच पुलांना सुद्धा धोका होतो. त्यामुळे आपण सक्शन पंपावर बंदी घातली. तरी सुद्धा राज्यामध्ये सर्रास सक्शन पंप चालू आहेत. गेल्या वर्षभरात किती सक्शन पंपाच्या बाबतीत कारवाई केली याची माहिती माननीय मंत्री महोदय देऊ शकतील का ? जर माहिती नसेल तर ती पटलावर ठेवणार का ?

...2...

RDB/ D/ KTG/

ता. प्र. क्र. 27271....

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, ही माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल.

श्रीमती विद्या चव्हाण : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या निमित्ताने मला सभागृहाचे लक्ष वेधावयाचे आहे. त्या ठिकाणी समुद्र किनारे अतिशय स्वच्छ आहेत. कॅलिफोर्निया वगैरे ठिकाणी असतो तसा सुंदर समुद्र किनारा त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी अशी अवैध मार्गाने रेती उपसा होत असेल तर कोठे तरी कडक कारवाई करून त्या समुद्र किनाऱ्याजवळ असे लोक फिरकू नये म्हणून या समुद्र किनाऱ्यावर संपूर्ण प्रोहिबिशन केले पाहिजे. समुद्र किनारा सिल केला पाहिजे जेणेकरून त्या ठिकाणी कायद्याप्रमाणे असे उत्खनन करताच येणार नाही. कारण इतका सुंदर समुद्र किनारा आता राहिलेला नाही. मुंबईमध्ये सुध्दा नाही. मला इतके दिवस असे वाटत होते की, लोक नदीची वाळू उपसून वापरतात पण अशा प्रकारे समुद्र किनाऱ्यावरची वाळू उपसत असतील तर या समुद्र किनारपट्टीला फार धोका आहे. पर्यटनासाठी चांगले क्षेत्र उपलब्ध राहण्यासाठी शासन काही प्रयत्न करणार आहे का ?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, हा प्रश्न जरी व्यापक असला तरी निश्चितपणे समुद्र किनाऱ्याचे महत्व आणि पर्यटन उद्योगाशी निगडित बाब असल्यामुळे या समुद्र किनाऱ्यावर अवैध वाळू तस्करी होणार नाही किंवा उत्खनन होणार नाही या बाबतीत निश्चितपणे खात्यामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.

**सभापती :** प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे.

---

...3...



पृ.शी./मु.शी.: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठेवणे

श्री. अजित पवार (उप मुख्यमंत्री ) सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाने विषय क्रमांक 1 व विषय क्रमांक 2 बाबत शासनास सादर केलेला अहवाल त्यावरील कारवाईच्या अहवालसह (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे.

श्री. अजित पवार : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सन 2010-2011 या वर्षाचे (1) वित्तीय लेख अहवाल खंड-1 व खंड -2, (2) विनियोजन लेखे, (3) राज्य वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल क्र.1, (4) नागरी अहवाल क्र. 2 व (5) महसुली जमा अहवाल क्र. 3 सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले आहेत.

यानंतर श्री. खंदारे ....

श्री.अजित पवार : सभापती महोदय, मी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा दिनांक 31 मार्च, 2011 रोजी संपलेल्या वर्षाचा (वाणिज्यिक) अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो.

सभापती महोदय, हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवत असताना मला एक गोष्ट आपल्यामार्फत सभागृहाच्या निदर्शनास आणून द्यावयाची आहे की, सन 2010-11 या वर्षाच्या महसुली जमा अहवालाच्या मराठी व इंग्रजी प्रतींची तुलना केली असता काही परिच्छेदांमध्ये विसंगती आढळून आलेली आहे. उदा.परिच्छेद क्र.4 (2) (9) "Irregularity in allotment of land for housing purpose" संदर्भात इंग्रजी अहवालातील पृष्ठ क्र.66 मधील पहिल्या ओळीत नियम 27 असे नमूद केलेले आहे. तथापि, मराठी अहवालात याच परिच्छेदांमध्ये वास्तव्यासाठीच्या जमिनीच्या वाटपातील अनियमितता पृष्ठ क्र.69, नियम 27 असे नमूद करण्यात आले नाही. अहवालाच्या अन्य परिच्छेदांमध्ये अशा प्रकारची विसंगती आहे किंवा कसे याबाबत मराठी व इंग्रजी अहवालाच्या प्रतींची फेर छाननी करून आढळून आलेल्या विसंगतीबाबत शुध्दीपत्रक शासनास सादर करण्याबाबत क्र.भानिम/2012/प्र.क्र.50/लोलेस, दि.16.4.2012 च्या पत्रान्वये महालेखाकार कार्यालयास कळविण्यात आले आहे. महालेखाकार कार्यालयाकडून शुध्दीपत्रक प्राप्त झाल्यावर ते वितरित केले जाईल.

**सभापती :** अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा लेखा अहवाल सभागृहासमोर सादर केला जातो. त्यानंतर तो अहवाल लोकलेखा समितीकडे गेल्यावर लोकलेखा समिती आपला अहवाल सभागृहासमोर मांडते. ही प्रक्रिया आहे त्याची सर्वांना माहिती आहे. या वेळी कॅगच्या अहवालाबाबत चर्चा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कॅगचा अहवाल पाहिल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आहे असे वाटले आहे. अहवालात नमूद केलेले खोटे निघाले तर सरकारची इभ्रत तरी वाचेल असे मला वाटत होते. पण अहवाल वाचल्यानंतर त्यामध्ये वस्तुस्थिती मला दिसून आली आहे. माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल सभागृहासमोर मांडलेला आहे तो आम्ही कधी तरी वाचू. परंतु या अहवालावर आम्हाला चर्चा करण्याची संधी

2...

श्री.विनोद तावडे....

मिळाली पाहिजे. लोकलेखा समितीचे अहवाल नेहमी सभागृहासमोर सादर केले जातात त्याप्रमाणे या अहवालाबाबत कार्यवाही केली जाईल. तशा प्रकारची प्रक्रिया मान्यही केली असती. पण कॅगच्या अहवालात राज्यातील काही मंत्र्यांच्या प्रकरणांचा उल्लेख केलेला आहे. जर या अहवालावर चर्चा केली तर संबंधित मंत्र्यांनाही वैयक्तिक स्पष्टीकरण करण्याची संधी मिळू शकते. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीनेच विरोधी पक्ष नेता बोलत आहे अशी याबाबत स्थिती निर्माण झाली आहे. या अहवालात जर काही चुकीचे आले असेल तर त्याबाबत सत्ताधारी पक्षातील लोकांना स्पष्टीकरणाची संधी मिळावी असाही आमचा उद्देश आहे. प्रथा व परंपरेनुसार लोकलेखा समितीचा अहवाल सभागृहासमोर आला पाहिजे असे म्हटले जाते. लोकलेखा समिती या सभागृहाने निर्माण केलेली आहे. आपल्या सोयीसाठी त्या समितीची निर्मिती केलेली आहे. ती समिती घटनेनुसार निर्माण झालेली नाही. हे सभागृह घटनेनुसार निर्माण झालेले आहे. सन्माननीय राज्यमंत्री श्री.भास्कर जाधव यांनी बसल्या बसल्या म्हटल्याप्रमाणे ही बाब गंभीरपणे घ्यावयाची झाली तर लोकलेखा समितीमध्ये महालेखाकार यांच्याकडून आलेल्या अहवालाच्या छाननीचे काम केले जाते.

विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सभागृहाची रचना ही भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 168 अनुसार झालेली आहे. अनुच्छेद 171 अनुसार विधानपरिषद विवक्षित अशी तरतूद आहे. तसेच 170 मध्ये या तरतुदीनुसार नियम करून लोकलेखा समिती निर्माण करता येते. सभागृहाने नियम तयार करून लोकलेखा समिती निर्माण केलेली आहे. हे सभागृह घटनेतील तरतुदीनुसार निर्माण झालेले आहे. घटनेनुसार निर्माण झालेली जी बॉडी असते ती नेहमीच सर्वोच्च मानली जाते. The Judiciary have to act as per the mandate of the Constitution and they cannot override the provisions of the Constitution. यातील फरक माननीय विधी व न्याय राज्यमंत्री श्री.भास्कर जाधव यांना माहित असावा. सर्वोच्च न्यायालयात केशवानंद भारती यांच्या प्रकरणाच्या वेळी याबाबत निर्णय झालेला आहे. त्याचा रेफरन्स सुध्दा मी मंत्री महोदयांच्या माहितीसाठी पाठवून देतो. कारण मंत्री महोदय सकाळी लवकर उठून कामकाजाचा अभ्यास करतात असे त्यांनीच एकदा सांगितले होते.

यानंतर श्री.शिगम....

श्री. विनोद तावडे...

हा अभ्यास त्यांना पुढे कामाचा ठरेल. सभापती महोदय, माझी एवढीच विनंती आहे की, या सदनमध्ये हा जो अहवाल मांडलेला आहे या अहवालावर चर्चा केली तर जे काही भ्रष्टाचाराचे मळभ राज्यामध्ये जमलेले आहे ते दूर होण्यासाठी, वास्तव समोर येण्यासाठी मदत होईल म्हणून सन्माननीय सदस्यांना या अहवालावर चर्चा करण्याची संधी द्यावी अशी माझी आपणास विनंती आहे.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सभागृहाच्या प्रथा आणि परंपरा आम्हाला आणि आपणाला देखील माहित आहेत. घटनात्मक परिस्थिती काय आहे, सदनच्या भावना काय आहेत हे माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी आता नमूद केलेले आहे. हा अहवाल या विधिमंडळामध्ये येण्यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये असे काही वातावरण निर्माण झालेले आहे की त्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा अहवाल विधिमंडळापुढे येण्यापूर्वी त्यावर बाहेर चर्चा झाली. ती चर्चा योग्य की अयोग्य, बरोबर की चूक या खोलात मी जात नाही. चर्चेमधून असे बाहेर येत आहे की, महाराष्ट्र सरकारमधील अनेक मंत्री दोषी आहेत. या संदर्भात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी हिंमत करून सांगितले की हा अहवाल 16 एप्रिलला सभागृहामध्ये मांडला जाईल. एक दिवस तो उशिरा मांडला ही बाब वेगळी. हा अहवाल आम्हाला दिल्यानंतर तो आम्ही वाचू. कदाचित ज्यावर बाहेर चर्चा होत आहे तेवढीच पाने आम्ही वाचू. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल पूर्णपणे वाचलेला असल्यामुळे त्यामध्ये नक्की काय आहे हे त्यांनाच माहित आहे. मंत्रिमंडळामध्ये काय घडले हे वर्तमानपत्रातून छापून आलेले आहे. मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा होत असताना एकमेकाला कसे दोष देण्यात येतात, मंत्रिमंडळातील मंत्री कसे एकमेकांच्या विरोधात आहेत यासंबंधीची चर्चा बाहेर होत असते आणि ती तुमच्या आमच्या कानावर येते. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. असे वातावरण बाहेर असल्यामुळे लोक आम्हाला सारखे विचारतात की तुम्ही काय करता ?

या अहवालाच्या संदर्भात सभागृहाची नैतिक जबाबदारी निर्माण झालेली आहे. या अहवालाबाबत लोकलेखा समितीमध्ये चर्चा होईल. सरकारची तशी इच्छा असेल तर ते सरकारने सांगावे. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितल्या प्रमाणे हा चर्चेचा उपाय सत्ताधारी पक्षाकरिता आहे, विरोधी पक्षाकरिता नाही. जे कोणी दोषी आहेत ते कसे दोषी नाहीत हे सांगण्याची संधी त्यांना या चर्चेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. म्हणून या अहवालावर जुजबी का होईना पण चर्चा

..2..

श्री. दिवाकर रावते...

करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील 10 कोटी जनता याचे काय झाले, त्याचे काय झाले अशी सारखी विचारणा करित असते. हे महाराष्ट्राचे प्रतिष्ठीत सरकार तीनदा निवडून आले असे वारंवार सांगितले जाते. तेव्हा या तिनदा निवडून आलेल्या सरकारने अभिमानाने सांगितले पाहिजे की आम्ही दोषी नाही, आम्ही स्वच्छ चारित्र्याचे आहोत आणि ते सांगण्यासाठी ही जुजबी चर्चा करण्याची संधी तासाभराने द्यावी अशी माझी आपणास विनंती आहे.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जी मागणी केली तिला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. या राज्यामध्ये पहिल्यांदाच असे झालेले आहे की, महालेखापालांचा अहवाल आल्यानंतर अॅडव्होकेट जनरल यांना कॅबिनेटपुढे बोलावण्यात आले. या राज्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच असे घडले की, महालेखापालांचा अहवाल या सभागृहामध्ये मांडण्यापूर्वी तो फुटला आणि त्यावर झालेली चर्चा वर्तमानपत्रातूनही प्रसिध्द झाली. या अहवालामुळे अडचणी निर्माण होतील अशा प्रकारचे वातावरण राज्यामध्ये निर्माण झाले. हा अहवाल स्वीकारता येऊ नये यासाठी कॅबिनेटपुढे अॅडव्होकेट जनरल यांना बोलावण्यात आले होते ही गोष्ट खरी आहे काय ? आम्ही वृत्तपत्रातून जे वाचले ते खरे आहे काय, हे या सभागृहाला समजले पाहिजे. महालेखापालांचा अहवाल कॅबिनेटपुढे आल्यानंतर त्या बाबतीत अॅडव्होकेट जनरल यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवायलाच पाहिजे असे सांगितले. नियमाप्रमाणे हा अहवाल सभागृहापुढे ठेवल्यानंतर तो लोकलेखा समितीकडे जातो. त्यामुळे त्या अहवालावर चर्चा करण्याचा या सभागृहाचा अधिकार आहे, कारण सभागृहाच्या संमतीने तो अहवाल लोकलेखा समितीकडे जातो. म्हणून या अहवालावर चर्चा झाली पाहिजे. यासंदर्भात सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जी मागणी केली तिला पाठिंबा देतो आणि अहवालावर चर्चा करण्याची आम्हाला संधी द्यावी अशी विनंती करतो.

...नंतर श्री. गिते...

श्री एस. क्यू. ज़मा : सभापति महोदय, सीएजी की रिपोर्ट अभी ऑफिसिअली सदन के पटल पर रखी गयी है. लेकिन इसके बारे में वर्तमान पत्रों में तथा और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उनके पास सीएजी की रिपोर्ट है.

सरकार की ओर से माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि वे इस बात की जांच करेंगे कि यह रिपोर्ट पत्रकारों को तथा दूसरे लोगों को लीक कैसे हुई ? इस बारे में सीडी भी दिखाई गई. इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बात की जांच आपने की या नहीं की, तथा उस जांच में क्या पाया गया ?

सभापति जी, मुझे यही पूछना है कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम पड़ने से पहले पत्रकारों को तथा बाहर के लोगों को इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिल गयी, इसकी जांच सरकार ने की है या नहीं और यदि जांच की है तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है ?

श्री. अजित पवार : सभापती महोदय, मी आपल्या परवानगीने कॅगचा जो काही रिपोर्ट आला तो सभागृहासमोर सादर केल्यानंतर सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री.विनोदजी तावडे, सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते व सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र.पाटील यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले. सभापती महोदय, आपण विधिमंडळामध्ये अतिशय सिनिअर आहात. कॅगचा अहवाल विधानमंडळास सादर होतो. त्यानंतर मंत्रालयातील संबंधित विभागांना त्यातील परिच्छेद अभिप्रायासाठी पाठविले जातात. संबंधित विभागाकडून परिच्छेदांच्या संदर्भात स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने तयार करून ती विभागीय सचिवांच्या मान्यतेने महालेखाकारांकडे अभिप्रायासाठी पाठविली जातात. सभापती महोदय, महालेखाकारांकडून स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने प्राप्त झाल्यावर सादर स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने पुढील कार्यवाहीसाठी लोकलेखा समिती कक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे पाठविली जातात. या गोष्टीचा उल्लेख सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी देखील केला. सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना ही पध्दत माहिती आहे.

महोदय, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनाच्या अनुषंगाने लोकलेखा समिती मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांच्या साक्षीसाठी बैठका आयोजित करते. लोकलेखा समितीच्या साक्षीच्या बैठकीस प्रधान महालेखाकार उपस्थित असतात. लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षाना मदत करण्यासाठी आमच्या वित्त

श्री. अजित पवार.....

विभागाचे सचिव, लेखा व कोषागारे हे देखील बैठकीसाठी उपस्थित असतात. या साक्षीच्या बैठकीमध्ये प्रत्येक परिच्छेदावर सांगोपांग चर्चा होत असते. लोकलेखा समितीचे सदस्य व अध्यक्ष हे मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांना साक्षीच्या बैठकीत प्रश्न विचारतात आणि अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर समिती शिफारशीसह आपला अहवाल विधिमंडळास सादर करते. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासन पुढील कार्यवाही करित असते. या अहवालावर चर्चा केली गेली पाहिजे अशी मागणी माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी केली आहे. लोकलेखा समितीचे जे अधिकार आहेत, त्यानुसार या समितीच्या बैठकीमध्ये दोन्ही सभागृहातील दोन्ही बाजूचे सदस्य उपस्थित असतात. या अहवालावर या सभागृहात चर्चा केली तर त्यांच्या कामामध्ये आपण कोठे तरी अतिक्रमण केल्यासारखे होईल. जी परंपरा चालत आलेली आहे. नियमाने ज्याला आपण बिझिनेस अॅप्रूव्हल म्हणतो, त्या पध्दतीने गोष्टी चालत आलेल्या आहेत. त्यामध्ये वेगळे फाटे फुटू नयेत अशी माझी या चर्चेच्या निमित्ताने विनंती आहे.

सभापती महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी विचारणा केली की, अॅडव्होकेट जनरल यांना कॅबिनेटसमोर बोलाविण्यात आले होते काय ? सभापती महोदय, अॅडव्होकेट जनरल यांना अजिबात कॅबिनेटसमोर बोलाविण्यात आलेले नाही. अलीकडच्या काळामध्ये वृत्तपत्रात कोठल्या तरी बातम्या छापून येतात. त्या बातम्या छापून वातावरण खराब केले जाते, लोकांच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण केली जाते. एका गोष्टीचे समाधान मानले पाहिजे की, आपल्याकडे लोकशाही जीवंत राहण्याकरिता जनता अतिशय साधक-बाधक विचार करून कौल देत असते. कालच पाच महानगरपालिकांचा कौल काय लागला हे सर्वांनी बघितले. राज्यातील लोकांना कळते की, वस्तुस्थिती काय आहे. काही ठिकाणचे कौल दिले होते, परंतु त्या कौलानुसार आकडे पार पाडता आले नाहीत. या महानगरपालिकांमध्ये आघाडी सरकारला निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. हा काही आज सांगण्यासारखा विषय नाही. परंतु नेहमी असे झाले, तसे झाले अशा पध्दतीने आरोप केले जातात.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा यांनी कॅगच्या अहवाल सिडीच्या माध्यमातून लिंक करण्यात आला याबाबतचा उल्लेख केला आहे.

यानंतर श्री. भोगले...

श्री.अजित पवार.....

त्याची चौकशी झाली पाहिजे. राज्य सरकारच्या वतीने निश्चितपणे याची चौकशी केली जाईल आणि नक्की कोणी अहवाल फोडला, कशा पध्दतीने सी.डी.मिळविली हे पाहिले जाईल. ती सी.डी.वित्त विभागाकडे आलेली नव्हती. आम्हाला त्यांनी मराठी व इंग्रजी भाषेतील जो काही अहवाल दिला तो मी आताच सभागृहाच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यामध्ये थोडीशी चूक झाली होती. त्याबद्दल देखील मी आपल्या संमतीने स्पष्टीकरण केलेले आहे.

सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.ज़मा यांना मी सांगू इच्छितो की, या प्रकरणाची निश्चितपणे चांगल्या पध्दतीने पोलीस विभागामार्फत चौकशी होईल. कोण नक्की याच्या पाठीशी आहे, कोणी अहवाल फोडला, कोण चुकीच्या पध्दतीने व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करित आहे हे शोधण्यात येईल. हे सगळे होत असताना दूरदर्शनवर वेगवेगळ्या चॅनेल्सवर मंत्र्यांची नावे दाखविली जातात. आता सभागृहात माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी स्वच्छ चारित्र्याचे सरकार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वच्छ चारित्र्याचे सरकार आहे म्हणूनच तीन वेळा सत्तारूढ झालेले आहे. कालच्या निवडणुकीमध्ये पाचही महानगरपालिकांमध्ये सत्ता काबीज केली आहे.

सभापती महोदय, आदर्श प्रकरणामध्ये सगळेच चुकीचे आहे. आदर्श गृहनिर्माण संस्थेची इमारत उभी राहिल्याबद्दल माननीय विरोधी पक्षाला वाटले असेल की तो मुद्दा उपस्थित करावा म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यातून काहीतरी कळेल. संरक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या वतीने आयोगासमोर मांडलेला मुद्दा विचारात घेऊन संरक्षण मंत्रालय त्या भूखंडावर त्यांची मालकी सिध्द करण्यास यशस्वी ठरले नाही. या उलट महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 294 मधील तरतुदीनुसार जमिनीची मालकी ही राज्य शासनाची असल्याचे सिध्द करण्यास महाराष्ट्र शासन मात्र यशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन राज्य शासनाच्या मालकीची असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.

सभापती महोदय, त्यामध्ये संरक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन तसेच आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या वतीने वादग्रस्त जमीन किंवा संस्थेचे सदस्यत्व हे संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा कारगील युद्धातील शहिदांच्या गृहनिर्माणाकरिता राखीव नसल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. त्यामुळे वादग्रस्त जमीन किंवा संस्थेचे सदस्यत्व संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी

..2..



श्री.अजित पवार.....

किंवा कारगील युद्धातील शहिदांच्या गृहनिर्माणाकरिता राखीव नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. सभापती महोदय, या संदर्भात एवढे गंभीर वातावरण देशात निर्माण केले गेले की, संरक्षण विभागाची जमीन कोणाला तरी दिली गेली. त्यातून आतापर्यंत जी काही त्याची किंमत मोजावी लागली ती कोण भरून देणार?

सभापती महोदय, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष हे विरोधी पक्षाचे असतात. त्यामुळे त्या अहवालाची चर्चा त्या समितीमध्ये होण्यास काही हरकत नाही. त्या अहवालावर या ठिकाणी वेगळी चर्चा करण्याचे काही कारण नाही असे माझे मत आहे.

(विरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्यासाठी उभे असतात)

श्री.दिवाकर रावते : अहवालावर चर्चा झालीच पाहिजे.

**सभापती** : या ठिकाणी माननीय विरोधी पक्षनेते श्री.विनोद तावडे, माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी यापूर्वी काही मुद्दे मांडले आहेत.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, आपल्या निर्णयाबद्दल बोलणे उचित होणार नाही, त्यामुळे आपल्या निर्णयापूर्वी मी माझे म्हणणे मांडू इच्छितो.

**सभापती** : सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला व त्या दृष्टीकोनातून विरोधी पक्षाकडून काही वक्तव्य केले गेले. त्या संदर्भात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी देखील काही भाष्य केले आहे. आपली मागणी अशी होती की, कॅगच्या अहवालावर सदनामध्ये कधीतरी चर्चा होणे आवश्यक आहे.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, आपल्या निर्णयापूर्वी मला विनंती करावयाची आहे.

**सभापती** : हे दोन वेगवेगळे भाग आहेत.

नंतर श्री.खर्चे...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

MM-1

PFK/ D/ ST/

पूर्वी श्री. भोगले.....

13:25

**सभापती** .....

आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा जो अहवाल आहे त्या अनुषंगाने माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी दुसरा मुद्दा मांडला. पण त्यापूर्वी कॅगच्या अहवालाबाबत सभागृहात दोन तीन सन्माननीय सदस्यांना मी विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली. सन्माननीय सदस्यांनी या विषयावर कधी तरी चर्चा करावयाची आहे असाही मुद्दा उपस्थित केला. तसेच शासनाच्या वतीने माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी बाजू मांडली, त्यासंबंधीचा निर्णय मला देणे आवश्यक आहे. तेव्हा सन्माननीय सदस्यांनी सभागृहात शांतता ठेवावी, अशी माझी विनंती आहे.

श्री. विनोद तावडे : महोदय, आपण जरूर आपला निर्णय द्यावा पण तत्पूर्वी माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी आदर्श सहकारी गृह निर्माण संस्थेबाबत स्पष्टीकरण देत असताना आमचा उल्लेख केला त्यासंदर्भात आमची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.

( सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य उभे राहून हरकत घेतात )

**सभापती** : माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना मी सांगू इच्छितो की, शासनाच्या वतीने कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला असून त्या विषयाच्या संदर्भात आपण स्वतः, माननीय श्री. दिवाकर रावते, माननीय सदस्य श्री. जयंत पाटील यांनीही आपले म्हणणे थोडक्यात मांडले व या अहवालावर चर्चा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्याच संदर्भात मला माझा निर्णय द्यावयाचा आहे.

श्री. विनोद तावडे : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी आमचा उल्लेख केला म्हणून आमची बाजू मांडण्याची संधी आम्हाला द्यावी.....

**सभापती** : कॅगचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्यानंतर त्यासंदर्भात लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समितीकडे या अहवालाची छाननी करणे व अभिप्राय देण्यासाठी सोपविण्यात येतो. या अहवालाची छाननी केल्यानंतर समिती आपल्या शिफारशी सभागृहासमोर ठेवते. यापूर्वी अशा अहवालावर सभागृहात कधी चर्चा झाली असे पूर्वोदाहरण नाही, त्यामुळे कॅगच्या अहवालावर चर्चा करण्याची परवानगी देता येणार नाही.

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, आमचा विषय आदर्श सोसायटीचा आहे.....

**सभापती** : सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी कृपया खाली बसावे. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री. उल्हास पवार यांना काही तरी सांगायचे आहे.

.....2

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

MM-2

PFK/ D/ ST/

पूर्वी श्री. भोगले.....

13:25

( सन्माननीय सदस्य श्री. उल्हास पवार, बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.)

श्री. विनोद तावडे : महोदय, आपण मला बोलण्याची परवानगी दिली आहे.....

( दोन्ही बाजूचे काही सन्माननीय सदस्य आपापल्या जागेवरून बोलत असतात )

श्री. विनोद तावडे : महोदय, कॅगच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मी, सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते आणि श्री. जयंत पाटील तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. एस.क्यू.जमा यांनी सुध्दा थोडक्यात आपले विचार मांडले, त्यानंतर माननीय उप मुख्यमंत्री त्यासंदर्भात बोलले. पण कॅगसंबंधी स्पष्टीकरण देत असताना नंतर त्यांनी पुन्हा आदर्श सहकारी गृह निर्माण संस्थेबाबतचे मत व्यक्त केले. मंत्री महोदयांनी कॅगच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देत असताना लगेच आदर्शसंबंधी बोलले, त्यानंतर आपण सुध्दा बोललात. पण माननीय उप मुख्यमंत्री बोलत असताना किंवा त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर आदर्श सोसायटीच्या बाबतीत जे काही झाले ते सर्व साफ झाले, अगदीच स्वच्छ आहे, असा जो मुद्दा समोर आणला त्याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने मला बोलावयाचे आहे. कारण आदर्श सोसायटीच्या संदर्भात ज्या 13 टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस आहेत त्यापैकी फक्त 2 चीच माहिती समोर आली, बाकी 11 च्या बाबतीत काय, आम्हाला अपेक्षा होती की.....

( दोन्ही बाजूचे काही सन्माननीय सदस्य आपापल्या जागेवरून बोलत असतात )

**सभापती** : दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी कृपया सभागृहात शांतता राखावी.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

( सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते वेलमध्ये येतात.)

श्री. विनायक मेटे : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे.

**सभापती** : सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते बोलत आहेत. सन्माननीय सदस्य श्री. विनायक मेटे यांना त्यांचा हरकतीचा मुद्दा मांडण्यासाठी नंतर संधी दिली जाईल.

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, माझा मुद्दा असा आहे की, आदर्श प्रकरणाच्या संदर्भात दोन अहवाल आलेले आहेत. त्यामध्ये भूखंड यांचा होता की, त्यांचा होता, त्यासंदर्भात लष्कर प्रमुखांचे पत्र होते त्यामध्ये आम्हाला कारगीलच्या शहीद जवानांना घर द्यावयाचे होते वगैरे वगैरे...आरक्षण नव्हते परंतु पत्र होते. या प्रकरणाच्या संदर्भात हाय कोर्ट स्वतः देखरेख करित आहे त्यामुळे त्यातून सर्व काही बाहेर येईल याबाबत आमच्या मनात काहीही शंका नाही. या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असे भासविले की, "आम्ही सर्व निर्दोष तसेच स्वच्छ चारित्र्याचे असतांना विरोधकांनी आम्हाला दोषी दाखविले"यालाच आमचा आक्षेप आहे. आदर्श सोसायटी पहिल्यांदा 8 मजल्याची असतांना तिचे 32 मजले कसे काय झाले अशी लोकांच्या मनात शंका आहे. आदर्श सोसायटीत मेहुणीला फ्लॅट कसे मिळाले,पर्यावरणाचे खोटे सर्टिफिकेट कसे आले याबाबत आमचा आक्षेप आहे. या आक्षेपावर चर्चा झाली आहे काय ? या अहवालातील पर्यावरणाचे सर्टिफिकेट खरे होते, बीईएसटीचा एफएसआय आदर्शला दिला तो बरोबर होता, श्री. जयराज फाटक निर्दोष आहेत असा काही उल्लेख अहवालात आला आहे काय ? याबाबत काहीही माहिती अहवालात आलेली नाही. विधान परिषदेचे सभागृह हे वरिष्ठ सभागृह आहे. बघू...सगळा रिपोर्ट आल्यानंतर चर्चा करू. आम्ही यासंदर्भात काहीही चर्चा मागत नाही. याविषयाच्या संदर्भात या सभागृहात चर्चा झाली तर लोकलेखा समितीला मदतच होईल. या चर्चेवर सदस्यांनी साधकबाधक विचार व्यक्त केले, त्यावर मंत्री महोदयांनी आपले म्हणणे मांडले व या ठिकाणची चर्चा लोकलेखा समितीमध्ये गेली तर समितीला याचा फायदाच होईल.

( दोन्ही पक्षाचे सन्माननीय सदस्य जागेवर उभे राहून बोलण्याचा प्रयत्न करित असतात.)

श्री. दिवाकर रावते : हा काय प्रकार चालला आहे.

**सभापती** : कॅगच्या रिपोर्टच्या अनुषंगाने सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते, सन्माननीय उप मुख्यमंत्री यांनी जे विचार मांडलेले आहेत त्यासंदर्भात मी

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

NN-2

SGJ/ ST/ D/

प्रथम श्री. खर्चे.....

13:30

**सभापती .....**

माझा निर्णय दिलेला आहे. कॅगच्या रिपोर्टसंदर्भात लोकलेखा समिती तसेच सार्वजनिक उपक्रम समिती चर्चा करित असते. या समितीमध्ये होणारी चर्चा ही खऱ्या अर्थाने प्रथा परंपरे नुसार होत असते. त्यामुळे कॅगचा अहवाल मी लोकलेखा समितीकडे तसेच सार्वजनिक उपक्रम समितीकडे पाठविणार असून सदर समिती कडून हा अहवाल पूर्णतः तपासला जाईल. या समितीमध्ये सर्व पक्षाचे सदस्य असतात. या विषयाच्या संदर्भात मी निर्णय दिलेला आहे.

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, मी माझे बोलणे पूर्ण करतो. आदर्श प्रकरणाच्या संदर्भातील सर्व वस्तुस्थिती बाहेर येईलच. कॅगच्या रिपोर्टच्या बाबतीत माननीय भुजबळ साहेबांनी खालच्या सभागृहात उल्लेख केला आहे की, "बाकीच्यांना ज्या भूखंडाचे वाटप केले त्यावर त्यांचे नाव नाही. केवळ समीर भुजबळांचे नाव आले. ए.जी.च्या अहवालात केवळ समीर भुजबळ यांचे नाव कसे काय आले" ? तसेच त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, "हा माझ्या बदनामीचा कट आहे." तीन महिने माननीय भुजबळ साहेब बदनामी मध्ये फिरत आहेत हे कसे चालेल. माननीय भुजबळ साहेबांना बदनाम करण्याचा कट रचला आहे त्यावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. माननीय जयंत जाधव साहेब माननीय भुजबळ साहेबांना येथे दोषी ठरविले जात आहे हे बरोबर आहे काय ?

यानंतर श्री. भारवि...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

001

BGO/ D/ ST/

जुन्नरे..

13:35

(दोन्ही बाजूकडील सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.)

**सभापती** : अशा परिस्थितीत सभागृहाचे कामकाज करणे शक्य नसल्यामुळे मी सभागृहाची बैठक 15 मिनिटांकरिता स्थगित करित आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 1.35 ते 1.50 वाजेपर्यंत स्थगित झाली.)

.....

यानंतर श्री.सरफरे....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

PP 1

DGS/ D/ ST/

13:50

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. मोहन जोशी)

तालिका सभापती : सभागृहाची बैठक 15 मिनिटांकरिता स्थगित करण्यात येत आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 1.50 ते 2.05 वाजेपर्यंत स्थगित झाली)

---

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

QQ-1

APR/KTG/

पूर्वी श्री.सरफरे . . . .

14:05

(स्थगितीनंतर)

**सभापतीस्थानी - माननीय सभापती**

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, . . . .

**सभापती** : मी सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांना बोलण्यासाठी परवानगी देतो.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मला एकच खुलासा पाहिजे.आपला निर्णय अंतिम आहे आणि तो आम्ही नेहमीच मानतो. मी त्याबद्दल पुढे काही बोलत नाही. परंतु माननीय सभापती महोदय, फक्त एकच सांगावयाचे आहे की, सभागृहामध्ये जे अहवाल ठेवले जातात त्यावर आपण प्रथा आणि परंपरेनुसार चर्चा करीत नाही. पण याबाबतीत नियमामध्ये काय तरतूद आहे हे रेकॉर्डवर आले पाहिजे. या सदन्याचे काम नियमाने चालते असे मला वाटते. त्यामुळे याबाबतीत नियमामध्ये काय तरतूद आहे हे रेकॉर्डवर आले पाहिजे. जेणेकरून पुढच्या वेळेस अशा विषयांच्या बाबतीत वेळेचा अपव्यय होणार नाही. कारण जर नियमाप्रमाणेच चर्चा करता येत नसेल तर मग तशी मागणी होणार नाही आणि चर्चाही होणार नाही. पण याबाबतीत जर नियमच नसेल परंतु ज्या प्रथा आणि परंपरा आहेत त्याप्रमाणे आपण कामकाज चालवित आहोत हे तरी रेकॉर्डवर येऊ द्या. एवढीच माझी विनंती आहे म्हणजे मला तो निर्णय बदलावयाचा नाही.पण आम्हाला हे कळले पाहिजे जेणेकरून पुढे कामकाज करताना अडचण येणार नाही.

श्री.उल्हास पवार : सभापती महोदय, माझा पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशन आहे. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी प्रथा,परंपरा आणि नियम याचा जो उल्लेख केला तो अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्या कक्षा कॅंगने ठरविलेल्या आहेत आणि त्या बाबतीतील प्रथा व परंपरा केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सर्व राज्यांमध्ये सर्वांना लागू केलेल्या आहेत. म्हणून पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून आमच्या ज्ञानामध्ये अधिक भर पडावी यादृष्टीने आपल्याला विचारू इच्छितो.

यानंतर श्री.बरवड . . . .



श्री. उल्हास पवार ....

आपल्या शेजारच्या गुजरात राज्यामध्ये सुध्दा कॅगचा अहवाल शेवटच्या दिवशीच मांडला. त्या ठिकाणी सुध्दा 22 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा कॅगच्या माध्यमातून पुढे आलेला आहे. आपल्या शेजारच्या छत्तीसगड राज्यामध्ये कॅगच्या अहवालाच्या माध्यमातून जवळजवळ 24 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा निदर्शनास आलेला आहे. दुर्दैवाने आपल्या राज्यातून राज्यसभेवर भारतीय जनता पक्षाचे जे सदस्य निवडून गेलेले आहेत ते त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे फार आवडते कायकर्ते आहेत आणि त्यांच्याही नावाचा उल्लेख झालेला आहे. सिंगल बिड त्यांना त्या ठिकाणी दिलेले आहे. या प्रथा परंपरा त्या राज्यांमध्ये मोडल्या आहेत का ? केंद्राने ठरवून दिलेल्या मर्यादा सर्व राज्यांना सारख्याच असल्यामुळे त्या ठिकाणी काही फरक आहे का ? तसे काही असेल तर आमच्या झानामध्ये भर पडावी यादृष्टीने मी आपल्याला विनंती करतो.

श्री. विनोद तावडे : यामध्ये पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय आहे ?

**सभापती :** सन्माननीय सदस्यांचा पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एवढाच दिसतो की, कॅगच्या अहवालाच्या अनुषंगाने घटनेतील ज्या काही तरतुदी आहेत त्या सर्व राज्यांना लागू आहेत तसेच केंद्र सरकारलाही लागू आहेत, संसदेलाही लागू आहेत आणि त्या ठिकाणची प्रथा परंपरा काय आहे एवढेच त्यांना मर्यादित विचारावयाचे होते. मी त्या दृष्टीने आवश्यक असणारी माहिती जरूर घेईन. आज त्यावर लगेच उत्तर देता येणार नाही.

श्री. विनायक मेटे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. उल्हासदादा पवार यांनी या ठिकाणी जे सांगितले ती त्यांची काळजी खरोखरच योग्य आहे.

**सभापती :** आपला हरकतीचा मुद्दा आहे की, पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे ?

श्री. विनायक मेटे : मी आता पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर बोलत आहे पण माझा हरकतीचा मुद्दा सुध्दा आहे.

**सभापती :** सन्माननीय सदस्य श्री. विनायक मेटे यांनी कृपया खाली बसावे. माझ्या दालनामध्ये सभागृहाचे नेते सन्माननीय श्री. अजित पवार साहेब, विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय श्री. विनोदजी तावडे, सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते, सन्माननीय सदस्य श्री. पांडुरंग

RDB/ KTG/

**सभापती ....**

फुंडकर आणि दोन्ही बाजूचे अन्य सन्माननीय सदस्य उपस्थित असताना अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली की, हा अत्यंत महत्वाचा अहवाल आहे आणि हा अहवाल लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून आणि सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या माध्यमातून सर्वोच्च प्राधान्याने हा रिपोर्ट तपासण्यात यावा. दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांची तीच अपेक्षा आहे. लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती यांचे जे कामकाज आहे, त्यांचे जे अधिकार आहेत त्याला कोणत्याही पध्दतीची बाधा न येता मी त्यांना या सभागृहाच्या भावना समजावून देणार आहे. त्यांनी हा रिपोर्ट सर्वोच्च प्राधान्याने तपासावा या दृष्टीने मी हा निर्णय दिलेला आहे.

या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी दुसरा मुद्दा उपस्थित केला त्या बाबतीत तो रिपोर्ट पूर्ण तपासून झाल्यावर आपल्याला कामकाज सल्लागार समितीमध्ये जावे लागेल आणि त्या ठिकाणी जो निर्णय होईल त्या पध्दतीने आपल्याला या बाबतीत बघावे लागेल.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माननीय श्री. अजितदादा पवार यांनी आदर्श सोसायटीच्या संदर्भात एक मोठे निवेदन केले होते. तो मुद्दा कोणी उपस्थित केलेला नव्हता. मला फक्त त्या संदर्भात सांगावयाचे आहे...(अडथळा).. आता माननीय सभापती महोदयांनी जो निर्णय दिला तो कॅगच्या अहवालाच्या संदर्भात आहे. लोकलेखा समितीकडे कॅगचा रिपोर्ट जाणार आहे.

**सभापती :** सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकरजी रावते यांना सांगू इच्छितो की, कॅगचा रिपोर्ट सादर केल्यानंतर मंत्री महोदयांनी आदर्श गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत जो अंतरिम अहवाल आलेला आहे तो या सदनसमोर सादर केला आणि तो सादर करीत असताना त्यांनी त्या अनुषंगाने काही भावना व्यक्त केल्या.

यानंतर श्री. खंदारे ...

**सभापती....**

तो अहवाल ए.टी.आर.सह सादर केलेला आहे. या ए.टी.आर.मधील शिफारशीही शासनाने स्वीकारलेल्या आहेत.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, या अहवालाच्या प्रती मराठीतून देणे आवश्यक होते.

**सभापती** : मराठी भाषेतून हा अहवाल येणार आहे. हा अहवाल आज इंग्रजी भाषेतून सादर झालेला आहे.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, हा अहवाल इंग्रजी भाषेतून सादर करण्याची सरकारला घाई का झाली होती ? सरकारला हा अहवाल मराठी भाषेत सादर करता आला असता.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आपण दिलेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी मी बोलत नाही. मी त्यासंबंधी चर्चाही करीत नाही. परंतु या सदनाने नेते व माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात त्या संदर्भात प्रचंड मोठे निवेदन केलेले आहे. (अडथळा) त्याबाबत आम्हाला आमचे म्हणणे मांडू द्यावे. या सदनमध्ये सभागृहाच्या नेत्यांनी म्हणणे मांडावयाचे व त्याबाबत आम्ही या सदनमध्ये आमचे म्हणणे मांडावयाचे नाही काय ?

श्री.विनायक मेटे : सभापती महोदय, आपले म्हणणे मांडण्याची ही कोणती पध्दत आहे ?

**सभापती** : मी सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांना बोलण्याची परवानगी दिलेली आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.विनायक मेटे यांनी कृपया खाली बसावे.

श्री.दिवाकर रावते : सन्माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातील गोंधळाच्या वातावरणामध्ये अहवाल सादर केला आहे. आम्हाला त्यांचे म्हणणे ऐकू येऊ नये अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली होती. तरी देखील सन्माननीय सदस्यांच्या संमतीने आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकलेले आहे. आमच्यासमोर हा अहवाल आलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी असे म्हटले होते की, आदर्श सोसायटीची जमीन सरकारची आहे. परंतु बरीच वर्षे ती जमीन सैन्याच्या ताब्यात होती. हे त्यांचे पहिले वाक्य होते. त्याच्या मेरिटमध्ये मी जात नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ज्यांना नेमण्यात आले होते त्यांनी एकूण 13 गोष्टीबाबत चौकशी केलेली आहे. ही जमीन कोणाची होती, असे प्रथम विचारले आहे. हौसिंग सोसायटीकरिता होती काय असा दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे.

2....

( सत्ताधारी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य उभे राहून बोलत असतात. )

श्री.दिवाकर रावते.....

माननीय सभापतींनी मला बोलण्याची परवानगी दिलेली आहे.

**सभापती** : सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांना मी सांगू इच्छितो की, मी आपल्याला एक मुद्दा मांडण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. सभागृहात आदर्श गृहनिर्माण सहकारी संस्थेबाबत अंतरिम अहवाल सादर झालेला आहे. त्याबाबतचा ए.टी.आर.सरकारने स्वीकारलेला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला येथे चर्चा करता येणार नाही.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आपण आमचे परमेश्वर आहात. त्यामुळे आम्हाला आपले ऐकावे लागेल. मुस्कटदाबी सहन करून मी खाली बसतो.

श्री.विनायक मेटे : सभापती महोदय, मी मघाशी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी उभा राहिलो होतो. सभागृहात खेळीमेळीचे वातावरण होते. आपल्या सूचनेनुसार मी खाली बसलो होतो. परंतु सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते हे केव्हाही बोलण्यासाठी उभे राहतात. त्यांची ज्येष्ठता लक्षात घेऊन आपण त्यांना बोलण्याची परवानगी देत असता. परंतु त्यांनी आपल्याला परमेश्वर असे संबोधणे म्हणजे एक प्रकारे हिणवण्यासारखे आहे. मघाशी ते वेलमध्ये येऊन आपल्यासमोर दमबाजीच्या भाषेत बोलत होते. कोणताही मुद्दा काढून बोलत राहणे, ही कसली परंपरा व संस्कृती आहे ? ते ज्येष्ठ सदस्य आहेत. पण आपल्यालाही ते परमेश्वर म्हणतात, ही त्यांची ज्येष्ठता आहे काय, हे त्यांचे श्रेष्ठत्व आहे काय, ही त्यांची संस्कृती आहे काय ?

यानंतर श्री.शिगम....

श्री. दिवाकर रावते : सर्वानी मिळून दादागिरी करू नका असे मी बोललो. तुमचे नेते बोलले त्यावेळी आम्ही ऐकून घेतले....

श्री. राजेंद्र दर्डा : सभापती महोदय, आपण दोन वेळा 15-15 मिनिटे सभागृहाची बैठक स्थगित केली आणि आपल्या दालनात आपण निर्णय घेतला.

**सभापती** : मी निर्णय दिलेला आहे. फक्त सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांना मी बोलण्यासाठी परवानगी दिली होती. दुसरे असे की, सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते हे ज्येष्ठ सदस्य आहेत. प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांची बोलण्याची काही पध्दत असते. सन्माननीय सदस्य श्री. विनायक मेटे यांची बोलण्याची जशी विशिष्ट पध्दत आहे तशी सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांची देखील बोलण्याची विशिष्ट पध्दत आहे. तेव्हा या संपूर्ण चर्चेवर मी आता पडदा टाकत आहे.

--

...2...

**पृ.शी./मु.शी.:** कागदपत्रे सभागृहासमोर ठेवणे

श्री. सचिन अहिर (उद्योग राज्य मंत्री) सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद यांचा सन 2010-2011 चव्वेचाळिसावा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे.

--

श्री. सचिन अहिर : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कोकण विकास महामंडळ मर्यादित, यांचे सन 2000-2001 व 2001-2002 चा तिसावा व एकतिसावा वार्षिक अहवाल व लेखे सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** वार्षिक अहवाल व लेखे सभागृहासमोर ठेवण्यात आले आहेत.

--

श्री. सचिन अहिर : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2006-2007 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे.

--

श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील (कृषी व पणन मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मर्यादित यांचा सन 2010-2011चा चौतिसावा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो.

**सभापती :** वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे.

--

...3..

**पु.शी./मु.शी.:** सार्वजनिक उपक्रम समितीचा अहवाल सादर करणे

श्री. हेमंत टकले (समिती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सार्वजनिक उपक्रम समितीचा नववा (अनुपालन) अहवाल सभागृहाला सादर करतो.

**सभापती :** सार्वजनिक उपक्रम समितीचा अहवाल सभागृहाला सादर झाला आहे.

--

श्री. रमेश शेंडगे : सभापती महोदय, कोकण विकास महामंडळ मर्यादितचे 10-10 वर्षापूर्वीचे अहवाल आता सभागृहाला सादर होत आहेत. या सभागृहामध्ये कोकणाच्या विकासाच्या संदर्भात सातत्याने चर्चा होत असते. खरे म्हणजे आता सन 2009-2010चे अहवाल सभागृहाला सादर व्हायला पाहिजे होते. हे अहवाल इतक्या विलंबाने सादर होतात त्यासंबंधी आपण निर्देश देखील दिलेले आहेत.

**सभापती :** केंगच्या अहवालाकडे मी वेगळ्या पध्दतीने पहातो. कोकण विकास महामंडळाचा अहवाल आणि अन्य जे अहवाल सदनासमोर येतात ते विषय कामकाज सल्लागार समितीसमोर ठेवून त्यातील महत्वाच्या अहवालावर चर्चा होण्याची गरज आहे अशी मी त्यांना सूचना करीन.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, आपण या सभागृहामध्ये प्रश्न तहकूब ठेवल्यानंतर 31 मार्चला स्वतःच्या अधिकारात पुन्हा 16 कोटी रुपये वापरण्यात आलेले आहेत.

**सभापती :** आपण जेव्हा चर्चा करू त्यावेळी या मुद्यावर देखील चर्चा करू.

..4..

पृ.शी.: स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) विधेयक

L.C. BILL NO. VII OF 2012

(A BILL TO MAKE PROVISIONS TO ESTABLISH A NEW SCHOOL INCLUDING PROVISION FOR UP-GRADATION OF EXISTING SCHOOL ON SELF-FINANCED BASIS, TO MAKE SUITABLE PROVISIONS WITH REGARD TO REQUIREMENTS AND NORMS FOR ESTABLISHING SUCH NEW SCHOOL OR UP-GRADATION OF EXISTING SCHOOL, FOR CREATING AN ENDOWMENT FUND, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH OR INCIDENTAL THERETO.)

श्री. राजेंद्र दर्डा (शालेय शिक्षण मंत्री) :सभापती महोदय, सन 2012चे वि.प.वि. क्रमांक 7 स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करण्यासह विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी तरतुदी करणे, तसेच अशी नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी आवश्यक असणा-या बाबी आणि प्रमाणके ठरविणे, दाननिधी निर्माण करणे यांकरिता आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी योग्य त्या तरतुदी करण्याकरिता विधेयक मांडण्यासाठी मी सभागृहाची अनुमती मागतो.

...नंतर श्री. गिते..



17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

UU-1

ABG/ KTG/

प्रथम श्री.शिगम

14:25

श्री. राजेंद्र दर्डा....

सभापती महोदय, महाराष्ट्राला शिक्षणाची फार मोठी परंपरा आहे. या राज्यात शिक्षणाचा फार मोठा विस्तार झालेला आहे. राईट टू एज्युकेशन आपल्याकडे आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करित असताना ज्या ठिकाणी नजिकची शाळा उपलब्ध नाही. त्या ठिकाणी शाळा देण्यासाठी बृहत आराखडा अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. सन 2012 चे वि.प.वि.क्र.7- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) विधेयक, 2012 मांडण्यासाठी मला सभागृहाची अनुमती मिळावी.

प्रश्न प्रस्तुत झाला.

2...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

UU-2

ABG/ KTG/

प्रथम श्री.शिगम

14:25

श्री.रामनाथ मोते ( कोकण विभाग शिक्षक ) : सभापती महोदय, या ठिकाणी वि.प.वि.क्रमांक 7- स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करण्यासह विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढ करण्यासाठी तरतुदी करणे, तसेच नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी आणि प्रमाणके ठरविणे, दाननिधी निर्माण करणे याकरिता संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबीसाठी योग्य त्या तरतुदी करण्यासाठीचे विधेयक सन्माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी शासनाच्या वतीने सभागृहात मांडले आहे. नवीन शाळांना परवानगी देण्याच्या संदर्भात आणि दर्जावाढ करण्याच्या संदर्भात या विधेयकात ज्या काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्यात मोठया प्रमाणात त्रुटी आहेत. या त्रुटी दूर होणे, यासंदर्भात सखोल चर्चा होणे, पुन्हा या सर्व तरतुदींचा नव्याने विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अत्यंत घाईघाईने हे विधेयक या सभागृहात मांडून चर्चा न करता, विधेयकातील त्रुटी दूर न करता मंजूर करणे योग्य होणार नाही. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित हे विधेयक आहे, म्हणून हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात यावे अशी माझी सूचना आहे.

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला.

सभापती : अनुमती देण्यात आली आहे.

3...

श्री. विक्रम काळे : सभापती महोदय, शिक्षणाच्या दृष्टीने हे विधेयक अतिशय महत्वाचे आहे. माननीय शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी वि.प.वि.क्रमांक 7 हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे...

**सभापती** : हे विधेयक ज्यावेळी विचारात घेण्यात येईल, त्यावेळी या विधेयकाच्या बाबतीत आपल्याला अतिशय सविस्तरपणे विचार मांडता येतील. सन्माननीय सदस्य श्री. रामनाथ मोते यांना सांगू इच्छितो की, या विधेयकाच्या कन्सीडरेशनच्या स्टेजला चर्चा करू, त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या सूचनेच्या अनुषंगाने स्वतंत्र प्रस्ताव द्यावा लागेल.

श्री.विक्रम काळे : मी या विधेयकाच्या अनुषंगाने भाषण करणार नाही. मला फक्त काही सूचना करावयाच्या आहेत.

**सभापती** : विधेयक कन्सीडरेशनच्या स्टेजला येईल, त्यावेळी सूचना मांडण्यासाठी मी आपणास निश्चितपणे परवानगी देईन.

श्री. राजेंद्र दर्डा : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2012 चे वि.प.वि.क्रमांक 7 मांडतो.

**सभापती** : विधेयक मांडण्यात आले आहे.

यानंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

श्री.राजेंद्र दर्डा : सभापती महोदय, हे विधेयक अत्यंत महत्वाचे आहे. अधिवेशनाचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. सभागृहाच्या भावना अशा आहेत की, हे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात यावे आणि त्याला माझी मान्यता आहे. त्याला शासनाची काही हरकत नाही. तेव्हा मी तातडीने तसा प्रस्ताव सभागृहापुढे आणू इच्छितो.

**सभापती** : मंत्री महोदय, आपण मला दालनामध्ये येऊन भेटावे. त्यादृष्टीने विचार करू.

---

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पृ.शी./मु.शी.:** नियम 93 अन्वये सूचना

**सभापती** : सन्माननीय सदस्य श्री.रामदास कदम यांनी "बोरीवली पूर्व येथील एस.टी.महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या सी.टी.एस.क्र.14 येथील 8, 9 व 10 या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील, डॉ.नीलम गोहे यांनी "पुणे जिल्हयातील जेजुरी गडावरील दिपमाला मोडकळीस येणे तसेच गायमुखी कुंडाची तोडफोड झालेली असणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, संजय केळकर, श्रीमती शोभा फडणवीस यांनी "गोंदिया जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अर्जुनी मोरगाव शाखेत दिनांक 18 फेब्रुवारी, 2012 रोजी झालेला गैरव्यवहार" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी "ज्ञान प्रसारक मंडळ (संदेश विद्यालय, विक्रोळी) या संस्थेतील शिक्षकांच्या नावावर क्रेडिट सोसायटीमधून आणि बँकातून सक्तीने लाखो रुपयांचे कर्ज काढले जात असून ते संस्थाचालक स्वतःच्या खाजगी कारणासाठी वापरत असल्याबाबत" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.धनंजय मुंडे यांनी "बीड जिल्हयात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याबाबत" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

..3..

सभापती.....

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.पांडुरंग फुंडकर यांनी "सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 1, अकोला येथे शासकीय निवासी इमारतीच्या परिरक्षण व दुरुस्तीच्या खर्चात झालेला भ्रष्टाचार" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

-----

..4..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी./मु. शी. : पडघा, ता.शहापूर, जि.ठाणे येथे वाशेरे गावात जप्त केलेली स्फोटके याबाबत डॉ.नीलम गोन्हे, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री.सतेज ऊर्फ बंटी डी.पाटील (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, नियम 93 अन्वये दिलेल्या सूचनेला अनुलक्षण, आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी निवेदन क्रमांक-3 सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

**सभापती** : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे )

...5...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

VV.5

SGB/ KTG/

14:30

निवेदन क्रमांक-3....

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, पडघा येथे वारंवार अशी स्फोटके पकडण्याचा प्रसंग घडत असतो. 7 आरोपींना अटक केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सध्या हे आरोपी जामिनावर सुटले आहेत की अटकेत आहेत? त्यांचा परवाना रद्द केला आहे असे म्हटले आहे. तरी सुध्दा स्फोटक माल विकण्याच्या घटना घडतात.

नंतर श्री.खर्वे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही



डॉ. नीलम गोन्हे.....

निवेदनात आपण म्हटले आहे की, जॅक एंटरप्रायजेसच्या मालकाने बेकायदेशीरपणे हा माल विकत घेतला होता. वास्तविक या कंपनीचा परवाना रद्द केलेला होता तरी देखील त्यानी हा बेकायदेशीर माल विकत घेतला, म्हणून हा एक प्रकारे संघटित स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे दिसते. यासंदर्भात पोलिसांनी कोणकोणती कलमे लावलेली आहेत. हे आरोपी अटक आहेत की जामिनावर सुटलेले आहेत, तसेच त्यांचा जामीन रद्द करणार आहे काय ?

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी.पाटील : महोदय, या भागात खाणी भरपूर असल्याने ने-आण चालूच असते. तसेच टेम्पोचा चालक अमित वाधी याचा परवाना रद्द केला होता तरी देखील त्याने जहीर अहमद खानकडून अशा प्रकारची स्फोटके विकत घेतली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल झालेला आहे व आरोपी अद्यापही अटकेतच आहेत.

**पृ.शी./मु.शी.** : आदिवासी विकास विभागातील शिक्षण विभागात असलेली

रिक्त पदे याबाबत सर्वश्री रामनाथ मोते, विनोद तावडे, संजय केळकर, भगवानराव साळुंखे, नागो पुंडलिक गाणार, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. बबनराव पाचपुते ( आदिवासी विकास मंत्री ) : सभापती महोदय, सर्वश्री रामनाथ मोते, विनोद तावडे, संजय केळकर, भगवानराव साळुंखे, नागो पुंडलिक गाणार, वि. प. स. यांनी "आदिवासी विकास विभागातील शिक्षण विभागात असलेली रिक्त पदे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

**सभापती** : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे )

... ..

....3

श्री. रामनाथ मोते : महोदय, आदिवासी विभागात स्वतंत्र शिक्षण विभाग असून या शिक्षण विभागाच्या पदांबाबतचा हा विषय आहे. मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितले आहे की, आश्रमशाळेतील शिक्षण विभागाची जवळपास 1200 पदे रिक्त असून ती शासनाने रद्द केलेली आहेत. त्यात प्रामुख्याने मुख्याध्यापकांची 56 पदे, केंद्र प्रमुखांची 144, कामाठी 400, स्वयंपाकी 400 आणि 80 पदे चौकीदाराची आहेत. या निमित्ताने माझा प्रश्न असा आहे की, ही रिक्त पदे रद्द करण्यासंबंधीचा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर घेण्यात आला आहे काय, त्याचबरोबर नव्याने जी 1465 पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाने सुरु केली त्यांची विगतवारी काय आहे ?

श्री. बबनराव पाचपुते : महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ही 1200 पदे अनेक दिवसांपासून रिक्त होती व ती भरण्याबाबत चर्चा सुध्दा वेळोवेळी झाल्या. ज्यावेळेस आदिवासी विभागात स्वतंत्र शिक्षण विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय झाला त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात न्यायालयाने सुध्दा तसे आदेश दिले. दुसरे म्हणजे आपण न्यायालयात तसे शपथपत्र दिले की, आम्ही आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र शिक्षण विभाग सुरु करू, तेव्हा न्यायालयाने मान्यता दिली. पण वित्त विभागाकडे गेल्यानंतर 1200 पदे समर्पित करून नव्याने 1600 पदे मंजूर करता येतील अशी चर्चा झाली. त्यातून या 1465 पदांना वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुध्दा झाली व ही 1200 पदे समर्पित करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 1465 पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली व त्यानंतर ती पदे भरण्याची कार्यवाही चालू केली. सन्माननीय सदस्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जरी 1200 पदे रद्द झाली असली तरी आपण नव्याने 1465 पदे भरत असल्याने कोणतीही अडचण येणार नाही, उलट त्यापेक्षा जास्त पदे भरण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यामागचा हेतू असा आहे की, आदिवासी विभागात स्वतंत्र शिक्षण विभाग असल्याने चांगल्या प्रकारे काम व्हावे व यावर्षी शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर भर आपण दिला आहे. यात प्रामुख्याने जिल्हा स्तरावर 450 कर्मचारी, अधीक्षकाची 156 पदे अशी विविध पदे त्यात आहेत. आदिवासींच्या मुलांना शिक्षण देण्याच्या संदर्भात यापूर्वी देखील शासन चांगल्या प्रकारे प्रयत्न करित होते म्हणून आदिवासींची 18 लाख मुले आज शाळेत जात आहेत आणि त्यासाठीच आपण स्वतंत्र शिक्षण विभागाची स्थापना केली आहे.

यानंतर श्री. जुन्नरे ..

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, विद्यार्थ्यांची देखभाल करण्यासाठी, एकूणच कामकाज व्यवस्थित होण्यासाठी कामाट्यांची 400, स्वयंपाक्यांची 400, चौकीदारांची 80 तसेच काही मुख्याध्यापकांची पदे आहेत. त्यामुळे नवीन 1465 पदांमध्ये वरील पदे आहेत काय ?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, मुळात आपण शिक्षण विभागच स्वतंत्र करित आहोत. त्यामुळे ही सर्व पदे शिक्षण विभागाला जोडली जातील. विस्थापित पदे रद्द केल्याशिवाय शिक्षण विभाग स्वतंत्र सुरु करण्यासाठी 1600 पदांची मागणी केली होती. परंतु या ठिकाणी आता जी काही चर्चा झालेली आहे त्या चर्चे प्रमाणे काम होईल एवढे मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो.

-----

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**सभापती** : सन्माननीय सदस्यांना मी विचारु इच्छितो की, जेवणाची सुट्टी घ्यावी का ? आज सभागृहासमोर भरपूर कामकाज आहे. त्यामुळे कोणाला जेवणासाठी जावयाचे असेल तर व्यक्तिगत जावे अशी माझी सूचना आहे.

### **नियम 93 अन्वयेच्या निवेदनाबाबत**

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, 93 च्या निवेदनावर या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे. परंतु अजून 93 ची पुष्कळ निवेदने येणे बाकी आहेत. विभागाकडून सर्व निवेदने यावीत अशी आपली अपेक्षा असते. आता अधिवेशनाचे केवळ 3 दिवस उरलेले आहेत. अजून 93 ची अनेक निवेदने आलेली नाहीत. 93 ची निवेदने शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली गेली तर 93 च्या निवेदनाचे महत्व निघून जात असते. 93 ची सूचना स्वीकृत झाल्यानंतर त्याचे उत्तर विशिष्ट कालावधीत आले पाहिजे याबाबत नियम ठरविण्याची आवश्यकता आहे. दर वेळेला 93 च्या निवेदनाच्या संदर्भातील हा विषय सभागृहात उपस्थित होत असतो व शेवटच्या दिवशी 93 ची निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जातात ते काही संयुक्तिक नाही म्हणून याबाबतीत आपण स्वतः दखल घेऊन शासनाला सूचना केली तर योग्य होईल.

**सभापती** : यापूर्वी देखील हा प्रश्न उपस्थित झाला होता त्यावेळी मी मुख्य सचिवांना कळविले होते की, त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून त्या त्या विभागाला 93 च्या निवेदनाच्या बाबतीत कळवावे. त्या प्रमाणे त्यांनी कार्यवाही केलेली आहे. यावेळेस एकंदर 68 निवेदने त्यांकडून येणार होती. परंतु त्यापैकी 40 निवेदने आतापर्यंत आलेली असून राहिलेली 28 निवेदने दोन तीन दिवसात येण्याच्या दृष्टीने सुध्दा जरूर सूचना दिल्या जातील.

---

...3..

**पु. शी.** : राज्यातील अनु.जाती, अनु. जमातीच्या विविध महामंडळाच्या तसेच इतर योजनांसाठी निधीचा अभाव

**मु. शी.** : राज्यातील अनु.जाती, अनु. जमातीच्या विविध महामंडळाच्या तसेच इतर योजनांसाठी निधीचा अभाव यासंबंधी सर्वश्री विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, संजय केळकर, रामनाथ मोते, डॉ.रणजित पाटील, वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री. विनोद तावडे ( विरोधी पक्ष नेता ) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती यांच्या करीता शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, तसेच, यासारख्या इतर योजनांमध्ये असलेला निधीचा अभाव, असंख्य दलित अर्जदारांचे कर्जासाठीचे अर्ज प्रलंबित असणे, तसेच, या योजनांच्या प्रादेशिक कार्यालयातील अनेक पदे रिक्त असणे, बदलत्या काळाबरोबर अशा सर्व योजनांचा आढावा घेऊन त्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता, कर्नाटक तसेच मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील (MIDC) औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडांमधील २२% भूखंड (SC/ST) अनुसूचित जाती/जमाती यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावे अशी दलितांकडून होणारी मागणी, दलित समाजातील होतकरु उद्योजकांना मार्गदर्शन करून त्यांना उद्योगाच्या नामी संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या DICCI (डिक्की) सारख्या संस्थांना MCHI च्या धर्तीवर शासनाने मान्यता देणे आवश्यक आहे"

श्री. शिवाजीराव मोघे ( सामाजिक न्याय मंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

**सभापती** : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे )

..4..

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, खाजगी कंपन्यांमध्ये सुध्दा आरक्षण दिले गेले पाहिजे अशी मागणी काही वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. ज्यावेळी ही मागणी करण्यात आली होती त्यावेळी माननीय पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना उद्योगपतींचे तसेच सीआयआयचे शिष्ट मंडळ भेटले होते. दलित उद्योजकांना प्रमोट करावयाचे असेल तर इंडस्ट्री म्हणून आम्ही काही पुढाकार घेऊ शकतो असे आग्रहाने प्रतिपादन केल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबतीत एक पॉलिसी ठरवली होती. यासंदर्भात पॉलिसी ठरविल्यानंतर केंद्रामध्ये व काही राज्यामध्ये यासंदर्भातील कामे सुरु झाली होती. विशेषतः दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने असा विषय मांडला होता की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित उत्थानामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, नोकरी या विषयांमध्ये काम केले होते. परंतु आर्थिक उदारीकरणामध्ये दलित समाज हा नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारा झाला तर सामाजिक उत्थानाची चळवळ अधिक गतीने पुढे जाऊ शकेल. महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, शाहू-फुले-आंबेडकरांचा आहे असे आपण सांगत असतो. डिक्कीचे प्रमुख श्री. मिलींद कांबळे व त्यांचे सहकारी वारंवार भेटत असतात आपली बाजू मांडत असतात. त्यामुळे यासंदर्भात मला दोन तीन प्रश्न विचारावयाचे आहे की, आपल्याकडे अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ आहे परंतु त्यांची अवस्था काय आहे याची वास्तविक आपल्याला माहिती आहे. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की,राज्यात दलित तरुण उद्योजक निर्माण होत आहेत.

यानंतर श्री. भारवि...

**(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती)**

श्री.विनोद तावडे...

लघु व मध्यम उद्योगामध्ये दलित उद्योजकांना प्राधान्य देऊ शकलो तर बरे होईल. अमेरिकेमध्ये काळ्यांची चळवळ झाली त्यावेळी एक फिलॉसॉफी पुढे आली होती. त्यातून पुढे जाऊ हे आग्रहाने आले होते. आज आपण पाहतो की, दलित समाजातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर उद्योजक होत आहे. त्यामुळे अशा समाजातील तरुण उद्योजकांना पुश करण्यासाठी आपले राज्य अग्रेसर राहिले तर ते महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे मला माननीय मंत्रिमहोदयांना एवढेच विचारावयाचे आहे की, केंद्र सरकारने प्रॉक्युरमेंट पॉलिसी करून अमुक टक्के माल या उद्योगांकडूनच घ्यावा असे घोषित केले आहे. तसे आपण काही घोषित करू शकतो काय ? जेवढा टक्के समाज आहे तेवढे टक्के आरक्षण असते. दुसरा मुद्दा एमआयडीसीतील प्लॉट्स देण्यासंबंधातील आहे. दलित समाजाला एमआयडीसीतील प्लॉट घेण्यासाठी किंमतीमध्ये सूट नको आहे. ते दुसऱ्यांशी स्पर्धा करायला तयार आहेत. आज आपली प्रतीक्षा यादी खूप मोठी आहे. तेव्हा एमआयडीसीतील प्लॉट दलित समाजातील उद्योजकांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय शासन घेणार आहे काय ?

तिसरा मुद्दा असा आहे की, सन 2030 मध्ये जगामध्ये सर्वात तरुण देश भारत असेल. कारण भारतामध्ये सगळ्यात जास्त युवकांची संख्या राहिल. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर एच.आर. स्कील्ड डेव्हलप झाले पाहिजे म्हणून दरवर्षी 800 कोटी रुपयांची तरतूद करून काही प्रयोग करीत आहेत. त्यांनी अशा प्रकारचे 30 सेक्टर्स निवडले आहेत. जगातील सर्व देशांमध्ये सिनिअर सिटीझन्स वाढणार आहे. त्यामुळे तेथील रूटीन चालविण्यासाठी युवक लागणार आहेत. ते युवक भारत देऊ शकतो. अशी आपली भौगोलिक स्थिती राहणार आहे. त्यामुळे तो ह्युमन रिसोर्स हा दलित समाजातील असू शकतो. त्यासाठी स्वतंत्र योजना करण्यासाठी राज्य शासन आणि डिक्की मिळून काही विचार करू शकते काय ? डिक्कीच्या कार्यक्रमाला स्वतः माननीय श्री.शरद पवार साहेब गेले होते, श्री.दिग्विजय सिंह आले होते, स्वतः मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आले होते. त्यांच्या बरोबर ते नियमित बैठक घेतात.



श्री.विनोद तावडे...

परवा माननीय पंतप्रधानांनी बजेट नंतर फिक्कीच्या बरोबर चर्चा केली होती. त्यावेळी डिक्कीच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील बोलाविले होते. असे अॅपेक्स इंडस्ट्रीजचे स्वप्न आपण डिक्कीला दिले तर बरे होईल. कारण यात महाराष्ट्रातीलच बरीच मंडळी आहेत. हा विषय सगळ्या अर्थाने गतीने पुढे नेण्यास उपयोगी पडेल. तेव्हा शासन असे प्रयत्न करणार आहे काय ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री.विनोदजी तावडे यांनी अतिशय चांगला, दूरदृष्टीचा विषय मांडलेला आहे. याची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये 2-3 वर्षांपूर्वी झालेली होती. दलित माणसाने स्वतःच्या पायावर उभे राहिले पाहिजे. तो अधिक स्वाभिमानी झाला पाहिजे, स्वावलंबी झाला पाहिजे या दृष्टीकोनातून आपण औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून जवळ जवळ 7 कोटी रुपये एका प्रकल्पाला देण्याची सुरुवात केली होती. राज्यामध्ये जवळ जवळ 372 संस्था अशा होत्या. यापैकी काही संस्था यशस्वी ठरल्या तर काही अपयशी ठरल्या आहेत. त्या दृष्टीने आमचा पाठपुरावा झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये उद्योगीकरणाचे शासकीय जाळे हे एमआयडीसीच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. या स्पर्धेमध्ये दलित बांधव टिकू शकेल किंवा नाही याबाबत शंका आहे. दलित समाजाच्या उद्योजकांसाठी एमआयडीसीमध्ये भूखंड राखीव ठेवण्यासंबंधी माननीय उद्योग मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. मला विश्वास आहे की, एस.सी.आणि एस.टी.संवर्गासाठी काही भूखंड राखीव ठेवण्यासंबंधी विचार होईल.

येथे डिक्कीचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे.त्यांच्या समवेत चर्चा करण्यात येईल. आमचा दलित बांधव त्या उद्योगामध्ये कसा भाग घेऊ शकेल हे पाहिले जाईल. पैसा आपण उपलब्ध करू देऊ शकतो. पण तो सक्सेस झाला पाहिजे. यासाठी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तो देखील आम्ही करू. केंद्र शासना संबंधीचा एक चांगला मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र शासन वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करित असते. सदर खरेदी मागासलेल्या संस्थांकडून करण्याचा फार महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. त्या निर्णयासाठी आपण लायक आहोत काय, तसे उद्योग आपल्याकडे आहेत काय हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याप्रमाणे दलित समाजातील उद्योजकाला सक्षम करण्याचा प्रयत्न करू या.

यानंतर श्री.सरफरे...

श्री. शिवाजीराव मोघे...

त्याप्रमाणे एक बैठक आयोजित करण्यात येईल. त्या बैठकीसाठी माननीय विरोधी पक्षनेते, माननीय सदस्य श्री. सुभाष चव्हाण आणि डिक्कीचे प्रतिनिधी यांनाही बोलाविण्यात येईल.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, निवेदनामध्ये सांगितल्याप्रमाणे अन्य राज्यांमध्ये कोणते धोरण आहे हे पाहून आपण धोरण ठरविणे योग्य नाही. शाहू-फुले यांच्या राज्याने दुसऱ्या राज्याकडे बघण्याची गरज नाही तर आपण स्वतः प्रयत्न केले पाहिजेत. अमेरिकेसारख्या देशाने प्रिव्हेंटीव्ह ॲक्शन घेतली आहे आणि तेथील सर्व आफ्रो अमेरिकनांना सर्व प्रकारच्या सत्तेमध्ये सहभाग दिला. त्यामध्ये एशियन गटाचा देखील समावेश होतो. आपल्या राज्यामध्ये एस.सी., एस.टी. आणि इतर मागासवर्ग या सर्वांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात केवळ एम.आय.डी.सी. नाही तर सर्व व्यवस्थेत सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यामध्ये ठराविक लोकांना टोल वसुली कां दिली जाते, ज्यांच्याकडे भरपूर आहे त्यांना आपण टोल वसुलीचे काम न देता मागासवर्गीयाना देणार काय, रस्त्यांच्या कामामध्ये त्यांना सहभागी करून घेणार काय? आपल्या विधिमंडळाने पूर्वी एक कायदा करून तो माननीय राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविलेला आहे, तो अजून मंजूर झालेला नाही. खाजगी क्षेत्राकडून होईल तेव्हा होईल परंतु राज्य सरकार स्वतःकडील काही गोष्टी देणार आहे काय? राज्य सरकारच्या उपलब्ध असलेल्या सोर्ससमधून आपण देणार काय? त्यासाठी अन्य राज्यांकडे पहाण्याची गरज नाही. या लोकांना किती आणि कसे शेअर देणार आहात?

श्री. शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी इतर राज्यांमध्ये अशाप्रकारचे आरक्षण आहे असे म्हटल्यामुळे ते कशाप्रकारचे आहे याची माहिती घेण्यात येईल असे म्हटले होते. महाराष्ट्र हे ॲडव्हान्स राज्य असल्यामुळे माहिती घेण्याचा प्रश्न नाही. परंतु महत्वाच्या ठिकाणी रिझर्व्हेशन असावे या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करण्यात येतील.

श्री. सुभाष चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी अत्यंत सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून ही लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. जोपर्यंत औद्योगिक क्रांती होणार नाही तोपर्यंत जातीयता आणि विषमता नष्ट होणार नाही असे मी नेहमी म्हणतो. आपण ही लक्षवेधी सूचना 10 ओळींची विचारली असून तिला 60 ओळींचे उत्तर माननीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी दिले आहे. चर्मोद्योग विकास महामंडळामार्फत अंबरनाथ येथे चर्मोद्योग प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्या ठिकाणी दुसऱ्या देशातील उद्योगपती आले आहेत. परंतु त्या भागातील गटई कामगार कुठे गेला, त्याला गाळा का मिळत नाही, त्याला जागा का मिळत नाही? आपण दिलेल्या

श्री.सुभाष चव्हाण....

निवेदनाला अनुसरुन मला दोन प्रश्न विचारावयाचे आहेत. सभापती महोदय, महात्मा फुले विकास महामंडळ आणि अण्णाभाऊ साठे मातंग समाज विकास महामंडळ यांच्यामार्फत विविध 172 योजना राबविल्या जातात, असे सांगत असतांना काही नवीन योजना सुरु केल्या जाणार आहेत. म्हणून मला असे विचारावयाचे आहे की, काही नवीन योजना सुरु करीत असतांना या 172 योजना आपण बंद करणार आहात काय? माननीय सदस्य श्री. रमेश शेंडगे अध्यक्ष असलेल्या महामंडळाला एकही देणगी मिळत नाही. माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी या ठिकाणी अनुसूचित जातींच्या दोन महामंडळांचा उल्लेख केला आहे, त्या महामंडळामार्फत उद्योगपती होण्यासाठी त्यांच्या भागभांडवलामध्ये काही वाढ करणार आहात काय? अर्थसंकल्पामध्ये जर तरतूद करण्यात आली नसेल तर आपल्या विभागामार्फत ही वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणार काय?

श्री. शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, मुंबई शहर सोडले तर अन्य ठिकाणी गटई कामगारांसाठी असलेली योजना एक वर्षभर बंद होती. त्याकरिता टेंडर फायनल झाले असून या वर्षी आपण ही योजना मोठ्या प्रमाणात सुरु करू. त्या मार्फत जेवढे बेनिफिशरीज येतील त्या सर्वांना स्टॉल देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. दुसरे असे की, 172 योजनांपैकी बहुतांशी योजना या काळाच्या ओघामध्ये उपयोगी राहिलेल्या नसल्यामुळे त्या बंद करुन नवीन कॉम्प्युटराईज अशाप्रकारच्या योजना सुरु केल्या तर त्यामुळे मार्केट मिळेल आणि त्यामधून लोकांना चार पैसे मिळू शकतील. या मध्ये अर्थ हा एक महत्वाचा विषय असून अर्थ नसेल तर माणसाच्या जीवनाला अर्थ रहात नाही. मागासलेल्या लोकांना कमी लेखण्यामागील कारण असे की, त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत, गरिबी आहे. त्यामुळे हा माणूस उद्योगपती झाला पाहिजे किंवा उद्योगामध्ये भागीदार झाला पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील.

श्री. रमेश शेंडगे : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देतांना सांगितले की, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडे जी प्रकरणे आली त्यापैकी 3 हजार 501 प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडे 20 हजार 451 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रलंबित असलेली प्रकरणे आपण केव्हा निकाली काढणार आहात, प्रकरणे मंजूर करण्याकरिता शासनाने घातलेल्या अटीमध्ये लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्याला दोन साक्षीदार आणण्यास सांगितले जाते.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

त्याला 7:12 चा उतारा आणावयास सांगितले जाते आणि बाकीच्याही काही अटी आहेत. या अटी शिथिल करण्याचे कबूल केले होते. त्यानुसार या अटी व शर्ती शिथिल करणार आहात काय ? तसेच यासंबंधातील प्रलंबित प्रकरणे केव्हा निकाली काढण्यात येणार आहेत ?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकालामध्ये काढण्यासाठी पूर्वी महात्मा फुले महामंडळाला 15 कोटी रुपये मिळत होते.परंतु मागच्या वेळेला 136 कोटी रुपये आणि उत्तरामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे 2012-2013 मध्ये 150 कोटी रुपये दिलेले आहेत. अशा प्रकारे एवढ्या प्रमाणात मदत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला 2010-2011 मध्ये फक्त 15 कोटी रुपये दिले होते आणि 2011-12 या वर्षामध्ये 68 कोटी रुपये दिले आणि यावर्षी 75 कोटी रुपये ठेवण्यात आलेले आहेत. जेणेकरून प्रकरणे निकालात निधू शकतील. या बाबतीत असे होते की, मला मिळाले, त्याला मिळत नाही अशा तक्रारी येतात. आपल्याकडे फंड कमी असून मागणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे याबाबतीत आता अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की, अशा वेळी जे पात्र असतील त्यांच्या नावाच्या चिठ्या काढण्यात याव्यात म्हणजे प्रश्न निर्माण होणार नाही.

श्री.राजन तेली : सभापती महोदय, आता माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले की, दोन्ही महामंडळाच्या बाबतीत सांगावयाचे तर काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.अशा वेळी ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी काही कालावधी ठरविला आहे काय? एखादे प्रकरण सर्व टेबल्सवरून गेल्या नंतर त्याबाबत किती दिवसामध्ये निर्णय घेणार? कारण ही प्रकरणे वर्षानुवर्षापासून पेंडींग आहेत.दुसरा प्रश्न असा आहे की,मागासवर्गीयांनी उद्योजक व्हावे अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केलेली आहे आणि त्यानुसार प्रत्येक उद्योजकाला 7 कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्याच्या बाबतीत योजना सांगितली.माझा मुद्दा असा आहे की,या योजनेचा लाभ मागासवर्गीय न घेता दुसरेच लोक घेत आहेत.त्याठिकाणी केवळ मागासवर्गीयांची नावे दिलेली आहेत.अशी जिल्हानिहाय बरीच प्रकरणे झालेली आहेत.केवळ मागासवर्गीयांची नावे घेण्यात आली आहेत आणि प्रत्यक्षात विशिष्ट लोक याचा फायदा घेत आहेत.या सगळ्या प्रकरणांचा आपण तपास करणार आहात काय? मी केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उदाहरण देतो.त्याठिकाणी 7 प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत.त्या ठिकाणी स्वतः मागासवर्गीय उद्योग चालवित आहेत की दुसरे अन्य कोणी चालवित आहेत की दलाल चालवित आहेत याबाबत शहानिशा करून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणार आहात काय?

श्री.शिवाजीराव मोघे : सन्माननीय सदस्य श्री.राजन तेली यांनी असा प्रश्न विचारलेला आहे की, 372 संस्था आहेत, त्यामध्ये मागासवर्गीयांच्या नावाने इतर कोणी फायदा घेत आहेत काय? याबाबतीत मी 100 टक्के "नाही" असे म्हणणार नाही पण एखादा टक्का असे असू शकते.मात्र कायदा असा आहे की, या योजनेमध्ये 70 टक्के सभासद हे अनुसूचित जातीचे असावयास पाहिजेत आणि त्या संस्थांमध्ये अध्यक्ष, सेक्रेटरी सुद्धा असले पाहिजेत. तसेच नॉन दलितही असावयास पाहिजे आणि बाकी सारेजण मॅनेजमेंटवर असले पाहिजेत. अशा प्रकारे एवढे सगळेजण असल्यानंतर अनुचित प्रकार होऊ नये असे वाटते.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.राजन तेलीसाहेबांनी व्यक्त केलेली भीती खरी आहे. त्यामुळे त्याचे नियम करताना इक्वीटी किती असावी याचा विचार केला पाहिजे, नाहीतर मजूर सोसायटीच्या बाबतीत सांगावयाचे तर तेथे नावाला मजूर आणि ती सोसायटी कॉन्ट्रॅक्टर चालवितो अशी आपण अनेक उदाहरणे पहातो. त्यामुळे हे फुलपुफ करता येऊ शकते आणि तसे अनेकांनी केलेले आहे. माननीय मंत्री महोदय देखील पॉझिटीव्ह आहेत. हा विषय केवळ समाजकल्याण विभागाशी संबंधित नाही. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावयास पाहिजे. त्यामुळे आपण हे किती दिवसामध्ये पूर्ण करणार आहात? याबाबतीत टाईम बाऊंड काही सांगितले तर होईल म्हणजे पहिली बैठक एक महिन्यामध्ये घेऊ.

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, पहिली बैठक एक महिन्यामध्ये घेऊ आणि गरज असली तर अनेक वेळा बैठक घेऊ. कारण . . . .

(अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.)

श्री.शिवाजीराव मोघे : सभापती महोदय, मी गरज असली तर असे म्हटलेले आहे. कारण एका बैठकीमध्ये सर्व गोष्टी होत नसतात.

(अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.)

श्री.शिवाजीराव मोघे : मात्र सन्माननीय सदस्यांचे समाधान होत नाही. परंतु आपला जो उद्देश आहे तो सफल होण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू.

----

. . . .3ए-3

पृ.शी.: राज्यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने  
उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा होत असलेला  
गैरवापर.

मु.शी.: राज्यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने  
उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा होत असलेला  
गैरवापर यासंबंधी श्री.विक्रम काळे, अॅड.उषा  
दराडे, सर्वश्री रमेश शेंडगे, हेमंत टकले वि.प.स.  
यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना

श्री.विक्रम काळे (औरंगाबाद विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये  
पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय शालेय शिक्षण  
मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे अशी विनंती करतो.

"राज्यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे जिल्हा  
परिषदांच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने चालविलेल्या शाळांनाही त्यांच्या भौतिक सुविधे  
साठी निधी उपलब्ध होत असणे, त्यातून शाळांच्या वर्ग खोल्यांचे बांधकाम ग्राम समितीकडून करवून  
घेणे, सरपंच व त्या संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त खात्यावरून त्या निधीचा उपयोग  
करण्यात येणे, यामुळे वारंवार सरपंचांनी मुख्याध्यापकावर दबाव आणून त्या निधीचा गैरवापर  
करण्यात येणे, मात्र वर्गखोल्याच्या बांधकामाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर येणे, याची परिणीती  
म्हणून अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यातील मौजे पिंपळगाव (खांड) येथील काचोरी वस्ती  
वरील शाळेच्या श्री.जालीधर जाधव या मुख्याध्यापकाची जबाबदारी असणाऱ्या शिक्षकाने या  
बांधकामाच्या तणावातून माहे फेब्रुवारी, 2012 मध्ये केलेली आत्महत्या, यामुळे शिक्षण क्षेत्रात  
उडालेली खळबळ व पसरलेली नाराजी, यामुळे राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांकडील हे शाळा  
खोल्यांचे बांधकाम तातडीने काढून घेण्याबाबत शासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली  
कारवाई, उपाययोजना व शासनाची प्रतिक्रिया."

श्रीमती फौजिया खान (शालेय शिक्षण राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचने-  
संबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन  
आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवते.

. . . .3 ए-4

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3A-4

APR/KTG

14:55

**उप सभापती** : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन  
(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे.)

. . . .3 ए-5

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3A-5

APR/KTG

14:55

श्री.विक्रम काळे : सभापती महोदय, राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वशिक्षा अभियान सुरु आहे.त्यांच्यावतीने शाळा-कॉलेजचे बांधकाम करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या

माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी येत असतो आणि हे काम कोणाकडे सोपविलेले आहे? याबाबतीत सांगावयाचे तर ज्या गावामध्ये जिल्हा परिषदेची वर्गखोली बांधावयाची असेल तर त्याठिकाणी एक शालेय समिती गठित करण्यात आली असून त्याचे अध्यक्ष सरपंच आहेत. तसेच सरपंच आणि मुख्याध्यापक या दोघांच्या जाईट खात्यामध्ये हे पैसे जमा होतात आणि हे आपल्यालाही माहिती आहे.अनेक ठिकाणी असे होते की,तेथील सरपंच आणि तेथील लोकप्रतिनिधी दबाव आणून हे पैसे काढून घेतात परिणामी बांधकाम होत नाही. मग याबाबतीत शेवटी त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकावर जबाबदारी येते आणि त्यातूनच अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यातील मौजे पिंपळगाव खांड येथील काचोरी वस्ती येथे एक जिल्हा परिषदेची शाळा होती. तेथील बांधकामामध्ये काही अनियमितता झाली म्हणून सरपंचांना गाडीत अटक झाली.

यानंतर श्री.बरवड . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी



श्री. विक्रम काळे ....

परंतु त्यामध्ये मुख्याध्यापकाने भयभीत होऊन आत्महत्या केलेली आहे. अशा प्रकारे ही एकच आत्महत्या झालेली नाही तर या बांधकामामुळे महाराष्ट्रामध्ये तीन ते चार आत्महत्या झालेल्या आहेत. कालच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळब तालुक्यात श्री. निकम नावाच्या शिक्षकावर बांधकामामध्ये अनियमितता झाली म्हणून 2 लाख रुपयांची रिकव्हरी काढली. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन विनंती केली की, माझी चूक नाही तरी मी पैसे भरण्यास तयार आहे. तरी सुध्दा त्यांच्यावर पोलीस कारवाई केली. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. विक्रम काळे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. राज्याचे गृहमंत्री ज्यावेळी विरोधी पक्षात होते त्यावेळी त्यांना लक्षवेधीकार म्हणून प्रेस स्वीकारत होते. माझी सभागृहाच्या वतीने विनंती आहे की, किमान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांना लक्षवेधी सूचनेवर प्रश्न कसे विचारावयाचे, किती प्रश्न विचारावयाचे याचा एकदा अभ्यासवर्ग श्री. आर. आर. पाटील यांनी घ्यावा.

**उप सभापती :** आपण जेव्हा त्यांना लक्षवेधीकार अशी उपमा दिली तेव्हा माझ्या मनात त्यांच्या बाबतीत प्रश्न-कम-उत्तराकार अशी एक उपमा आली. प्रश्न त्यांचा असतो आणि उत्तरही त्यांचेच असते. सबकुछ तेच असतात.

श्री. विक्रम काळे : सभापती महोदय, मुख्याध्यापकांकडून हे काम काढून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे. आपल्या जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र बांधकाम यंत्रणा आहे, इंजिनिअर्स आहेत. त्यांच्याकडे हे काम का देत नाही ? निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, 2007 मध्ये कमिटी केली आणि त्यांनी सांगितले की, आता कार्यपध्दती बदलण्याची गरज नाही. दोनच दिवसांपूर्वी या सभागृहामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले की, आम्ही त्यांच्याकडून बांधकाम काढून घेण्याच्या संदर्भात केंद्र शासनाला लिहिलेले आहे. कालच ग्रामविकास खात्याचे मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी सांगितले की, आम्ही मुख्याध्यापकांकडून बांधकाम काढून घेत आहोत. माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की, शाळेचे बांधकाम आपण मुख्याध्यापकांकडून काढून घेणार का ? स्टार माझा वाहिनीने आवाज उठविला. त्यांनी

RDB/ KTG/ ST

श्री. विक्रम काळे ....

स्टोरी केली आणि शासनाचे वाभाडे काढले. त्याची तरी आपण दक्षता घेणार का ? शाळेचे बांधकाम मुख्याध्यापकांकडून किती दिवसात काढून घेणार ?

**उप सभापती :** आपण लक्षवेधी सूचना देण्याच्या ऐवजी लक्षवेधी सूचनेच्या रूपात जेवढे काही प्रश्न असतील ते द्यावेत म्हणजे आपल्याला बोलण्याचीही तोशीस नको.

प्रा. फौजिया खान : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याबद्दल अनेकदा या सभागृहामध्ये चर्चा झालेली आहे. ही गोष्ट खरी आहे की, सर्व शिक्षा अभियानाचे जे बांधकाम आहे त्या संदर्भात सरपंच आणि मुख्याध्यापक यांचे संयुक्त अकाऊंट होते. त्यामुळे काही दबाव निर्माण झाला असण्याची शक्यता होती. परंतु आता शिक्षणाचा अधिकार कायदा आलेला आहे. त्यानुसार आता ही पध्दत बदललेली आहे. आता सरपंच आणि मुख्याध्यापक यांचे संयुक्त अकाऊंट नसून आता पालक हे शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत. आता पालक आणि सदस्य सचिव म्हणून मुख्याध्यापक राहणार आहेत. त्यामुळे दबावाचा जो प्रश्न होता तो थोडाफार मिटलेला आहे असे मला वाटते.

श्री. हेमंत टकले : सभापती महोदय, या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देत असताना निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, शासन स्तरावर 2007 मध्ये समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या गरजा विचारात घेऊन कार्यपध्दतीत बदल न करण्याची शिफारस केलेली आहे. आता माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितले की, आपण ही कार्यपध्दती बदललेली आहे. जर ही कार्यपध्दती बदलली असेल तर ती खालपर्यंत गेली आहे का आणि जर ती गेली नसेल आणि त्या मुख्याध्यापकाला विषयाचा संबंध नसलेल्या बांधकामासारख्या कामामध्ये जर गुंतविले तर त्या ठिकाणी जे राजकीय वातावरण असते त्यामुळे त्या ठिकाणी असणाऱ्या सरपंचांचा दबाव त्या मुख्याध्यापकावर येणे अतिशय स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना यातून मुक्त करण्याची सूचना या ठिकाणी केली.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.हेमंत टकले....

परंतु या प्रकरणामध्ये एका मुख्याध्यापकाचा जीव गेला आहे. त्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याची काळजी घ्यावीच. परंतु जी बाधित कुटुंबे आहेत त्यांच्यासाठी शासन काय करणार आहे ?

प्रा.फौजिया खान : सभापती महोदय, सध्याची पध्दत चालू ठेवावी, त्यात बदल करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची शिफारस त्या समितीने केलेली आहे. थर्ड पार्टी मूल्यांकन करण्यात आले त्यामध्ये 90 टक्के बांधकाम समाधानकारक असल्याचे दिसून आलेले आहे. 2 वर्षांमध्ये त्यांचे टारगेटही पूर्ण होणार आहे. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर या कामाचा ताण असतो. कारण सध्या नवीन नवीन योजना येत असल्यामुळे त्यांच्यावरील ताण वाढत आहे. पोलीस विभागातील कर्मचाऱ्यांवर सुध्दा ताण असतो. आर.टी.आय.मुळे अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. परंतु कामाचा ताण पडणे व काम बाजूला काढणे यात फरक आहे. काम बाजूला काढणे बरोबर नाही. प्रोसिजर स्ट्रीम लाईन झाली पाहिजे हे खरे आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीला बांधकामे पूर्ण करण्याची मुभा देत असल्यामुळे ती समितीच यावर खर्च करणार आहे. त्या कामासाठी टप्पे केले पाहिजेत. बांधकामाचा ठराविक टप्पा पूर्ण झाल्यावर काही रक्कम वितरित केली जाईल. ते काम तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्याशिवाय होणार नाही. असे निकष बदलले व ते राज्यात लागू केले तर ही स्ट्रीम लाईन होऊ शकेल. अशा प्रकारचा विचार शासन करणार आहे.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिले आहे त्यापेक्षा वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आपण मला बोलण्याची संधी द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. जालंदर जाधव नावाच्या मुख्याध्यापकांनी आत्महत्या केली आहे. मी त्यांच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांना भेटून आलो आहे. जालंदर जाधव यांच्याप्रमाणे अनेक आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापूर्वीही सुधाकर ठाकरे, भगर, निंबाळकर, भालचंद्र या लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. कोणी गळफास लावून तर कोणी विष प्राशन करून आत्महत्या केलेली आहे. मंत्री महोदयांनी असे सांगितले आहे की, मुख्याध्यापकांकडून हे काम काढून घेतले जाईल. सर्वशिक्षा अभियानाची कक्षा

2...

श्री.रामनाथ मोते...

वाढविली आहे, त्या समितीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. जालंदर जाधव यांना गावच्या लोकांनी व सरपंचांनी मारहाण केली होती. त्यांना दमदाटी केली जात होती. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांना होत असलेल्या त्रासाबाबत लेखी तक्रार तालुका गट शिक्षणाधिकारी, गट विकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. परंतु त्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्याची प्रत माझ याजवळ आहे. हे बालंट आपल्यावर येऊ नये, या जाचाला कंटाळून त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांचा राजीनामा सुध्दा स्वीकारण्यात आला नव्हता. त्यांनी स्वतः पतपेढीतून कर्ज काढून पैसे भरले होते. ते स्वतः त्या बांधकामावर पाणी मारत होते. त्याबाबतचे माझ्याजवळ फोटो आहेत. अत्यंत वाईट अवस्थेत जाधव यांनी आत्महत्या केली आहे. अशा प्रकारची घटना राज्यातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये घडू नये म्हणून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडून हे काम काढून घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणार आहे काय, ज्या अधिकाऱ्यांना कळविल्यानंतरही त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यांनी दखल घेतली असती तर जालंदर जाधव यांचे प्राण वाचू शकले असते. म्हणून त्यांच्या तक्रारीची ज्यांनी दखल घेतली नाही त्या अधिकाऱ्यांवर शासन भा.दं.वि.मधील कलम 306 अन्वये गुन्ह्याची नोंद करील काय ?

यानंतर श्री.शिगम....

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3D-1

MSS/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

15:10

प्रा. फौजिया खान : जालिंधर जाधव याच्या आत्महत्येच्या संदर्भात डिटेल माहिती मला द्यावी लागेल. जालंदर जाधव हे हेडमास्तर होते. 2007-08मध्ये बांधकाम सुरु झाले. परंतु प्रत्यक्षात 2009मध्ये बांधकामाला सुरुवात झाली. ते जॉईंट अकौण्ट होल्डर होते. त्यातील गंगाधर गणपत शेट्टे हे सरपंचे होते. ते अर्धवट काम सोडून निघून गेले. जालंदर जाधव यांनी कारागिरांना 62 हजार रुपये धनादेशाद्वारे दिले. नंतर दुसरे कारागीर देखील काम सोडून गेले. त्यानंतर 38 हजार रुपये त्यांनी पुन्हा बँकेमध्ये ठेवले. नवीन सरपंच आले त्यांनी पुन्हा 1 लाख रुपये काढून घेतले. ते पुन्हा अर्धवट काम सोडून गेले. जालंदर जाधव यांनी गट शिक्षण अधिका-यांकडे तक्रार केली. गट शिक्षण अधिका-यांनी विस्तार अधिका-यांना चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केले. विस्तार अधिका-यांनी चौकशीला सुरुवात केल्यानंतर ज्यांनी एकमेकांच्या विरोधात तक्रार केली होती त्यांनी आम्ही एकमेकाविरुद्धची तक्रार परत घेत आहोत असे पत्र दिले. त्यामुळे तक्रार विथ्झा करण्यात आली. गंगाधर गणपत शेट्टे आणि भरत विठ्ठल शेट्टे या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यांच्यावर आणखी खुनाच्या केसेस आहेत. त्यांना अटक करण्यात आलेली असून चौकशी चालू आहे. मी पहिल्यांदा सांगितल्या प्रमाणे आत्महत्येची कारणे पोलीस शोधत आहेत. ताण कमी करण्यासाठी दोन उपाय आहेत. एक म्हणजे शालेय व्यवस्थापन समितीमध्ये आता पालक अध्यक्ष असतात, सरपंच नसतो. त्यामुळे राजकीय दबाव कमी झालेला आहे. ही प्रोसेस स्ट्रीमलाईन केली, एकाच वेळी सर्व पैसे त्यांच्या हातामध्ये राहाणार नाहीत या दृष्टीने काही नॉर्म्स ठरविले तर हा ताण कमी होऊ शकतो असे शालेय विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.

---

..2..

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3D-2

MSS/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

15:10

**पु. शी. :** दोडामार्ग तालुक्यातील (जि.सिंधुदुर्ग) तिलारी धरण परिसरात गांजाच्या झाडाची लागवड करुन त्याची होत असलेली तस्करी

**मु. शी. :** दोडामार्ग तालुक्यातील (जि.सिंधुदुर्ग) तिलारी धरण परिसरात गांजाच्या झाडाची लागवड करुन त्याची होत असलेली तस्करी यासंबंधी सर्वश्री विजय सावंत, एस.क्यू.जमा, जयप्रकाश छाजेड व एम.एम.शेख,वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री. विजय सावंत ( विधानसभेने निवडलेले ) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय गृह मंत्र्याचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"दोडामार्ग तालुक्यातील (जिल्हा सिंधुदुर्ग) तिलारी धरण परिसरात तसेच मांगेली, विडी, शिरंगे, केंद्रे, पाट्ये, फुकेरी, वीजघर, सोनावल, तेरवण, मेढे, मुळस, हेवाळे, कुंब्रल, परमे, घोडगेवाडी, खानयाळे व इतर गावात गेल्या काही दिवसापासून केरळ मधील मूळ रहिवासी असलेल्या काही लोकांनी स्थानिक जमीन दलालांना लाखो रुपयाचे आमिष दाखवून अनेक लोकांची सामायिक जमीन काही लोकांना ठराविक रक्कम देऊन, तसेच, इतर भाग-धारकांना कल्पना न देता त्यांच्या खोट्या सह्या करुन बनावट जमीन विक्री करण्याचे वाढते प्रकार, सदरहू जमिनीत रबर व केळी लागवडीच्या बहाण्याने फार मोठ्या प्रमाणावर गांजाच्या झाडाची लागवड करुन त्यांची तस्करी करण्याचे सुरु असलेले वाढते प्रकार, काही दिवसापूर्वी याच परिसरातील लागवड केलेल्या गांजाची तस्करी करताना एक डंपर जप्त करण्यात येणे, या प्रकारांमुळे स्थानिक नागरिकातील वाढता असंतोष, यासंदर्भात शासनाने करावयाची तातडीची कारवाई व शासनाची प्रतिक्रिया."

श्री.सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

**उप सभापती :** निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापाने )

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

..3..

3D-3

MSS/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

15:10

श्री. विजय सावंत : या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली होती. परंतु पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असे निवेदनामध्ये नमूद केलेले आहे. तेव्हा पोलिसांनी लूपहोल्स ठेवल्यामुळे हे आरोपी सुटले काय ? या प्रकरणी पुन्हा चौकशी करण्यात येईल काय ?

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील : आरोपींना अटक करण्यात आली होती, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु साक्षीदार होस्टाईल झाल्यामुळे आरोपी सुटले. याप्रकरणी पोलिसांनी कोणताही हलगर्जीपणा केलेला नाही.

श्री. दिवाकर रावते : पुराव्या अभावी गुन्हेगार सुटले असे निवेदनामध्ये नमूद केलेले आहे. त्यामध्ये असेही नमूद केलेले आहे की, "सन 2007 मध्ये केरळीयन लोकांनी जमिनीमध्ये रबर व केळीच्या बहाण्याने दोडामार्ग येथील तिलारी खो-यातील बुडीत क्षेत्राला लागूनच असलेल्या जमिनीत मोठ्या प्रमाणात गांजा, अफूची लागवड केल्याबाबत पोलिसांना गोपनीय बातमी मिळाल्याच त्या बातमीच्या अनुषंगाने दि. 20.05.2007 रोजी छापा टाकला असता, पाल गावाच्या क्षेत्रात सुमारे रु. 19,63,680/- किंमतीची गांजाची झाडे व रु. 47,500/- किंमतीचा तयार गांजा, रु. 33,540/- किंमतीचा सुकवलेला गांजा, रु. 4090/- किंमतीची पी.व्ही.सी. पाईपलाईन व अन्य साहित्य असा एकूण रु. 20,48,810/- किंमतीचा माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. त्या प्रमाणे घटनासथळी आरोपी नं. (1) शाजी मामाचंद देवशा, (क) के.पी.जोसेफ उर्फ कानेरतांकुणल फिलिप जोसेफ यांना अटक करण्यात आलेली आहे. एवढा किंमती माल पोलिसांनी पकडलेला आहे. असे असताना आरोपी पुराव्या अभावी सुटले असे निवेदनामध्ये नमूद केलेले आहे. यामधून शासनाला नक्की काय सूचित करावयाचे आहे ? पोलिसांनी सक्षमतेने पुरावे सादर केले नसल्यामुळे आरोपी सुटले आहेत किंवा चुकीचे आरोपी पकडून ख-या आरोपींना लपविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असा यामधून अर्थ निघतो. तेव्हा वस्तुस्थिती काय आहे ?

श्री. आर.आर.पाटील : सन्माननीय सदस्य श्री. विजय सावंत आणि सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते या दोघांनी येथे प्रश्न उपस्थित केले. दोघांच्याही मताशी मी सहमत आहे.

...नंतर श्री. गिते...

श्री.आर.आर.पाटील...

एक तर जागेवर मुद्देमाल सापडला होता, त्यामुळे त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे होती. परंतु त्यांना शिक्षा झाली नाही. ही एक टेस्ट केस म्हणून या प्रकरणाचा योग्य तपास झाला होता काय, या प्रकरणातील उर्वरित सात आरोपी शेवटपर्यंत फरार राहिले त्यांना पकडण्यासाठी योग्य पध्दतीचे पुरेसे प्रयत्न पोलिसांनी केले होते काय, हे आरोपी कसे काय सुटले, ते आरोपी सुटण्यामध्ये कोणाचा दोष आहे काय, ही गोष्ट एखाद्या चांगल्या वकिलाला विचारून घेण्यात येईल आणि वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करतील.

**उप सभापती :** या अनुषंगाने मी एक महत्वाची गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. आपले एक जन्मगाव असते, त्या ठिकाणी आपली शेतजमीन असते. ती शेतजमीन सांभाळण्यासाठी आपण तेथे एखादे कुटुंब ठेवतो. पुणे जिल्ह्यात प्रकर्षाने असे जाणवते आहे की, बाहेरची मंडळी शेती करण्यासाठी येत आहेत. मी माझी शेतजमीन बाहेरच्या मुस्लीम समाजाच्या माणसांना दिली आहे. या शेत जमिनीतील अर्धे उत्पन्न ते घेतात आणि अर्धे उत्पन्न मला देतात. परंतु असे प्रकार ऐकल्यानंतर मला देखील माझ्या शेत जमिनीत या लोकांनी कुठे अफू लावली आहे काय हे बघण्याची वेळ आलेली आहे. सध्या या राज्यात बाहेरून लोक येत आहेत, त्यांना आपण आपली शेत जमीन शेती करण्यासाठी देत आहोत. असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून यात काही तरी मार्ग काढावा लागेल असे मला वाटते. मुळात या लोकांना शेत जमीन द्यावयाची की नाही हा आमचा प्रश्न आहे. परंतु त्या लोकांना शेत जमीन शेती करण्यासाठी दिली आणि त्याने शेतात कोठे अफूची लागवड केली तर शेत मालकाला शिक्षा भोगण्याची वेळ येईल.

श्री.आर.आर.पाटील : यात शेत मालकाचा काही संबंध नाही. या आरोपींना अफू, गांजा लावला होता तर त्यातील हिस्सा मालकाला जात होता काय, ही बाब निश्चितपणे तपासून घेतली जाईल.

**उप सभापती :** शेती सांभाळण्यासाठी आपापल्या विभागातील माणसे मिळत नाहीत अशी परिस्थिती या राज्यात निर्माण झालेली आहे. सभागृहातील अनेक सदस्य शेती व्यवसाय करणारे आहेत. ते देखील ही बाब मान्य करतील.

श्री. दिवाकर रावते : कायद्यात त्या अनुषंगाने शासनाने दुरुस्ती करावी.

2...



श्री. आर.आर.पाटील : अनेक वेळा भाड्याने घरे दिली जातात, काही ठराविक वर्षासाठी जमिनी कराराने दिल्या जातात. त्या मधल्या कालावधीत कोणी काय केले हे बघणे आवश्यक आहे. मालकाच्या हे सर्व नॉलेजमध्ये असेल तर मालक नक्कीच जबाबदार आहे. अशाही गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत की, शेत जमिनीच्या मूळ मालकाचे येणे जाणे कमी असल्यामुळे दुसरीच व्यक्ती त्याच्या शेतावर जाऊन रोप लावते. गावात भांडणे असतील तर गांजाच्या चार बिया टाकल्या जातात आणि पोलिसांना इन्फर्मेशन देतात असेही काही वेळा घडते. त्यामुळे या सर्व प्रकरणी नेमका दृष्टीकोन बघूनच कारवाई केली जाईल.

श्री. परशुराम उपरकर : दोडामार्ग तालुक्यात केरळी लोक मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत. या केरळी लोकांची पोलीस स्टेशनमध्ये अथवा कामगार आयुक्तालयाकडे नोंद होण्याची आवश्यकता आहे. हे लोक या ठिकाणी येऊन गुन्हे करतात आणि निघून जातात. दोडामार्ग तालुक्यात जेवढे खून झालेले आहेत, त्या खुनांचे आरोपी अद्याप पोलिसांना मिळालेले नाहीत. त्या दृष्टीने चौकशी करण्यात येईल काय ? दोडामार्ग तालुक्यात केरळी लोक येऊन शेत जमीन करीत आहेत. ते शेत जमिनीच्या पुढील भागात केळी किंवा अननस लावतात आणि आतील भागात गांजाची लागवड करतात. आता सापाचे विष काढून त्याची तस्करी करण्याचा प्रकार देखील सुरु झालेला आहे अशी बातमी ऐक्यात आहे. या बाबतची देखील सखोल चौकशी केली जाईल काय ?

श्री.आर.आर.पाटील : सापाच्या विषाचा प्रश्न याच सदनात उपस्थित झाला होता. ज्या वृत्तपत्रात ही बातमी छापून आली होती, त्यांच्याकडून माहिती घेतली असता, त्यांनीही सांगितले की, आम्हाला देखील ऐकीव माहिती मिळाली होती. त्यात काही तथ्य नव्हते.

यानंतर श्री. भोगले...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3F.1

SGB/ ST/

15:20

श्री.आर.आर.पाटील.....

लक्षवेधी सूचना क्र.3....

दोडामार्ग तालुक्यात 1839 हेक्टर जमीन अनेक वर्षे केरळी माणसांनी घेतली आहे. एकाच केसमध्ये पोलिसांना माहिती मिळाली की, तेथे गांजाचे उत्पादन घेतले जाते. पोलिसांना तो माल जप्त केला असून दोन आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. त्यानंतर कोणत्याही अनुचित प्रकाराबद्दल पोलिसांकडे तक्रार आलेली नाही. माननीय सदस्यांकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी द्यावेत, निश्चितपणे त्याची चौकशी केली जाईल.

-----

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पु. शी.** : पनवेल, जि.रायगड येथे 50 वर्षांपासून राहणाऱ्या आदिवासींची घरे तोडण्याबाबत सिडको प्रशासनाने दिलेली नोटीस

**मु. शी.** : पनवेल, जि.रायगड येथे 50 वर्षांपासून राहणाऱ्या आदिवासींची घरे तोडण्याबाबत सिडको प्रशासनाने दिलेली नोटीस यासंबंधी श्री.हेमंत टकले, अॅड.उषा दराडे, सर्वश्री रमेश शेंडगे, विक्रम काळे, किरण पावसकर, अरुण गुजराथी, श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना

श्री.हेमंत टकले (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील तक्का गावात सुमारे ५० वर्षांपूर्वीपासून राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांची घरे तोडण्याची सिडको प्रशासनाने दिनांक २९ जानेवारी, २०१२ रोजी वा त्यासुमारास दिलेल्या नोटीसा, त्यामुळे आदिवासी लोकांत पसरलेले चिंतेचे वातावरण, सदर गावात राहणारे आदिवासी हे सिडको अस्तित्वात येण्यापूर्वी पासून तेथे रहिवास करीत असणे, तसेच त्यांचे सन १९९५ च्या मतदार यादीत नांव असणे, असे असतांना देखील सिडकोने आदिवासी लोकांना घरे तोडण्याची नोटीस दिल्यामुळे तेथील नागरिकांत निर्माण झालेला तीव्र असंतोष, यासंदर्भात चौकशी करून शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची कारवाई."

श्री.भास्कर जाधव (नगरविकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

**उपसभापती** : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे )

लक्षवेधी सूचना क्र.4....

श्री.हेमंत टकले : सभापती महोदय, सिडकोच्या जागेमध्ये निवास करणाऱ्या आदिवासींच्या घरांचा हा प्रश्न आहे. फक्त दोनच व्यक्ती आदिवासी होत्या असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. 50 वर्षापूर्वीची त्यांची घरे आहेत असे सांगितले गेले. त्या संदर्भात निवेदनात काही माहिती आलेली नाही. याची चौकट ठरवून दिलेली आहे. दोनच व्यक्तींबद्दलचा हा प्रश्न असला तरी तेथे रहात असलेल्या लोकांना पुराव्यानिशी सिध्द करता आले नसेल, परंतु ते प्रत्यक्ष राहतात त्या भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे, त्यांना पर्यायी जागा द्यावयाची असल्यास किती जागा लागेल? कोणत्याही प्रश्नाला व्यापक व सर्वसाधारण रुप न देता स्पेसिफिक केस म्हणून तो प्रश्न सोडविला तर गरीब लोकांचे प्रश्न सुटू शकतील. दोनच व्यक्तींचा हा प्रश्न असल्यामुळे सिडकोला तो सोडविता येईल काय?

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, दोघांचा प्रश्न असल्यामुळे सिडकोला तो सोडविता येईल काय असा सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारला आहे. एक प्रकारे मानवतावादी दृष्टीकोनातून हा प्रश्न सोडवावा अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हा विषय तसा नाही. अशा प्रकारचा निर्णय झाला तर तो बऱ्याचदा पायंडा पडू शकतो आणि अनेकांना तो लागू होतो.

सभापती महोदय, 1972-73 मध्ये सिडकोकरिता जमीन अधिग्रहण केली गेली. तेथे असलेल्या जमिनी व गावठाण यांचा विस्तार वाढत्या लोकसंख्यानुसार करावयास पाहिजे होता, परंतु तो केला गेला नाही. 1986 साली गावठाण विस्ताराचा निर्णय झाला. ती योजना अंमलात आली. त्याचा फायदा 7 गावांना झाला. त्यामध्ये 29 हेक्टर जमीन गावठाणाबाहेरच्या लोकांना विस्ताराकरिता देण्यात आली, तो विषय तेथेच संपला. त्यानंतर असा निर्णय झाला की, अस्तित्वात असलेल्या गावठाणांपासून 200 मीटरच्या आतमध्ये जेवढी घरे गरजेपोटी बांधण्यात आली आहेत ती घरे कायमस्वरूपी करावीत. ती घरे निष्कासित करू नये किंवा अनधिकृत आहेत असा अर्थ लावून त्यांच्यावर कारवाई करू नये. त्यानंतर 1990 साली ज्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली त्यांना 12.5 टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर एक निर्णय असा झाला की, 2007 पर्यंत ज्यांनी ज्यांनी घरे बांधली आहेत ती कायमस्वरूपी करावीत. त्यानंतर 22.10.2010 रोजी पुन्हा एक निर्णय घेण्यात आला की, सवलतीच्या दराने प्रिमियम आकारून इतरापेक्षा कमी

..4...

श्री.भास्कर जाधव.....

दराने पूर्वी ज्यांना जागा दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे यांना जागा देण्यात यावी. अशा अनेक गोष्टी सिडकोने केलेल्या आहेत. तरी देखील जी मंडळी 200 मीटरच्या पलीकडे सिडकोची जागा आहे तेथे पुरावे न देता एक मजली, दोन मजली, तीन मजली घरे बांधतात, त्यांच्यावरील कारवाईचा हा प्रश्न आहे.

-----

नंतर श्री.खर्चे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पृ. शी.** : नवीन कायद्यामुळे जुन्या सुरक्षा रक्षकांच्या मनात नोकरीबाबत निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण

**मु. शी.** : नवीन कायद्यामुळे जुन्या सुरक्षा रक्षकांच्या मनात नोकरीबाबत निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण यासंबंधी श्री दिवाकर रावते, वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना

श्री. दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय गृहमंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"राज्यातील खासगी आस्थापनांकडे असलेल्या असंख्य सुरक्षा रक्षकांची होणारी अमानुष पिळवणूक थांबविण्यासाठी शासनाने सन 1981 साली महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण कायदा करून स्थापना केलेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळात सभासदासाठी विहित आठवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे सुमारे 23 हजार सभासद नोंदणीकृत असणे, तथापि शासनाने दिनांक 11 मार्च, 2010 रोजी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, 2010 अन्वये महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळात सभासदत्वासाठी बारावी उत्तीर्ण ही अर्हता निश्चित करणे, परिणामी जुन्या सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सभासदांना या नव्या महामंडळाचे सभासदत्व मिळणे दुरापास्त होणे, तथापि, अधिनियमातील कलम 23 च्या तरतूदीनुसार सुरक्षा रक्षक मंडळ व माजी सैनिक महामंडळ या दोन संस्थामधील सुरक्षा रक्षकांना महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामध्ये त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये अहितकारी बदल न करता सरसकट सामावून घेण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात येणे, सन 1981 साली स्थापन केलेले महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि सन 2010 मध्ये स्थापन केलेले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्यातील विविध कलमे, सेवाशर्ती, नियम व कार्यक्षेत्र एकच असणे, त्यामुळे सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, 2010 मधील कलम 23 चा वापर करून दोन्ही सुरक्षा मंडळाचे एकच महामंडळ स्थापन करून ते अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची भूमिका, व प्रतिक्रिया."

श्री. सतेज उर्फ बंटी डी.पाटील (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

.....2

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

( प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छपावे )

-----

.....3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. दिवाकर रावते : सन 1981 च्या कायदानुसार सुरक्षा रक्षकांची निर्मिती केली त्यावेळेस त्या कायदानुसार कमी शिकलेले सुरक्षा रक्षक होते. मला आठवते की, 26.11.2008 च्या हल्ल्याच्या निमित्ताने सभागृहात निवेदन करताना पोलिसांवर सुरक्षेबाबत पडणारा ताण लक्षात घेऊन नवीन सुरक्षा रक्षक महामंडळाची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता व त्या कायद्याप्रमाणे बारावी पास झालेले व शस्त्र परवाना असलेले सुरक्षा रक्षक नेमले जातील असे त्यात होते. त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतही केले होते. या निमित्ताने असा प्रश्न निर्माण होतो की, नवीन सुरक्षा रक्षक महामंडळापूर्वीच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक मंडळातील 40-50 हजार सुरक्षा रक्षकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे की, त्यांन कामावरून कमी करतील. म्हणून शासनाने हे सर्व आपल्या नियंत्रणाखाली घेऊन या जुन्या सुरक्षा रक्षकांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली जाणार आहे काय ?

श्री. आर.आर.पाटील : महोदय, ज्या 23 हजार सुरक्षा रक्षकांच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली त्या अनुषंगाने मी प्रथम सांगू इच्छितो की, सुरक्षारक्षक मंडळातील या 23 हजार कामगारांपैकी कोणाच्याही नोकरीवर गदा येणार नाही. आपण नव्याने कायदा करून जे सुरक्षा रक्षक महामंडळ निर्माण केले त्यामागचा उद्देश एवढाच आहे की, पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करणे, वेगवेगळ्या आणि मोठ्या आस्थापनांमध्ये हत्यारी सुरक्षा रक्षकांची मागणी असते ती पुरविणे यासाठी हा कायदा सन 2010 मध्ये तयार केला. या नवीन महामंडळात भरती करण्यासाठी 12 वी पासची अट घातली असून पोलिसांचे काही अधिकारही आपण त्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिकारात हत्यार धारण करण्याचे अधिकार देत आहोत पण सरसकट या नवीन महामंडळामार्फतच सुरक्षा रक्षक पुरवावेत असे शासनाने कोठेही म्हटले नाही किंवा तशी शासनाची कल्पनाही नाही. सन 2010 च्या कायदानुसार सुरक्षा रक्षक महामंडळाच्या निर्मितीप्रमाणे जुन्या सुरक्षा रक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याची माहिती देण्यात आली पण असे कधीही होणार नाही हे देखील मी सांगतो. तसेच हा नवीन कायदा केला त्यानुसार आपण कितीही लोकांनानेमू शकतो असे असले तरी त्याचा परिणाम म्हणून ही सर्वच जबाबदारी घेणे सुध्दा योग्य होणार नाही, कारण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा रक्षकांची गरज भासते व काही महत्वपूर्ण

.....4



श्री. आर.आर.पाटील.....

संस्थांमध्येच या नवीन महामंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक पाठविले जातील. तसेच जुन्या सुरक्षा रक्षक मंडळात आणि नवीन कायदानुसार तयार केलेल्या महामंडळाच्या कामात ओव्हरलॅपिंग होत असल्याचे जाणवत असल्याने त्यासंबंधी स्वतंत्रपणे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत माननीय कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून या दोन्ही मंडळ व महामंडळाकडे किती अधिकार प्राप्त झाले आहेत, त्यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले ते दूर करण्यासाठी कायद्यात कोणता बदल करण्याची गरज आहे काय हे देखील कामगार विभागामार्फत सुचविण्यात येईल आणि पुढील अधिवेशनात तसा कायदा आणून योग्य तो बदल करण्यात येईल, पण पुन्हा सांगू इच्छितो की, जुन्या मंडळातील कोणाच्याही नोकरीवर गंडांतर येणार नाही.

श्री एस. क्यू. ज़मा : सभापति महोदय, सुरक्षा रक्षक का जो कानून है वह श्रम मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा कि वे एक मीटिंग बुलाएंगे. मेरे दो प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से हैं. मेरा कहना है कि सुरक्षा रक्षकों का जो महामंडल बना है उसमें भर्ती के लिए आपने जो भी कंडीशन्स निर्धारित की हैं, उसके अनुसार महाराष्ट्र के होम गार्ड के जो लोग एलिजिबल हैं, उनको वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के अंदर करीब 8-10 लाख लोग प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं, परन्तु अभी तक 30 साल में सिर्फ 23 हजार लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसलिए मुझे पूछना है कि जब आप श्रम मंत्रालय के साथ मीटिंग करेंगे तो बाकी लोगों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आप वहां पर चर्चा करेंगे या नहीं ?

श्री. आर.आर.पाटील : महोदय, कामगार विभाग यासंदर्भात निश्चित चर्चा करील तसेच गृह विभागाशी संबंधित जो प्रश्न विचारला त्याबाबत मी सांगू इच्छितो की, होम गार्डसना या नवीन भरतीत प्राधान्य दिले जाईल.

श्री. किरण पावसकर : महोदय, सन 1981 मध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्याची निर्मिती करण्यात आली, त्यानंतर सन 2010 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळ अधिनियम असा कायदा केला. खरे म्हणजे यासंदर्भात सभागृहात मागील वेळेसही चर्चा झाली होती की, विमानतळासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी देखील खाजगी सुरक्षा रक्षकच ठेवले जातात....

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

श्री. किरण पावसकर ...

हाय अलर्टच्या जागेवर काही ठिकाणी हे लोक काम करीत आहेत. सिनेमा क्षेत्राला यांच्याकडून सर्रास सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जात आहे. परप्रांतामधील लोक ऑल इंडियाचे लायसन्स घेऊन सुरक्षा रक्षकाचे काम करीत आहेत. मागच्यावेळी 24 ते 40 एजन्सीवर आपण कारवाई केली होती. या एजन्सीवर आपण कारवाई केलेली असतांनाही हे लोक आपली मॅनपॉवर पुरवून सुरक्षा देण्याचे काम करीत आहेत. महामंडळातर्फे सुरक्षेचे काम व्हावे असा शासनाचा उद्देश आहे परंतु अशा प्रकारे मिसयुज करणाऱ्या एजन्सीवर कोणती कारवाई केली जाणार आहे ?

श्री. आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, शक्यतो शस्त्राचा परवाना स्वतःच्या रक्षणासाठी, संरक्षणासाठी दिला जात असतो. काही आस्थापना लोकांच्या सुरक्षेसाठी काम करीत असतात त्यांनाही व्यावसायिक परवाना दिला जात असतो. परंतु स्वतःच्या संरक्षणासाठी परवाना घ्यावयाचा व त्याचे परमीट ऑल इंडिया करावयाचे आणि त्याचा वापर नोकरीसाठी करावयाचा हे काम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा गार्डला ठेवून जर कोणी एजन्सी चालवित असतील तर त्या एजन्सीचा परवाना रद्द करण्यात येईल.

---

...2...

**विशेष उल्लेख**

**पृ.शी./मु.शी.** : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत श्री.हेमंत टकले, वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री. हेमंत टकले (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

"मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत. सन 2005 मध्ये तामिळ, कन्नड व तेलगू ह्या भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. त्याबरोबरच मल्याळम् भाषेला तो नाकारला गेला आहे. आपल्या राज्याने सुरु केलेला प्रयत्न केंद्राच्या सर्व निकषांच्या कसोटीवर उतरेल याची काळजी घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला सहाय्य करण्यासाठी राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांचा व अभ्यासकांचा सहभाग मिळविणे आवश्यक आहे. त्या निमित्ताने राज्य शासनाने एक शीघ्र कृती कार्यक्रम आखून त्याची सत्वर अंमलबजावणी करावी, ही विनंती.

---

..3..

**पृ.शी./मु.शी.** : दिल्ली पॅटर्न अंतर्गत सीबीएससी शाळांच्या वेळात

त्या त्या राज्याच्या हवामानानुसार बदल करण्याबत

श्रीमती शोभा फडणवीस, वि.प.स. यांनी दिलेली

विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्रीमती शोभा फडणवीस (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडते.

भारतात सी.बी.एस.सी. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा दिल्ली पॅटर्न अंतर्गत केजी-1 ते स्टॅंडर्ड-10 पर्यंत सुरु असणे, सदर शाळा सुरु असतांना वेगवेगळ्या राज्याचा हवामान वेगवेगळ्या पध्दतीने असणे, परंतु एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळा सुरु होणे, परंतु याच कालावधीत दिल्लीमध्ये उन्हाळा नसणे, दिल्लीत ज्यावेळेस उन्हाळा असतो त्यावेळेस आपल्याकडे उन्हाळा नसणे, परंतु दिल्ली पॅटर्न नुसार दिल्ली येथे एप्रिल महिन्यात पाहिजे त्या प्रमाणात गरम हवामान नसणे, परंतु विदर्भातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लहान मुलांना होणारा उन्हाचा त्रास सहन करावे लागणे, त्यामुळे कित्येक मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे आढळून येणे, त्या त्या राज्याच्या हवामानानुसार तरी सदर दिल्ली पॅटर्न अंतर्गत सी.बी.एस.सी. शाळांच्या वेळेमध्ये व कालावधीमध्ये बदल करून शाळा सुरु करण्याची आवश्यकता, शासनाने यावर करावयाची कार्यवाही.

-----

..4...

**पृ.शी./मु.शी. :** पुणे शहरातील कचरा निर्मितीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेवून नागरी घन कचरा निकषांबाबत फेरविचार करण्याबाबत श्री. मोहन जोशी, वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री. मोहन जोशी (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

एकीकडे पुणे महानगरपालिका नागरी घन कचरा नियम 2000 याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा प्रयत्न करते त्यानुसार उरुळी देवाची/फुरसुंगी येथील जागेवर कचरा टाकणे बंद केलेले आहे. परंतु, पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या सुमारे 1300 ते 1400 मे.टन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनेचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावर उपाय म्हणून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुणे शहरात 11 ठिकाणी शहराच्या चारही बाजूस कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पासाठी नव्याने जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शासनाने मान्य केलेल्या शहराबाहेरील वढूखुर्द, तुळापूर व शिंदवणे या जागावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत स्थानिकांचा प्रचंड विरोध असल्यामुळे या जागा अद्याप मनपाच्या ताब्यात मिळालेल्या नाहीत.

यानंतर श्री. भारवि...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

31 1

BGO/ ST/

जुन्नरे..

15:35

श्री.मोहन जोशी...

जागेच्या अडचणी व ग्रामस्थाचा विरोध पाहता शहरातच विकेंद्री पद्धतीने प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याकरिता केंद्र शासनाने 1 कोटी 27 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यासाठी पुणे मनपाच्या ताब्यातील जागांवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याकरिता मा.जिल्हाधिकार्यांच्या जागा निवड समितीची आवश्यकता आहे. परंतु, नागरी घन कचरा नियम 2000 नुसार जागा निवडीबाबत देण्यात आलेले निकष हे प्रामुख्याने लँडफील व डंपिंगसाठी आहेत. लँडफीलसाठी असणारे निकष प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ठेवल्यामुळे जागा निवड समितीची मान्यता मिळण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे वाढते शहरीकरण व शहरातील उंचावलेले राहणीमान लक्षात घेता कचरा निर्मितीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन नागरी घन कचरा नियम 2000 मधील निकषांबाबत फेरविचार करून शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन नियम शिथिल करण्यात यावा अशी मागणी मी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आहे.

.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पृ.शी./मु.शी.:** : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसरात  
असलेली अनधिकृत दुकाने या बाबत श्री.किरण पावसकर,  
वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री.किरण पावसकर (विधान सभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखसंबंधीची सूचना मांडतो व त्याबाबत कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

मुंबईतील प्रभादेवी भागातील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसरामध्ये दोन्ही मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आत मध्ये फुले तसेच पूजा साहित्याची अनेक दुकाने आहेत. त्यामधील अनधिकृत दुकानांची संख्या अधिक असून त्यांच्या मार्फत वाजवी पेक्षा जास्त दराने पूजा साहित्याची विक्री करून भाविकांची लुबाडणूक केली जाते. हे फुल विक्रेते भाविकांना अडवून वाजवीपेक्षा जास्त दराने फुले व पूजा साहित्य विकत घेण्याची जबरदस्ती करतात. आम्ही देवाचे दर्शन घेण्यासाठी पुढे पाठवू असे सांगतात. फुल विक्रेत्यांच्या दुकानावरील कामगारांची संख्या निश्चित नसल्याने अधिक व्यक्तींना कामावर ठेवून असे अडवणुकीचे प्रकार केले जातात. या फुल विक्रेत्यांच्या दुकाना बाहेर व आजूबाजूस फुले, हार, दुर्वा इ.चा पसरा पडलेला असतो. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापनास मंदिर परिसर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये अडचणी उद्भवतात.

श्री.किरण पावसकर...

महोदय, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर हे सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबईतील अतिसंवेदनशील ठिकाण आहे. त्या फुल विक्रेत्यांच्या दुकानामधील कामगारांची संख्या निश्चित नसणे, त्यांना ओळखपत्र नसणे, सामानासह त्यांची ये-जा चालू असणे, इत्यादी बाबींमुळे या संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी संपुष्टात आणण्याची नितांत गरज आणि अनधिकृत दुकान निष्कासित करण्यामध्ये होत असलेला विलंब तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांचा भाविकांना होत असलेला उपद्रव या बाबतीत मुंबई पोलीस व मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी करून देखील कारवाई करण्यास होत असलेली अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. या प्रकरणी शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने मी विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे.

**उप सभापती :** हा विशेष उल्लेख सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. मी देखील स्वतः या मंदिरात जातो. हा अनुभव निश्चितच दुःख दायक आहे. या मंदिराच्या आतील बाजूमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे आहेत. मंदिराच्या व्यवस्थापनाने महानगरपालिकेला आणि पोलिसांना वेळोवेळी कळवून देखील अद्याप पर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हे अतिसंवेदनशील ठिकाण आहे. त्यामुळे तेथे प्रचंड बंदोबस्त असतो. असे असताना पोलिसांच्या समक्ष तेथे अनधिकृत दुकाने थाटली आहेत. यास महापालिका जेवढी जबाबदार आहे तेवढे पोलीस देखील आहेत. यासंबंधी मी राज्य शासनाला असे निदेश देतो की, ताबडतोब या प्रकरणी महानगरपालिकेला कारवाई करण्यास सांगावे. तसेच, पोलिसांकडून कठोर पावले उचलण्याच्या संदर्भात शासनाने येत्या चार दिवसांच्या आत कारवाई करावी आणि कोणती कारवाई केली हे शुक्रवारी अधिवेशन संपण्याच्या आत सांगावे.

प्रा.लक्ष्मणराव ढोबळे : होय.

.....

...4



पृ.शी./मु.शी.: सावंतवाडी (जि.सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील जंगल संपत्तीला लावण्यात येत असलेला वणवा याबाबत श्री.सुभाष चव्हाण वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री.सुभाष चव्हाण (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखसंबंधीची सूचना मांडतो.

सावंतवाडी (जि.सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील जंगल संपत्तीला लावण्यात येत असलेल्या वणव्यामुळे जंगलातील वनसंपदा, वन्य प्राणी व जीव सृष्टीला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होत असून अनेक वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होत असल्यामुळे वन्यप्राण्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे आढळून येणे, त्याच प्रमाणे वनसंपत्तीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच पर्यावरणात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाची वाढ होत असणे, अवैध वृक्षतोड करण्यात आल्यानंतर वृक्षांच्या मुळाचे बुंधे वणव्यात खाक होतात व त्यामुळे अवैध वृक्षतोड झाल्याचा पुरावाही राहत नाही.

यानंतर श्री.सरफरे...

श्री. सुभाष चव्हाण...

यामुळे जंगलांना आगी लावण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. जंगलातील वन्यप्राण्यांचे, वन्य पक्षांचे, जीव सृष्टीचे व वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी व पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबाबत जंगलांना लावण्यात येत असलेल्या आगीचे प्रकार रोखण्याबाबत तसेच या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वन अधिकारी व वन कर्मचारी यांचेवर कठोर कारवाई करण्याबाबतची आवश्यकता, अशा या अतिशय महत्वाच्या व गंभीर विषयावर मी विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे".

-----

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पृ. शी./मु. शी. :** बीड जिल्ह्यातील बाराशे गावांमध्ये निर्माण झालेली तीव्र पाणी

टंचाई याबाबत अॅड. उषा दराडे, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

अॅड. उषा दराडे (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडते.

"बीड जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. बाराशे गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या 1 हजार 757 विहिरींपैकी तब्बल अकराशे विहिरींनी तळ गाठला आहे. एकूण 9 हजार 151 हातपंपापैकी जवळपास बाराशे हातपंप कायमचे बंद पडले आहेत. तब्बल दीड हजार हातपंप कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे पाणी टंचाईचे सावट गडद झाले आहे.

जिल्ह्यात 1 हजार 20 ग्रामपंचायती आहेत. छोटी गावे वाड्या, वस्ती, तांडे मिळून 3 हजार 437 गावे आहेत. जिल्ह्यात 1192 पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. गावठाण सार्वजनिक विहिरींची संख्या 565 आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील व गावठाण मिळून 1 हजार 757 सार्वजनिक विहिरी आहेत. जिल्ह्यातील 110 विहिरींचे प्रातिनिधीक स्वरूपात दर तीन महिन्याला निरीक्षण करून पाणी पातळीचा सर्व्हे केला जातो. सध्या साधारणतः 60 टक्के विहिरी तळाला गेल्या आहेत. तेव्हा लोकसंख्येची अट न घालता टॅंकर पुरविण्याची आवश्यकता, या बाबत एकंदर पाणी टंचाईचा सर्व्हे करून लोकसंख्येची अट शिथिल करून नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात यावा अशी मी या विशेष उल्लेखाद्वारे मागणी करीत आहे.

प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे (पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी सादर केलेली माहिती तपासून न पहाता ती वस्तुस्थितीला धरून आहे असे समजून ज्या ठिकाणी विहिरींनी तळ गाठला असेल किंवा ज्या भागामध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसेल अशा भागामध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना सूचना देऊन त्या भागांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरविण्याबाबत सक्त ताकीद देण्यात येईल.

पृ. शी./मु. शी. : बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना दोन वर्षांपासून मजुरी न मिळणे याबाबत श्री.धनंजय मुंडे, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री. धनंजय मुंडे (विधानसभेन निवडलेले : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

"सभापती महोदय, बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील 16 गावांच्या 3 हजार मजुरांनी रोजगार हमी योजनेच्या केलेल्या कामांची दोन वर्षांपासून देयके प्रलंबित असणे, अधिकाऱ्यांनी वेळेमध्ये वरिष्ठांकडे निधीची मागणी न केल्यामुळे तसेच कामाचा साप्ताहिक अहवाल त्याच दिवशी ऑनलाईन न केल्यामुळे ही देयके दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दरवेळी निधी नसल्याचे कारण सांगून मजुरांना निधीसाठी ताटकळत ठेवायचे आणि दुसरीकडे गुत्तेदारांनी रोजगार हमी योजनेच्या केलेल्या कामाचे मस्टर मात्र वेळेवर पूर्ण करून त्यांची देयके द्यायची. मात्र विहिरीचे काम करणाऱ्या मजुरांचे हक्काचे पैसे दफ्तर दिरंगाईमध्ये अडकल्यामुळे मजुरांना नाहक त्रास सहन करावा लागणे, त्यामुळे मजुरांवर आलेली उपासमारीची वेळ, त्यांच्यामध्ये शासनाविषयी पसरलेला तीव्र असंतोष व शासनाने करावयाची कारवाई व उपाय योजना."

----

पृ. शी./मु. शी. : जाम-वरोरा राज्य महामार्गावरील विद्युत खांब स्थलांतरीत करण्याची आवश्यकता याबाबत श्री.जयंतराव जाधव, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्री. जयंतराव जाधव (नाशिक स्थानिक प्राधिकारी संस्था) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

"जाम-वरोरा राज्य मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्णत्वास आल्याने रस्ता वाहतुकीस खुला करण्यात येणे, रस्ता रुंदीकरणामुळे या महामार्गावरील सा.क्र.17/300 कि.मी. व 25/300 कि.मी. मधील 66 केव्ही विद्युत खांबामुळे अपघाताला निमंत्रण देणारी स्थळे निर्माण होणे, हे विद्युत खांब स्थलांतरीत करण्यासाठी शासनाकडून कार्यकारी अभियंता क्र. 1 यांना निधी प्राप्त असूनही त्यांचेकडून विद्युत वितरण कंपनीला रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात येणे, परिणामी रस्ता वाहतुकीस खुला होऊनही अद्यापपर्यंत हे विद्युत खांब स्थलांतरीत न झाल्याने या ठिकाणी सतत अपघात होत असणे, सतत अपघात व जीवित हानी होऊनही प्रशासकीय यंत्रणेकडून केली जाणारी डोळेझाक, परिणामी येथील स्थानिक नागरिकांत असणारा तीव्र संताप, या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विद्युत वितरण कंपनीला रक्कम उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता. याबाबत शासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी मी विशेष उल्लेखाद्वारे करित आहे."

---

(अपूर्ण - यानंतर श्रीमती रणदिवे)

पृ.शी./मु.शी.: चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत

क्रिडा व कार्यानुभव हे तीनही विषय प्राथमिक अभ्यास-  
क्रमात शिकविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे याबाबत  
श्री.भगवान साळुंखे वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष  
उल्लेखाची सूचना.

श्री.भगवान साळुंखे (पुणे विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील  
विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कला, क्रीडा व कार्यानुभव हे तिन्ही  
विषय प्राथमिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रभावीपणे शिकविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा प्रारंभ  
करण्यात आला. प्रत्येक प्राथमिक शाळेत कला, क्रीडा व कार्यानुभव प्रशिक्षित शिक्षक लमसम  
वेतनावर नेमावेत असे आदेश देण्यात आले. हे प्रशिक्षित शिक्षक ग्रामशिक्षण समितीला देण्यात आले.  
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने निधीचे वितरणही करण्यात आले. काही जिल्ह्यामध्ये या  
निधीचे ग्रामपातळीपर्यंत वितरणही झाले व ग्रामविकास समितीने कला, क्रीडा व कार्यानुभव प्रशिक्षित  
शिक्षकांच्या नेमणुकाही केल्या.दरम्यान राज्य शासनाने या कामी एकसूत्रीपणा आणण्या साठी राज्य  
स्तरावरून अंमलबजावणीचा कृती आराखडा ठरविण्यासाठी स्थानिक पातळी वरील नेमणुकांना  
प्रतिबंधक केला. आता एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही अद्याप राज्य शासनाने आपला कृती  
आराखडा घोषित केलेला नाही. त्यामुळे जे शिक्षक नेमलेले आहेत त्यांचे भवितव्य अंधारमय झाले  
आहे, तसेच केंद्राकडून निधी उपलब्ध होऊन उर्वरित शाळेतून कला, क्रीडा, कार्यानुभव प्रशिक्षित  
शिक्षकांच्या नेमणुकाही होऊ शकलेल्या नाहीत. प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासार्थ सुरु  
असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीस विलंब होत आहे.

सभापती महोदय, या विशेष उल्लेखाद्वारे मी शासनास विनंती करतो की, कला, क्रीडा व  
कार्यानुभव प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याबाबतचा कृती आराखडा एका महिन्यात घोषित  
करून नवीन शैक्षणिक वर्षापासून सदर शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या जाव्यात. तसेच आज कऱ्हाड येथे  
माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थाना समोर कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी धरणे आंदोलन  
केले असून पोलिसांनी 700 लोकांना पकडलेले आहे, याबाबत मी शासनाला अशी विनंती करीन  
की, सदरहू प्राध्यापकांची "कायम" हा शब्द काढण्याची मागणी मंजूर करावी आणि ज्यांना पकडण्यात  
आले आहे, त्यांनाही मुक्त करावे.

पु.शी./मु.शी : नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण न होणे  
याबाबत श्रीमती अलका देसाई वि.प.स.यांनी दिलेली  
विशेष उल्लेखाची सूचना.

श्रीमती अलका देसाई (विधानसभेद्वारा निर्वाचित) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने  
पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडते.

नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील नागरिकांना निवासाची उत्तम व्यवस्था व्हावी यासाठी 2004  
साली राज्य शासनाने बांधकामास सुरुवात केली. याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील असून देखील  
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन सुसज्ज करण्यासाठी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिक श्री.चमनकर  
यांना कंत्राट दिलेले असणे, महाराष्ट्र शासनाचे काम करून देण्यासाठी त्यांना मुंबईतील अंधेरीमधील  
आर.टी.ओ.ची जमीन सन 2004 साली देण्यात येणे, सदर जमिनीचा ताबा श्री. चमनकर यांनी घेऊन  
बांधकाम करून विक्रीही करण्यात येणे, तथापि अजूनपर्यंत म्हणजे 2012 साल उजाडले तरी  
महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण न होणे. फर्निचरचे काम होत आहे या नावाखाली वेळकाढूपणा करत  
असणे, त्यामुळे नवी दिल्ली येथे जाणाऱ्या नागरिकांची निवासाची अत्यंत गैरसोय होत असल्याने व  
सन 2004 पासून महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण न झाल्याने शासनाप्रती निर्माण झालेली असंतोषाची  
भावना, हा विषय अत्यंत महत्वाचा असल्याने यावर त्वरित कार्यवाही करण्याची आवश्यकता  
असल्याने मी हा विषय विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून सभागृहात मांडत आहे. कृपया स्वीकृत  
करण्यात यावा, ही विनंती.

-----

3 के-3 ....

## माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर करण्यात आलेली निदर्शने

श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.भगवान साळुंखे यांनी विशेष उल्लेख केला की, कऱ्हाड येथे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना पोलीस तेथे पोहोचण्यापूर्वीच साक्षीदारांना आपापल्या घरी डिटेन केलेले आहे. त्यासंदर्भात माननीय सभापतींनी सांगावे.

**तालिका सभापती (श्री.मोहन जोशी) :** याबाबतीत नोंद घेतलेली आहे. तसेच माननीय मंत्री महोदयांनी अशी विनंती केलेली आहे की, आजच्या कामकाज पत्रिकेवर सन 2009 चे वि.स.वि.क्रमांक 42-महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) विधेयक दाखविण्यात आलेले आहे, त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्याप्रमाणे सदरहू विधेयक चर्चेसाठी घ्यावयाचे आहे काय ?

### सभागृहातील कामकाजाबाबत

डॉ.नीलम गोऱ्हे : सभापती महोदय,मागच्या आठवड्यामध्ये सरकारने आम्हाला विनंती केली म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या संदर्भातील चर्चा आज मंगळवारी घेण्यात येत आहे. तसेच आज निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांसाठी निरोप समारंभाचा कार्यक्रम आहे. याठिकाणी चर्चेसाठी एवढे महत्वाचे विषय असताना विधेयक चर्चेसाठी घेण्यात यावे असेही आपण सांगत आहात. त्यामुळे यापध्दतीने कामकाज होऊ शकत नाही. तसेच याठिकाणी माननीय विरोधी पक्ष नेतेही उपस्थित नाहीत. तसेच आमचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत महत्वाचा प्रस्ताव देखील सभागृहापुढे आहे.

**तालिका सभापती :** ठीक आहे.

यानंतर श्री.बरवड . . . .



**पु. शी.** : राज्यात गुन्हेगारीचे वाढलेले प्रमाण

**मु. शी.** : राज्यात गुन्हेगारीचे वाढलेले प्रमाण या विषयावर सर्वश्री विनोद तावडे, दिवाकर रावते, पांडुरंग फुंडकर, रामदास कदम, जयंत प्र. पाटील, संजय केळकर, डॉ. दीपक सावंत, अॅड. प्रीतमकुमार शेगांवकर, श्री. चंद्रकांत पाटील, डॉ. नीलम गोन्हे, श्रीमती शोभा फडणवीस, सर्वश्री रामनाथ मोते, केशवराव मानकर, भगवान साळुंखे, सय्यद पाशा पटेल, नागो पुंडलिक गाणार, वि. प. स. यांचा प्रस्ताव

डॉ. नीलम गोन्हे ( विधानसभेने निवडलेल्या ) : सभापती महोदय, आमचे सर्व सहकारी सन्माननीय सदस्य सर्वश्री विनोद तावडे, दिवाकर रावते, पांडुरंग फुंडकर, रामदास कदम, जयंत प्र. पाटील, संजय केळकर, डॉ. दीपक सावंत, अॅड. प्रीतमकुमार शेगांवकर, श्री. चंद्रकांत पाटील, डॉ. नीलम गोन्हे, श्रीमती शोभा फडणवीस, सर्वश्री रामनाथ मोते, केशवराव मानकर, भगवानराव साळुंखे, सय्यद पाशा पटेल, नागो पुंडलिक गाणार यांनी हा प्रस्ताव दिलेला आहे. मी आपल्या अनुमतीने नियम 260 अन्वये पुढील प्रस्ताव मांडते.

"महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी शहरात सोनसाखळी चोऱ्या, अपहरण, चोऱ्या, खून, दंगली, इत्यादीचे प्रमाण वाढलेले असणे, एकूण गुन्हेगारीत वाढ झालेले असताना पोलिसांच्या व विधी व न्याय खात्याच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण गतवर्षी केवळ 9.6 टक्के असताना यावर्षी ते 9 टक्के इतके खाली आलेले असणे, शिक्षा झालेले आरोपी देखील हजारोंच्या संख्येने फरारी झाल्याचे निदर्शनास येणे, तसेच महिला व बालकांवरील अत्याचारात पुरोगामी महाराष्ट्राने मागास राज्यांनाही मागे टाकणे, मुंबईमध्ये डान्सबार बंद करण्याची घोषणा करून देखील समाज शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच डान्सबार सुरु असणे, जेष्ठ नागरिकांच्या हत्या देखील वाढलेल्या असणे, सायबर

RDB/ ST/

डॉ. नीलम गोन्हे .....

गुन्ह्यांच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक करण्याच्या घटनेत वाढ झालेली असणे, 26/11 च्या हल्ल्यानंतर सीसीटिव्ही यंत्रणा बसविण्याची घोषणा करुन देखील अद्यापपर्यंत सीसीटिव्ही यंत्रणा बसविलेली नसणे, सिमी सारख्या संघटनेची पाळे-मुळे बुलढाण्यासारख्या ग्रामीण भागात पोहोचल्याचे नुकतेच निदर्शनास येणे, सिध्दार्थ महाविद्यालयातील प्राध्यापिका श्रीमती साळुंखे यांनी सन 2005-06 मध्ये आझाद मैदान पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक श्री.अविनाश सोनावणे यांच्याकडे तेथील प्रिन्सिपलची तक्रार केली असता त्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करुन उलटपक्षी श्रीमती साळुंखे यांच्याकडून 22 ग्राम सोन्याची चेन घेणे, श्रीमती चित्रा साळुंखे यांनी सन 2009 मध्ये आयपीएस अधिकारी श्री.बिष्णोई यांनी एल.एल.बी. च्या अंतिम वर्षाची प्रात्यक्षिक परीक्षा न देताच पास झाल्याची तक्रार करुन देखील त्याची दखल न घेतल्याने मा.उच्च न्यायालयाने पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढणे, साताऱ्यातील पोलीस निरीक्षक श्री.मोरे यांनी एका युवतीशी अश्लील संभाषण करुन लगट करण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्याविरोधात सातारा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केल्यानंतर देखील निरीक्षक श्री.मोरे यांच्याविरुद्ध कारवाई न होणे, दिनांक 1 एप्रिल, 2012 रोजी पुणे जिल्ह्यातील शुभम शिर्के याची 50 हजार रुपयाच्या खंडणीसाठी दोन अल्पवयीन मुलांबरोबर एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याने निर्घृण हत्या करणे, पुण्यातीलच कल्याणी देशपांडे यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ न करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब सुर्वे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ए.सी.बी.) नुकतीच अटक करणे, यासर्व बाबींमुळे पोलीस दलाबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष व याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यावी."

सभापती महोदय, प्रचंड प्रश्न आहेत, प्रचंड समस्या आहेत. कोटून सुरुवात करावी याचा विचार करावयास लागलो तर साधारणपणे जे चित्र दिसते त्यावर मी सुरुवातीला बोलणार आहे आणि त्यानंतर काही उदाहरणे आणि आकडेवारीकडे मी जाणार आहे. एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की, ठिकाठिकाणी अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. मुंबईत विनयभंगाच्या घटनांमध्ये 47 टक्के वाढ झालेली आहे. दंगलींच्या प्रमाणामध्ये 38 टक्के वाढ झालेली आहे. घरफोडी आणि

...3...

RDB/ ST/

डॉ. नीलम गोन्हे .....

सोनसाखळ्या चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये 24 ते 35 टक्क्याने वाढ झालेली आहे. राज्यभरात 26 कोटी रुपयांची मंगळसूत्रे लंपास झालेली आहेत. तीन वर्षात 6 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लांबविला. राज्यभरात अशा सोनसाखळी चोरांकडून अवघ्या तीन वर्षात 26 कोटी 81 लाख 87 हजार 945 रुपयांची मंगळसूत्रे लांबविली गेली आहेत. आज या ठिकाणी चर्चेला येत असताना दागिने घालून यावे की दागिने न घालता यावे असा प्रश्न पडला होता. आज अशी परिस्थिती झालेली आहे की, नगरसेवक असो किंवा सामान्य लोक असो, ते वेगवेगळ्या पध्दतीने अत्याचार, दरोडे यांचे बळी होत आहेत. त्यामध्ये महिला अत्याचारात महाराष्ट्राचा क्रमांक सहावा आहे. बालकांवरील अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2010 मध्ये महिलांवरील 15737 अत्याचारांची नोंद करण्यात आलेली आहे तर बालकांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत राज्यात 3264 गुन्हे नोंदविण्यात आले. या सगळ्यामध्ये भरीस भर म्हणून एका बाजूला आपण सातत्याने पोलीस अधिकारी यांची संख्या कमी आहे असे सांगत असतो. परंतु त्याचवेळी आपल्याला असेही दिसते की, शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

यानंतर श्री. खंदारे ...

डॉ.नीलम गोन्हे...

त्याबद्दल पोलीस विभागाकडून काही आकडेवारी प्रकाशित केली जाते. त्याच्या तपशीलामध्ये गेले नाही तरी एक चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

सभापती महोदय, किती गुन्हे घडतात व किती गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होते त्याची आकडेवारी पाहिली तर त्याचा रेट 169.4 टक्के आहे. पुणे शहरामध्ये 237.8 टक्के आहे, नाशिकमध्ये 270 टक्के, अकोल्यामध्ये 228 टक्के, नागपूर शहरामध्ये 292 टक्के आहे. ग्रामीण भागामध्ये म्हणजे लातूरमध्ये 136 टक्के, नागपूर ग्रामीणमध्ये 158 टक्के, नाशिक ग्रामीणमध्ये 100 टक्के, पुणे ग्रामीणमध्ये सरासरीच्या 167.6 टक्के आहे. आपण मुंबई, पुणे, ठाणे व नाशिक या शहरांची चर्चा करित आहोत. त्याच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर अमरावतीमध्ये 359.7 टक्के, मुंबईमध्ये 238.3 टक्के हा रेट आहे. औरंगाबादमध्ये 286.2 टक्के शहरी विभागाचा रेट आहे. कोल्हापूरमध्ये या टक्केवारीत वाढ झाल्याची दिसून येते.

याच्या तुलनेत पोलिसांकडून ज्या केसेस डिस्पोज केल्या जातात किंवा ज्या केसमध्ये आरोपींवर चार्जशीट ठेवली जाते. त्याचे सरासरी प्रमाण 64 टक्के इतके आहे. परंतु लातूर, नागपूर यासारख्या शहरामध्ये केसेसचा डिस्पोज रेट चांगला दिसत असला तरी अन्य ठिकाणचा रेट 60 टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 9 टक्के आहे. याचा अर्थ 91 टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा न झाल्यामुळे मोकळे सुटतात. शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाहिले तर चिंता वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. याचे प्रमाण सरासरी 9 टक्के आहे. परंतु नाशिक सारख्या शहराच्या ठिकाणी हे प्रमाण 4.5 टक्के इतके आहे. म्हणजे सरासरीपेक्षाही कमी आहे. नाशिक ग्रामीणमध्ये 4.6 टक्के आहे. लातूरमध्ये 3.8 टक्के, नागपूरमध्ये 4.9 टक्के, अकोल्यामध्ये 1.4 टक्के आहे. मुंबईत 21 टक्के, औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये 7 टक्के, नवी मुंबईमध्ये 4.6 टक्के असे प्रमाण आहे. ही एक आश्चर्याची बाब आहे. कोल्हापूरमध्ये 6 टक्के असे प्रमाण आहे. हे सर्व चित्र पाहिले तर पुणे आयुक्तालयामध्ये याबाबतचे प्रमाण 18.3 टक्के, राज्याचे माननीय गृह मंत्री श्री.आर.आर.पाटील हे सांगली जिल्ह्याचे असल्यामुळे तेथे गुन्हे कमी होण्याचे प्रमाण कमी नसले तरी शिक्षा होण्याचे प्रमाण मात्र 21 टक्के आहे. पुणे ग्रामीणमध्ये ते फक्त 6 टक्के आहे.

सभापती महोदय, आम्ही नेहमी माननीय गृह मंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांची उत्तराची

2....

NTK/ ST/

डॉ.नीलम गोन्हे....

भाषणे ऐकतो त्यांच्या भाषणाचा शेवट आता आम्हालाही पाठ झालेला आहे. त्यामुळे मी आता नवीन मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माननीय गृह मंत्री नेहमी असे सांगत असतात की, पोलिसांची संख्या कमी आहे. पण पोलीस विभागाच्या अहवालातूनच वस्तुस्थिती समोर आली असल्यामुळे त्याचे पुन्हा एकदा स्मरण करून देणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे 135 पोलीस असे प्रमाण आवश्यक आहे. परंतु पुणे शहरामध्ये हे प्रमाण 138 इतके आहे. त्यामुळे एक लाख लोकसंख्येमागे कमी आहे असे म्हणता येणार नाही. पुणे ग्रामीणमध्ये 135 पोलीस पाहिजे त्याऐवजी केवळ 56 आहेत. नाशिक ग्रामीणमध्ये 63, नागपूरमध्ये कागदोपत्री पोलिसांची संख्या 254 आहे. गडचिरोली, नाशिक शहर व अमरावती येथे 170 पेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रात जेथे पोलिसांची संख्या कमी आहे ती शहरे म्हणजे पुणे व औरंगाबाद ग्रामीण ही आहेत. बीड व जालना जिल्ह्यातही ही संख्या कमी आहे.

यानंतर श्री.शिगम....

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3N-1

MSS/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

16:00

डॉ. नीलम गो-हे...

विशेष म्हणजे जेथे 70 पेक्षा कमी पोलीस आहेत असे काही भाग आहेत. पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नगर, सोलापूर, कोल्हापूर या ग्रामीण भागामध्ये 135च्या तुलनेत पोलीसांची संख्या 70 पेक्षा कमी आहे हे शासनाच्याच आकडेवारीवरून दिसून येते.

गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण देखील कमी दिसते, सोलापूर, नाशिक, पुणे या ठिकाणी प्रकरणांचा निपटारा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. आयपीसी अंतर्गत कन्व्हिक्शन रेट कमी प्रमाणात दिसून येतो. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की जिल्ह्यातील गुन्हाचे प्रमाण 2007च्या तुलनेत वाढलेले आहे. 2007मध्ये गुन्हाचे प्रमाण 25.2 टक्के होते ते गेल्या 5 वर्षांमध्ये 6.2 टक्क्यांनी वाढलेले असल्याचे दिसून येते. या पोलीस रिपोर्टमध्ये जे शीर्षक वापरण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल असे शब्द वापरण्यात आलेले आहेत. या बाबतीत माझी अशी सूचना आहे की, इम्पोर्टेशन ऐवजी अॅण्टीट्राफिकिंग हा शब्द वापरावा. एखादी निर्जीव वस्तू असेल तर त्या बाबतीत इम्पोर्ट-एक्स्पॉर्ट असे शब्द वापरले जातात. माणसाची अनैतिक स्वरूपाची जी ने-आण केली जाते त्यासाठी अॅण्टीट्राफिकिंग असा शब्द आहे. तेव्हा हे शीर्षक बदलले गेले पाहिजे अशी माझी सूचना आहे.

सभापती महोदय, या ठिकाणी वर्तमानपत्रातील बातम्यावरून बोलले जाते अशी टीका होत असते. ज्या प्रकरणांच्या चौकशीमध्ये मी स्वतः लक्ष घातलेले आहे आणि मी ज्याचा पाठपुरावा केलेला आहे त्या प्रकरणांकडे मी या निमित्ताने माननीय मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधू इच्छिते. पुण्यामध्ये शुभम शिर्केची हत्या झाली. त्या घटनेवरून असे दिसून येते की. पुण्यासारख्या गजबजलेल्या भागामध्ये खंडणीसाठी शाळेत जाणा-या मुलाचे अपहरण केले जाते आणि त्याची निर्दयपणे हत्या केली जाते. शुभम शिर्के प्रकरणी पोलीस आयुक्तालयामध्ये 100 नंबरवर मुलगा गायब झाल्याचे कळविण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, भोसरी पोलीस स्टेशनला तक्रार करा. भोसरी पोलीस स्टेशनने सांगितले की ती आमची हद्द नाही. म्हणजे तक्रारीची दखल घेऊन मुलाचा शोध करण्यामध्ये साडेपाच तासाचा विलंब झाला. त्या विलंबाची भरपाई कोण आणि कशी करणार ? 5.30 वाजता 100 नंबरवर तक्रार केल्यानंतर ताबडतोब कारवाई झाली असती तर

..2..

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3N-2

MSS/ ST/

पूर्वी श्री. खंदारे

16:00

डॉ. नीलम गो-हे...

शुभमचे प्राण वाचले असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे काही घडलेले नाही.

दुसरी घटना अशी आहे की, या ठिकाणी बाळासाहेब सुर्वेचा उल्लेख झालेला आहे. कल्याणी देशपांडे या वेश्या व्यवसायामधल्या दलाली करणा-यावर अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. काही वेळा ट्राफिकर लोकांना सोडून देण्याच्या बाबतीत त्यांच्यावर बरेचसे आरोप झालेले आहेत. याच हिंजवडी पोलीस स्टेशनमध्ये कोकणअधिकारी नावाच्या मुलीचा आणि तिच्या बाळाचा धुराने घुसमटून मृत्यू झाला. लग्नाला 5 वर्षे झालेली होती. तिचा हुंड्यावरून छळ होत होता म्हणून त्या प्रकरणी 498 खाली गुन्हा दाखल करावा यासाठी आमचे कार्यकर्ते पोलीस स्टेशनला जाऊन सांगत होते. जवळ जवळ तीन महिन्यापूर्वी ही घटना घडली आणि एक दीड महिना या प्रकरणी आमचे कार्यकर्ते सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. त्यांना पोलिसांकडून असे सांगण्यात येत होते की त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती आलेली नाही. अहवाल आलेला नाही. हा बाळासाहेब सुर्वे सातत्याने कार्यकर्त्यांना परतवून लावत होता आणि हीच व्यक्ती कल्याणी देशपांडेच्या केसमध्ये लाच घेताना सापडलेली आहे. या निमित्ताने माझी अशी मागणी आहे की, बाळासाहेब सुर्वे याच्या बरोबर ज्या अधिका-यांनी केसेस रजिस्टर करण्यामध्ये दिरंगाई केली मग ते भोसरी पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी असतील किंवा 100 नंबर वरून माहिती दिल्यावर पुढे भोसरी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. पुणे शहरातील कोर्टांमध्ये टोळीयुद्धाच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. साक्षीदारावर गोळीबार करून त्यांना ठार मारण्याच्या घटना घडना घडलेल्या आहेत. धनकवडी परिसरामध्ये टोळीयुद्धाच्या घटना घडलेल्या आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्या मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक यासारख्या शहरामध्ये सातत्याने होताना दिसतात. या सभागृहामध्ये आम्हाला उत्तर दिले होते.

...नंतर श्री. गिते...

डॉ.नीलम गोन्हे..

आणि त्या उत्तरामध्ये सांगण्यात आले होते की, 25 हजार आरोपी पॅरोलवर सुटलेले आहेत. पॅरोलवर सुटलेल्या आरोपींचा शोध घेण्याचे काम सुरु आहे. गेल्या चार पाच दिवसापासून केस गाजते आहे. चित्रपट निर्माता श्री.करणकुमार कक्कड याचे अपहरण करुन त्याची हत्या केली गेली. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला दिसले आहे की, श्री. विजय पालांडे हे त्या आरोपीचे टोपण नाव होते आणि श्री. अरुणकुमार टिकू आणि श्री. करणकुमार कक्कड या दोघांच्या हत्येच्या संदर्भामध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, त्याने अगोदरचा गुन्हा करताना अशाच पध्दतीचा वापर केला होता. अंधेरी मधल्या स्कॉयलॉक सोसायटीमध्ये बाग दाम्पत्याची हत्या केल्यानंतर त्याला जन्मठेप झाली. त्याने परत पॅरोलवर सुटून अशाच प्रकारचा पुन्हा गुन्हा केला.

महोदय, पुणे येथील कोथरुड येथील तन्मय सोसायटीमध्ये दुचाकी चोरी झाली असे श्री.अविनाश देशमुख नावाच्या नागरिकाच्या लक्षात आले. त्यांनी दुचाकी चोरीच्या संदर्भात संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविली आहे. त्यांच्या तक्रार अर्जाची प्रत मी आणलेली आहे. तसेच यासंबंधीची सी.डी.देखील माझ्याकडे उपलब्ध आहे. कॉमन पार्किंगमधून, फाटकाच्या आत मोटार सायकल पार्क केलेली होती. तेथून ती मोटार सायकल चोरीला गेली. त्यासंबंधी ते वार्दे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांच्याकडे सदर पोलीस स्टेशनकडून 2 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. वार्दे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवून आल्यानंतर त्यांना दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास फोन आला. त्यांच्या वडिलांच्या नावावर ही मोटार सायकल होती, त्याच्या नावाने हा फोन आला होता. त्यानंतर त्यांनी सी.सी.टी.व्ही.फुटेज पाहिले. मी देखील स्वतः ते सी.सी.टी.व्ही.फुटेज पाहिले आहे. माननीय गृहमंत्र्यांसाठी त्या फुटेजची मी सी.डी. आणलेली आहे. त्या सी.डी.मध्ये दोन्ही फुटेज आहेत. पोलीस आधी एकदा बघून गेले, त्यानंतर त्या चोराने कागदपत्रे चोरली, कागदपत्रे चोरी झाल्यानंतर सदरील मोटार सायकल पोलीसच उचलून नेताना दिसत आहेत. त्या ठिकाणी पोलीस अधिकारी श्री.ज्ञानेश्वर फडतरे आहेत. त्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले की, पोलीस त्यांचे नियमित काम करीत होते. मला अजूनही स्पष्ट झालेले नाही की, कागदपत्रे चोरीला गेल्यावर ती मोटार सायकल तिकडचीच आहे, तेथील रहिवाश्यांची ती असू शकते, तेथे राहणाऱ्या रहिवाशाने मोटार सायकल त्या ठिकाणी पार्क केली होती काय याबाबतची माहिती सकाळी जाणून न घेता पोलीस त्या ठिकाणी येतात आणि ती मोटार सायकल उचलून

2...



डॉ.नीलम गोन्हे...

टेम्पोमध्ये टाकतात आणि तो टेम्पो तेथून घेऊन जातात. या सर्व गोष्टीचा अर्थ काय काढावयाचा ? प्रत्येक शहरामध्ये जे प्रश्न दिसून येत आहेत, त्यात पोलीस रिफॉर्म सारखा विषय हाताळला गेलेला नाही. त्याचबरोबर वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

महोदय,पोलीस अधिकारी हे तेथल्या तेथे फिरत असतात. प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या लांब अंतराच्या ठिकाणी बदल्या करा असे माझे म्हणणे नाही. जे योग्य असेल, जे नियमाने असेल, ज्याची जशी गुणवत्ता असेल त्याप्रमाणे आपण बदल्या करू शकता. परंतु पुणे जिल्हयात तसेच इतर अनेक जिल्हयात चित्र दिसून येईल की, या पोलीस स्टेशनमधून दुसऱ्या पोलीस स्टेशनमध्ये बदल्या दाखविल्या जातात. खरे तर त्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नसतात. मी निवडणुक आयोगाकडे मागणी केली होती की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खरोखरच बदल्या झाल्या आहेत काय याचा आपण आढावा घ्यावा. पोलीस अधिकाऱ्यांची एका झोनमधून दुसऱ्या झोन मध्ये बदली केली. आपण त्यास बदली म्हणावयाची काय ? ग्रामीण भागातून शहरात आणि शहरातून पुन्हा रेल्वेत अशा प्रकारे बदल्या केल्या जातात. पुणे जिल्हयात आठ-आठ, दहा -दहा वर्षे एकाच ठिकाणी असलेले अनेक पोलीस अधिकारी आढळून येतील. त्या ठिकाणाहून त्यांची बदली होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा परिणाम असा होतो आहे की, वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणात लाचार झालेले दिसून येत आहेत. त्या लाचारीमुळे कोणत्याही बाबतीत ते अधिकारी स्पष्टपणे चौकशी करू शकत नाही.

महोदय,मला वैयक्तिक नावे घेण्यास आवडत नाही. परंतु मला या ठिकाणी सांगितले पाहिजे की, विश्रामबाग पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत प्राण्यांना तपासणीसाठी नेण्याचा प्रकार येथीलच आहे. कोथरुड जेलमधील एका गुन्ह्यातील आरोपीला गाडी चालविण्यासाठी बसविण्यात आले. जंगली महाराज रोडवरून वाहन चालविताना त्या आरोपी असलेल्या वाहन चालकाने कित्येक लोकांना वाहनाचे धक्के दिले आणि तो तेथून निघून गेला. अशा वेळेला स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर पांघरुण घालणे एवढेच काम ए.सी.पी.आणि डी.सी.पी.करीत असतील तर ते खरोखर किती सुस्पष्टपणाने भूमिका घेणार आहेत हा फार मोठा प्रश्न तयार होतो. मोटार सायकल चोरीच्या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर पुणे आयुक्त कार्यालयाकडे याबद्दल चौकशी करण्याची कुठलीही नैतिक किंवा कायदेशीर इच्छाशक्ती शिल्लक राहिलेली नाही की काय असे वाटू लागते.

यानंतर श्री. भोगले...

त्याचबरोबर या सर्व प्रश्नांवर आपण विचार करित असताना मी पुणे शहरातील प्रश्नांबाबत बोलण्याचा प्रयत्न करित आहे.

श्री.जयंत पाटील हे राज्याचे गृहमंत्री असताना पुण्यातील भूखंड माफियाची केस गाजली होती. श्री.आर.आर.पाटील हे राज्याचे गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांना मी या प्रकरणाची माहिती दिली आहे. त्या काळात श्री.सत्यपाल सिंह हे पुण्याचे पोलीस आयुक्त होते. श्री.उज्ज्वल निकम यांची या केसमध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करु अशी शासनाने घोषणा केली होती. एकाच व्यक्तीविरुद्ध 18 केसेस नोंदविलेल्या होत्या. परंतु या केसेस सिव्हिल मॅटर म्हणून नोंदल्या आहेत. गुन्हेगारी पध्दतीने भूखंड बळकावतात म्हणून स्वतः श्री.जयंत पाटील यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. श्री.सत्यपाल सिंह यांची बदली करण्यात येऊन श्रीमती मीरा बोरवणकर यांची पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. आता या घटनेला तीन वर्षे होऊन गेली आहेत. श्रीमती पूर्णिमा प्रभू यांनी भूखंड माफियाबद्दल केस दाखल केली. श्री.उज्ज्वल निकम यांना नेमून कारवाई करु या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही.

सभापती महोदय, कर्वे रोड येथे एक भूखंड आहे. माझ्याकडे एका डॉक्टरांनी तक्रार केली. आमच्या घरावर लोक दगडफेक करावयास लागले आहेत. त्यामुळे आम्हाला संरक्षण द्या. मी ती तक्रार घेऊन विश्रामबाग पोलीस स्टेशनवर गेले. तेथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मॅडम बिल्डर स्वतः इथे आलेला आहे, तुम्ही त्याच्याशी का बोलत नाही? मी म्हटले, बिल्डरशी बोलायला पोलीस स्टेशन ही जागा असू शकत नाही. बोलावयाचे असते तर आमची तक्रार ऐकून घेतली असती. एका सर्व्हे नंबरवर अन्यायाने नाव लागले आहे. तो माणूस गेली 30 वर्षे महापालिकेला टॅक्स भरतो आहे, त्या जागेची मालकी त्याच्याकडे आहे. अशा वेळेला स्पष्टपणे सांगावयाचे झाले तर भूखंडाच्या तक्रारी घेऊन लोक जर का आले तर ती प्रकरणे सिव्हिल मॅटर म्हणून ट्रीट केली जातात. पुण्यामध्ये अशी नवीन कार्यपध्दती तयार झाली आहे. आज सुध्दा भूखंड माफिया असतात ते येऊन स्वतः अगोदर मारामारी करतात, दगडफेक करुन प्लॉट ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये पोलीस अधिकारी देखील सामील असतात. ते अधिकारी असे सांगतात की, लिटिगेशनची केस आहे म्हणून पोलीस मध्ये पडू शकत नाही.

..2..

डॉ.नीलम गोन्हे.....

सभापती महोदय, मध्यंतरी निवडणुकीनंतर प्रचंड कायदा व सुव्यवस्थेबद्दल गोंधळाची स्थिती झाली होती. धनकवडी भागात एक घटना घडली. या घटनेने स्पष्ट चित्र दिसून आले की, पुण्याच्या पोलीस आयुक्त श्रीमती मीरा बोरवणकर या त्यांच्या कामकाजामध्ये अपयशी ठरल्या आहेत. श्रीमती मीरा बोरवणकरांच्या अपयशाचे चित्र आहे तसे चित्र मावळच्या गोळीबारातील श्री.संदीप कर्णिक यांच्याबाबत दिसून आले आहे. घटना घडल्यानंतर चौकशी समिती नेमली जाते, आयोग नेमला जातो. मग पूर्वीच्या गोळीबाराच्या संदर्भातील चौकशी समित्या असतील, आयोग असतील याबद्दल त्यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी काय करतो याचा विचार होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सातत्याने श्रीमती पूर्णिमा प्रभू या भूखंड माफिया यांच्याबद्दल हायकोर्टामध्ये गेल्या आहेत. पोलिसांनी चौकशी करावी म्हणून सातत्याने कोर्ट सूचना देते. प्रत्यक्षात एकही अहवाल कोर्टापर्यंत पोहोचत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सभापती महोदय, श्री.अविनाश देशमुखांचे कोथरुड येथील आणि त्याच भागातील एसीपी यांचे उदाहरण दिले. श्रीमती चित्रा साळुंखे यांना घेऊन मी स्वतः श्री.आर.आर.पाटील यांच्याकडे गेले होते. श्री.के.एल.बिष्णोई हे वरिष्ठ आय.पी.एस.अधिकारी आहेत. त्यांनी कायद्याच्या परीक्षेला बसतो असे सांगूनही ते प्रत्यक्षात गोल्फ क्लबवर हजर होते. याबद्दलचे पुरावे कोर्टात मांडले होते. यांची चौकशी करण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली त्यातील अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून उलट श्री.बिष्णोई यांना विलन चीट दिली. या संदर्भात हायकोर्टाचे आदेश मी स्वतः श्री.आर.आर.पाटील यांना दिले. हे प्रकरण फार गाजले. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, श्रीमती चित्रा साळुंखे तक्रार दाखल करावयास गेल्यावर श्री.अविनाश सोनावणे या आज्ञाद मैदान पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री.सुरेश मराठे यांना चौकशीचे आदेश दिले. इतकेच नव्हे श्रीमती साळुंखे यांनी लेखी कोर्टात सादर केले आहे. श्री.अनिवाश सोनावणे या अधिकाऱ्याने सोन्याची साखळी तिच्याकडून ताब्यात घेतली.

नंतर श्री.खर्चे...

डॉ. नीलम गोन्हे .....

पहिली गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी यांना रोखावयाचे असेल तर पोलीस रिफॉर्म्स करणे आवश्यक आहे, ते शासन कधी करणार याचा खुलासा झाला पाहिजे. दुसरा मुद्दा म्हणजे पोलिसांच्या खूप समस्या आहेत असे बोलले जाते, त्यांना घरबांधणीसाठी कोणतेही कर्ज मिळू शकत नाही, साध्या अधिकाऱ्यांनाही असे कर्ज मिळू शकत नाही या वस्तुस्थितीच्या संदर्भात शासन कोणती भूमिका घेणार हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्याचबरोबर राज्यात पोलिसांची संख्या कमी असल्याचे बोलले जाते परंतु नागपूर व पुणे शहरांमध्ये पोलिसांची पुरेपूर संख्या असताना सुध्दा चांगल्या प्रकारची सुरक्षा नागरिकांना मिळत नाही आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे पोलिसांवर शासनाचा वचकच राहिलेला नाही. पोलिसांची भूमिका "सदरक्षणाय, खलनिग्रहणाय" अशी आहे असे आपण म्हणतो पण आता हेच वाक्य उलट म्हणजे "खलरक्षणाय, सदनिग्रहणाय" असे करण्याची वेळ आली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. त्यानुसार वागले तरी पोलिसांना वाटते की आपल्याला संरक्षण मिळेल. त्यात मग तपासातील त्रुटी, चार्जशीट उशीरा दाखल करणे, आरोपी पळून जाणे, ज्याप्रमाणे ससून रुग्णालयातील नयना पुजारी केसमधील आरोपी पळून गेले होते तसे. त्यानंतर विलंब लागणे हा तर नित्याचाच प्रकार झाला आहे. तसेच महिला व बालगृह, मतिमंद मुलींचा आश्रम असेल किंवा लहान मोलकरणीवर झालेला अत्याचार असेल असे काही विषय महत्वाचे आहेत. प्रामुख्याने पोलिसांनी बालगृहांमध्ये सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने महिला व बालविकास विभागाबरोबर काम करणे आवश्यक आहे, याकडे शासनाचे लक्ष वेधू इच्छिते.

महोदय, नक्षलवाद्यांचा प्रादूर्भाव नागपूर व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सुध्दा जाणवू लागला आहे. या सर्वांमध्ये वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराच्या बरोबर काही निवृत्त पोलीस अधिकारी खाजगीत सांगतात की, पोलिसांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात जातीयवाद सुध्दा चालू आहे. विशेषतः माजी गृह मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांच्या काळात एक लॉबी काम करीत होती आणि आता माननीय श्री. आर.आर.पाटील गृह मंत्री झाल्यापासून वेगळीच लॉबी काम करीत आहे.....अडथळा.....मी कोणत्याही व्यक्तिके नाव घेतलेले नाही, कृपया आपण मला संरक्षण द्यावे.

....2

श्री. किरण पावसकर : सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी जे वाक्य वापरले त्याला माझी हरकत असून जर कोणाचे नाव घ्यावयाचे असेल तर ते त्यांनी नोटीस देऊन सभागृहाच्या पटलावर ठेवावे.

श्री. कपिल पाटील : सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी सभागृहात दोन मंत्र्यांची नावे घेतली आहेत. जर सन्माननीय सदस्यांनी त्याबाबत अगोदर नोटीस दिली असेल तर माझी काहीच हरकत नाही पण नोटीस दिली नसेल तर अशा प्रकारचे हेत्वरोप त्यांना करता येणार नाहीत. त्यांनी जातीच्या संदर्भात लॉबी काम करीत आहे असा उल्लेख केला, अशा प्रकारे त्यांना नोटीस दिल्याशिवाय सभागृहात हेत्वरोप करता येणार नाही.

डॉ. नीलम गोन्हे : महोदय, पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर आमची हद्दच नाही असे सामान्य माणसांना सांगण्यात येते व त्यांना परत पाठविण्यात येते. ....अडथळा.....माझे बोलणे अगोदर पूर्णपणे ऐकून घ्यावे, अशी मी सन्माननीय सदस्यांना विनंती करते. अशा प्रकारे पोलिसांनी वागू नये एवढेच माझे म्हणणे आहे. तसेच माननीय श्री. छगन भुजबळ गृह मंत्री असताना त्यांच्या काळात जे चालत होते आणि आता माननीय श्री. आर.आर.पाटील यांच्या काळात जे प्रकार घडतात....अडथळा.....

श्री. कपिल पाटील : महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांचे भाषण मी लक्षपूर्वक ऐकत आहे. त्यांनी जातीच्या संदर्भात उल्लेख केला. त्यानंतर दोन मंत्र्यांनी नावे घेतली. त्यांना नोटीस दिल्याशिवाय असे बोलता येत नाही, दिली असेल तर माझी हरकत नाही. पण तसे न करता पोलिसांनी जातीयवाद केला असे बोलणे गंभीर आहे म्हणून ते कामकाजातून काढून टाकावे.

श्री. अरुण गुजराथी : महोदय, पोलिसांच्या जातीयवादाबाबत जे बोलले गेले तसेच दोन मंत्र्यांची सुध्दा नावे घेतली गेली हे कामकाजात राहणे योग्य नाही. सन्माननीय सदस्यांना तशाच प्रकारे काही बोलावयाचे असेल तर त्यांनी खाजगीत बोलावे, पण सभागृहात अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे योग्य होणार नाही म्हणून हा भाग कामकाजातून वगळण्यात यावा.

**तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) :** सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी जातीयवाचक जो उल्लेख केला तो व दोन मंत्री महोदयांचे नाव घेतले तो भाग कामकाजातून वगळण्यात येईल.

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मी गुपीझम आणि लॉबी असाही शब्द माझ्या भाषणात वापरला होता. मी असेही म्हणू शकते की, आतापर्यंत जे जे गृहमंत्री होऊन गेले .....

श्री. आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, मी बऱ्याच काळापासून राज्याचा गृहमंत्री म्हणून काम करीत आहे. आपल्या राज्यामध्ये पालिसांना प्रमोशनस हे एसीआर बघून दिले जात असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रमोशन देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी असून त्या कमिटीने शिफारस केलेल्या नावाच्या पलीकडे कोणत्याही गृहमंत्र्यांना जाता येत नाही. खालच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनसाठी अधिकाऱ्यांच्या कमिट्या आहेत. गृहमंत्र्यांना एखाद्या अधिकाऱ्याला प्रमोशन द्यावयाचे असेल तर तो मन मानेल त्या ठिकाणी प्रमोशन देऊ शकत नाही किंवा कोणाला तो पदानवत सुध्दा करू शकत नाही. कायद्याप्रमाणे आपल्या राज्यात प्रमोशन दिली जात असतात. सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी जनरल आरोप करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे कुठल्या मर्जीतील लोकांना प्रमोशनस दिले, नियम डावलून कोणाला पोस्टिंग दिली याची माहिती असेल तर ती त्यांनी उदाहरणासह द्यावी. त्यांचे आव्हान मी ओपनली स्वीकारावयास तयार आहे. माझ्याकडून कोठे काही चुकले असेल तर महाराष्ट्रातील तमाम 10 कोटी जनतेची तत्क्षणी माफी मागेन व हे सदन सांगेन ते करण्यास तयार राहीन. परंतु पोलिसांच्या लॉब्या आहेत, कोणाला खतपाणी घातले जाते असा जनरल आरोप करणे बरोबर नाही. माझ्यापुढे माझे सर्व पोलीस दल एका कलरचे आहे. पोलिसांची जात, धर्म कधीही बघितले जात नाही तर गुणवत्तेला प्रोत्साहन दिले जाते व अलीकडच्या काळात बदल्या व प्रमोशनस गुणवत्तेनुसारच करण्यात आलेली आहेत.

श्री. किरण पावसकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य या सभागृहात जे काही बोलत असतात त्याचा उल्लेख मिडियामध्ये येत असते. काही ठिकाणी प्रसिद्धीसाठी बोलण्याचा काहीना शोक असेल तर ते या ठिकाणी पुरा करीत असतात. पोलीसदल रात्रंदिवस पहारा देत असते त्यामुळेच आपण महाराष्ट्रात सुखात राहत असतो. मुंबईवर हल्ला झाला त्यावेळेस आपण हे सर्व काही बघितले आहे. असे असतांना त्याच पोलीस दलावर आपण आरोप करीत आहात. दोन मंत्र्यांनी काही दले वाटून घेतली आहेत काय ? जाती धर्माच्या आधारावर पोलीस वाटून घेतले आहेत काय? तसेच यासंदर्भात आपल्याला बोलण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे काय ? त्याच पोलीस अधिकाऱ्याने आणि त्याच पोलीस दलाने जर पुण्यामध्ये व्यवस्थित काम केले नसते तर

श्री.किरण पावसकर..

कदाचित् दूरध्वनीवरुन जे संभाषण मिळवले त्यामध्ये बसेस जाळा, ट्रक जाळा असे झाले नसते. कर्तव्यदक्ष पोलीस दलाने जे काम केलेले आहे त्यांना खरे म्हणजे बक्षीस द्यावयाचे की, त्यांच्यावर सभागृहात येऊन आरोप करावयाचे ? अशा पध्दतीने सन्माननीय सदस्यांनी पोलीस दलावर विचार मांडणे हे पोलीस दलासाठी योग्य नाही तसेच पोलीस दलाचा आपण अपमान करीत आहात असे मला वाटते.

श्री. आर.आर.पाटील :सभापती महोदय, विरोधी पक्षात असतांना मी अनेक वेळा टीका केलेली आहे. राजकीय अभिनिवेशातून टीका केली तर मी ते समजू शकतो. परंतु पोलीस दलातील कर्मचारी कोणाच्या तरी लॉबीत सहभागी होतात ही टीका थांबवली गेली पाहिजे. ज्या हेमंत करकरे यांनी या राज्यासाठी व देशासाठी हौतात्म्य पत्करले होते त्यांच्या मृत्यूपूर्वी 8 तास अगोदर त्यांच्यावर कशा पध्दतीची टीका केली जात होती याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ज्याच्यावर आपण टीका करतो ती माणसे आपल्या राज्यासाठी मरण्यासाठी सुध्दा तयार आहेत. म्हणून किमान वर्दीतील माणसांवर टीका करतांना ती जपून केली पाहिजे एवढेच मला म्हणावयाचे आहे.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, पोलीसांच्या कार्यक्षमतेवर सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी कोणतीही टीका केलेली नाही. पोलीस अकार्यक्षम आहे,ते काम करीत नाहीत असा उल्लेख त्यांनी केला नव्हता. त्यांनी फक्त गटबाजीचा उल्लेख केला होता. गटबाजीचा अर्थ जातीचा नव्हता.

यानंतर श्री. भारवि...

श्री.दिवाकर रावते..

येथे त्यांनी गुपीझमचा विषय मांडायचा प्रयत्न केला आहे. आपण एक लक्षात घ्यावे. आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. तेव्हा सरकारच्या संदर्भात अशा प्रकारचे बोलणे हे योग्य की अयोग्य हा नंतरचा भाग आहे. पण ते आपले मंत्री आहेत. आपण येथे सर्वजण उभे राहतात. त्याचा अर्थ असा होतो की, आपले मंत्री कार्यक्षम नाहीत. अकार्यक्षम आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. ते तेवढ्या ताकदीचे मंत्री आहेत म्हणून त्यांनी आता येथे उत्तर दिलेले आहे.

श्री.आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी तसा अर्थ लावू नये. कारण सन्माननीय सदस्या श्रीमती नीलमताई गोन्हे ह्या तरी कुठे कमी आहेत? श्री.रावते साहेब आपण देखील त्यांच्या मदतीला उभे राहिलात. त्या देखील सक्षम आहेत. आपण त्यांच्या मदतीला कशासाठी उभे राहिला आहात ? त्या सक्षम असताना आपण देखील त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलात ना.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, श्री.आर.आर.पाटील यांना मदतीची गरज लागते हे मला कळल्यामुळे बरे वाटले आहे.

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मी माननीय श्री.जयंत पाटील यांचे नाव घेतले होते काय ? मी दोन गृह मंत्री असा उल्लेख केला होता. माझा यात मुद्दा असा आहे की, मला राजकीय लॉबीचेच बोलायचे असते तर मी म्हटले असते की, दोघांची लॉबी असली तरी खरी लॉबी ही माननीय मंत्री श्री.अजित पवार यांचीच आहे. असे मी बोलू शकले असते. पण बोलले नाही. ..(अडथळा).. सभापती महोदय, मला अजून सूचनांकडे यायचे आहे. शिफारशींकडे यायचे आहे. ..(अडथळा).. माननीय सभापती महोदय, मी आपल्याकडे बघूनच बोलते आहे. तरी देखील येथे गडबड करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत देखील मी बोलू शकते. गटबाजीच्या मुद्यासंबंधी माझे असे म्हणणे आहे की, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार आणि राजकीय पक्षपात ....

.....(गोंधळ)...

**तालिका सभापती** : सन्माननीय सदस्यांनी खाली बसावे.



डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, ही कुठली पद्धत आहे ? मी आता काय बोलले आहे?

**तालिका सभापती** : सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोन्हे यांनी कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलावे.

श्री.किरण पावसकर : सभापती महोदय, यांच्या वक्तव्याने समाजाला त्रास होतो, हानी होते.

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, असे आहे की, पोलीस रिफॉर्म्स ..... (अडथळा).... सभापती महोदय, कोणी मला नैतिक अधिकार शिकवू नये. युनियन कडून हप्ते घेतात त्यांना बोलण्याचा काही अधिकार नाही. पक्षातून ज्यांना लाथ मारली जाते ते तात्पुरता आसरा घेत असतात. तेथे तुम्हाला कुत्राच्या छत्री सारखे स्थान आहे हे आम्हाला देखील माहिती आहे. मी पोलीस रिफॉर्म्सच्या मुद्यांवर बोलते आहे. त्यावर बोलत असताना कारण नसताना राजकीय भांडवल करण्यात येत आहे. श्री.रिबेरो.... (अडथळा)... सभापती महोदय, सभागृहात मवालीपणा चालला आहे. आम्ही मांडतो काय आणि ते बोलतात काय ? ही काय पद्धत आहे.

**तालिका सभापती** : माझी सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी खाली बसावे. आपली महत्त्वाच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे. तेव्हा माझी सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोन्हे यांना विनंती आहे की, त्यांनी प्रस्तावातील मुद्यांवरच बोलावे.

श्री.किरण पावसकर : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सन्माननीय सदस्या आता जे काही बोलल्या आहेत त्यावर माझी हरकत आहे.

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, माझे जे भाषण आहे त्यामध्ये हरकत घेण्यासारखे काय आहे ? असे जर चालणार असेल तर आपण मला वेळ वाढवून द्यावा.

श्री.किरण पावसकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या माझे नाव घेऊन बोलल्या आहेत.

डॉ.नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मी नाव घेतलेले नाही.

श्री.किरण पावसकर : सभापती महोदय, त्यांनी म्हटले आहे की, पार्टीतून लाथ मारून काढल्यानंतर. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, मी ज्या पक्षामध्ये आधी होतो तेव्हा माझे नेते स्वतः माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते साहेब होते. मी त्या पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन, सर्व पदांचा राजीनामा देऊन एका नवीन पक्षामध्ये चांगल्या ध्येयधोरणाने, विकासाची कामे

श्री.किरण पावसकर....

करण्यासाठी आलो. माननीय श्री.अजितदादा पवार आणि माननीय श्री.शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाकडे बघून मी इकडे आलो आहे.

यानंतर सरफरे....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/

16:30

श्री. किरण पावसकर...

मला कोणत्याही पक्षाने बोलावून घेतलेले नाही किंवा मी कोणत्याही पक्षामध्ये आमदार होण्यासाठी आलेलो नाही. आपण स्वतः दहा पक्षांमध्ये फिरला तसा मी फिरलो नाही. मी आमदार म्हणून निवडून आलो. मला विश्वास वाटतो की माझा पक्ष या राज्यासाठी काहीतरी चांगले करील म्हणून मी या पक्षामध्ये आलो, आपल्यासारखे दहा पक्षांमध्ये फिरण्याची माझ्यावर वेळ येणार नाही.

डॉ. नीलम गोऱ्हे : आपण आपले पोलीस संरक्षण काढा आणि हिंमत असेल तर रस्त्यावर चला....

(गोंधळ)

(सत्ताधारी पक्षाचे अनेक माननीय सदस्य उभे राहून एकाच वेळी बोलू लागतात.)

श्री. किरण पावसकर : अहो मी तर रस्त्यावरच लडून पुढे आलो आहे....

**तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) :** माननीय सदस्यांनी कृपया आपापल्या जागेवर शांत बसावे.

श्री. आर. आर. पाटील : सभापती महोदय, ज्यांना रस्त्यावरील भाषा बोलावयाची असेल आणि रस्त्यावर येण्याचे आव्हान दिले जात असेल तर त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. एका बाजूला या राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था नाही असे म्हणावयाचे, या राज्याची कायदा व सुव्यवस्था कोण बिघडवीत आहे? या सभागृहामध्ये रस्त्यावर येण्याची आव्हाने दिली जात असतील तर बाहेर काय होत असेल याचा आपण विचार केला पाहिजे. सभापती महोदय, यांनी जर फक्त गप्प बसण्याची, शांतता राखण्याची भूमिका घेतली तर हे राज्य आपोआप शांत होईल.

श्री. अजित पवार : सभापती महोदय, नियम 260 अन्वये एका महत्वाच्या विषयावर माननीय विरोधी पक्षनेते व गटनेत्यांनी चर्चा उपस्थित केली आहे व त्यानुसार ही चर्चा सुरु झाली आहे. परंतु चर्चा सुरु झाल्यापासून एकंदरीत आपण जे पहात आहोत ते बघितले तर मला असे वाटते की, आपण ही चर्चा आता या ठिकाणी थांबवावी आणि या सभागृहामधून निवृत्त होणाऱ्या माननीय सदस्यांना निरोप देण्याचा कार्यक्रम सुरु करावा. आता साडे चार वाजले असल्यामुळे उद्या सकाळी 10 ते 11.30 वाजेपर्यन्त विशेष बैठक घेऊन ही चर्चा करण्यात यावी. आज रात्री

DGS/

16:30

श्री. अजित पवार....

शांतपणे आराम केल्यानंतर कदाचित उद्या चांगल्या प्रकारे चर्चा होऊ शकेल अशी माझी आपणास विनंती आहे. माझ्या या प्रस्तावाला सभागृहाने मान्यता द्यावी अशी विनंती आहे.

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मी माझे म्हणणे दहा मिनिटांमध्ये संपविणार आहे...

(गोंधळ)

श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, आपण आपला निर्णय द्यावा....

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मला या ठिकाणी बोलू न देता माझा वेळ वाया घालविला जात आहे.

(गोंधळ)

श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, आपण निर्णय द्यावा....

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, मी या ठिकाणी शांतपणे माझे म्हणणे मांडीत आहे. यामध्ये पोलीस रिफॉर्म्सचा मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामध्ये निवृत्त झालेल्या पोलीस आयुक्त रिबेरो यांच्यापासून अनेक अधिकार्यांची केंद्र सरकारमार्फत चौकशी होत आहे. या राज्यामधील पोलीस अधिकारी पोलीस महासंचालकाच्या पदावरून निवृत्त होतात त्यांच्या बाबतीत बाहेर चर्चा होत असते. हे पोलीस महासंचालक शासकीय सेवेमधून निवृत्त झाल्यानंतरच आपले मुद्दे जनतेसमोर कां मांडतात? पोलीस यंत्रणेमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी ते आपले म्हणणे लोकांसमोर मांडीत असतात. यामध्ये महत्वाचा भाग असा की, अशा निवृत्त पोलीस महासंचालकांनी व्यक्त केलेले मत त्यावेळी आपण ऐकतो त्यावेळी पोलीस अधिकारी म्हणून मोठ्या हुद्द्यावर काम करीत असतांना त्याची असलेली ऑर्गनायझेशनल मेमरी, त्या हुद्द्यावर काम करीत असतांना बाळगलेली दक्षता या बाबतची माहिती आपल्या पोलीस यंत्रणेसाठी उपयुक्त ठरणार असेल तर तिचा वापर आपल्या यंत्रणेमध्ये होतो किंवा नाही या संदर्भात आपल्यासमोर प्रश्न उभा रहातो.

सभापती महोदय, तिसरा महत्वाचा प्रश्न असा की, श्री. रामराव वाघ यांच्यासारखे काही चांगले अधिकारी पोलीस दलामध्ये आहेत. मला यामध्ये कोणतेही राजकारण आणावयाचे नाही किंवा कोणताही अधिकारी अमुक पक्षाचा आहे असे मी म्हटलेले नाही. आज अँटीकरण ब्युरोचे प्रमुख म्हणून श्री. रामराव वाघ यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. अँटीकरण ब्युरोची अनेक प्रकरणे शासनाकडे पाठविण्यात आलेली आहेत, त्यामध्ये प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकार्याची

DGS/

16:30

डॉ. नीलम गोन्हे....

चौकशी करुन कारवाई करणे आवश्यक असतांना त्या बाबत राज्य शासनाकडे विनंती करुन सुध्दा वर्षानुवर्षे ती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशावेळी एखादा निस्पृह अधिकारी अँटीकरण ब्युरोमध्ये असतांना त्या शूर अधिकाऱ्याला चांगल्या प्रकारची संधी दिली नाही आणि त्यासंबंधीची प्रकरणे अँटी करण ब्युरोकडे तपासासाठी पाठविली नाहीत तर त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे हे कसे सिध्द करणार? सभापती महोदय, पोलिसांच्या बढत्या आणि बदल्या त्याचबरोबर पोलीस रिफॉर्म्सचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडू इच्छिते.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

डॉ.नीलम गोन्हे . . . .

मला सर्व प्रथम असे सांगावयाचे आहे की, आज्ञाद मैदान पोलीस स्टेशनमधील श्री.अविनाश सोनावणेचे निलंबन झाले पाहिजे. पुणे येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात टोळी युद्ध भडकलेले आहे, त्या संदर्भात अनेक अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केला आहे. पाच-सहा वर्षे एकेक अधिकारी हद्द बदलून तिथल्यातिथेच फिरत आहेत आणि याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्या बदल्या झाल्या पाहिजेत. तिसरी बाब निदर्शनास आणून देऊ इच्छिते की, पोलिसांची संख्या व्यवस्थित आहे पण नागपूर, नाशिक सारख्या शहरामध्ये क्राईम रेट हाताळण्यासाठी जरी पोलिसांची संख्या योग्य असली तरी संबंधितांच्या शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे आणि याची कारणे तपासत असताना जेथे-जेथे चार्टशीट मध्ये त्रुटी दिसत आहेत त्या पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत जाऊन चौकशी करावयास पाहिजे याकडे लक्ष वेधावयाचे आहे.

सभापती महोदय, महिला व बालकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलतेचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याबाबतीत आपण पोलीस महानिरीक्षकाचे पद निर्माण केले. आज श्री.अरुण पटनाईक यांचे मी स्टेटमेंट वाचले. त्यामध्ये म्हटलेले आहे की, "लैंगिक छळ करणाऱ्या पोलिसांना जरब बसविणार." विशाखा निकाल पत्रानुसार समित्या तयार करण्यासाठी गृह विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रा-मध्ये सूचना दिल्या. पण पोलीस विभागाकडे या संबंधीच्या तक्रारी येत आहेत. मग साताऱ्याची तक्रार असेल किंवा मुंबई मधील तक्रार असेल किंवा मुंबईमध्ये काही महिला पोलिसांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. तसेच दैनिक लोकसत्ता यांनी चौकट टाकलेली असून त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, वेगवेगळ्या पध्दतीने अश्लील छायाचित्रे काढण्यात आली. सभापती महोदय, ही घटना अतिशय भयंकर आहे. सहाय्यक आयुक्तांनी आपल्याला कसली तरी मिठाई खाण्यास दिली आणि मग मी शुद्ध हरपून बसले, त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांनी अश्लील छायाचित्रे काढली. अशा प्रकारची महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रार केलेली आहे. म्हणून एका बाजूला विशाखा निकाल पत्राच्या अंमलबजावणी बरोबरच याचाही विचार केला पाहिजे की, लहान मुलींचा व्यापार चालतो, त्यात पुण्यातील काही अभिनेत्री देखील या रॅकेटमध्ये सापडलेल्या आहेत. मुंबईमध्ये देखील टिककूच्या केसमध्ये एक मॉडेल सापडलेली आहे. म्हणून चित्रपट आणि गुन्हेगारी यांचे साटेलोटे झाल्याचे आपल्याला सातत्याने दिसत आहे आणि त्यामध्ये सायबर क्राईम याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जात आहे. सभापती महोदय, मी यासंबंधातील सी.डी.आपल्यामार्फत माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब यांच्याकडे पाठविते.

डॉ.नीलम गोन्हे . . . .

सभापती महोदय, मला असे सांगावयाचे की, या सी.डी.मध्ये जे पोलीस अधिकारी दिसत आहेत ते केवळ एका पोलीस स्टेशनचे नाहीत तर कोथरुड पोलीस ठाण्यातील दुसरे अधिकारी सुध्दा यामध्ये आहेत. त्यामुळे ते या मोटर सायकलचे नक्की काय करणार होते? माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांनी कै.करकरे यांचा उल्लेख केला. मी याठिकाणी उल्लेख करते की, पुण्याचे पोलीस उप आयुक्त श्री.मुश्रीफ यांनी श्री.मुलांनीवर आरोप केले होते.श्री.मुश्रीफ हे तर सरळसरळ वेगळ्या विचारांचे आहेत हे त्यांनी त्यांच्या पुस्तकातच म्हटलेले आहे आणि त्याबाबत आमचे मतभेद असतील पण आपल्याला जर ते योग्य वाटत आहे तर श्री.मुश्रीफ यांनी ज्या अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत, त्याबाबतीत श्री.मुश्रीफ यांना बोलविण्यात यावे आणि त्यांनी जे आरोप केले आहेत त्यामध्ये काय वस्तुस्थिती आहे हे तपासून, मग त्या-त्या लोकांवर कारवाई करून आपण त्यासंबंधातील व्हाईट पेपर आमच्यासमोर मांडावा आणि असे झाले तरच पोलीस विभागामध्ये काही काळेकुट्ट नाही असे आम्हाला म्हणता येईल एवढेच मी याठिकाणी सांगू इच्छिते धन्यवाद.

प्रस्ताव प्रस्तुत झाला.

---

. . . .3 यु-3

श्री.चंद्रकांत पाटील (पुणे विभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्था या विषयावर नियम 260 अन्वये सदनमध्ये चर्चा उपस्थित झालेली आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळत असल्याची अनेक उदाहरणे आपण सर्वजण पहात आहोत. खरे म्हणजे गेल्या गुरुवारी ही चर्चा घेण्यात येणार होती, त्यादिवशी एका वर्तमानपत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेसंबंधीच्या बातम्या मी सहजपणे बाजूला काढल्या. त्यावेळी असे दिसून आले की, एका दिवसामध्ये किमान आठ मोठ्या घटना घडलेल्या आहेत. सध्या मुंबईमध्ये अधिवेशन सुरु असतानाच मालाड मध्ये भरदिवसा नटराज मार्केट परिसरामध्ये श्री.पारस परमार नावाच्या व्यापाऱ्या वर खुनी हल्ला झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याच दिवशी कल्याण येथे तीन बांगला देशी लोकांना अटक झाली. तसेच घाटकोपर पूर्व येथे कामराज नगर, गल्ली क्र.105 मध्ये श्री.कन्नन पिल्ले नावाच्या एका तरुणाने गोविंदा नावाच्या तरुणाची हत्या केली.ओशिवरा येथे अरुणकुमार टिककू हत्या प्रकरणात फरारी असलेल्या पलांडेला पोलिसांनी पुन्हा शिताफीने पकडले. पण असे लक्षात आले की, त्यात पोलीस अधिकारीच दोषी होते. त्यामुळे दोन पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि दोन पोलीस शिपायांवर कारवाई करण्यात आली. सांगली येथे परप्रांतीयांची टोळी लॉजवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीमध्ये असताना जेरबंद झाली. तसेच गेल्या सहा महिन्यामध्ये 50 हून अधिक टॅक्सी पळवून त्यातील महत्वाचे पार्ट्स काढून विकणाऱ्या महम्मद युनूसला अटक झाली आहे. अशा प्रकारे एक ना दोन अनेक घटना घडत असल्याचे आपण कोणत्याही दिवसाचे वर्तमान पत्र उघडले तर दिसून येईल.

सभापती महोदय, आजचे वर्तमानपत्र काढले तर त्यामध्ये एक धक्कादायक बातमी असल्याचे दिसून येईल.

यानंतर श्री.बरवड . . .



श्री. चंद्रकांत पाटील .....

आपण आजचे वर्तमानपत्र काढले तर त्यामध्ये 'पोलीस निरीक्षक अखेर निलंबित' अशी अतिशय धक्कादायक बातमी आलेली आहे. लोहारा पोलीस स्टेशन क्षेत्राच्या बाबतीत ही बातमी आहे. त्या घटनेमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर ती गर्भवती झाली. तिच्या आई-वडिलांनी तक्रार केल्यानंतर ती तक्रार नोंदवून घेतली नाही. उलट त्या मुलीला परभणीला नेऊन तिला बाळंत करून गुन्हा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे श्री. ए.ए.नंदूरकर यांना औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. मितेशकुमार यांनी आजच निलंबित केले. एका बाजूने मी हे मान्य करतो की, आपल्याकडे जी काही अपुरी पोलीस यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेच्या सहाय्याने आपण गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करित आहात पण ही गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. बाकीची आकडेवारी सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोन्हे यांनी दिलेली आहे त्यामुळे मी त्याची पुनरुक्ती करणार नाही. परंतु सन 2009 च्या तुलनेमध्ये 2010 मध्ये राज्यातील दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये 4.3 टक्के वाढ झालेली आहे. या प्रस्तावामध्ये दिलेल्या प्रमुख शहरातील दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये 6 टक्के वाढ झालेली आहे. एकूण या नऊ प्रमुख शहरांमध्ये, ज्या ठिकाणी 30 टक्के लोकसंख्या आहे, त्या ठिकाणी एकूण 84 हजार 217 इतक्या दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे असे मला वाटते.

सभापती महोदय, या सभागृहातच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्यामध्ये खूप वेळ गेल्यामुळे मी कमी वेळेमध्ये प्रामुख्याने महिलांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात माझे बोलणे जास्त केंद्रित करणार आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत 2009 च्या तुलनेत 2010 मध्ये 5.7 टक्के वाढ झालेली आहे. म्हणजे 842 गुन्हे जास्त झाले. त्यातील एक दोन गुन्ह्यांच्या प्रकाराचा उल्लेख करावयाचा झाला तर हुंड्यासाठी खून 2008 साली 175 झाले होते तर 2010 साली 214 खून झाले. प्रामुख्याने ज्याच्या बदल आपल्या समाजामध्ये अधिक चिंता निर्माण झाली पाहिजे त्या बलात्काराच्या घटना 2008 साली 1558 झाल्या तर 2010 मध्ये 1599 बलात्काराच्या घटना झाल्या. प्रामुख्याने मुंबई शहरामध्ये 2010 या एका वर्षामध्ये बलात्काराच्या 201 घटना घडलेल्या आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि प्रामुख्याने मुंबई, पुणे,

RDB/

श्री. चंद्रकांत पाटील .....

नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर सारख्या शहरामध्ये हा खूप चिंतेचा विषय झालेला आहे. महिलांसंबंधीच्या घटना का वाढत आहेत ?

सभापती महोदय, एक महिन्यामध्ये सातारा जिल्ह्यामध्ये चार मोठ्या घटना घडल्या. आंतरजातीय विवाह करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुलीला वडिलांनी मारण्याची घटना घडली. पाटण तालुक्यामध्ये एका गावामध्ये एका महिलेला विवस्त्र करून तिची धिंड काढण्याचा प्रयत्न झाला. फलटण तालुक्यामध्ये बलात्काराची घटना घडली. जो विषय सातारा शहरामध्ये गाजत आहे त्या बाबतीत माननीय गृह मंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांच्या उत्तराकडे सातारा जिल्ह्याचे गेले आठ दिवस लक्ष आहे. आम्हाला त्यांना रोज सांगावे लागते की, आज चर्चा झाली नाही. तो विषय म्हणजे एका महाविद्यालयीन तरुणीला एक तरुण खूप त्रास देत होता म्हणून ती पोलीस स्टेशनला तक्रार करावयास गेली. ती तक्रार सोडविली गेली. जो महाविद्यालयीन तरुण मागे लागला होता त्याला पोलिसांनी बोलावून दम दिला आणि त्याचा ससेमिरा थांबला. पण ज्यांची पाश्वभूमीच गुन्हेगारीची आहे आणि ज्यांना एका प्रकरणात दंडाधिकार्यांच्या चौकशीमध्ये निलंबित करण्याचे आदेश दिले पण निलंबित झाले नाही अशा श्री. सिताराम मोरे नावाच्या पोलीस निरीक्षकाने या मुलीच्या मागचा त्या तरुणाचा ससेमिरा थांबविला परंतु हा पोलीस निरीक्षक तिच्या मागे लागला. त्या पोलीस निरीक्षकाने एकूण 20 ते 22 वेळा तिला जे फोन केलेले आहेत, ज्या प्रकारे लगट वाढविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तो समळा संवाद कॅसेटच्या स्वरूपामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे सादर झाला. त्यामध्ये चौकशी समिती नेमलेली आहे. परंतु सातारा जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे या घटनेकडे लक्ष आहे. कारण या महिनाभरातील ही चौथी घटना आहे.

सभापती महोदय, एका बाजूला आपण असे म्हणतो की, महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले ही खूप चांगली बाब आहे. महिला बाहेर पडावयास लागल्या. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये महिला पोलिसांचे लैंगिक शोषण झाले. त्या संदर्भात माननीय गृह मंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी तत्परता दाखवली आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसह अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले.

...3...

RDB

श्री. चंद्रकांत पाटील .....

पण त्यावेळी आपण ज्या सात कमिट्या नेमल्या त्यातील एकाही समितीचा अहवाल नागरिकांसाठी खुला झाला नाही. त्या बाबतीत नेमके काय झाले, कोण दोषी होते ? ज्यांना निलंबित केले त्यातील काही लोक दोषी नव्हते असेही होऊ शकते. पोलिसांवरच हा आरोप करतो असे नाही. परंतु एखादी चौकशी समिती नेमली जाते त्या चौकशी समितीचा अहवाल जर समोर आला आणि त्या अहवालातून जर लोकांच्या लक्षात आले की, अतिशय निःपक्षपातीपणे चौकशी झाली, जे दोषी होते त्यांच्यावर दोषारोपण झाले आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली, तर ते योग्य असते.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.चंद्रकांत पाटील...

2 वर्षे झाल्यानंतरही कोल्हापूरच्या महिला पोलिसांना न्याय मिळत नाही. नियम 260 अन्वये प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना माननीय गृह मंत्र्यांनी श्री.सिताराम मोरे यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली पाहिजे. जे पोलीस चुकीचे वागतात त्यांच्यामध्ये धाक निर्माण होईल. या राज्यातील महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याबाबत या अधिवेशनामध्ये चिंता व्यक्त केली पाहिजे. शासनाने त्याबाबत योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.

सभापती महोदय, ज्या काही घटना घडत आहेत त्यासाठी पोलिसांना दोष देऊन चालणार नाही. या निमित्ताने पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलतीची मी आकडेवारी देऊ इच्छितो. पोलीस कल्याण निधीसाठी व विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या अंशदानामध्ये गेल्या 3 वर्षात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. त्याच्या उलट सन 2011-12 मध्ये धान्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या आसवनीसाठी मूळ तरतूद 1 कोटी रुपये असताना पुरवणी मागण्यांद्वारे 77 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे हा विरोधाभास आहे. सन 2011-12 मध्ये कारागृहाच्या विविध योजनांसाठी मूळ तरतुदीपेक्षा कमी खर्च होईल असे सुधारित अंदाज सांगतात. नक्षलग्रस्त क्षेत्रासाठी 2011-12 या वर्षासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली. सुधारित अंदाजानुसार त्या भागात 5 कोटी 20 लाख रुपये खर्च झालेला आहे. एका बाजूला वेगवेगळ्या घटनांना पोलीस दोषी आहेत असे म्हटले जाते. दुसऱ्या बाजूला या पोलिसांना ज्या सोयी सवलती दिल्या जातात त्यामध्ये गेल्या 3 वर्षात एक रुपयाची सुध्दा वाढ झालेली नाही. त्यांच्या घरांचा विषय प्रत्येक अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला जातो. परंतु याबाबत लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईल असे सांगून तो विषय संपविला जातो.

माननीय गृह मंत्री हे सांगली जिल्ह्यातील असल्यामुळे मी 2-3 घटना सांगून माझे भाषण संपवितो. कोल्हापूर येथील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे माननीय गृह मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. त्या संस्थेच्या रोजच्या कामकाजाशी त्यांचा संबंध नसतो. त्यांच्या कामात ते हस्तक्षेप करीत नाहीत. गृह खाते त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांना शिक्षण संस्थेकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. पण ते ज्या शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत तेथील दोन तरुणांनी गेल्या सहा महिन्यात

2...

NTK/

श्री.चंद्रकांत पाटील....

काही उमेदवारांना नोकरीचे आमिष दाखवून 3 कोटींचे कलेक्शन केलेले आहे. सध्या त्या दोघांच्या अटकेची कारवाई सुरु आहे. त्या दोघांविरुद्ध खटला दाखल झाल्यामुळे ते हायकोर्टामध्ये अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या संदर्भात माननीय गृह मंत्री कोणती कारवाई करणार आहेत ? ते स्वतः त्या शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष असल्यामुळे त्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत की, त्या दोन तरुणांवर कारवाई करणार आहेत ते त्यांनी उत्तरातून सांगितले पाहिजे. ज्यांनी त्या दोघांना पैसे दिले आहेत त्यापैकी एकाने आत्महत्या केली आहे. आपले पैसे वाया गेले आहेत, आपल्याला नोकरी मिळणार नाही या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे शासन अशा तरुणांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी अभय देणार आहे काय ? स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेमार्फत 400 शाळा चालविल्या जातात.

कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. तेथे वेगवेगळ्या टोळ्या काम करीत आहेत. त्याच्यात खुलेआम टोळीयुद्ध सुरु आहे. आर.सी.गँग विरुद्ध भास्कर कांबळे, डॉन ग्रुप, अवधूत माळी विरुद्ध संजय भास्कर, शिवाजी कवाळे हे सगळे राजरोसपणे टोळ्यांमध्ये कार्यरत आहेत आणि राजकीय पक्षांमध्ये मोठमोठी पदेही भूषवित आहेत. त्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने कारवाई केली पाहिजे.

चंदगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मटक्याचा धंदा चालतो. माननीय गृह मंत्री व माननीय गृह मंत्री चंदगडपासून जवळ असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राहतात. त्यामुळे मटक्याला पायबंद घालण्यासाठी योग्य ती कारवाई त्यांनी केली पाहिजे. अनेक पोलीस अधिकारी बदली केल्यानंतरही बदलीच्या ठिकाणी कामावर रुजू होत नाहीत, सध्या कार्यरत असलेले पोलीस स्टेशन सोडत नाहीत. सभापती महोदय, कोल्हापूर जिल्हा महिला पोलिसांचे लैंगिक शोषणाचा विषय, साताऱ्यातील सिताराम मोरे यांच्या निलंबनाची लोकांनीच केलेली मागणी, या सगळ्याच विषयासंबंधी माननीय गृह मंत्र्यांनी ठोस आश्वासन द्यावे अशी मागणी करुन मी माझे दोन शब्द संपवितो.

-----

यानंतर श्री.शिगम....

श्री.किरण पावसकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, नियम 260 अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी उभा आहे.

सभापती महोदय, प्रत्येक अधिवेशनामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेवर चर्चा होते आणि या विषयावर चर्चा केल्या शिवाय अधिवेशन पूर्ण होत नाही. ही एक प्रथा आहे. नियम नाही. आपण मागचा रेकॉर्ड पाहिला तर प्रत्येक अधिवेशनामध्ये ही चर्चा झालेली असल्याचे आपणास दिसून येईल. या चर्चेमध्ये भाग घेत असताना अनेक सन्माननीय सदस्य एकूणच आपल्या व्यवस्थेविषयी बोलले. आपल्या राज्याची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे, गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे, गुन्हेगारीची पध्दत बदलत आहे, सायबर क्राईम वाढत आहेत. जशी लोकसंख्या वाढत आहे तसे गुन्द्यांचे स्वरूप वाढत आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना आज राज्याचे पोलीस खाते हे जनतेसाठी रात्रंदिवस काम करीत असताना त्यांनी जी चांगली कामगिरी केलेली आहे ती देखील समोर येणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी बोलत असताना सन्माननीय सदस्यांनी गुन्द्यांचा उल्लेख करून अजून त्यांचा तपास लागला नाही असे सांगितले. मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो की, आपण तंटामुक्ती गाव योजना आणली. या योजनेला आज मोठ्या प्रमाणावर यश लाभलेले आहे. या यशामध्ये महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाचा मोठा वाटा आहे. या तंटामुक्ती योजनेमध्ये पोलीस दलाने जे काम केले आहे त्याबद्दल आपल्याला पोलीस दलाचे आभार मानावे लागतील. सुरुवातीला या तंटामुक्ती गाव योजनेला लोकांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. परंतु आता प्रत्येकजण माझे गाव तंटामुक्त म्हणून केव्हा जाहीर होईल यासाठी प्रयत्न करताना दिसतो इतका या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे. ही योजना केवळ कागदावरच न राहाता ती वाड्या-वस्त्यांपर्यन्त पोहोचलेली आहे. याचे सर्व श्रेय पोलीस दलाला आणि अधिका-यांना द्यावे लागेल. ही तंटामुक्ती गाव योजना माननीय मंत्री महोदयांनी आणली म्हणून त्यांचे देखील आपल्याला आभार मानावे लागतील.

सभापती महोदय, मुंबई शहराकडे एक औद्योगिक नगरी म्हणून बघितले जाते. या मुंबई शहरामध्ये पूर्वी अनेक गँगस्टरच्या गँग कार्यरत होत्या. या गँगना आणि त्यांच्या कारवायांना आटोक्यात आणण्याचे काम राज्याच्या पोलीस दलाने केलेले आहे. 1980 पासूनची परिस्थिती अशी होती की मरीन लाईन्स येथे एखादा लग्न समारंभ असेल, चांगली सजावट केलेली असेल तर त्या

..2..

श्री. किरण पावसकर...

समारंभामध्ये काही लोकांना धमक्यांचे फोन येत होते. एखाद्याकडे मर्सिडीज गाडी असेल, एखादा कारखानदार असेल तर त्याला धमक्यांचे फोन येत होते. परंतु पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे हे फोन येण्याचे बंद झालेले आहे हे मला येथे आवर्जून सांगावयाचे आहे. या गँगवर पोलिसांनी नियंत्रण आणले नसते तर शहरामध्ये गुन्हेगारीचा भडका उडाला असता.

सभापती महोदय, बारबालांचा विषय फार गाजला होता. या बारबालांच्या संदर्भात दोन्ही बाजूने भूमिका घेतल्या जात होत्या. असंख्य लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे, एक इंडस्ट्री चालते, समाजामध्ये अराजकता माजेल असे बोलले जात होते. तरीही या बारबालांना हद्दपार करण्यात आले आणि त्याचे श्रेय गृह विभागाकडे जाते.

...नंतर श्री. गिते...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3Y-1

ABG/

प्रथम श्री. शिगम

16:55

श्री.किरण पावसकर...

महोदय,पोलीस खात्यातील बदल्याच्या बाबतीत सांगावयाचे झाले तर पूर्वी पोलीस खात्यातील बदल्यांचा कालावधी जवळ आला की, वृत्तपत्रात रकानेच्या रकाने छापून येत होते. काही प्राईम पोलीस स्टेशनस म्हटली जात होती, काही प्राईम विभाग म्हटले जात होते. क्राईम ब्रँच असेल, ॲन्टी करप्शन विभाग असेल, काही पोलीस स्टेशन प्राईम पोलीस स्टेशनस म्हणून ओळखली जात होती. आपण मागील दहा वर्षांचा बदल्यांचा इतिहास पाहिला तर मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत पोलीस खात्याच्या बदल्यासंदर्भात एकही बातमी वृत्तपत्राला छपावी लागली नाही. पोलीस खात्यात मोठया प्रमाणात बदल्या होणार आहेत, त्यात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये शर्यत लागलेली आहे, त्यासाठी कोणाला तरी जाऊन भेटावे लागते आहे, कोणाची तरी शिफारस घ्यावी लागते अशा पध्दतीने बदल्या न होता, अतिशय पारदर्शकता मॅटेन करून अधिकाऱ्यांच्या मागणी प्रमाणे पोस्टिंग दिल्या जात आहेत. मी ही माहिती पोलीस खात्याच्या आस्थापना विभागाच्या बाबतची दिली आहे.

सभापती महोदय, पोलिसांच्या सोयी सुविधा तसेच तसेच पोलिसांना कामाचा खूप ताण असणे, त्यांना कायम स्वरुपी बंदोबस्तांची कामे देण्यात येणे, सणाच्या दिवशी देखील त्यांना बंदोबस्तासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये बोलाविण्यात येणे इत्यादी विषयाच्या बाबतीत आपण सभागृहात अनेक वेळा चर्चा करतो. पोलीस खात्यावर एवढा प्रचंड ताण पडलेला आहे, त्याला कोण जबाबदार आहेत, मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला यास कोण जबाबदार आहे ? आपण सभागृहात चर्चेच्या वेळी अलंकारीक शब्द वापरतो, अतिशय सुसंस्कृतपणा दाखवितो, कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चांगली भाषणे करावयाची. परंतु प्रत्यक्षात पोलिसांचा वर्कलोड कमी न करता उलट प्रत्येक घटनेस पोलिसांना जबाबदार धरले जाते हे बरोबर नाही. 2004 या वर्षी महानगर या वृत्तपत्राचे संपादक श्री.निखिल वागळे यांच्यावर हल्ला झाला होता. 20 नोव्हेंबर, 2009 रोजी आय.बी.एन.लोकमत कार्यालयावर देखील हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यांचे प्रमाण बघितले तर ते हल्ले थांबविण्याची लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी नाही काय ? एकाच गुपकडून, अशा लोकांकडून वारंवार हल्ले केले जात आहेत. परंतु त्या घटनेस जबाबदार धरून पोलिसांकडे बोट दाखवावयाचे. पोलिसांच्या सतर्कतेवर कुठे तरी प्रश्न चिन्ह उभे करावयाचे हे योग्य नाही. 2010 मध्ये माय नेम

2..

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3Y- 2

ABG/

प्रथम श्री. शिगम

16:55



## सभापतीस्थानी माननीय सभापती

श्री. किरण पावसकर...

ईज खान या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या एक विषय पुढे आला होता. त्यावेळी किती तरी पोलीस बळ घेऊन आपल्याला रस्त्यावर उतरावे लागले. श्री. शाहरुख खान यांच्या बंगल्यावर आणि सर्व चित्रपट गृहांवर बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. विनाकारण पोलीस दलाला त्रास सहन करावा लागला. या राज्यात असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून ही कोणाची जबाबदारी आहे अशा प्रकारांबाबतची नैतिक जबाबदारी कोणी स्वीकारणार आहे काय ? दिनांक 28 जानेवारी, 2012 रोजी महाराष्ट्र टाईम्सच्या कार्यालयावर हल्ला करण्यात आला. दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2012 रोजी एका ठिकाणी व्याख्यान सुरु होते, त्या ठिकाणी देखील हल्ला करण्यात आला. आपण कायदा व सुव्यवस्थेवर नेहमी बोलतो. परंतु कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलत असताना मात्र आपण आपली नेमकी भूमिका विसरून जातो. एका पक्षाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण या सभागृहात येऊन बसतो. परंतु सभागृहाबाहेर मात्र आमचे वर्तन वेगळ्या पध्दतीचे असते. त्यामध्ये कुठे वेगळा प्रकार झाला. पोलिसांना घटनास्थळी लाठीचार्ज करावा लागला, पोलिसांनी थोडी कडक भूमिका घेतली तर आपण सभागृहात येऊन पोलिसांवर आपले आक्षेप नोंदवित असतो. अशा घटनांची सर्वस्वी जबाबदारी लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपण सर्वांनी घेण्याची गरज आहे असे मला वाटते.

सभापती महोदय, पोलिसांच्या सुट्या, पोलीस खात्याचे आधुनिकीकरण यासंदर्भात माननीय गृहमंत्र्यांनी या सभागृहात उत्तर दिलेले आहे. 2011 मध्ये मुंबई शहरावर झालेला दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या विविध उपायोजना राज्य शासनाने केलेल्या आहेत. त्या विषयाची माहिती माननीय गृहमंत्र्यांनी सभागृहास दिलेली आहे. गुप्तवार्ता विभाग सक्षम करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गुप्तवार्ता विभाग सक्षम व्हावा म्हणून वेगळी पदे भरली गेली याबाबतची देखील माहिती या ठिकाणी देण्यात आली होती. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणा संदर्भात देखील माहिती दिली होती. मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, मी अनेक पोलीस वसाहतींना भेटी दिलेल्या आहेत. पोलिसांच्या घरांची समस्या हा जटील प्रश्न आहे. पोलीस वसाहतींना आमदार फंडातून काही मदत करता आली तर ती मदत जरूर करतो. इंग्रजांच्या

3...

17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

3Y-3

ABG/

प्रथम श्री. शिगम

16:55

श्री.किरण पावसकर...

काळात बांधण्यात आलेल्या 180 चौरस फुटाच्या खोलीत पोलिसांचे कुटुंब रहात आहे. अतिशय लहान खोल्यांमध्ये पोलीस कुटुंबे रहात आहेत. पोलिसांच्या घरांची समस्या या जटील प्रश्नावर या सदनात गांभीर्याने चर्चा केली पाहिजे. मी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की, एखाद्या शाळेसाठी, एखाद्या संस्थेसाठी भूखंड देतो, त्याप्रमाणे....

**सभापती :** You will be on leg. आता निवृत्त सदस्यांना निरोप देण्यात येईल.

यानंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**पृ.शी./मु.शी.: निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना निरोप**

**सभापती** : सन्माननीय सदस्यांना याची कल्पना आहे की, या सभागृहाचे दहा सन्माननीय सदस्य येत्या 31 मे, 21 जून व 7 जुलै, 2012 रोजी निवृत्त होणार आहेत. निवडून आलेल्या दहा सदस्यांना नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे भावपूर्ण निरोप देण्याच्या निमित्ताने विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या पोर्चमध्ये एकत्रित छायाचित्र काढण्याचा व त्यानंतर विधानभवनातील दुसऱ्या मजल्यावरील विधानपरिषद सभागृहाच्या लॉबीमध्ये चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. कृपया सर्वांनी उपस्थित रहावे.

सर्वश्री अनिल दत्तात्रय तटकरे, दिलीप दगडोजीराव देशमुख, सुरेशदादा देशमुख, जगदीश मोतीलाल गुप्ता, जैनुद्दीन मोहसीनभाई जव्हेरी, जयवंतराव पुंडलिकराव जाधव, संजय मुकुंद केळकर, डॉ.दीपक रामचंद्र सावंत, सर्वश्री कपिल हरिश्चंद्र पाटील, प्रा.दिलीपराव शंकरराव सोनवणे हे दहा सन्माननीय सदस्य निवृत्त होणार आहेत.

श्री.आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, याची जी प्रोसीजर आहे त्याला माझी हरकत आहे. हरकत अशा अर्थाने आहे की, यातील काही माननीय सदस्यांना निवृत्त होण्यास अजूनही महिना ते दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. इतक्या अगोदरच त्यांना निरोप घ्यायला आपण एवढे उत्सुक का आहोत? तसे पाहता निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांपैकी कोणीही निरोप घ्यायला उत्सुक असत नाही. कारण त्यांना पुन्हा सभागृहात यायचे असते. आज निरोप दिला आणि जर पुन्हा ते निवडून आले तर आपल्या सगळ्यांचे प्रयत्न वाया जातील. ते पुन्हा निवडून आले तर त्यांना निरोपाचे दिलेले पान आणि भाषण परत घेता येत नाही. प्रोसिडिंगवरून देखील ते काढून घेता येत नाही. एकदा निरोप दिला आणि ते जर पुन्हा सभागृहात निवडून आले तर भावी पिढीला काय वाटेल? म्हणून या प्रोसीजरमध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे.

**सभापती** : सन्माननीय मंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांनी अत्यंत प्रेमाचा हरकतीचा मुद्दा मांडला आहे. पुढील पावसाळी अधिवेशन साधारणपणे 10 ते 12 जुलैपासून सुरु होण्यापूर्वी दहा ते बारा माननीय सदस्य निवृत्त होणार आहेत. ते 31 मे, 21 जून व 7 जुलै, 2012 रोजी म्हणजे पुढील अधिवेशनापूर्वी निवृत्त होणार आहेत त्यांना आमदार म्हणून त्यांनी जी कारकीर्द केली

..2..

सभापती.....

त्याबाबत त्यांना आज आपण अधिकृत निरोप दिला नाही तर पुढील अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी त्यांना निरोप देता येणार नाही. म्हणून हा कार्यक्रम आज आयोजित केला आहे. मांडण्यात आलेला मुद्दा हा गांभीर्याने मांडला आहे असे समजून याबाबत आणखी काय करता येईल का हे जरूर पाहिले जाईल.

--

..3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.अजित पवार (उप मुख्यमंत्री) : सभापती महोदय, विधानपरिषदेचे सन्माननीय सदस्य सर्वश्री अनिल दत्तात्रय तटकरे, दिलीप दगडोजीराव देशमुख, सुरेशदादा देशमुख, जगदीश मोतीलाल गुप्ता, जैनुद्दीन मोहसीनभाई जव्हेरी, जयवंतराव पुंडलिकराव जाधव, संजय मुकुंद केळकर, डॉ.दीपक रामचंद्र सावंत, सर्वश्री कपिल हरिश्चंद्र पाटील, प्रा.दिलीपराव शंकरराव सोनवणे हे अनुक्रमे 31 मे, 21 जून व 7 जुलै, 2012 अशा वेगवेगळ्या तारखांना निवृत्त होणार आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून या सभागृहाचे सदस्य या नात्याने त्यांचा सहवास व सहकार्य आपल्या सगळ्यांनाच लाभले आहे. या सभागृहातील त्यांचा कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केला. सगळ्यांनाच सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी मिळाली नाही. या सभागृहातील सदस्यत्वाची मुदत सहा वर्षांची असते. सहा वर्षांसाठी माननीय सदस्य निवडून येत असतात.

नंतर श्री.खर्चे...

श्री. अजित पवार .....

सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव व श्री. अनिल तटकरे हे पोट निवडणुकीच्या माध्यमातून या सभागृहात फार थोड्या काळासाठी आले आहेत. या सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या परीने अतिशय चांगल्या पध्दतीने काम केले आहे. आताच आमचे सहकारी माननीय श्री. आर.आर.पाटील यांनी सुध्दा काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. परंतु एकंदरित पक्षीय भेदाभेद विसरून त्या भागाचे प्रतिनिधीत्व हे करीत असतात, सामान्य माणसाच्या प्रश्नावर लोक प्रतिनिधी म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन आपला कार्यकाल पूर्ण केला आहे. तसेच या सर्वांनी नेहमीच सभागृहाचे पावित्र्य टिकविण्याचा प्रयत्न आणि सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा नेत्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपणा सर्वांचेच कर्तव्य आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे या कोकणच्या सुपुत्राला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून या सभागृहात येण्याची संधी मिळाली. आताचे माननीय राज्य मंत्री श्री. भास्कर जाधव हे विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर पोट निवडणूक झाली व त्यात श्री. अनिल तटकरे हे निवडून आले आहेत, त्यामुळे त्यांना पूर्ण काळ मिळाला नाही, पण एकंदरित सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांचे प्रतिनिधीत्व त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केले आणि कोकणच्या विकासासाठी तळमळीने प्रश्न सोडविण्याचे काम करीत होते. मला वाटते पुन्हा त्यांना संधी मिळू शकेल आणि ते या सभागृहात येऊ शकतील अशी शुभेच्छा श्री. अनिल तटकरे यांच्या भावी वाटचालीला मी देतो आणि त्यांच्या हातून कोकण व परिसराचा विकास होईल असाही विश्वास व्यक्त करतो.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव देशमुख हे अनेक वर्षे या सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. मधल्या काळात थोड्या गंभीर आजारांना त्यांना सामोरे जावे लागले. कालच आपण बघितले की, लातूर महानगर पालिकेत काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद सत्ता मिळाली आणि हे निर्विवाद बहुमत मिळविण्यात सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव देशमुख यांनी जी भूमिका बजावली त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. श्री. दिलीपराव यांच्याकडे आपण एक शांत आणि प्रफुल्लीत करणारे व्यक्तिमत्व म्हणून पाहतो. मागील काळात मंत्रिमंडळात सुध्दा आम्ही एकत्र काम केले. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री. भाऊसाहेब फुंडकर आणि सन्माननीय

.....2

श्री. अजित पवार .....

सदस्य श्री. जयंत पाटील यांनी आणि आम्ही राज्य सहकारी बँकेत अनेक वर्षे काम केले. तसेच मराठवाड्यातील फार थोड्या सहकारी बँका ज्या चांगल्या चालू आहेत त्यात लातूर जिल्हा सहकारी बँक चांगल्या प्रकारे काम करित आहे.

शासनाने अलीकडच्या काळात साखर कारखाना काढण्यासाठी बंदी आणली होती त्या काळात माननीय श्री. दिलीपराव देशमुख यांनी "रगना" या नावाने ओळखला जाणारा खाजगी साखर कारखाना काढला आणि तो आज चांगल्या प्रकारे चालू आहे. थोडक्यात कोणतीही जबाबदारी चांगल्या प्रकारे पार पाडण्याचे काम माननीय श्री. दिलीपराव देशमुख यांनी केलेले आहे. त्यांचे बंधू माननीय श्री. विलासराव देशमुख यांनी या राज्याचे मंत्री व मुख्य मंत्री म्हणून अनेक वर्षे काम केले आणि आता केंद्रातही त्यांची कारकीर्द चांगल्या प्रकारे चालू आहे. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे गंभीर आजारामुळे सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपरावांना सभागृहात उपस्थित राहता आले नाही पण परमेश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो की त्यांना उत्तम आरोग्य लाभो व त्यांच्या हातून आणखी समाज सेवा घडो अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो.

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्ध झालेले

श्री. अजित पवार ....

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर हे रामभाऊ म्हाळगी यांच्या सारख्या आदर्श लोकप्रतिनिधींच्या विचार आणि संस्कारामध्ये वाढलेले आहेत. त्यांचे विचार फारच चांगले आहेत. आदर्श पंरपरा जपण्याचे ते नेहमी प्रयत्न करीत असतात. श्री. संजय केळकर हे कोकण पदवीधर मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतांना ते व्यवसायाने कर सल्लागार असून त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात खूप तळमळीने काम केलेले आहे. त्यांनी बूट-पॉलीश कामगारांची संघटना उभी केली आहे. त्यांनी खूप सान्या संघटनांमध्ये काम केलेले आहे. एवढे सारे करुन नाटकासाठीही त्यांच्याकडे वेळ असतो. त्यांनी एका पाठोपाठ 4-5 नाटकांचे प्रयोग करुन नाटकामधील विक्रम केलेला आहे. त्यांच्या राजकीय नाटयाचा हा अंक संपलेला असला तरी दुसरा अंक लवकरच ते सुरु करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास काहीच हरकत नाही. अष्टपैलू सदस्य म्हणून सभागृहाला त्यांची उणीव निश्चितपणे जाणवेल.

सभापती महोदय, सभागृहात आरोग्य विभागाचा कोणताही प्रश्न आल्यानंतर सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी विचार मांडले नाही असे कधीच झाले नाही. डॉ. सावंत यांचे व्यक्तिमत्व हे अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्याचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून केलेले आहे. त्यांना सामाजिक प्रश्नाची अचूक जाण व संसदीय कार्यपध्दतीची माहिती असल्यामुळे त्यांची कामगिरी सभागृहात प्रभावीपणे आपल्याला बघावयास मिळाली आहे. ते अभ्यासू आणि उत्तम वक्ता असल्यामुळे त्यांनी उत्तम संसदपट्ट म्हणून छाप पाडल्याचे आपण सर्वांनी बघितले आहे. एकंदरीत वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांनी डॉक्टरेट पदवी मिळवली असल्यामुळे त्यांनी कुपोषण, मलेरिया निर्मूलन, शैक्षणिक व साहित्य क्षेत्रात उल्लखनीय कार्य केलेले आहे. डॉ. सावंत यांनाही आपल्याला आज निरोप द्यावा लागतो आहे. पुढील काळात त्यांचा पक्ष त्यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी सोपवेल आणि त्यांचे सामाजिक कार्य यापुढेही सुरु ठेवण्यास त्यांचा पक्ष विचार करेल असा मला विश्वास वाटतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील हे मुंबई विभाग शिक्षक मतदार संघातून निवडून आले होते. राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी त्यांनी वेळोवेळी



श्री. अजित पवार ....

आवाज उठविल्याचे आपण सर्वांनी बघितले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला चहापानाचा कार्यक्रम असतो त्यावेळेस श्री. कपिल पाटील हे आवर्जून उपस्थित राहत असत. ज्याप्रमाणे विधानसभेचे सदस्य श्री. गणपतराव देशमुख अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला उपस्थित राहतात त्याच प्रमाणे सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील हे सुध्दा उपस्थित राहत असत. त्यांनी आपल्या परीने प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी सुरुवातीला छात्रभारतीच्या माध्यमातून विद्यार्थी नेता म्हणून आपली प्रतिमा तयार केली व नंतर शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून शिक्षकांचा नेता व आता लोक भारतीच्या माध्यमातून जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी जनमानसात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेले आहे. परवा बिहारचे मुख्यमंत्री श्री. नितीश कुमार मुंबईत आले होते त्यावेळी त्यांचा सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला होता.

सभापती महोदय, मला आठवते की, सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी दैनिक आज दिनांकचे संपादक म्हणून झुंजार पत्रकारितेचे दर्शन दिलेले आहे. पत्रकारितेमध्ये बड्या निखिलला छोट्या कपिलने दिलेली झुंज सर्वांनी पाहिलेली आहे. ही झुंज मराठी वाचक आजपावेतो विसरलेले नाहीत.

यानंतर श्री. भारवि...

श्री.अजित पवार...

सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील हे शिक्षक मतदार संघातून निवडून आले आहेत. श्री.पवार साहेबांनी नाशिकला सांगितले होते की, सरपंचाचा मतदार संघ झाला पाहिजे आणि सरपंचाने तेथे प्रतिनिधीत्व केले पाहिजे. त्यानंतर शिक्षक मतदार संघातील सन्माननीय सदस्य हादरले की, आता काय होणार. या बाबत साहेबांनी त्यांची भूमिका मांडली, असे मला वाटते.

18 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी युवकाला आता मतदानाचा अधिकार घटनेने प्राप्त झालेला आहे. शिक्षक मतदार संघातून निवडून यायचे असेल तर 30 वर्षांची वयोमर्यादा आहे. एखादा विद्यार्थी किंवा पत्रकार मतदार संघ निर्माण केला तर श्री.कपिल पाटील यांचे कायमचे काम होऊन जाईल. ते विद्यार्थी मतदार संघात देखील शोभून दिसतील आणि पत्रकार मतदार संघात देखील शोभून दिसतील. शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमीच अतिशय आक्रमकपणे बाजू मांडण्याचे काम माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी केले आहे. त्यांना मी पुढील वाटचालीकरिता मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. इथून पुढे देखील ते असेच काम करत राहतील अशी आशा देखील व्यक्त करतो.

माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव शंकरराव सोनावणे हे नाशिक शिक्षक विभागातून निवडून आले आहेत. ज्यावेळी ते जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी पार्टीचे सदस्य होते त्यावेळी श्री.अरूण गुजराथी साहेब राष्ट्रवादी पार्टीचे प्रांताध्यक्ष होते. त्यांना निवडून आणण्याकरिता त्यांनी देखील त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी देखील आपल्या कारकिर्दीमध्ये शिक्षकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. महत्त्वाच्या चर्चेत अभ्यासपूर्ण असा सहभाग त्यांनी घेतला आहे. वेगवेगळ्या विषयांच्या मुद्देसूद गोष्टी त्यांनी मांडल्या आहेत. ते मुद्दे सभागृहाला पटवून देण्यात देखील यशस्वी झालेले आहेत. शिक्षक व्यवस्थेसमोरील अनेक आव्हानासंबंधी त्यांनी सभागृहासमोर अभ्यासपूर्ण चर्चा केलेली आहे.

मी एक बघितले आहे की, या सभागृहात निवडून आलेली व्यक्ती दोन टर्म तरी राहते. पण ज्यावेळी त्यांनी स्वतःच ठरविले की, मी परत उभा राहणार नाही. त्यांनी दुसऱ्याची शिफारस केली आहे. दुसऱ्याला संधी मिळावी अशा प्रकारची भूमिका आमच्या श्री.दिलीपराव सोनावणे साहेबांनी घेतली आहे. मी त्यांच्या सामाजिक क्षेत्रातील भावी वाटचालीला आपल्या सर्वांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो.

...2

श्री.अजित पवार...

सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंत जाधव हे एक वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली म्हणून येथे आले. सन्माननीय सदस्य डॉ.वसंत पवार हे अतिशय चांगले असे व्यक्तिमत्व होते. ते सभागृहात अतिशय अभ्यासपूर्ण अशी चर्चा करायचे. नियतीच्या पुढे आपले चालत नसल्यामुळे त्यांना अचानक बोलावणे आले.ते गेल्यानंतर एक वर्ष राहिले नसताना देखील ती निवडणूक लागली. त्यामध्ये श्री.जयवंत जाधव या तरुण आणि तडफदार सदस्याला संधी मिळाली. माननीय सदस्य श्री.जयवंत जाधव यांची ही पहिली टर्म आहे. या सभागृहामध्ये नवीन असूनही चांगल्या पद्धतीने आपला उसा उमटविण्याचे काम त्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये हे सभागृह ज्येष्ठांचे, वरिष्ठांचे म्हणून ओळखले जाते. तेथे चांगल्या प्रकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. हे तरुण नेतृत्व राजकारणामध्ये लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने पुढे राहिल याबाबत मला कुठलीही शंका वाटत नाही. पुन्हा त्यांना सहा वर्षे सभागृहामध्ये राहण्याची संधी मिळो अशी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीला देखील आपणा सर्वांच्या वतीने सुयश चिंतितो.

सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेश देशमुख हे परभणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करतात. सन्माननीय सदस्य सर्वश्री.जगदीश गुप्ता, जैनुद्दीन जव्हेरी, यांनी देखील आपल्या परीने लोकांच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभागृहाच्या नियमांचे पालन करून आपले विचार प्रभावीपणे मांडण्यामध्ये ते यशस्वी झाले आहेत. सभागृहातील चर्चेत भाग घेऊन आपण आग्रही भूमिका मांडत आहोत हे देखील दाखवून दिले आहे. या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी येथे केलेल्या सहाकार्या बद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या भावी वाटचालीला सभागृहाच्या वतीने, माझ्या वतीने, सरकारच्या वतीने मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो. धन्यवाद.

.....

श्री.सरफरे....

श्री. विनोद तावडे (विरोधी पक्षनेता) : सभापती महोदय, या सभागृहामधून निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना निरोप देण्याच्या समारंभप्रसंगी माननीय गृहमंत्री श्री. आर.आर. पाटील साहेब म्हणाले की, याला निरोप समारंभ म्हणावयाचा काय? मला असे वाटते की, ज्या माननीय सदस्यांनी आपली अधिकृत टर्म किंवा सहा वर्षांचा कालखंड पूर्ण केला आहे त्यांना शुभेच्छा देण्याचा हा या सभागृहाच्या कामकाजातील एक भाग आहे. निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांपैकी ठिकाणी जातात, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी होत असतात. त्यामुळे या कार्यक्रमाला निरोप समारंभ न म्हणता निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी या सभागृहाचे कामकाज चालवीत आहोत असे मला वाटते. निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांपैकी 10 जण जुलैच्या अधिवेशनापर्यंत राहणार आहेत त्यानंतर विधानसभेमध्ये निवडून आलेले 11 जण निवृत्त होणार आहेत, त्यांपैकी बरेच माननीय सदस्य या सभागृहामध्ये पुन्हा येणार आहेत. त्यामुळे आता आपण निवृत्त होणाऱ्या दहा माननीय सदस्यांना शुभेच्छा देण्याचा कार्यक्रम करीत आहोत.

सभापती महोदय, कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे हे निवडून आले आहेत. ते माननीय मंत्री श्री. सुनील तटकरे यांचे बंधू असले तरी कोकण भागामध्ये त्यांची स्वतःची अशी स्वतंत्र ओळख आहे. त्यांचे शिक्षण क्षेत्रामध्ये असलेले काम, कुडाळ भागामध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळाची त्यांनी केलेली स्थापना, किंवा रायगडच्या परिसरात चालविण्यात येत असलेल्या इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळा व त्या ठिकाणी त्यांचे चालणारे प्रत्यक्ष काम पाहिले तर त्यांची एक स्वतःची सामाजिक व राजकीय अशी ओळख त्या ठिकाणी आहे. ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिबिर आयोजित करणे, ग्रामीण भागातील विशेषतः कोकणातील तरुणांना रोजगाराच्या कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहेत त्यामध्ये ते कशाप्रकारे पुढे जाऊ शकतात या संबंधीचे मार्गदर्शन करणे या दृष्टीने प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याला या विधानपरिषदेमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. मला वाटते की, माननीय श्री. अजित दादांनी व माननीय श्री. भास्कर जाधव साहेबांनी गुहागरची जागा जिंकून माननीय श्री. सुनील तटकरे यांच्या बंधूसाठी ही जागा निर्माण केली याची सुध्दा नोंद होणे महत्वाचे ठरते.

DGS/

17:20

श्री. विनोद तावडे...

सभापती महोदय, या सभागृहामध्ये कोकणचे प्रश्न मांडले जात त्यावेळी माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे यांचे त्यामध्ये असलेले योगदान व त्याचबरोबर सभागृहाच्या बाहेर देखील त्यांचे असलेले योगदान महत्वाचे ठरते. त्यामध्ये पर्यटनाचा विषय असेल किंवा रायगड जिल्ह्यातील जे.टी.चा विषय असेल किंवा अन्य महत्वाचे विषय असतील त्या विषयांची योग्यरितीने मांडणी झाली पाहिजे यासाठी तो विषय ध्यानामध्ये ठेवून ते आग्रहाने मांडीत असल्याचे मी पाहिले आहे. त्यांचा जो रितसर सभागृहामध्ये निवडून आल्याचा कार्यकाल होता तो आता पूर्ण होत असल्यामुळे मी त्यांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो.

सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव देशमुख यांची ओळख म्हणजे लातूरमधील एक चांगला प्रशासक अशी करता येईल. विशेषतः लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन म्हणून त्यांनी केलेले उत्तम काम, त्यानंतर त्यांनी वित्त राज्यमंत्री म्हणून या सभागृहामध्ये अर्थसंकल्प मांडला. आपण सर्वांनी त्या अर्थसंकल्पाची चर्चा सामाजिक न्यायाचे बजेट अशाप्रकारे केली होती. या सभागृहाच्या माननीय नेत्यांनी त्यांच्या तब्येतीविषयी उल्लेख केला. त्यांची सभागृहामधील व सभागृहाबाहेर एखाद्या कार्यक्रमांमधील अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवते. अशावेळी वेगवेगळ्या गोष्टींवर आपल्यासमवेत बोलत राहणे अशाप्रकारचा त्यांचा स्वभाव आहे. माननीय श्री. दिलीपराव देशमुख यांनी लातूरमध्ये केलेल्या कामाबरोबर पुण्याच्या वसंतदादा सहकारी साखर संस्थेमधील त्यांचे योगदान महत्वाचे ठरते. उत्कृष्ट ऊस उत्पादन करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देणे या अॅक्टिव्हिटीमध्ये त्यांचा असलेला सहभाग लक्षणीय आहे. मी साखर कारखान्याच्या विषयांमध्ये अॅक्टिव्ह झाल्यानंतर मला त्यांचे हे कार्य पहावयास मिळाले आहे. अशा या सन्मान्य व्यक्तीचे या सभागृहामध्ये आणि या सभागृहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये असलेले योगदान मोलाचे ठरले आहे.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

सन्माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव देशमुख यांना त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल शुभेच्छा देत असताना त्यांनी यशस्वीपणे त्यांच्या आजारावर मात करून त्यांना दीर्घायुष्य मिळावे अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशदादा देशमुख हे सभागृहामध्ये असल्यानंतर परभणी, मराठवाड्याचा विषय आल्यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री जैनुद्दीन जव्हेरी आणि सुरेशदादा देशमुख हे माईक शिवाय सुध्दा बोलू शकतात आणि आमच्या बाजूला बसणारे सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील हे सुध्दा माईकशिवाय बोलू शकतात. या तिन्ही सन्माननीय सदस्यांच्या बाकावरील माईक काढले तरी त्यांचा आवाज खणखणीत असल्याने येथे मांडण्यात आलेला विषय मार्गी लागू शकतो अशा पध्दतीने सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशदादा देशमुख यांचा या सभागृहातील सहभाग हा देखील तेवढाच खणखणीत होता. स्थानिक स्तराच्या नगरसेवक पदापासून ते नगराध्यक्ष पदापर्यंतच्या सगळ्या भूमिका सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशदादा देशमुख यांनी यशस्वीपणे बजावल्या आहेत. मला आठवते की, त्यांनी त्यांच्या भागामध्ये सामुहिक विवाहाचे कार्यक्रम आयोजित केले आणि त्यावेळी आम्हाला देखील निमंत्रित केले होते.अशा प्रकारे त्या भागामध्ये या पध्दतीने सर्वधर्मियांचे सामुहिक विवाह परभणीसारख्या ठिकाणी आयोजित करून अशा उपक्रमांना बढावा देण्याचे काम महत्वाचे आहे असे मी मानतो आणि त्यांनाही मी मनापासून शुभेच्छा देतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जगदीश गुप्ता हे युती शासनाच्या काळामध्ये महसूल राज्यमंत्री होते आणि आमचे अमरावतीचे सक्रीय कार्यकर्तेही होते. सन्माननीय सदस्य श्री.जगदीश गुप्ता यांनी महसूल राज्यमंत्री म्हणून काम करित असताना मी पक्षाचा सरचिटणीस म्हणून त्यांचे काम पाहिलेले आहे. मी त्यांच्याकडे एखादे काम घेऊन गेलो आणि त्यांना सांगितले की, जगदीशजी अमुक-अमुक काम आहे, जरा नीट तपासून पहावे. त्यावेळी श्री.जगदीश गुप्ता म्हणाले की, विनोदजी, आम्ही काय काम आहे ते पहाण्यापेक्षा ते काम कोण घेऊन येतो हेच पहात असतो आणि ज्याअर्थी तुम्ही हे काम आणलेले आहे, त्याअर्थी ते पक्ष म्हणून महत्वाचे आहे. त्या अर्थाने ते नियमानुसार कसे करता येईल याचा प्रयत्न करू.अशा प्रकारे त्यांच्याकडे येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविणे आणि जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी कॉन्फीडन्स वाढविणे म्हणजे यांनी आणलेले काम हे होऊ शकते अशा पध्दतीची भूमिका श्री.जगदीश गुप्ता यांची नेहमीच राहिलेली

आहे. त्यांनाही मी मनापासून शुभेच्छा देतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांच्या बाबतीत सांगावयाचे तर मघाशी म्हटल्याप्रमाणे त्यांचा खणखणीत आवाज आणि विदर्भाविषयी असणारी त्यांची कमिटमेंट प्रकर्षाने दिसून येते. सदानामध्ये आल्यानंतर साधारणपणे कोण-कोण उपस्थित आहेत ते आम्ही पहातो. यामध्ये सुध्दा आम्ही काही जणांना पहातो आणि काहीजणांचे आवाज ऐकून ते सदानामध्ये आले आहेत हे समजते. माननीय सभापती सभागृहामध्ये आल्यानंतर "जय विदर्भ" असा समोरून आवाज आला नाही तर सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांना सदानामध्ये यावयास थोडा उशीर आहे हे आमच्या लक्षात येते. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूला असून सुध्दा जेव्हा माननीय मंत्री महोदय मोघम स्वरूपाचे किंवा चुकीचे उत्तर देतात त्यावेळी जनतेच्या प्रश्नावर पोटतिडकीने उभे राहून बोलणे ही विशेषता मी सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांची पाहिलेली आहे. आपण याच अधिवेशनातील प्रसंग पाहिला तर त्यामध्ये पक्ष आणि पक्ष नेतृत्वाबद्दल असणारी त्यांची जी कमिटमेंट आहे, ती लक्षणीय आहे. त्यावेळी कोणते शब्द उच्चारले गेले तो भाग सोडून देऊ. पण त्यावेळी त्यांचे जे चिडणे होते ते म्हणजे त्यांची पक्ष नेतृत्वावर असणारी श्रध्दा आहे, निष्ठा आहे. त्यातून ज्या सहज अशा भावना व्यक्त होतात आणि मला असे वाटते की, लोक सहजपणे कपडे बदलावेत त्याप्रमाणे पक्ष बदलत असताना सन्माननीय सदस्यांची अशा प्रकारची कमिटमेंट पहावयास मिळणे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि ही बाब सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांच्यामध्ये मी नेहमी पहातो.

सभापती महोदय, अगदी कै.श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या अटकेपासून आंदोलनामध्ये सक्रीय असणारे सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांना आपण पहात आहोत. यापुढेही आम्हाला सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांचा खणखणीत आवाज सदानामध्ये ऐकावयास मिळेल, विदर्भातील आवाज अधिक बुलंद होताना दिसेल. फक्त "जय विदर्भ" म्हणण्यापूर्वी "जय महाराष्ट्र" असे म्हणावे असा सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांचा आग्रह सन्माननीय सदस्य पूर्ण करतील. त्यामुळे सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांना शुभेच्छा देत असताना त्यांचा आवाज आवर्जून जनतेसाठी घुमावा अशीच अपेक्षा व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव हे अतिशय हुशार आहेत. त्यामुळे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.अजितदादा पवार यांनी त्यांना पुन्हा येथे येण्याची संधी मिळेल

श्री.विनोद तावडे . . . .

असे म्हटल्यानंतर ते लगेचच कामाला लागणार नाहीत. कारण जोपर्यंत सन्माननीय मंत्री श्री.छगन भुजबळ साहेब सांगणार नाहीत तोपर्यंत सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव कामाला लागतील असे नाही आणि मग दोन्ही बाजूंनी कामाला लागले तर त्यात काही अडचणच नाही. मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते साहेब तत्परतेने बोलले. पण ते लगेच समोर मफलरकडे काय आहे अशा अर्थाने पहात होते.

यानंतर श्री.बरवड . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही



श्री. विनोद तावडे .....

श्री. जयवंतराव जाधव यांना मी कॉलेजच्या स्टुडंट युनियनच्या निवडणुकीपासून पाहतो. कॉलेज जीवनापासून ते सक्रीय राहिलेले आहेत. कॉलेज जीवनापासून ते महापालिका शिक्षण मंडळ आणि इतर विविध प्रकारच्या कार्यक्रम आणि उपक्रमामध्ये मी त्यांची सक्रियता पाहिलेली आहे. जसा एखादा बॅट्समन खेळपट्टीवर आल्यानंतर पहिले दोन ओव्हर्स इकडे तिकडे फिल्डींग वगैरे बघत बघत सावकाश खेळतो, आता आपल्याला काही करावयाचे नाही अशा पध्दतीने खेळतो त्याप्रमाणे सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव या सभागृहात येताना आपल्याला दीर्घकाळ बॅटींग करावयाची आहे अशाच पध्दतीने आले. आपले नाव वर्तमानपत्रात आले पाहिजे अशी घाई त्यांनी केली नाही. पण जेव्हा त्यांनी विषय देण्यास सुरुवात केली त्यानंतर मग त्यांच्या बॅटींगमध्ये सातत्य राहिले. मला असे वाटते की स्टेडी बॅटींग करणाऱ्या श्री. जयवंतराव जाधव यांना पक्षाकडून परत बॅटींगची संधी मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जी काही आकडेवारी दिसते त्यावरून ती संधी त्यांना पुढे मिळू शकेल असे मला वाटते. तशा प्रकारच्या शुभेच्छा मी सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव यांना देतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. संजयजी केळकर हे आमचे सहकारी आहेत. सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर असतील किंवा सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपकजी सावंत असतील, विरोधी पक्षातील जी सेकंड ऑर्डरची बॅटींग असते त्यातील हे दोघेही खंदे खेळाडू होते. पुढचे जे खेळाडू असतात ते जोरात बॅटींग करून मध्येमध्ये बाहेर जातात पण हे दोघे शेवटपर्यंत म्हणजे अर्धा-तास चर्चा संपेपर्यंत थांबणारे असे आमचे खेळाडू आहेत. त्यावेळी सुध्दा जर सन्माननीय सदस्य श्री. विक्रम काळे यांनी चुकीचे वाक्य वापरले तर या ठिकाणी उभे राहण्यासाठी आमचे दोन सदस्य सभागृहात नक्की उपस्थित आहेत. हा विश्वास हे दोघे सभागृहात असताना पहिल्या बाकावर बसणाऱ्या सदस्यांना आहे. श्री. संजयजी केळकर ज्यावेळी निवडणुकीला उभे राहिले त्यावेळी त्यांच्या विरोधामध्ये काही नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाची मक्तेदारी मोडून काढणार अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या होत्या. पण त्यांना मक्तेदारी मोडण्याची संधी न देता श्री. संजयजी केळकर निवडून आले.

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार म्हणाले ते खरे आहे की, श्री. संजयजी

RDB/

श्री. विनोद तावडे .....

केळकर यांचा सर्व क्षेत्रामध्ये वावर होता. विशेष म्हणजे त्यांचा मतदारसंघ एवढा मोठा असताना सर्व भागातील लोकांशी नियमितपणे संपर्क ठेवणे अवघड असते. पण त्यांनी जे वेळापत्रक ठरविले असेल त्यामध्ये जर दर मंगळवारी रत्नागिरीला असावयाचे ठरविले असेल तर दर मंगळवारी ते रत्नागिरीला असणारच. हे त्यांनी सहाही वर्षे पाळलेले आहे. त्या भागातील मतदाराला, सामान्य माणसाला असे वाटते की, हे त्या दिवशी भेटतील आणि त्याप्रमाणे ते भेटतात. श्री. संजयजी केळकर यांना जे सातत्य टिकविता आले ते त्यांच्या राजकारणातील यश निश्चितपणे मानतो. ठाण्यामध्ये आमचे श्री. वसंतराव पटवर्धन, श्री. अशोकराव मोडक किंवा श्री. अरविंदराव पेंडसे यांच्यानंतर सातत्याने या भागात लोकांमध्ये फिरणे, आदिवासी असतील, मच्छीमार असतील, कोकणातील लोक असतील, शहरातील लोक असतील या सगळ्यांमध्ये फिरणारे अशा पध्दतीचे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे. पेण अर्बन बँकेच्या संदर्भातील आंदोलन असेल किंवा आंबा उत्पादकांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न असेल अशा विविध प्रश्नांच्या बाबतीत सन्माननीय सदस्य श्री. संजयजी केळकर यांचे चांगले योगदान नेहमी या सभागृहात राहिलेले आहे. माननीय श्री. डावखरे साहेबांच्या शुभेच्छेने पुन्हा त्यांना या सभागृहात पाहण्याची संधी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण श्री. डावखरे साहेब हे सर्वांचेच पालक असतात. ते त्यांच्या शुभेच्छा त्यावेळी जाहीर करतील.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांच्या बाबतीत आम्ही गमतीने असे म्हणतो की, आमचा आरोग्य मंत्री ठरलेला आहे. खऱ्या अर्थाने आरोग्याच्या संदर्भात काही प्रश्न असतील, लक्षवेधी सूचना असेल किंवा चर्चा असेल आणि जर त्यासंबंधी काही माहिती लागली तर त्याचे आमचे रेडी रेकनर म्हणजे सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत आहेत. केवळ मेडिकल विषयाचीच माहिती नाही तर त्या विषयाच्या संदर्भात त्या गावात, त्या खेड्यात प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे, याची माहिती त्यांच्याकडे असे. ती माहिती ते वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे सांगत नसत तर ते त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन आलेले असत. आदिवासी भागातील कुपोषणाचा विषय अनेक वेळा वर्तमानपत्रातील कात्रणांच्या आधारे त्या ठिकाणी न राहणारे प्रतिनिधी मांडत असतात.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.विनोद तावडे...

परंतु सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत हे मुंबईत विलेपार्ले येथे राहत असतानाही त्या भागामध्ये लोकप्रतिनिधी या नात्याने जाऊन येत. तेथे आपल्या पक्षाच्यावतीने अॅक्टिव्हिटी करीत असताना पक्षाच्या नेतृत्वाला सुध्दा तेथे घेऊन जाणे ही मोठी गोष्ट आहे. अशा प्रकारचे कार्य करीत असताना हाडाचा कार्यकर्ता म्हणून एक प्रतिमा तयार होत असते. सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत यांनी मेळघाट, जव्हार, मोखाडा या सगळ्या भागात त्या त्यावेळी काम केलेले आहे. ते एकदा विधानसभेत निवडून गेले होते. एकदा मुंबई विभाग पदवीधर मतदार संघातून या सभागृहात आले आहेत. त्यांना पुन्हा या सभागृहात येण्याची आवर्जून संधी मिळेल अशा मी शुभेच्छा देतो.

चळवळीतील एखाद्या कार्यकर्त्याला जर विधिमंडळामध्ये संधी मिळाली तर तो त्या संधीचे कसे सोने करू शकतो त्याचे उदाहरण म्हणून सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील त्यांच्याकडे पाहता येईल. ते डहाणूकर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होते आणि मी समोरच्या पार्ले कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होतो. तेव्हापासून आम्ही दोघे एकमेकांना ओळखत आहोत. त्यामुळे आमच्या दोघांमध्ये डहाणूकर कॉलेज चांगले आहे की, पार्ले कॉलेज चांगले आहे या विषयावर गंमतीने वाद होत असे. मी त्यावेळी त्यांना असे म्हणत असे की, डहाणूकर कॉलेज एका विषयाबाबत चांगले आहे. त्यावेळी श्री.कपिल पाटील खूष होत असत. त्यावेळी मी त्यांना असे सांगत असे की, डहाणूकर कॉलेज हे पार्ले कॉलेजच्या समोर आहे, जेथे विनोद तावडे शिकत होते. सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील हे समाजवादी चळवळीशी कमिटेड राहिलेले आहेत. समाजवादी चळवळीतील त्यांचे अनेक मित्र काँग्रेस पक्षात गेले असतील. त्यांनीही त्यांना तसे सुचविले होते. परंतु त्या पक्षात ते गेले नाहीत. त्यांनी स्वतःचा पक्ष तयार केला, स्वतःचे राजकीय अस्तित्व बनविले. चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला बाहेर आंदोलने, मोर्चे, हा नेहमीचा विषय असतो. आपण विधिमंडळामध्ये येऊन हे प्रश्न मार्गी लावू शकतो असे वाटल्यानंतर सभागृहात सदस्य म्हणून काम करीत असताना ते अपेक्षित असते. परंतु सभागृहात येण्यासाठी कोणत्याही पक्षाशी तडजोड करावयाची नाही असे ठरवूनच ते सभागृहात आले. कोणत्याही सन्माननीय सदस्यांनी पददलितांचा विषय मांडल्यावर त्या विषयाच्या मागे राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या....

2...

श्री.विनोद तावडे....

सभागृहात येण्यापूर्वी एक चांगले पत्रकार म्हणून सर्वाना परिचित आहेत. पण खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्य करित राहण्यासाठी त्यांच्या राजकीय आयुष्यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो.

सन्माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव सोनावणे यांनी 1996-97 मध्ये काही काळ चोपडा पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून काम केलेले आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव सोनावणे आणि सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी ही दोन टोके आहेत. हे दोघेही काय बोलले आहेत हे समजण्यासाठी जवळ जाऊन ऐकावे लागते. इतके ते मितभाषी आहेत. परंतु नेहमीच सातत्याने शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लॉबीतही कागदपत्रे घेऊन बसल्याचे मी पाहिलेले आहे. मी काही दिवसांपूर्वी पुणे पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी भेटलो होतो. एखादा विषय घेऊन बोलणे, एखादा विषय 24 तास डोक्यामध्ये ठेवून बोलत राहणे यादृष्टीने आम्ही सन्माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव सोनावणे यांच्याकडे पहात असतो. आपल्या मतदार संघातील लोकांचे प्रश्न कसे सोडविले पाहिजेत, त्यासाठी काय केले पाहिजे, पुढच्या वेळी आपण बोलाल का अशा पध्दतीने ते काम करित असत. मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. निवृत्त होणाऱ्या दहाही सन्माननीय सदस्यांना आपण निरोप न देता शुभेच्छा देऊ या. त्यांच्या व्यक्तिगत, सामाजिक, राजकीय कार्यासाठी सर्व विरोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांच्या वतीने मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो.

-----

यानंतर श्री.शिगम....

श्री. दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, निवृत्त होणा-या सदस्यांना निरोप देणे हा आपल्या सदनातील होणारा एकमेव कार्यक्रम. हा कार्यक्रम म्हणजे सन्माननीय सदस्यांचा सन्मान असतो. आज निवृत्त होणा-या सदस्यांच्या यादीमध्ये 10 सदस्य आहेत. या विधानपरिषदेमधून एक तृतीयांश सदस्य जात असतात आणि एक तृतीयांश सदस्य येत असतात.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे हे या अधिवेशनामध्ये दिसले नाहीत. ते आमच्या मंत्री महोदयांचे सामर्थ्य सांभाळत असावेत. रायगडमध्ये कुठेही गेलो की ते तेथे असतात. ते रायगड जिल्हापरिषदेमध्ये होते. ते या सभागृहामध्ये जास्त बोलले नाहीत. कोकणाचा विषय असला की ते बोलायचे. त्यांचा चेहरा कायम हसतमुख. बाहेर लॉबीमध्ये कधी बसलेले असले तर एखाद दुसरा शब्द बोलायचे. निवृत्त होणा-या सदस्यांचे मतदार संघ वाचले. हे मतदारसंघ खूप प्रबळ आहेत. जळगावच्या निवडणुकी बाबत ज्या भावना व्यक्त केल्या गेल्या त्यावरून हे मतदारसंघ किती वजनदार आहेत हे महाराष्ट्राला कळलेले आहे. त्यासाठी धाडस लागते. अनेकांच्या अंगी असे धाडस असते. त्या धाडसातून बाहेर पडायचे, असे हे मतदारसंघ. सन्माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे हे पुन्हा येथे येतील असे मला वाटते. शेवटी तो त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री. सुरेशदादा देशमुख हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतानापासून त्यांचा आणि माझा संबंध आला. आपल्या विषयाचा प्रचंड अभ्यास. लातूर जिल्ह्याच्या विकासाचा त्यांचा ध्यास आणि तोही पध्दतशीरपणे, आराखडा वगैरे आखून. विकासाची तळमळ असलेले असे श्री. सुरेशदादा देशमुख. मराठवाड्यामध्ये जे जे जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष झाले ते सक्षम असे झाले. येथे आल्यानंतर ते आवर्जून भेटत असत. ते दुर्धर आजारपणामुळे येथे केवळ दोन वेळा येऊन गेले. ते आजारपणातून व्यवस्थित बाहेर पडत अशा शुभेच्छा त्यांना आहेतच. लातूरमध्ये साखर कारखान्याचा विषय असेल, ज्वारी पासून ग्लुकोज तयार करण्याचा प्रकल्प असेल असे विविध प्रकल्प राबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. परभणीमध्ये काँग्रेसपक्षाचे प्राबल्य टिकविण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी काम करणारे असे श्री. सुरेशदादा देशमुख. धाराशिवचा अध्यक्ष त्यांनी विराजमान केला..(अडथळा). शेवटी भीडू कोणता घेतो यापेक्षा सत्ता कोणाकडे रहाते याला महत्व असते. सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव देशमुख आणि माझे वर्षानुवर्षांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. आमचे

..2..

श्री. दिवाकर रावते...

संबंध निरपेक्ष आहेत. ते निवृत्त होत आहेत. ते पुन्हा या सभागृहामध्ये आले तर मला आनंदच आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. सुरेशदादा देशमुख हे आमच्या परभणीचे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी धडाडी दाखवली. तरी श्री. सुरेशदादा देशमुख हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असले तरी त्यांची आणि माझी कायमची मैत्री राहिली. परभणीसाठी मी काही तरी करणार अशी हिंमत असणारे श्री. सुरेशदादा देशमुख या सभागृहामध्ये पुन्हा यावेत अशी आमची इच्छा आहे. परंतु यावेळी ते कठीण दिसते. माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी मनावर घेतले तर सुरेशदादांचे ठीक आहे. कारण राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची संख्या तिकडे वाढलेली आहे. तरीही सुरेशदादांमध्ये येथे येण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यांनी येथे यावे यासाठी माझ्या त्यांना खास शुभेच्छा आहेत.

सन्माननीय सदस्य श्री. जगदीश गुप्ता अमरावतीचे. त्यांनी आणि मी अमरावतीमध्ये एकत्र काम केलेले आहे. आज अमरावतीमध्ये त्यांचे स्वतःचे प्राबल्य आहे. ते दोनदा त्या मतदारसंघातून निवडून आले. श्री. जगदीश गुप्ता हे अमरावतीचे प्रबळ मर्मस्थान. त्यांचा भाजपशी संबंध नसल्यामुळे त्या पक्षाच्या तिकिटावर येणे हा विषय आता त्यांच्यासाठी राहिलेला नाही.

...नंतर श्री. गिते...

असुधारित प्रत / प्रारंभिक रूप

श्री.दिवाकर रावते...

ही बाब उघड आहे. त्यांनी मनावर घेतले तर ते पुन्हा या सभागृहात सदस्य म्हणून येऊ शकतात एवढे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे. त्यांनी त्यांच्या विभागात भरपूर विकासाची कामे केलेली आहेत. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे असे माझे मित्र श्री. जगदीश गुप्ता हे निवृत्त होत आहेत. त्यांना मी शुभेच्छा देतो.

सभापती महोदय, आमचे मित्र सन्माननीय सदस्य जैनुद्दीन जव्हेरी हे देखील निवृत्त होत आहेत. सभागृहात त्यांचा आवाज ऐकला नाही तर आम्हाला चुकल्या सारखे वाटते. सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी हे मराठीत बोलतात. ते जय महाराष्ट्र बोलतात. ते मराठी बोलतात म्हणून वेगळा विदर्भ होत नाही. परंतु सन्माननीय सदस्य हिंमतवान आहेत. त्यांना विधानसभेसाठी उभे रहावयाचे होते, परंतु तो मतदार संघ राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे त्यांना ती संधी मिळाली नाही. काही चमत्कार करुन ते पुन्हा सभागृहात येतील अशी अपेक्षा आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी यांनी आमच्याकडे यावे असे आम्हा सर्वांना वाटते. इकडे आल्यानंतर मूठभर भरुन आम्हाला गोळ्या मिळतील. त्यांची विदर्भाच्या बाबतीत अतिशय निष्ठा आहे. प्रत्येकाने आपल्या पक्षाशी कडवट निष्ठावंत असले पाहिजे. अशी माझी प्रत्येक सदस्यांविषयी धारणा आहे. मी दुसऱ्या पक्षाच्या सदस्यांना कितीही मदत केली तरी मी माझ्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहे. मी उलट सदस्यांना असे सांगतो की, आपल्याला ज्याने मोठे केले आहे, त्याच्याशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे. त्यांच्याशी प्रामाणिक सहिला तर भविष्यात मोठे व्हाल. प्रत्येकाने आपल्या पक्षाशी निष्ठावंत असले पाहिजे. सन्माननीय सदस्यांच्या पक्ष निष्ठेबद्दल दाद हरकत नाही. आजही इंदिरा गांधीचे नाव काढल्यानंतर तेवढ्याच तडफेने ते काम करतात म्हणून आज काँग्रेस पक्ष आणखी त्या ताकदीने उभा राहतो आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. जव्हेरी यांच्याबद्दल आम्हाला नेहमी आदर आहे. त्यांचा आम्हाला अभिमान वाटतो. ते आम्हा सर्वांना हवे हवेसे वाटतात. या सभागृहात ते सदस्य म्हणून येतील याची आम्ही वाट पाहतो आहे. म्हणून त्यांना निरोप का द्यावयाचा असा मला प्रश्न पडतो.

सभापती महोदय, श्री.संजय केळकर हे सभागृहात माझ्या बाजूला बसत असत.पूर्वी तेथे माजी सन्माननीय सदस्य डॉ.अशोक मोडक हे बसत होते. ते निवृत्त झाल्यानंतर मला एक पोकळी निर्माण झाली होती. श्री. संजय केळकरांनी ती पोकळी भरुन काढली आहे. सामान्य माणसांची नस

2..

श्री.दिवाकर रावते...

ओळखणारे, लोकांमध्ये फिरणारे, सामान्यांची व्यथा मांडणारे, तडफ आहे पण तडकूपणा नाही असे एक वेगळे व्यक्तिमत्व सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांचेमध्ये आहे. अफझलखानाच्या समाधीचा मुद्दा उपस्थित झाला की, मला माजी सदस्य डॉ. अशोक मोडक यांची आठवण येते. ते निवृत्त झाले आहेत. परंतु तो मुद्दा सभागृहात आल्यानंतर मला आता सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांची आठवण होते. ते अतिशय निष्ठेने आणि ध्येयाने काम करतात. ते संस्कारीत आहेत त्याबद्दल वादच नाही. ते अतिशय अभ्यासू आहेत, त्यांचा जनसंपर्क देखील दाडंगा आहे या गोष्टी त्यांच्या वक्तव्यातून जाणवतात. या सभागृहात धोरणात्मक बाबी उपस्थित करुन लोकांचा न्याय मिळवून त्यांनी नेहमी प्रयत्न केलेला आहे. कोकणातील पदवीधरांना न्याय मिळवून देण्याबाबत देखील त्यांचा नेहमी कटाक्ष असे. त्यांचे व्यक्तिमत्व असे वेगळे आहे. त्यामुळे ते पुन्हा आपल्यात असतील अशी मला अपेक्षा आहे.

महोदय, डॉ.दीपक सावंत यांच्याबद्दल प्रश्न नाही. ते पुन्हा मुंबई पदवीधर मतदार संघातून निवडून येतील त्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. या सभागृहातील त्यांचे योगदान हे अवर्णनीय आहे.

यानंतर श्री. भोगले...



SGB/

17:50

श्री.दिवाकर रावते.....

माननीय उप मुख्यमंत्री म्हणाले तसेच आहे. ते तेवढे श्रम घेतात. आरोग्याच्या संदर्भातील कोणताही प्रश्न असो, आदिवासी भागातील कुपोषण आणि आश्रमशाळा हा त्यांनी स्वतःचा विषय बनविला आहे. नुकतीच त्यांची पी.एचडी पूर्ण झाली. या प्रश्नामध्ये त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला सुध्दा समर्थपणाने बरोबर घेऊन काम केले. आदरणीय श्री.उध्दवजी ठाकरे हे त्यांच्यासोबत मेळघाटमध्ये गेले होते. ते काही प्रचार करीत नाही. आम्ही करतो हे सांगण्याचा तो विषय नाही. तो सेवेचा विषय आहे. माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत आणि श्री.उध्दवजी ठाकरे तेथे जाणारच. मेळघाटमध्ये त्यांनी आदिवासींच्या सेवेकरिता, कुपोषित बालकांसाठी अद्यावत ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तेथे पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. परंतु तेथील वन खात्याच्या ताब्यात त्या ॲम्ब्युलन्स देऊन आदिवासी समाजाची सेवा करण्याचे कार्य त्यांनी केले आहे. आजही ते स्वतः अनेक दुर्गम भागात जातात, स्वतः पाहणी करतात आणि आपल्या मनाला जे पटते ते या सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये सरकारला धारेवर धरण्याचा विषय नसतो. मला एका गोष्टीचा आनंद होतो की, सभापती महोदय, त्यांच्या या कृतीशील भावनांशी समर्पित होऊन आपणही त्यांना मुद्दा मांडण्याची संधी देता आणि काही वेळेला आपणही सरकारला या गोष्टी करण्यासाठी भाग पाडता. मग आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना, त्या भागात काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या माध्यमातून सहाय्य मिळते तेव्हा आनंद होतो. जे आम्ही काम करतो त्याची जाणीव सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे सामर्थ्य आपल्याकडून मिळत असते. माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत हे पुन्हा निवडून येतील एवढी मी खात्री बाळगतो आणि त्यांना पुनरागमनाच्या शुभेच्छा देतो.

सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांना अचानक लॉटरी लागावी तसे झाले आहे. निकालाच्या दिवशी ते घरी झोपलेले होते. ते निवडून येण्याचा प्रश्न नव्हता. कारण मुंबई विभाग शिक्षक हा मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला होता. त्यांना कोणीतरी सांगितले की, तुम्ही निवडून आला आहात. कमीत कमी मतदान होऊनही ते निवडून आले. जेव्हा प्रचंड मतदान होते त्यावेळी सत्तापालट होत असतो. परंतु कमी मतदान झाल्यानंतर देखील सत्तापालट झाला आणि माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील निवडून आले. ते आमच्या दृष्टीने पत्रकार होते. ते विरोधी पक्षाचे की सत्ताधारी पक्षाचे हे अजूनही कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही.

..2..

श्री.दिवाकर रावते.....

कारण माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील हे कोणाच्या भोवती पिंगा घालीत असतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. ते त्यांच्या शिक्षक भारती पक्षात आहेत की नाही हे त्यांच्या पक्षाला देखील कळत नाही. त्यांनी सत्ताधारी पक्षाची बनवाबनवी केली. सत्ताधारी पक्षाला वाटते ते आमच्या बाजूचे आहेत. ते कोणत्या बाजूचे आहेत हे कळत नाही. मात्र त्यांनी शिक्षकांची कामे करून घेतली. शिक्षकांचे मूलभूत प्रश्न त्यांनी सभागृहात मांडले. त्यांच्या काही प्रश्नाबद्दल मी त्यांच्यासमवेत आहे. शिक्षणसेवक आणि त्यांचे मानधन हा विषय त्यांनी मांडला आणि आपण सगळ्यांनी त्या प्रश्नाला उचलून धरले. माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी सभागृहात अशासकीय विधेयक मांडले आणि तो प्रश्न सत्तारूढ पक्षातर्फे उचलून धरण्यात आला. परिणामी शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढविण्यात आले. शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करण्याचा विषय होता. तो विषय मी प्रथम मांडला होता. तो विषय त्यांनी स्वतःला चिकटवून घेतला. त्याचे कसब त्यांना बरोबर माहित आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत शिक्षकांना वेतन देण्याचा विषय त्यांनी मांडला. परंतु सगळ्या शिक्षकांनी त्यांच्या विरोधात एल्गार करून टाकला. माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी काय केले?

नंतर श्री.खर्चे...

श्री. दिवाकर रावते .....

ज्या प्रमाणे काल सभागृहात शिक्षकांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता तसे करुन सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी शिक्षकांच्या समस्या सोडवित आपला मतदारसंघ तयार केला. मुंबईत आता त्यांचे बस्तान चांगलेच बसलेले असल्याने त्यांचा पराभव करणे आता सोपे नाही, त्यांच्या पुनरागमनाची वाट पाहत असल्याने त्यांना निरोप देण्याची माझी इच्छा नाही पण शुभेच्छा मात्र जरूर देतो.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव सोनावणे हे जरी शिक्षक मतदारसंघातून निवडून आले असले तरी सन्माननीय सदस्य श्री. वसंतराव खोटे सारखे प्रा. बी.टी.देशमुख यांचा मुद्दा न सोडता शिक्षकांच्याच मागण्या मांडतात तसे मात्र श्री. दिलीपराव सोनावणे करीत नाहीत. ते शिक्षकांच्या समस्या तर मांडतातच पण जळगांव जिल्ह्यातील केळीचे नुकसान, अवकाळी पाऊस असो अथवा जलसंधारणापासून प्रत्येक विषयावर ते बोलतच असतात, सामान्य माणसांच्या प्रश्नांवर सुध्दा ते बोलतात. ते पुन्हा या सभागृहात येण्याची चिन्हे नाहीत असे ते म्हणाले. खरे तर असे म्हणण्यासाठी सुध्दा एक प्रकारचे सामर्थ्य लागते. ते पुढे असेही म्हणाले की, मी माझ्या भागातील लोकांची कामे करीन, मी त्यांच्या भावी कार्याला शुभेच्छा देतो.

सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव यांच्या बाबतीत मात्र मला तसे काही दिसत नाही. ते समता कर्मचारी संघटनेचे कार्यकर्ते असल्यामुळे माननीय मंत्री श्री. छगन भुजबळ आपल्यापासून कधीच दूर जाणार नाहीत. आपल्याला या सभागृहात येण्याचा सन्मान मिळाला तो दिवंगत डॉ. वसंतराव पवार यांच्या अकाली निधनाने. नाशिक जिल्ह्याला सापडलेली हे दोन रत्ने होती. त्यात एक म्हणजे दिवंगत डॉ. वसंतराव पवार आणि दुसरे सन्माननीय सदस्य श्री. हेमंत टकले. त्यांच्याकडे विद्वत्ता आणि इतर सर्व काही आहे, त्यांनी आपली बाजू कधी सोडली नाही. त्याप्रमाणेच आमचे मित्र सन्माननीय सदस्य श्री. उल्हास पवार व श्री. हेमंत टकले, या दोघांचे विषय सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर दोघेही बोललेच पाहिजेत, अशी परिस्थिती आहे. ही दोन नावे घेण्याचे कारण म्हणजे ते नाशिकचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला लाभलेले कोंदणातील कर्तृत्ववान हिरे आहेत. त्यांच्या भावी कारकिर्दीला मी शुभेच्छा देतो.

सन्माननीय सदस्या श्रीमती वंदना चव्हाणसारख्या कर्तृत्ववान महिला सभागृहातून निवृत्त झाल्या, अल्प काळासाठी त्या येथे आल्या होत्या.

....2

श्री. दिवाकर रावते .....

त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळेस मी म्हणालो होतो की, त्या पुन्हा या सभागृहात येणार नाहीत, तेव्हा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार म्हणाले होते की, त्यांचे कर्तृत्व खूप मोठे आहे, त्या कदाचित खासदार सुध्दा होतील. तत्पूर्वी त्या पुण्याच्या महापौर झाल्या. त्या जेव्हा महापौर झाल्या तेव्हा मी फोनवरून त्यांचे अभिनंदन केले होते आणि दादा म्हणाल्याप्रमाणे त्या खासदार झाल्या म्हणून श्री. अजितदादा बोलतात तेच होते, पण आज ते काहीच बोलले नाहीत, त्यांनी कोणालाच कमिटमेंट केली नाही, कारण ते बोलतात ते करतातच. सन्माननीय सदस्या श्रीमती वंदना चव्हाण खासदार झाल्यानंतर एकदा आल्या होत्या, त्यांच्या चेहऱ्यावर मला आनंद दिसून आला. त्या नक्कीच दिल्लीत चांगले काम करतील असे मला वाटते. त्याप्रमाणे सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव आपले वय अजून लहान असून भविष्यात आपण आणखी पुढे जाणार आहात. नाशिकमध्ये आपले असे एक स्थान असले पाहिजे, ज्याप्रमाणे माननीय श्री. छगन भुजबळ हे मुंबईतून गेल्यावर नॉलेज सिटीच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये पाय रोवून आहेत.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

असुधारित प्रत / प्रारंभिक

श्री. दिवाकर रावते .....

मा. भुजबळ साहेब आहेत तोपर्यंत डगमगायचे नाही. आज एवढे सारे झाले असले तरी मा. भुजबळ साहेब डगमगले नाहीत. मा. भुजबळ साहेबांबरोबर आम्ही काम केलेले आहे. खांद्याला खांदा लावून लढायचे कसे हे मा. भुजबळांकडून शिकता येते. त्यामुळे भविष्य काळात लढायचे कसे हे सन्माननीय सदस्य श्री. जयवंतराव जाधव यांनी मा. भुजबळांकडून शिकावे. विद्वत्तेने मोठे व्हावयाचे कसे याबाबत मा.भुजबळांचा आपण आदर्श घ्यावा अशी मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. या सभागृहात पुन्हा कोणकोणते सदस्य येऊ शकणार नाहीत याची मला महिती आहे. परंतु बाकीच्यांना शुभेच्छा देतो. सन्माननीय सदस्य श्री. जैनुद्दिन हे पुन्हा या सभागृहात येतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वाना माझ्या वतीने तसेच माझ्या पक्षाच्या वतीने शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.

-----

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. हेमंत टकले (विधानसभेने निवडलेले ) : सभापती महोदय, वरिष्ठ सभागृहातून आज आपले 10 मित्र निरोप घेणार आहेत. मराठीत म्हटले जाते की, घराबाहेर निघतांना "मी जातो" असे कधीच म्हणू नये तर "आता मी येतो" असे म्हणावे. आज निरोप घेणाऱ्या व्यक्तित्वाकडे, त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाकडे, त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे, त्यांनी मिळवून घेतलेल्या न्यायाकडे व त्यांनी सोडविलेल्या समाजाच्या प्रश्नांकडे आपण बारकाईने बघितले तर या प्रत्येकाची एक वेगवेगळी खासीयत सभागृहात आपल्याला अनुभवायास मिळालेली आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे असतील, माझे नाशिकचे सहकारी श्री. जयंतराव जाधव असतील त्यांना विधान परिषद सदस्यत्वाचा अतिशय कमी वेळ मिळाला आहे. परंतु जयंत जाधव सभागृहात आल्याबरोबर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. त्यावेळेला आम्हाला या सदनाच्या पूर्वीच्या सदस्या श्रीमती वंदनाताईची आठवण झाली होती. या सभागृहाचे कामकाज करतांना सभागृहाची जशी रचना आहे त्याप्रमाणे आपण विवक्षित मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी सभागृहात येत असतो. सभागृहात येतांना ज्या लोकांचे आपण प्रतिनिधीत्व करतो तेव्हा त्यांच्याही तुमच्याकडून काही अपेक्षा असतात. त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आपण सभागृहात काय करीत आहोत याकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असते. सर्वसाधारण मतदारसंघापेक्षाही स्पेशलाईज्ड मतदारसंघ तयार होतो त्याची कामगिरी आपल्याला करावी लागत असते. यासाठी आपल्याला अभ्यास, वेळ द्यावा लागतो, आपल्या भागातील लोकांच्या संपर्कात रहावे लागते. हे सर्व करीत असतांना एक प्रकारची तारेवरची कसरत करावी लागत असते. सभागृहाचे कामकाज करतांना आपण काही संघटनांचेही प्रतिनिधीत्व करीत असतो त्यामुळे त्यांचे प्रश्न मार्गी लावतांना आपल्याला काही वेळेला शासनाशी थोडे कठोरपणे वागावे लागते परंतु कामे करून घेण्यासाठी शासनाला पचेल अशा प्रकारे वर्तन करून प्रश्न मार्गी लावावे लागतात.

मला येथे कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख करावयाचा नाही परंतु तरी सुध्दा मला सन्माननीय सदस्य श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी या नावाबद्दल एक वेगळेच आकर्षण आहे. ते केवळ अल्पसंख्याक नाही, तर जो समाज राजकारणात फारसा वावरतांना दिसत नाही अशा बोहरी समाजाचे ते आहेत. बोहरी समाजाची शिकवण मी जवळून पाहिलेली आहे.

यानंतर श्री. भारवि...

श्री.हेमंत टकले..

संघटनात्मक काम कसे करावे याला फार महत्त्व आहे. धर्माचे अधिष्ठान आपण बाजूला ठेवू या. समाजपयोगी काम करणारा हा छोटासा समाज आहे त्याची बांधिलकी असताना श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी सारख्या एका माणसाला या वरिष्ठ सभागृहात काम करण्याची संधी मिळते. मला वाटते की, हा त्या समाजाचा झालेला बहुमान आहे, म्हणून मला त्यांचे विशेष कौतुक वाटते.

सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत यांच्या बदल मला नेहमीच कुतूहल वाटते. ते लॉबी मध्ये भेटल्यावर मी नेहमी विचारतो की, एवढी सगळी माहिती तुम्ही गोळा कशी काय करता ? काही सदस्यांना या सद्नात आल्यानंतर असे वाटते की, आता पुढची सहा वर्षे आरामाचा काळ आहे. थोडासा शांततेने घालवायचा काळ आहे. या सभागृहात वैचारिक आदानप्रदान व्हावे अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष फिल्डवरील जे काम आहे त्याच्याशी फारसा संपर्क नसला तरी हस्तीदंती मनोऱ्यासारखे याचे स्वरूप आहे काय ? याला छेद देण्याचे नेमके काम सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत यांना करताना पाहिले. त्यांनी जे विषय मांडले त्याच्या मूळाशी जाऊन त्याची सोडवणूक केली आहे. ही सोडवणूक करित असताना शासन यंत्रणेतील दोषांकडे अतिशय गांभीर्याने लक्ष वेधून फार मोठे काम केले आहे. त्यांनी वैद्यकीय तसेच शिक्षण क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशराव देशमुख म्हणजे मराठवाड्यातील नेतृत्वाचा जो चेहरा असतो त्या पद्धतीचा हा माणूस आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशराव देशमुख यांच्या समवेत मी काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वभावाची, कामाची, निष्ठेची मला अतिशय जवळून ओळख आहे. आमचे मित्र सन्माननीय सदस्य श्री.दिलीपराव सोनवणे यांच्याकडे बघताना मला नेहमी वाटते की, या सभागृहामध्ये जे जे विषय उपस्थित झाले, त्या वेळी या सगळ्या सन्माननीय सदस्यांनी आपले योगदान चर्चामध्ये ठेवले, प्रश्नांमध्ये दिले, त्यांच्या ज्या जाणीवा होत्या त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडण्याचे काम या सभागृहामध्ये केले. यातील काही जणांना आपण सभागृहामध्ये पुन्हा निश्चितच पाहणार आहोत. त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा अतिशय चांगला उपयोग आपल्याला पुढच्या काळात निश्चितच होणार आहे.

..2

श्री.हेमंत टकेल..

या सर्वांच्या निरोपाच्या वेळी मला एक गोष्ट आठवते. आपण सर्वजण विमान प्रवास हमखास करतो. विमानाची सोय आपल्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेव्हा आपले विमान विमानतळावर उतरते तेव्हा उद्घोषणा केली जाते. आमच्या बरोबर झालेला प्रवास सुखमय झाला. आपण आमच्या कंपनीची निवड केली, त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. पुन्हा आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी. आज निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांच्या बाबतीत देखील मी असेच म्हणेन की, आपणाला पुन्हा एकदा आमच्या बरोबर सहप्रवासी म्हणून प्रवास करण्याची संधी मिळेल. आपण आमच्या बरोबर पुन्हा याल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

ज्यांनी आपल्या स्वयंनिर्णयाने पुन्हा या सभागृहात येणार नाही अशी घोषणा केली आहे, त्या सन्माननीय सदस्य श्री.सोनवणे यांचे मला कौतुक वाटते. आपण जे क्षेत्र निवडले आहे, त्या क्षेत्रात केवळ येथे प्रतिनिधीत्व करणे एवढेच नाही तर त्या पलीकडेही सेवेचा फार मोठा परिघ आपली वाट पहात आहे. तेथे आपण जाणार आहात. दुसऱ्या कुठल्या तरी माध्यमातून या पेक्षा वेगळ्या सभागृहात जाण्याची संधी देखील या कामातून मिळेल. हे सर्व छान चालते असताना कोणाचे तरी स्टेशन येते. त्यामुळे त्यांना त्या गाडीतून उतरावे लागते. आपला प्रवास पुढे चालू राहतो. काही लोक तेथून खुष्कीच्या मार्गाने आपल्या गावाकडे जातात. काही लोक पुढच्या स्टेशनवर आपल्याच गाडीमध्ये येऊन बसतात.

यानंतर श्री.सरफरे...



17-04-2012

( असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही )

4N 1

DGS/DD/

18:10

श्री. हेमंत टकले...

या सर्वानी सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेतला. त्यामध्ये कटु प्रसंग असतील, गोड प्रसंग असतील अशा सर्व आठवणींची मनोरंजक शिदोरी असते ती आपल्या स्मरणात ठेवावी अशी भावना आपणा सर्वांबद्दल आमच्या मनामध्ये आहे. या सभागृहातील प्रत्येक माननीय सदस्यांच्या मनामध्ये ती आहे. या आठवणी आपण जपा आम्ही देखील जपू, आपला पुढील आयुष्यातील प्रवास, राजकारणातील प्रवास ,समाज सेवेतील प्रवास अतिशय उत्तम, चांगला व समाजोपयोगी होईल अशी सदिच्छा व्यक्त करुन माझे भाषण संपवितो.

-----

...2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

**उप सभापती :** सभापती महोदय, या सभागृहामधून निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना निरोप देण्यासाठी जमलो आहोत. या निमित्ताने मी सर्वच माननीय सदस्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करतो. प्रत्येक माननीय सदस्यांबद्दल मी स्वतंत्रपणे बोलणार नाही. परंतु गेली सहा वर्षे सातत्याने किंवा त्याही पेक्षा अधिक काळ या सर्व माननीय सदस्यांच्या कामाबद्दल आम्ही सर्वजण अत्यंत सुपरिचित आहोत. मी या ठिकाणी माझ्या भावना व्यक्त करण्यापेक्षा या सभागृहातील माननीय सदस्यांच्या या सभागृहाबद्दल काय भावना असतील या मी या ठिकाणी सांगणार आहे. सभागृहाचे नेते माननीय श्री. अजित पवार साहेब, माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते व त्याचप्रमाणे माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. विनोद तावडे यांनी मला खास सूचना केली. त्या सूचनेचा मी चांगल्या पध्दतीने या ठिकाणी समाचार घेणार आहे.

सभापती महोदय, गेली कित्येक वर्षे माननीय सदस्यांनी या सभागृहामध्ये काम केले आहे. त्यामुळे आता आपण या सभागृहामधून जाणार आहोत या भावनेने प्रत्येकजण व्यथित होतो. एकप्रकारची आपुलकी, जिव्हाळा आणि गोडवा या सभागृहामध्ये एकमेकांच्या नात्यामध्ये निर्माण होतो. त्यामुळे जाणारे प्रत्येक माननीय सदस्य स्वतःशी काय बोलत असतील याबद्दल मला स्वतःला असे वाटते की, ते असे म्हणत असतील

"तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी "

या ठिकाणी माननीय सदस्य प्रा. दिलीपराव सोनवणे साहेबांनी सांगितले की, मी यापुढे या सभागृहामध्ये येणार नाही. माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते साहेबांनी त्याचा चांगला आढावा घेतला. त्यावेळी आपल्या मनाला असे वाटले असेल की,

"तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना."

ज्यावेळी मला निरोप समारंभ दिला त्यावेळी मी सुध्दा असेच म्हणालो होतो की,

"तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना"

त्यावेळी ती खुर्ची माझ्याकडे पाहून मला म्हणाली की,

"जाओं कहीं भी सनम तुम्हें इसकी कसम, हमें याद रखना"

एवढे म्हटल्यानंतर आमच्या पक्ष श्रेष्ठींनी माझ्याबाबत विचार केला ही वस्तुस्थिती मी याठिकाणी सांगत आहे.

**माननीय उप सभापति**

"तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा"....

राजकारणातील प्रत्येक राजकीय व्यक्ती ही आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षांवर जगत असते. त्यांना पक्षभेद नसतो. प्रत्येकाची टर्म संपते आणि त्यांना या सभागृहामधून जाण्याचा प्रसंग येतो त्यावेळी ते त्या खुर्चीकडे बघून मनामध्ये म्हणत असतात की,

"तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है,

तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है".

असे म्हणण्याची पाळी आपणा सर्वांवरच येते. त्यासाठी आपण सर्वांनी तयारीत असले पाहिजे. सभापती महोदय, काही मंडळी तर इतकी नशीबवान असतात की, न मागता त्यांच्यासमोर खुर्ची येतच असते. ती खुर्ची त्या व्यक्तीकडे बघून म्हणत असते की,

"हमें तुमसे प्यार कितना, ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना"

माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते साहेब मी आपल्याकडे बघून हे म्हणत आहे. आपण गेली कित्येक वर्षे या सभागृहामध्ये आहात, आपण नशीबवान आहात हे मला आपल्याला सांगावयाचे आहे.

सभापती महोदय, या सर्व माननीय सदस्यांनी या सभागृहामध्ये त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. खासकरून माझे मित्र माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून निश्चितपणे जनमानसांवर ठसा उमटलेला आहे. आपण त्यांना या ठिकाणी निरोप देत नाही याचा मी उल्लेख करतो. परंतु एक गोष्ट नक्की आहे की, माझ्या शुभेच्छा या फक्त त्यांच्याच नव्हेतर या सभागृहातील प्रत्येक माननीय सदस्यांच्या पाठीशी आहेत.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

**उप सभापती . . .**

शुभेच्छा आणि सदिच्छांसाठी शासनाचा जी.आर.नसतो, त्या शुभेच्छा मोकळेपणे दिल्या जातात. त्यानुसार आज आपण ज्या सन्माननीय सदस्यांना निरोप देत आहोत त्यांना मी मनमोकळेपणानेच शुभेच्छा आणि सदिच्छा देत आहे. तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांच्या पाठीमागे माझ्या शुभेच्छा निश्चित राहतील. फक्त त्यांना प्रामाणिकपणे उमेदवारी द्यावी एवढेच सांगू इच्छितो.

**सभापती :** आपण सर्वांनी ज्या सन्माननीय सदस्यांना शुभेच्छा दिल्या त्या सन्माननीय सदस्यांना आपले मनोगत व्यक्त करावयाचे असेल तर त्यांनी ते व्यक्त करावे. सन्माननीय सदस्य प्रा.दिलीपराव सोनवणे यांनी आपले मनोगत मांडावे.

. . . .4 ओ-2

प्रा.दिलीपराव सोनवणे (नाशिक विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, सभागृहाचे नेते यांनी निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना निरोप देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या, काहींनी प्रत्यक्ष केल्या किंवा काही जण अव्यक्त चेहऱ्याने निरोप देत आहेत. या निरोपाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी येथे उभा आहे.

सभापती महोदय, लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिरामध्ये आज आम्हाला निरोप दिला जात आहे. अशा वेळी मनामध्ये निश्चितपणे कालवाकालव होत आहे, भावना भरून येत आहेत. सहा वर्षा पूर्वी म्हणजे 2006 मध्ये मला या सदानामध्ये येण्याची संधी मिळाली.या काळामध्ये मला लोकांचे विशेषतः शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची संधी सदानाच्या माध्यमातून मिळाली. मी ज्या उद्दिष्टांसाठी सदानामध्ये आलो ते साध्य झाले आणि आज अतिशय प्रसन्न आणि उदात्त भावनेने सर्वांचा निरोप घेत असताना मला सार्थ अभिमान वाटत आहे. येथे आल्यानंतर सहा वर्षे कशी निघून गेली हे मला कळले नाही. आज या निमित्ताने मला माझ्या नेत्यांच्या बाबतीत निश्चितपणे कृतज्ञता व्यक्त करावी असे वाटते.

सभापती महोदय, 30 वर्षापूर्वी माझ्या लहानशा आचळ गावाला आदरणीय श्री.शरदचंद्रजी पवार साहेब आले होते. माझी विद्यार्थीदशा चुकतीच संपलेली होती.त्यावेळी साहेबांच्या कर्तृत्वाकडे आणि त्यांच्या काम करण्याच्या पध्दतीकडे पाहून आपणही त्या पध्दतीनुसार पुढे जावे असे मला वाटले आणि विशेष म्हणजे मला तशा प्रकारची संधी मिळत गेली. राज्य शासनाचा प्राध्यापक म्हणूनही काम करण्याची मला संधी मिळाली आणि त्यातून खूप काही शिकण्यासही मिळाले. स्वतःची जबाबदारी सांभाळत असताना मी देखील गावाचा कोणीतरी लागतो हे लक्षात घेऊन तेथून मी कामाला सुरुवात केली. त्यानुसार विकास सोसायटी मग गावचा सरपंच, शेतकी संघटनेचा प्रेसिडेंट, पंचायत समितीचा सदस्य, जिल्हा परिषदेचा सदस्य अशा प्रकारे काम करित असताना मला माननीय श्री.शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या आर्शीवादाने जिल्हा परिषदेतून विधान परिषदेमध्ये येण्याची संधी मिळाली. टीडीएस संघटनेच्या माध्यमातून शिक्षक लोकशाही आघाडी सांभाळत असताना मला याठिकाणी काम करण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो.

सभापती महोदय, मला एक प्रसंग आठवतो.आदरणीय श्री.शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या भेटीसाठी जेव्हा मी बारामती मधील गोविंद पार्क गेलो तेव्हा माझ्याबरोबर श्री.प्रकाशभाई मोहाडीकर आणि आमच्या संघटनेचे नेते उपस्थित होते. तेथे गेल्यानंतर साहेबांशी बोलत असताना त्यांनी माझे सगळे बोलणे ऐकून घेतल्यानंतर असे सांगितले की,"तुझी लोकशाही पध्दतीने निवड झालेली आहे.

प्रा.दिलीपराव सोनवणे .....

तुला माझे सहकार्य राहिल परंतु मी ते आज बोलत नाही. माझे संकेत पोहोचतील. मी आदरणीय श्री.अजितदादा पवार यांची माफी मागेन.साहेबांनी जे शब्द म्हटले होते ते मला आजही आठवत आहेत. त्यांनी मला एवढेच सांगितले की, "तुम्ही जा, अजित, दिलीप आणि आर.आर.पाटील यांच्या माध्यमातून माझे संकेत पोहोचतील" आणि त्याचा परिणाम म्हणून मी 13,500 मतांनी या सदन मध्ये निवडून येऊ शकलो. हे सर्व सांगत असताना माझे मन भरून येत आहे. या सदनमध्ये आल्यानंतर आदरणीय सर्वश्री.अजितदादा पवारसाहेब, आर.आर.पाटीलसाहेब आणि छगन भुजबळ साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मला येथे काम करण्याची संधी मिळाली.

सभापती महोदय, मी नेहमी माननीय सभापती साहेबांकडे जात असे. त्यावेळी ते मला प्रश्न कसे लिहावेत ते सांगत असत.

यानंतर श्री.बरवड . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

प्रा. दिलीपराव सोनवणे ....

प्रश्न कसा विचारावयाचा, लक्षवेधी सूचना कशी असावी. मी आदरणीय सभापती महोदयांच्या केबिनमध्ये नेहमी जात असे आणि मला त्या ठिकाणी मार्गदर्शन मिळत असे. मला या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळत असताना माननीय उप सभापती श्री. वसंतराव डावखरे साहेबांची

निश्चितपणे आठवण येते. ते माननीय सभापतींच्या खुर्चीवर असले की, माझा नंबर लागे आणि मला बोलण्याची संधी मिळे. ती संधी मला निश्चितपणे मिळत गेली. सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते साहेबांच्या संदर्भात मला सांगावे लागेल. ते नेहमी म्हणावयाचे की, सोनवणे सर तुम्ही बोला, तुम्ही मांडा, आपले मांडणे बरोबर आहे. ते मला अशा पध्दतीचे प्रोत्साहन देत असताना अनेक वेळा पाहिले. सन्माननीय सदस्य श्री. पांडुरंग फुंडकर साहेबांच्या बाबतीत सुध्दा सांगावेसे वाटते. मी केव्हाही जाऊन भाऊसाहेबांबरोबर चर्चा करित असे. सन्माननीय सदस्य श्री. विनोदजी तावडे, सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील, सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलमताई गोन्हे, श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांच्या संदर्भात मी सांगेन की, माझे सभागृहात काही बोलणे झाले असेल तर माझ्या पाठीवर थाप देण्यासाठी निश्चितपणे त्यांचा हात असावयाचा.

सभापती महोदय, मला आज स्व. गुरुनाथजी कुलकर्णी यांची देखील आठवण होते. सभागृहामध्ये कसे बोलावे, कशा पध्दतीने भाग घ्यावा या बाबतीत नेहमी लॉबीमध्ये मला त्यांचे मार्गदर्शन मिळत असे. आज ते या सभागृहात नसले तरी त्या काळात त्यांचे मार्गदर्शन मला मिळत असे. आदरणीय सदस्य श्री. अरुणभाई गुजराथी हे तर माझे गुरुच आहेत. गावापासून इथपर्यंत सातत्याने भाईंचे मार्गदर्शन मिळत आले. तुम्ही निश्चितपणे या प्रश्नावर बोला, आपल्या भागातील प्रश्न असेल तर तो आपण आवर्जून मांडला पाहिजे अशा पध्दतीचे आमच्या भाई साहेबांचे मार्गदर्शन असावयाचे. आदरणीय सदस्य श्री. उल्हासदादा पवार, आदरणीय प्रा. सुरेश नवले साहेब, सन्माननीय सदस्य श्री. रमेशजी शेंडगे साहेब यांचे देखील सहकार्य मला नेहमी या सभागृहामध्ये मिळत असे. प्रा. बी.टी.देशमुख हे तर या सभागृहातील आमचे नेते होते. निरनिराळे

...2...

RDB/

प्रा. दिलीपराव सोनवणे .....

प्रश्न कसे विचारावे, त्यांची मांडणी कशी करावी या बाबत आम्हाला त्यांच्या रुममध्ये जाऊन खूप शिकावयास मिळे. निरनिराळ्या प्रकारची आयुधे कशी वापरावी, तारांकित प्रश्न असतील, लक्षवधी सूचना असतील, नियम 93 च्या सूचना असतील, औचित्य असेल, अर्धा-तास चर्चा असतील या बाबतीत देखील नेहमी त्यांचे मार्गदर्शन मिळत असे.

सभापती महोदय, या सभागृहात काही अनुभव आले. माझी अर्धा-तास चर्चा लागली पण ती कशी मांडावी हे मला कळत नव्हते. तेव्हा माझ्याजवळ आदरणीय सदस्या डॉ. नीलमताई गोन्हे आल्या आणि त्यांनी सांगितले की, मी माझ्या पध्दतीने तुम्हाला सांगते. त्यांनी मला मार्गदर्शन केले. त्या अर्धा-तास चर्चेमध्ये मला भाग घेण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर माननीय सभापती महोदयांचे आभार मानतो असे म्हणावयास पाहिजे परंतु ते काही मला बोलता आले नाही. ते देखील मला या ठिकाणी शिकावयास मिळाले. अशा प्रकारच्या खूप संधी मला या ठिकाणी मिळाल्या. माननीय सभापती महोदय, मला माहीत आहे की, आपण त्या खुर्चीवर बसून सभासदांकडे पाहता. दोन्ही बाजू आपल्याला सांभाळाव्या लागतात. इकडच्या बाजूकडे आणि तिकडच्या बाजूकडे आपले सगळे लक्ष असते पण आम्ही समोरचे सदस्य वंचित राहून जातो. मी या निमित्ताने विनंती करणार आहे की, या सभागृहात समोर आम्ही जे सदस्य बसतो त्यांना सुध्दा थोडीफार जास्त संधी मिळावी. आपल्याला मर्यादा आहेत हे मला माहीत आहे. मी अनेकदा प्रयत्न करीत असे परंतु शिक्षक असल्यामुळे मी कोठे तरी मर्यादेत राहिलो. मर्यादेच्या संदर्भामध्ये मला तसे वागावे लागले. मी कोठेही माझ्या भावनांचा अतिरेक होऊ दिला नाही परंतु हक्क मिळविण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करीत असताना सभापती महोदय, आपण मला संधी दिली याचा देखील मला आनंद वाटतो.

सभापती महोदय, या सभागृहात अनेक प्रश्न सुटलेले पाहात असताना आणि लोकप्रतिनिधी ते प्रश्न सोडवित असताना मी पाहिलेले आहे. आपले प्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भातील तळमळ मी आमच्या सदस्यांमधून अनुभवली. लोकप्रतिनिधी कसा असावा, लोकप्रतिनिधीने कशा पध्दतीने आपला प्रश्न मांडावा या बाबतीत मला अनेकदा खूप शिकण्याची संधी मिळाली. ही संधी मिळत असताना दोन्ही बाजूकडून मला प्रोत्साहन मिळत गेले आणि मला या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये



RDB/

प्रा. दिलीपराव सोनवणे .....

भाग घेण्याची संधी मिळत गेली. याचे सारे श्रेय या सभागृहातील माझ्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना आहे असे मी मानणारा आहे.

शिक्षक आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या संदर्भामध्ये निरनिराळ्या पध्दतीच्या चर्चा या ठिकाणी होऊ लागल्या. या संदर्भामध्ये अनेकदा सभागृहात विषय निघाला. शिक्षकांच्या किंवा शिक्षणाच्या प्रश्नावर मी बोलू लागलो की, आता शाळा सुरु झाली असा आवाज येत असे. सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते साहेबांचा नेहमी आवाज असावयाचा की, आता शाळा सुरु झाली. परंतु आमचे सन्माननीय सदस्य श्री. वसंतराव खोटे साहेब असतील, सन्माननीय सदस्य श्री. विक्रमजी काळे असतील, आदरणीय सदस्य श्री. भगवानराव साळुंखे साहेब असतील, आमचे बंधू असतील, आम्हाला या ठिकाणी शिक्षकांच्या संदर्भातील प्रश्न सोडविण्याची निश्चितपणे संधी मिळाली. या संदर्भात आदरणीय सदस्य श्री. रामनाथ मोते साहेबांचे मला नेहमी मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभत गेले याचा देखील मला सार्थ अभिमान आहे.

यानंतर श्री. खंदारे

प्रा.दिलीपराव सोनावणे....

महाराष्ट्राची प्रगती लोकांचे प्रश्न सोडविण्यामध्ये आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविले तर राज्याचा विकास करण्याची संधी मिळत असते. हा मला अनुभव मिळाला आहे.

सभापती महोदय, आपण मला येथे काम करण्याची संधी दिली आहे. त्या संधीचे काही प्रमाणात सोने करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे त्याचाही मनापासून मला आनंद वाटत आहे. मी या सभागृहाचा आनंदाने निरोप घेत आहे. या सदन्याचे आभार मानत असताना एक निराळा आनंद माझ्या मनामध्ये आहे. शिक्षक हा समाजप्रिय, समाजशील प्राणी आहे. त्याच्या संदर्भात भारताच्या संविधानामध्ये स्वतंत्र मतदार संघ तयार होत असताना शिक्षक मतदार संघ तयार झाला. समाजाचे प्रतिक म्हणून समाजामध्ये राहणारा म्हणून त्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी शिक्षक आमदारांना मिळत असते. या मतदार संघाबाबत कोठे तरी वेगळा विचार सुरु असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. त्याबाबत वेगळ्या भावना तयार होत असल्याचे समजत आहे. मी या सभागृहाला आणि माननीय सभापतींनाही विनंती करीत आहे की, शिक्षक मतदार संघातील सदस्य केवळ शिक्षकांचेच प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत तर समाजाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात. त्या काळामध्ये खूप खूप अडचणी होत्या, शिक्षकांचे प्रश्न मांडणारे कोणी नव्हते, समाजामध्ये, लोकांमध्ये राहणारा शिक्षक आहे. पण त्यावेळी केवळ पदवीधर मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य होते. ते प्रतिनिधी आजही त्यांच्या पध्दतीने त्यांचे काम करीत आहेत. शिक्षक मतदार संघाबाबत वेगळा विचार न करता त्यांच्या जागा वाढवाव्यात. सरपंच किंवा अन्य माध्यमातून काम करणारे लोकप्रतिनिधी असतील त्यांनाही येथे काम करण्याची संधी द्यावी. पण शिक्षक मतदार संघ अबाधित ठेवावा अशी मी विनंती करतो.

सभापती महोदय, माझ्या बरोबर निवृत्त होणाऱ्या काही सन्माननीय सदस्यांना या सभागृहात परत काम करण्याची संधी मिळू शकेल. मघाशी माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, मी या सभागृहात परत सदस्य म्हणून येणार नाही. आमचे नेते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांना मी दोन वर्षांपूर्वी हे म्हटले होते. मी ज्या पक्षामध्ये, संघटनेमध्ये काम करीत आहे तो पक्ष आदरणीय श्री.पवार यांच्या नेतृत्वाखाली व मार्गदर्शनाखाली काम करीत आहे. आमच्या पक्षाचे,

2....

NTK/

प्रा.दिलीपराव सोनावणे....

पीडीएफचे नो रिपिटेशन व रोटेशन असे सूत्र ठरलेले आहे. त्यामुळे मला पुन्हा संधी मिळणार नाही. परंतु मला स्वतःची चिंता नाही. कारण आमच्या पक्षाचे नेते माझ्यावर दुसरी जबाबदारी सोपवतील याची मला खात्री आहे. या सभागृहामध्ये माझ्या पक्षाच्या व संघटनेच्या माध्यमातून मला काम करण्याची संधी मिळाली आहे. सभापती महोदय, मला आपण माझ्या भावना मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो. मी सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. या सभागृहाच्या माध्यमातून त्यांचेही काम निश्चितपणे चालू राहणार आहे. मी सन्माननीय सदस्यांची वेळोवेळी भेट घेत राहीन एवढेच या निमित्ताने सांगून माझे दोन शब्द संपवितो.

-----

3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

NTK/

श्री.कपिल पाटील (मुंबई विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, मी निरोप घेण्यासाठी नाही पण पुन्हा या सभागृहात येण्यासाठी मला सर्वांनी दिलेल्या शुभेच्छांचे बळ मुठीत धरण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे.

सभापती महोदय, आपण आणि माननीय उप सभापतींनी मला जे मार्गदर्शन दिले त्यामुळे मी या सभागृहात थोडीशी कामगिरी करू शकलो. आपण मला पहिल्या दिवसापासून अतिशय ममत्वाने येथील नियमांची, कायदांची, परंपरेची जाणीव करून दिली आहे. त्यामुळे आपणा दोघांच्याही ऋणामध्ये सदैव राहण्यास मला आवडेल. या सभागृहामध्ये मी 6 वर्षे सदस्य म्हणून काम करित असलो तरी सभागृहाच्या पत्रकार गॅलरीमधून मी 15 ते 20 वर्षे हे सभागृह पहात आलो आहे. या काळात माझा अनेक नेत्यांशी जवळचा संबंध आला आहे तसा तो पूर्वीही होता. आजच्या या प्रसंगी मला तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री.विलासराव देशमुख यांची आवर्जून आठवण होत आहे. कारण त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये शिक्षणाच्या संदर्भातील अनेक महत्वाचे प्रश्न मी सोडवू शकलो. मग रात्रशाळांचा प्रश्न असेल, वस्तीशाळांचा प्रश्न असेल. सच्चर अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी असा मी सातत्याने आग्रह धरत होतो.

यानंतर श्री.शिगम....

श्री. कपिल पाटील...

त्यांनी पुन्हा ती संधी दिली आणि त्यातूनच अल्पसंख्याक विभाग सुरु होऊ शकला आणि मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या प्रश्नांना मला ऐरणीवर आणता आले.

जुलैच्या पुरामध्ये अनेक शाळांच्या इमारती वाहून गेल्या होत्या. मी त्या शाळांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे असा आग्रह विलासरावजीकडे धरला आणि त्यांनी तीन शाळांसाठी नवीन को-या इमारती उपलब्ध करून दिल्या. हे पहिल्यांदाच घडले होते. कारण पुनर्वसनाच्या बाबतीत तशी कोणतीही तरतूद नव्हती. नवीन मुख्यमंत्री माननीय श्री. पृथ्वीराजजी चव्हाण आल्यानंतर पुन्हा मला शाळांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधता आले आणि एका मोठ्या प्रश्नाला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी न्याय दिला. त्यांचे ऋण मला व्यक्त केले पाहिजे. झोपडपट्ट्यामधील शाळांना अधिकचा एफएसआय मिळावा, त्यांना चांगल्या इमारती मिळाव्यात, चांगले पर्यावरण मिळावे यासाठी मी आग्रह धरला. एफएसआयच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोबीने निर्णय घेतलेला नाही असे सांगितले जाते पण सार्वजनिक महत्वाचा विषय असेल तर मुख्यमंत्री विलंब लावत नाहीत हे मला झोपडपट्टीमधील शाळांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात लक्षात आले. त्यांनी एक क्षणही विलंब लावला नाही. अधिका-यांनी आश्चर्य व्यक्त करून हा एफएसआय तुम्हाला कसा काय मिळाला अशी विचारणा केली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितले की, हा शाळांसाठीचा एफएसआय आहे. बिल्डरांसाठी हा एफएसआय नाही. म्हणून अत्यंत कृतज्ञतेने मला माननीय मुख्यमंत्र्यांचे ऋण व्यक्त करावेसे वाटतात.

सभापती महोदय, या सभागृहाचे नेते आदरणीय श्री. अजितदादा पवार यांचा आणि माझा परिचय या सभागृहामध्ये येण्याच्या आधीपासूनचा आहे. तिरुपतीला मी काँग्रेसचे अधिवेशन कव्हर करण्यासाठी गेलो होतो त्यावेळी ते मला भेटले होते. विमानामध्ये त्यांच्या बाजूची सीट मला मिळाली होती. ते केवळ पुतणे नाहीत तर खरोखर सत्यशोधकीय विचारांचा वारसा त्यांच्या ठायी आहे आणि त्यांची भूमिका ही पक्की इहवादी आहे हे मला त्या भेटीतील क्षणामध्ये जाणवले. तेव्हा पासून मला त्यांच्याबद्दल आदर आणि प्रेम वाटत आले आहे. आदरणीय मंत्री महोदय श्री. छगन भुजबळ हे या सभागृहामध्ये कधी विरोधी बाकावर तर कधी सत्ताधारी बाकावर अनेक वादळे निर्माण करीत उभे आहेत. पण समता परिषदेची स्थापना असेल किंवा त्यांनी केलेले पहिले राजकीय बंड असेल, त्या प्रत्येक वेळी मला त्यांचा जवळून साक्षीदार होता आले. त्यांच्या प्रत्येक

....2...

श्री. कपिल पाटील...

सामाजिक चळवळीमध्ये मग ती ओबीसींची चळवळ असेल, मागासवर्गीयांची चळवळ असेल, त्यांच्या सोबत मला काम करता आले. त्यांनीही सातत्याने मला प्रेमाने सोबत घेतले. त्यांचेही ऋण मला या निमित्ताने व्यक्त केले पाहिजेत.

सभापती महोदय, मी शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून या सभागृहामध्ये आलो. मला तिन्ही शिक्षण मंत्र्यांचे मनापासून ऋण व्यक्त केले पाहिजेत. सुरुवातीला माननीय मंत्री महोदय श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे शिक्षण खाते होते. त्यांनी विनाअनुदानित शाळांच्या संदर्भातील "कायम" शब्द काढण्यास मदत केली. त्यांचेही ऋण मी व्यक्त करतो. त्यानंतर काही काळ हे खाते माननीय मंत्री महोदय श्री. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होते. त्यानंतर आता हे खाते माननीय मंत्री महोदय श्री. राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे आहे. त्यांचे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री महोदय श्री. राजेश टोपे या दोघांचेही मी ऋण व्यक्त करतो. परवा एका प्रश्नाच्या संदर्भात मंत्री महोदय श्री. राजेश टोपे यांनी न्याय दिला आणि माननीय मंत्री महोदय श्री. राजेंद्र दर्डा यांनी अनेक प्रश्नामध्ये मला न्याय दिला. मुंबईतील शिक्षकांचा पगार 1 तारखेला होण्याची मी वाट पहात होतो. सहकार क्षेत्रातील बँकाकडून पगार काढून ते राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये आणणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. हे केवळ मंत्री महोदय श्री. राजेंद्र दर्डा यांच्यामुळेच शक्य झाले.

सभापती महोदय, मला हे त्रिवार सांगितले पाहिजे की, या सभागृहाचे माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. विनोद तावडे हे विद्यार्थी चळवळीपासूनचे माझे मित्र आहेत. ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे आणि मी छात्र भारतीचा कार्यकर्ता होतो. पण आमची अतूट मैत्री होती. आमच्यामध्ये कधी कटुता आली नाही. संघर्ष तिथेही होत होते आणि सभागृहातही होत होते. पण तो संघर्ष विचारांचा असतो. व्यक्तिगत जीवनामध्ये अत्यंत प्रेमळ असे व्यक्तिमत्व माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. विनोदजी तावडे यांचे आहे.

सभापती महोदय, आदरणीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांचा मला येथे उल्लेख केला पाहिजे. विरोधी पक्षातील एका पक्षाचे गटनेते असतानाही त्यांनी मला विरोधी पक्षाचाच एक असल्यासारखे प्रेम दिले. त्याबद्दल मला त्यांचे ऋण व्यक्त केले पाहिजे. श्री. दिवाकर रावतेसाहेबांनी मला अडवत असतानाही खूप प्रेम दिले. लॉबीत गेल्या नंतर मला सांगायचे की मी

..3..

श्री. कपिल पाटील...

तुला अडवत असलो तरी तू योग्य बोललास, तुझे भाषण निश्चितच चांगले झाले. शिक्षण सेवकांच्या मुद्यावर त्यांनी मला जे बळ दिले त्यामुळेच प्रसंगी निर्णय होऊ शकले.

...नंतर श्री. गिते...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.कपिल पाटील...

त्यावेळी त्यांनी अतिशय ठामपणे माझ्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली.

सन्माननीय सदस्य श्री. उल्हासदादा पवार, श्री. अरुणभाई गुजराथी, श्री. हेमंत टकले यांचा मला आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख केला पाहिजे. त्यांच्याशी माझा जुना ऋणानुबंध आहे. सांस्कृतिक व सामाजिक चळवळीशी नाते असल्यामुळे, साने गुरुजीचा संबंध असल्यामुळे या मंडळीचा मला अतिशय स्नेह सातत्याने मिळाला आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. अरुण गुजराथी हे या सभागृहातील साने गुरुजीच आहेत. माझ्या सोबत छात्रभारतीमध्ये त्यावेळेस चळवळीत असलेले सन्माननीय सदस्य श्री. राजेद्र गावित हे आता मंत्री आहेत. त्यांनी नंतर आदिवासी एकता परिषद बांधली. पण आम्ही एकत्रितपणे काम केले ही गोष्ट मला सांगितली पाहिजे. सभागृहामध्ये लोकशाहीची परंपरा चालवित असताना आपण लोकांचे प्रतिनिधी असतो. आपण काही वरून आलेलो राज्यकर्ते किंवा नेते नाहीत. लोकांचे प्रतिनिधीत्व आपण करीत असतो. लोक खरे राजे आहेत. सर्व मर्यादा सांभाळून सभागृहात काम करावे लागते.

महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव सोनवणे हे पुन्हा या सभागृहात सदस्य म्हणून येणार नाहीत. परंतु त्यांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षकांवर आणि पदवीधरांवर प्रचंड विश्वास टाकला आणि जबाबदारी सोपविली. त्या जबाबदारीला पात्र होण्यासाठीचा प्रयत्न या सभागृहात प्रामाणिकपणे केलेला आहे. मी ही भावना व्यक्त करीत असताना सन्माननीय सदस्य श्री. अनिल तटकरे, नाटकांमध्ये रामकृष्ण परमहंसाची भूमिका करणारे व सभागृहात अतिशय निष्ठेने काम करणारे सन्माननीय सदस्य श्री. संजय केळकर, बाबा आमटेच्या मिशनने मेळघाट आणि ठाणे जिल्हयामध्ये कुपोषित बालकांसाठी काम करणारे डॉ.दीपक सावंत, विदर्भात काम करणारे सन्माननीय सदस्य श्री.जेनुदीन जव्हेरी, लातूरची तटबंदी सांभाळणारे आमचे मित्र सन्माननीय श्री.दिलीपराव देशमुख, माननीय श्री. भुजबळ साहेबांचे जवळचे स्नेही सन्माननीय सदस्य श्री.जयंतराव जाधव, विदर्भातील सन्माननीय सदस्य श्री. जगदीश गुप्ता, परभणीचे सन्माननीय सदस्य श्री. सुरेश देशमुख या सर्वांबद्दल मी स्नेह व्यक्त करतो आणि माननीय सभापती महोदय, आपल्याबद्दल आणि माननीय उप सभापतींबद्दल मी ऋण व्यक्त करतो व माझे मनोगत पूर्ण करतो.धन्यवाद.

2...



श्री. जैनुदीन जव्हेरी ( वर्धा,चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी संस्था ) : सभापती महोदय, मी वर्धा,चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी संस्थामधून निवडून आलेलो आहे. मी सभागृहात आल्यावर "जय विदर्भ" असे मोठया आवाजात बोलल्यानंतर माझ्यावर टीका करण्यात येते. बल्लारपूर शहर ऐतिहासिक आहे. बल्लारपूर शहर हे संपूर्ण भारताचे एक प्रतीक आहे. त्या ठिकाणी काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथील सर्व लोक आहेत. या शहरात पूर्वीपासून एक मोठी पेपर मील आहे. तसेच तेथे दगडी कोळशांच्या खाणी आहेत. आम्ही प्रथम भारतीय आहेत, हिंदुस्थानी आहोत. कारण तेथील मी नेतृत्व करतो. लहानपणापासून मी राजकारणात आहे. वयाच्या 16 व्या वर्षापासून काँग्रेस पक्षात आहे. प्रथम मी सेवादलात होतो. नंतर युवक काँग्रेस, नंतर काँग्रेस असा माझ्या जीवनाचा प्रवास सुरु झाला.

महोदय,मला काँग्रेस पक्षाकडून खूप प्रेम मिळाले. माननीय देवतळे साहेब, नरेंद तिडके साहेब यांनी मला खूप काही शिकविले. मी अतिशय लहान कार्यकर्ता होतो तरी देखील मुंबईला फोन केला तर आमची कामे होत होती. आजही मला पूर्वीप्रमाणेच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून प्रेम मिळत आहे. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांकडून देखील मला खूप प्रेम मिळाले आहे. मी चंद्रपूर, बल्लारशहा सोडून मुंबईच्या राजकारणात आलो. त्यावेळी मला असे माहिती झाले की, विदर्भाच्या विकासाचे अनेक प्रश्न आहेत. विदर्भातील उद्योगाच्या संदर्भातील प्रश्न आहेत. कास्तकारांचे प्रश्न मोठया प्रमाणात आहेत. नक्षलाईटचा प्रश्न आहे, असे महत्वाचे प्रश्न आहेत. विकास कामे करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांकडून मला चांगल्या प्रकारे सहकार्य मिळालेले आहे. त्यामुळे काही प्रश्न सोडविण्यात माझा देखील वाटा आहे असे मी नम्रपणे सांगू इच्छितो.

महोदय, या सभागृहात बैठक सुरु झाल्यानंतर मी "जय विदर्भ" असे बोललो तर सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते थोडे नाराज होतात. परंतु ज्यावेळी विदर्भातील प्रश्न सभागृहात चर्चेसाठी येतात, त्यावेळी मात्र ते आमच्या पाठीशी उभे राहून आक्रमकपणे बोलतात.

यानंतर श्री. भोगले...

श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी.....

या ठिकाणी मी काही बोलू शकत नाही. किमान आम्ही "जय विदर्भ" म्हटले तर आपण राग मानू नये. माझ्या गावातील जे आमचे मित्र आहेत, कास्तकार आहेत त्यांना असे वाटेल की, आमचा कोणीतरी माणूस आहे. जो सभागृहात आमच्या वतीने "जय विदर्भ" म्हणतो आहे. त्यामुळे आपण नाराजी ओढवून घेऊ नये. आम्ही विदर्भात रहात असलो तरी प्रथम भारतीय आहोत.

सभापती महोदय, एक गोष्ट मी प्रामाणिकपणे सांगू इच्छितो की, जी नेतेमंडळी आहेत, उद्योगपती आहेत त्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, छोटी छोटी राज्ये निर्माण केली तर जलद विकास होऊ शकतो. भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत केंद्र सरकारने छत्तीसगड, उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीला मान्यता दिली होती. छत्तीसगड राज्यातील मजूर आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मजुरीसाठी येत होते. त्यांना दररोज 20 ते 30 रुपये मजुरी मिळत होती. परंतु छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्या भागातून मजूर येणे बंद झाले. आज चंद्रपूर जिल्ह्यात मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. विदर्भामध्ये भरपूर खनिज संपत्ती आहे. कोकणात सर्वात जास्त पाऊस पडतो. परंतु पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता समुद्रात वाहून जाते. मुंबई व कोकणात पाऊस सुरु झाल्यानंतर विदर्भात पाऊस येतो. विदर्भात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते. आजही आमच्या भागात 150 ते 200 फुटावर जमिनीमध्ये पाणी लागते. पश्चिम महाराष्ट्रात 500 ते 600 फुटावर जाऊनही पाणी लागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आमच्या भागात खनिज आहे, जंगल आहे, परंतु आमच्या नशिबी प्रदुषणाची समस्या लाभली आहे. जंगल आमच्या भागात असले तरी पैसा आमच्याकडे येत नाही. खनिज आमच्याकडे असले तरी पैसा आमच्याकडे येत नाही. त्यामुळे आम्ही त्या भागातील लोकांसाठी "जय विदर्भ" म्हटले तर राग मानू नये.

सभापती महोदय, मी सहा वर्षे या सभागृहाचा सदस्य राहिलो आहे. पुन्हा निवडून येईन की नाही हे आज सांगता येत नाही. परंतु पक्ष नेतृत्वाकडे मी प्रेमाने विनंती करणार आहे. मला माननीय सभापती श्री.शिवाजीराव देशमुख, माननीय उप सभापती श्री.वसंतराव डावखरे, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.विलासराव देशमुख, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण व आजचे मुख्यमंत्री श्री.पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.अजितराव पवार तसेच मंत्रिमंडळातील माननीय मंत्री यांचे खूप सहकार्य लाभले आहे. मी ज्या ज्यावेळी बल्लारशाह, चंद्रपूर येथील नगरपरिषदेचे

..2..

श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी.....

प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे गेलो त्या त्यावेळी मला खूप सहकार्य लाभले आहे. 25 वर्षे मी नगरपरिषद सदस्य होतो. मी निवडून आलो, त्या निवडणुकीला तीन सदस्य उभे होते. परंतु मी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता होतो, त्या पक्षातील सदस्यांचे प्रेम होते म्हणून मी निवडून आलो.

सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री.हेमंत टकले यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी अल्पसंख्याक समाजाचा आहे. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद अनेक अल्पसंख्याक नेत्यांनी भूषविले आहे. मुंबईमध्ये आमच्या समाजाचा खूप मोठा भाग आहे. मला यापुढेही असेच प्रेम मिळेल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. मी ज्या ज्यावेळी माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री यांच्याकडे नगरपरिषदेला निधी मिळावा म्हणून गेलो होतो त्या त्यावेळी मला सहकार्य मिळाले आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हयाचे अनेक प्रश्न व समस्या शिल्लक आहेत. माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री यांचे आशीर्वाद लाभले आणि ईश्वराची कृपा झाली तर मी पुन्हा सभागृहात निवडून येईन. त्यांचे माझ्यावर खूप प्रेम आहे. मला निरोप देऊ नका. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले खास आभार मानतो.

नंतर श्री.खर्चे...

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी .....

शेवटी मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की, काहीही असो आपण सर्व भारतीय आहोत आणि पुन्हा सांगतो की, चंद्रपूर-बल्लारपूर सारख्या भागातून मी आलेलो आहे. माझे वडील विदर्भवादी होते, माझे काका, मामा सुध्दा विदर्भवादीच होते, त्यांच्या आशीर्वादाने मी किमान आमदार तरी झालो म्हणून काही द्या अथवा नका देऊन पण "जय विदर्भ" असे तरी म्हणू द्यावे अशी विनंती करतो आणि उपस्थितांचे आभार व्यक्त करुन माझे भाषण पूर्ण करतो.

-----

.....2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. जयवंतराव जाधव (नाशिक विभाग पदवीधर) : महोदय, मी या सभागृहाचा सदस्य म्हणून आलो आणि फार थोड्या कालावधीनंतर आज निवृत्तीचा समारंभ होत आहे या दरम्यानचा काळ अतिशय सुखद राहिला. हा सुखद काळ अविस्मरणीय असाच म्हटला पाहिजे. एका सर्व सामान्य कुटुंबातील मी कार्यकर्ता होतो आणि या सभागृहाचा सदस्य होऊ शकतो याचे कौतूक वाटते. खरे तर मला ही संधी आदरणीय मंत्री महोदय श्री. छगन भुजबळ साहेब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार तसेच माननीय शरदराव पवार यांच्यामुळे मिळाली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. या सभागृहाच्या बाबतीत बाहेर जेव्हा चर्चा ऐकायला मिळत होती तेव्हा खूप मोठी व महत्वाची चर्चा असल्याचे आम्हाला जाणवत होते पण मी आता प्रत्यक्ष काही दिवस हा सुखद अनुभव सुध्दा घेतला. सभागृहातील आमचे सहकारी सन्माननीय सदस्य सर्वश्री अनिल भोसले, संदिप बाजोरिया, किरण पावसकर, विक्रम काळे, विनायक मेटे यांचेही चांगले सहकार्य लाभले असून आम्ही एकत्रच जेवायला जात होतो. मग आज या मंत्री महोदयांकडे कोणत्या मंत्र्यांकडे जेवायला जात होतो तर कधी दुसऱ्या मंत्र्यांकडे जेवायला जात होतो.

महोदय, माझ्या शहरातून आलेले आमचे ज्येष्ठ सहकारी माननीय श्री. हेमंत टकले आणि जयप्रकाश छाजेड यांनी तर आपल्या घरातील मुलाप्रमाणेच सांभाळून घेतले, प्रसंगी मार्गदर्शनही केले. तसेच ज्येष्ठ सदस्य माननीय श्री. उल्हास पवार आणि सन्माननीय सदस्य सर्वश्री. अनिल भोसले, दिपक साळुंखे, संदिप बाजोरिया, किरण पावसकर, सतीश चव्हाण श्री. रमेश शेंडगे यांनी देखील चांगल्या प्रकारे सहकार्य केले त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तसेच सभागृहात प्रश्न कसा टाकावयाचा हे देखील त्यांच्याकडूनच मी शिकलो आणि नंतर तर तेच मला त्यांचे प्रश्नही टाकायला सांगत होते. तसेच मंत्रिमंडळातील मंत्री महोदयांचेही मला या काळात चांगले सहकार्य लाभले म्हणून मी सामाजिक कामे करू शकलो. माझ्या निरोप समारंभासाठी माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य मंत्री तसेच इतर मंत्री गण उपस्थित आहेत, माझ्याबद्दल त्यांनी गौरवाचे शब्द काढले यातच मी भरून पावलो. त्याचबरोबर माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. विनोद तावडे हे आमचे विद्यार्थी दशेपासूनचे मित्र आहेत. माननीय ज्येष्ठ नेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांचे भाषण मी नेहमीच लक्षपूर्वक ऐकत होतो. तसेच ज्येष्ठ सदस्य माननीय श्री. दिवाकर रावते यांनी माझ्या बद्दल जे गौरवोद्गार काढले त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. आमच्या वडिलांनी चांगले संस्कार केले आहेत तसेच पक्षानेही आमच्यावर संस्कार करून सामाजिक कार्य करण्यासाठी येथे आम्हाला पाठविले त्याचे आज फलित झाले असे मी समजतो.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

श्री. जयवंतराव जाधव ...

प्रा. सुरेश नवले साहेबांवर शिवाजीराव भोसले यांचे संस्कार झालेले आहे. अशा सर्व महानुभवांचा ठेवा, सहकार्य आम्हाला मिळाले आहे. या सभागृहात मा. सभापती, मा. उप सभापती किंवा तालिका सभापती यांनीही आम्हाला चांगले सहकार्य केलेले आहे. आमचा विशेष उल्लेख अगोदर दिला नसला तरी विशेष उल्लेख मांडण्याची संधी आम्हाला तालिका सभापतींनी दिलेली आहे.

सभापती महोदय, थोड्या वेळा पूर्वीच मला मा. गृहमंत्री भेटले व त्यांनी माझी चांगल्या प्रकारे विचारपूस केली. नाशिक येथील प्रचाराला मला व मा.अजित दादांना यावयाचे आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे. सगळ्या मंडळींनी आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे. मला सांगावेसे वाटते की, सभागृहाच्या कामकाजामध्ये प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, सह सचिव श्री.यु.के.चव्हाण, उप सचिव भाई मयेकर, विशेष कार्य अधिकारी श्री.श्रीनिवास जाधव यांचे मला चांगले सहकार्य मिळाले आहे. हे अधिकारी तुमचे भाषण चांगले झाले अशी एक ओळीची चिठ्ठी लिहून पाठवित असत त्यामुळे आम्हाला बळ मिळत असे. विधानमंडळाचा स्टाफ किंवा आमचे दप्तर आणून देणारे टोपीवाले मामा या मंडळींचेही सहकार्य आम्हाला लाभले आहे. त्यामुळे टोपीवाल्यांपासून ते सभापतीपर्यंत व माझ्या सहकाऱ्यांपासून ते मा.मुख्यमंत्र्यांपर्यंत मला जे सहकार्य मिळाले त्या सर्वांच्या ऋणात राहून मा. अजित दादा व मा. भुजबळ साहेबांनी जो आशीर्वाद दिलेला आहे त्या आशीर्वादाच्या बळावर पुनश्च भेटण्याचा प्रयत्न करू.

धन्यवाद.

---

..2..

**सभापती :** सदनातील 10 सहकाऱ्यांना आज शुभेच्छा देण्याचा हा प्रसंग आहे. या 10 सदस्यांनी आपल्या वागण्याने, बोलण्याने सभागृहातील चर्चेत भाग घेऊन जी आपुलकी निर्माण केली त्या माझ्या सन्माननीय सहकाऱ्यांना शुभेच्छा किंवा निरोप देण्यासाठीचा आजचा हा कार्यक्रम आहे. समाजामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये कसून काम केल्यानंतर या वरिष्ठ सभागृहात येण्याची संधी मिळत असते. या सभागृहात येत असतांना ज्या समाजाच्या आशीर्वादाने आपण येथे येतो त्या समाजाचे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक अनेक प्रश्न असतात. या सर्व क्षेत्रात आपापल्या परीने या ठिकाणी पोटतिडकीने प्रश्न मांडणे, प्रश्न सोडवून घेणे अशा पध्दतीने गेल्या सहा वर्षांपासून माझ्या सर्व सहकार्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेली आहे. या 10 सदस्यांना निरोप देत असतांना या सन्माननीय सदस्यांनी पुन्हा या वरिष्ठ सभागृहात यावे अशी माझी व्यक्तिगत शुभेच्छा आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री.अनिल तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यात अप्रतिम काम केलेले आहे. संघटना कशी बांधावी यादृष्टीने त्यांनी जे काम केलेले आहे ते उत्कृष्ट असे आहे. त्यांना या ठिकाणी काम करण्यासाठी फार अल्प वेळ मिळालेला आहे.

त्याच पध्दतीने सन्माननीय सदस्य श्री. दिलीपराव देशमुख यांनी मराठवाड्यात, लातूर जिल्ह्यात अत्यंत आखीव-रेखीव अशा पध्दतीचे काम केलेले आहे. त्यांनी साखर कारखान्याचे क्षेत्र अत्यंत चांगल्या पध्दतीने बांधलेले आहे. त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा राज्य सहकारी बँकेमध्ये फार चांगले काम केलेले आहे. सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी यांच्यासाठी पोटतिडकीने काम केलेले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणूनही त्यांनी जबरदस्त जिद्दीने काम केलेले आहे.

यानंतर श्री. भारवि...

**माननीय सभापती....**

मधल्या काळामध्ये 2-3 महिने काहीसे आजारी असल्यामुळे ते सभागृहामध्ये कमी आले. सामान्यातील सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडविण्याकरिता अशा प्रकारचे कमिटेड कार्यकर्ते सदनामध्ये असण्याची गरज आहे.

त्याच बरोबर सन्माननीय सदस्य श्री.सुरेशदादा देशमुख यांनी परभणी जिल्ह्यामध्ये अत्यंत चांगले काम केले आहे. ते परभणीचे नगराध्यक्ष होते. परभणी-मराठवाड्यातील सातत्याने प्रश्न मांडणाऱ्या सदस्यांपैकी ते एक आहेत.

सन्माननीय सदस्य श्री.जगदीश मोतीलाल गुप्ता हे अमरावती जिल्ह्यातील आहेत. यापूर्वी त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळामध्ये काम केले आहे. विधान परिषदेमध्ये ज्या ज्या वेळी ते होते त्या त्या वेळी त्यांनी विदर्भातील, राज्यातील प्रश्न अत्यंत जिद्दीने मांडले आहेत.

सन्माननीय सदस्य श्री.जैनुद्दीन मोहसीनभाई जव्हेरी म्हणजे अत्यंत खुल्या मनाचे कर्तृत्व आहे असे मला वाटते. त्यांचे हिंदीवर प्रभुत्व आहे. पण सातत्याने मराठी बोलण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. न कळत एखादा चुकीचा शब्द गेला तरी ते दुरुस्त करून बोलतात. विदर्भाच्या प्रश्नासंबंधी त्यांच्या मनामध्ये तळमळ आहे. विदर्भाचे चटके भोगणाऱ्यांची जी भावना आहे तीच त्यांची आहे. सदनामध्ये 6 वर्षे काम करीत असताना विदर्भातील विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता त्यांनी सातत्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. त्यांना पुन्हा एकदा या सदनामध्ये येण्याची संधी माझ्या पक्षाने द्यावी अशी माझी त्यांच्याबाबत अपेक्षा आहे.

अल्प काळात एखादा लोकप्रतिनिधी कसे कसून काम करू शकतो याचे आगळे वेगळे उदाहरण म्हणून सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव यांच्याकडे मी पाहीन. एक ते सव्वा वर्षे या सदनात काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. विधान परिषदेमधील तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, इत्यादी आयुधांचा अचूक वापर त्यांनी केला आहे. हे करीत असताना परिपूर्ण माहिती देऊन त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडून उत्तर घेण्याचे काम त्यांनी केले आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील प्रश्न त्यांनी सोडवून घेतले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक विषया संबंधी सातत्याने अतिशय परिश्रमपूर्वक काम करणारा अल्पकाळातील आमदार असे म्हणून कोणाला बक्षिस देण्याचा प्रसंग आला तर ते बक्षिस सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव यांना निश्चितच मिळेल.



**माननीय सभापती....**

सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर हे अत्यंत अभ्यासू आणि ध्येयवादी आहेत. ते त्यांच्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत. सर्वसामान्य समाजाचे जे प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करणे हा त्यांचा गुण आहे. एखादा प्रश्न उचलून धरल्यानंतर त्याचे उत्तर मिळविण्याच्या दृष्टीने शेवटपर्यंत काम करणारा असा माझा सहकारी आहे.

सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक रामचंद्र सावंत म्हणजे या विधान परिषदेतील चालता-बोलता आरोग्य विभाग आहे असे मी म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. त्यांनी राज्यातील आरोग्य विषयक बाबीवर चांगली चर्चा केली आहे. अनेक मूलभूत प्रश्न मांडले आहेत. त्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागावर अत्यंत चांगले मूलभूत प्रश्न मांडून ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक रामचंद्र सावंत यांच्याकडे अत्यंत हुशार, कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा, प्रामाणिक ध्येयवादीवृत्तीचा कार्यकर्ता म्हणून मी बघतो.

यानंतर श्री.सरफरे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्ध झालेले

**सभापती ....**

सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल हरिश्चंद्र पाटील हे मुंबई शिक्षक मतदारसंघामधून या सभागृहामध्ये निवडून आले. त्यापूर्वी ते या सभागृहाच्या गॅलरीमध्ये बसून सभागृहातील कामकाजाचे निरीक्षण करीत असत. अचूक निरीक्षण बरहुकूम काम करणारा माझा एक सहकारी असे मी त्यांचे वर्णन केले तर ते वावगे होणार नाही. एखादा महत्वाचा प्रश्न त्यांनी उचलून धरल्यानंतर मंत्री महोदयांकडून समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यन्त ते आपला प्रश्न सोडत नसत. अशाप्रकारे या सदन्यामध्ये अनेक प्रश्न मांडीत असतांना त्यामध्ये माध्यमिक शिक्षकांचे, प्राथमिक शिक्षकांचे किंवा अन्य क्षेत्रामधील प्रश्न सोडवीत असतांना माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी उत्कृष्ट असे काम केले आहे. याकरिता त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो.

माननीय सदस्य प्रा. दिलीपराव शंकरराव सोनवणे यांनी या विधान परिषद सभागृहामध्ये पुन्हा येण्याची शक्यता नसल्याचे जाहीर करून टाकले. परंतु मला असे वाटते की, यापूर्वीचे आपले एकंदरीत कार्यक्षेत्र पाहिल्यानंतर आपण पंचायत समितीचे सदस्य होता, जिल्हा परिषदेचे सदस्य होता त्या अनुषंगाने त्या क्षेत्रामध्ये सुध्दा अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम करण्याचा कस तुमच्यामध्ये आहे. आपण मितभाषी असल्यामुळे सभागृहामध्ये पाच-सहा प्रश्न विचारल्यानंतर आपण विचारलेला सातव्या प्रश्नावर जास्त वेळ चर्चा होत होती. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून या पुढील काळात अत्यंत चांगले काम करावे या दृष्टीने मी आपणास शुभेच्छा देतो. माझ्या या सर्व सहकारी मित्रांना त्यांच्या भावी आयुष्यात अशाच प्रकारचे कर्तृत्वाचे जीवन उभे करण्याची शक्ती परमेश्वराने आपणास द्यावी अशी प्रार्थना करून मी माझे भाषण संपवितो.

निवृत्त होणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना विशेष निरोप देण्याच्या निमित्ताने विधान भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या पोर्चमध्ये एकत्रित छायाचित्र काढण्याचा व त्यानंतर विधान भवनाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील विधान परिषद सभागृहाच्या लॉबीमध्ये चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया आपण सर्वांनी उपस्थित रहावे.

-----

**पृ.शी./मु.शी.: सलाम मुंबई फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई  
यांच्या वतीने "तंबाखू मुक्त महाराष्ट्र" या विषयावर  
आयोजित केलेल्या चर्चासत्राबाबत घोषणा**

**सभापती :** सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येते की, सलाम मुंबई फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, परेल, मुंबई यांच्या वतीने "तंबाखू मुक्त महाराष्ट्र" या विषयावर बुधवार, दिनांक 18 एप्रिल, 2012 रोजी सकाळी 9.45 ते 10.45 या वेळेत विधान भवन, मुंबई (मध्यवर्ती सभागृह, चौथा मजला) येथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे.

तरी सर्व माननीय सदस्यांनी या कार्यक्रमास उपस्थित रहावे.

सभागृहापुढील कामकाज संपलेले आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होऊन उद्या बुधवार, दिनांक 18 एप्रिल, 2012 रोजी सकाळी 11.00 वाजता पुनः भरेल.

सकाळी 11.00 ते 12.30 वाजेपर्यन्त विशेष बैठक होईल. त्यामध्ये महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 97 अन्वये श्री. दिवाकर रावते, वि.प.स. यांनी उपस्थित केलेली "मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या सवलती व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास होणारा विलंब" या विषयावर चर्चा होईल. त्यानंतर दुपारी 12.45 वाजता सभागृहाची नियमित बैठक भरेल.

-----